www.chauthiduniya.com

# चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 19 मार्च-25 मार्च 2012 | मूल्य 5 रुपये

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और चुनाव परिणाम के मायने

पेज-4

पंजाब पीपल्स पार्टी ने खेल बिगाड़ा

पेज-5

पर्यावरण संबंधी मुक़दमेबाज़ी का नया युग

पेज-7

साई की महिमा

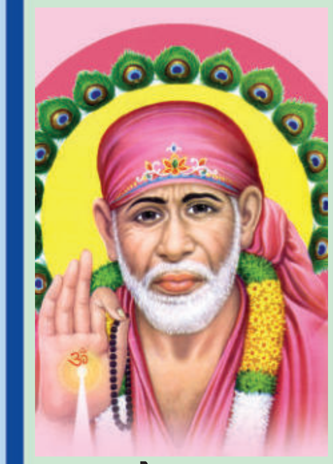

पेज-12

# कांग्रेस ऐसे हारी

सभी फोटो-***प्रभात पाण्डेय***

संतोष भारतीय

दिग्विजय सिंह और परवेज़ हाशमी को फांसी की सज़ा सुनाने की तैयारी हो चुकी है. कांग्रेस हाईकमान ने इन दोनों की राजनीतिक ज़िंदगी पर एक लंबा पूर्ण विराम लगाने का फ़ैसला ले लिया है. बस इसका औपचारिक ऐलान बाक़ी है. उत्तर प्रदेश के अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने पहले कांग्रेस का संगठन चौपट किया, ग़लत पीसीसी मेंबर बनाए. ज़िला एवं ब्लॉक का कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, जो संगठन चलाने की हैसियत नहीं रखते. बाद में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में दूसरी पार्टियों से आए लोगों को कांग्रेस का प्रत्याशी बना दिया. राहुल गांधी का कैंपेन इसलिए बिल्कुल काम नहीं आया. पिछले विधानसभा के 22 विधायकों में से सिर्फ़ आठ विधायक ही जीत कर आ सके. जो 20 नए लोग जीते वे कैसे जीते, इसे बाद में बताएंगे, लेकिन रायबरेली, अमेठी और सुलतानपुर में कांग्रेस पूरी तरह से हार गई. कांग्रेस के भीतर जो कहा जा रहा है कि इन सारी स्थितियों की ज़िम्मेदारी दिग्विजय सिंह और परवेज़ हाशमी की है. और शायद एक छोटी कमेटी बनाई जाए और इन दोनों के ख़िलाफ़ फ़ैसला ले लिया जाए. कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की कमियों को जानना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसके नुक़सान की भरपाई होना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां अभी भी मानसिकता जनता की आकांक्षा, उसकी चाह और उसके सपने को समझने की नहीं बन पाई है. कांग्रेस अभी भी जनता की परेशानियां नहीं जानना चाहती, बल्कि सोचती है कि वह जैसा चाहेगी, वैसे ही जनता को भरमा लेगी. इसलिए शायद वह न तो जनता को समझ पा रही है और न ही अपने कार्यकर्ताओं के मन को. सबसे पहले सोनिया गांधी के बीते 7 मार्च को दिए गए बयान को देखें. सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार का कारण ग़लत टिकट वितरण और महंगाई को बताया. वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नेतृत्व नहीं, नेता ज़िम्मेदार हैं. इन दोनों के बयानों में भी हार की पूरी ज़िम्मेदारी दिग्विजय सिंह और परवेज़ हाशमी पर थोपने का इशारा नज़र आता है.

कांग्रेस द्वारा लिया जाने वाला फ़ैसला और कांग्रेस के भीतर फैलाई जा रही बातें वैसी ही हैं कि कोई जान बूझकर ख़ुद को अधमरा करे और फिर ज़हर भी खा ले और कहे कि हमने दवा खाई है. इस पूरी कहानी में कांग्रेस भविष्य की इबारत लिखने जा रही है. भविष्य की इबारत में 2012 और 2013 में होने वाले हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के चुनाव में अपने लिए हार का फ़ैसला ख़ुद लिखा जाने वाला है. उसके बाद 2014 में आने वाला लोकसभा चुनाव अलग भविष्य लेकर आएगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए. इसलिए हमने खोजबीन की, जांच-पड़ताल की, ताकि हमें सच्चाई का पता चल सके और जिन कारणों को कांग्रेस तलाशना नहीं चाहती या नहीं तलाश पा रही है, उन कारणों को हम तलाशें और कांग्रेस के लोगों के सामने रखें, क्योंकि कांग्रेस का मरना देश में लोकतंत्र के मरने की एक और शुरुआत है. देश में कांग्रेस का मज़बूत रहना, लोकतंत्र के लिए उतना ही ज़रूरी है, जितना लोकतंत्र के हित में भारतीय जनता पार्टी का मज़बूत रहना, वामपंथी दलों का मज़बूत रहना और समाजवादी दलों का मज़बूत रहना. ये दोनों पक्ष और बाक़ी छोटे-छोटे पक्ष अपने सिद्धांत देश के सौ करोड़ से ज़्यादा लोगों के सामने रखें और सभी लोग लोकतंत्र के इस ख़ूबसूरत बग़ीचे में सभी फूलों को खिलाएं, यह बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने हम अनोखी कहानी जो सच में घटी और जिसे कांग्रेस के नेताओं ने घटित किया, उसे रख रहे हैं.

**कांग्रेस द्वारा लिया जाने वाला फ़ैसला और कांग्रेस के भीतर फैलाई जा रही बातें वैसी ही हैं कि कोई जान बूझकर ख़ुद को अधमरा करे और फिर ज़हर भी खा ले और कहे कि हमने दवा खाई है. इस पूरी कहानी में कांग्रेस भविष्य की इबारत लिखने जा रही है. भविष्य की इबारत में 2012 और 2013 में होने वाले हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के चुनाव में अपने लिए हार का फ़ैसला ख़ुद लिखा जाने वाला है. उसके बाद 2014 में आने वाला लोकसभा चुनाव अलग भविष्य लेकर आएगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए.**

बिहार के चुनाव हो चुके थे और कांग्रेस दो सौ करोड़ रुपये ख़र्च करने और राहुल गांधी के सघन प्रचार अभियान के बावजूद पूरी तरह हार गई. तभी लगा था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उस हार से सबक़ लेगी और उत्तर प्रदेश में उन ग़लतियों को नहीं दोहराएगी, जो बिहार में दोहराई गई थीं. लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 21 सांसद जीते और इस जीत ने यह मुग़ालता पैदा किया कि प्रदेश में कांग्रेस रिवाइव हो रही है. उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर था. उसी समय राहुल गांधी ने भी बयान दिया कि कांग्रेस के लिए सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा और जो अपने यहां सबसे ज़्यादा सदस्य बनाएंगे, उन्हें ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा और उन्हीं लोगों के बीच में से प्रदेश समिति के लोग, ज़िला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष चुने जाएंगे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाकर सदस्यता अभियान चलाया. अपने पैसे से घूमें और सचमुच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाकर, किसी ने चार हज़ार किसी ने पांच हज़ार, किसी ने दस हज़ार, किसी ने बीस हज़ार, किसी ने पचास हज़ार सदस्यता और जेनुईन सदस्य बनाए. गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले गए और कांग्रेस का बहुत दिनों के बाद लोगों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की. लोगों को यह अंदाज़ा था कि अब जो संगठन बनेगा, उसमें उन कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी, जिन्होंने सदस्यता अभियान सफलता पूर्वक पूरा करने में जान लगा दी है. लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अचानक पीसीसी के सदस्यों की सूची सामने आ गई. पीसीसी के सदस्यों की सूची आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगा जैसे उन्हें धोखा दिया गया हो.

हुआ यह कि सारे देश में कांग्रेस संगठन बनाने के मुख्य ज़िम्मेदार ऑस्कर फर्नांडिस थे. उन्होंने उत्तर प्रदेश में पवन घटवार, जेडी सीलम, कंग, सूरज और निर्मला सावंत को ज़िम्मेदारी सौंपी. सूरजजी राजस्थान के हैं, निर्मला सावंत महाराष्ट्र की हैं, कंग सरदारजी हैं. जीडी सीलम और पवन घटवार सांसद हैं. इन पांचों ने मिलकर प्रदेश में पीसीसी के सदस्यों की सूची तैयार की. सूची बनाने में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जीडी सीलम साहब और पवन घटवार ने निभाई. उन्होंने जो लिस्ट ऑस्कर फर्नांडिस को दी, उस पर ऑस्कर फर्नांडिस ने दस्तख़त कर दिए. उस दौरान भी प्रदेश में दिग्विजय सिंह और परवेज़ हाशमी ज़िलों-ज़िलों में घूम रहे थे, लेकिन उनसे इसके बारे कोई राय नहीं ली गई. कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बताया कि पीसीसी के सदस्य बनाने में बड़ी धांधली हुई. इसलिए जिन लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया, उन्हें कोई जगह नहीं मिली, बल्कि जिन्होंने बड़ी गाड़ियां दीं, जिन्होंने उनके रहने पर होटलों में पैसे ख़र्च किए, गिफ्ट दिए, जिन्होंने उनको कुछ और भी दिया.

**(शेष पृष्ठ 2 पर)**

मैथ्यु ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इन नियमों का पलन करें और अगर इनका पालन नहीं किया गया तो उनके सर्विस रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया जाएगा.



# दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

## राजस्थान के बाबुओं की परेशानी

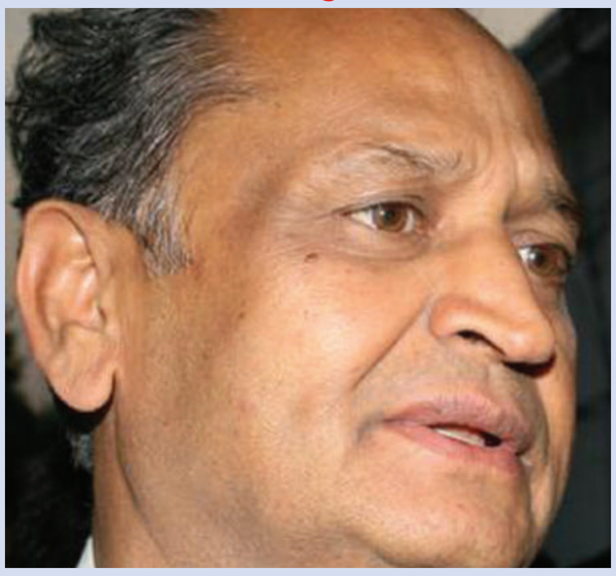

राजस्थान के बाबुओं के लिए फ़िज़ूलख़र्ची अब महंगी पड़ सकती है. पहले तो उनके विदेश जाने को लेकर सरकार ने रुख़ कड़ा कर दिया है. सरकार चाहती है कि बाबू अपने पहले के यात्रा ख़र्च का विवरण देने के बाद ही आगे विदेश यात्रा करेंगे. यही नहीं सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीके मैथ्यु ने एक सर्कुलर निकाला है, जिसमें इस बात का ज़िक्र किया गया है कि बाबुओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है. बाबुओं को इन नियमों का पालन करना है. मैथ्यु ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इन नियमों का पलन करें और अगर इनका पालन नहीं किया गया तो उनके सर्विस रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया जाएगा. यही नहीं उन्होंने सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य सचिव और सचिव को यह निर्देश दिया है कि अपने विभागों में इन नियमों का पालन कराएं. सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा अन्य कई नियम बनाए गए हैं, जिससे बाबुओं की फ़िज़ूलख़र्ची को कम किया जा सके. राज्य सरकार ने सरकारी कामों के लिए किराये पर गाड़ी लेने पर भी रोक लगाई है तथा बाबुओं के यात्रा पर ख़र्च होने वाले धन को कम करने का निर्णय लिया है. अब राजस्थान के सरकारी बाबू तो इससे परेशान होंगे ही.

## बाबुओं की चिंता

ऐसा कम ही होता है कि पंजाब और हरियाणा कैडर के बाबुओं के बीच किसी मुद्दे पर सहमति हो, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आई तो सभी के बीच आपसी सहमति दिखाई दे रही है. बात अगमोट कैडर के अधिकारियों को पंजाब और हरियाणा में कई महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाना है. इसके कारण पंजाब और हरियाणा कैडर के अधिकारी गुस्से में हैं. अब वे अपने संगठन के माध्यम से विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं. जिन पदों पर राज्य कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, उन पर भी अगमोट कैडर के अधिकारियों को नियुक्त किए जाने से राज्य कैडर के अधिकारी चिंतित हैं. राज्य कैडर के अधिकारियों के प्रतिनिधि ने यूटी सलाहकार केके शर्मा से मुलाक़ात की. इस मुलाक़ात में उन्होंने 2006 बैच के अधिकारी प्रेरणा पुरी को आईटी सेक्रेटरी बनाए जाने का विरोध किया है. यह मुद्दा पहली बार नहीं उठा है, इससे पहले भी राज्य कैडर के अधिकारियों को इस बात की शिकायत रही है, लेकिन सरकार ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया. अब यह मामला गरमाता जा रहा है, लेकिन यह मामला आसानी से सुलझता मालूम नहीं हो रहा है.

## स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की राह में बाधा

यह समझा जाता है कि कोई अधिकारी जब चाहे सरकारी नौकरी का परित्याग कर सकता है, लेकिन यह बात सही नहीं है. हाल में चेन्नई में 1983 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी के. अशोक वर्द्धन सेठी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपील की थी. सेठी नगर चेन्नई निगम विभाग में मुख्य सचिव हैं और अभी उनके सेवानिवृत होने में पांच साल का समय है. उन्होंने सेवानिवृत्ति के लिए सितंबर, 2011 में अपील की थी और कहा था कि 9 दिसंबर तक उन्हें पदमुक्त कर दिया जाए. लेकिन एआईडीएमके सरकार ने उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया तथा अब सेठी पर विजिलेंस की नज़र है. जब वह ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में काम कर रहे थे, उस समय वित्तीय अनियमितता के आरोप उन पर लगे थे. अब विजिलेंस ने इसकी जांच शुरू करने की ठानी है. जब सरकार ने उनका अनुरोध ख़ारिज कर दिया तो सेठी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की शरण लेनी पड़ी. कैट ने उनके अनुरोध तथा तर्क को सही पाया और उन्हें सेवानिवृत करने का फ़ैसला दिया. अब तमिलनाडु सरकार को उन्हें सेवानिवृत करना पड़ेगा और तीन महीने के भीतर सेवानिवृत्ति से जुड़े सारे लाभ सेठी को देने होंगे.

dilipcherian@gmail..com

# साउथ ब्लॉक

### मनोज झलानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालए गए

1987 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज झलानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाए गए हैं. वह ब्रज किशोर प्रसाद की जगह लेंगे.

### कविथा निदेशक बनेंगी

1998 बैच की आईसीएएस अधिकारी कविथा गोत्रु को शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) में निदेशक (प्रशासन) बनाया जाना लगभग तय हो गया है. वह आरके कर्ण की जगह लेंगी.

### उत्पल सिंह कृषि एवं सहकारिता विभाग में गए

1986 बैच के आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को कृषि एवं सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह पंकज कुमार की जगह लेंगे, जिन्हें दूरसंचार विभाग में सीवीओ बनाया गया है.

### जगदीश मीना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में

1983 बैच के आईएएस अधिकारी जगदीश प्रसाद मीना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाए गए हैं. जगदीश प्रसाद पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संयुक्त सचिव थे. वह अमृतलाल मीना की जगह लेंगे.

### टीवाई दास जेएस बने

1982 बैच के आईएएस अधिकारी टीवाई दास को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह प्रफुल्ल कुमार पटनायक की जगह लेंगे.

# कांग्रेस ऐसे हारी

पृष्ठ एक का शेष

वे लोग पीसीसी के सदस्य बन गए. इसके बाद दिल्ली में बैठकर ज़िला कांग्रेस के अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए. मज़े की बात यह है कि दिल्ली से जब ज़िला कांग्रेस के अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष की सूची लखनऊ ऑफिस में भेजी गई. इसमें जो नाम और फोन नंबर थे, तो लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर को उन लोगों से संपर्क करने में पसीना आ गया, क्योंकि न तो उनमें से बहुत सारे नाम मैच कर रहे थे और न ही उनके फोन नंबर कहीं मौजूद थे. यह संगठन जिस तरह से बना, वहीं से कांग्रेस ने अपनी हार की भविष्यवाणी ख़ुद लिखनी शुरू कर दी. पीसीसी और ब्लॉक अध्यक्ष का संगठन बनने के बाद यह संगठन दिग्विजय सिंह को सौंप दिया गया. दिग्विजय सिंह और परवेज़ हाशमी से कहा गया कि अब वे चुनाव की तैयारी करें. ये लोग जहां भी गए कार्यकर्ताओं ने इनका ज़बरदस्त विरोध किया. इन लोगों की परेशानी यह थी कि दोनों न कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना कर सकते थे और न जो हुआ है, उसे नकार सकते थे. इन लोगों ने नए आश्वासन देने शुरू किए कि जो काम करेगा और अच्छा काम करेगा, उसे ही टिकट देंगे और कांग्रेस के लोगों को ही टिकट दिया जाएगा. संयोग से उसी समय राहुल गांधी का दूसरा बयान आ गया. राहुल गांधी का पहला बयान सदस्यता अभियान को लेकर था कि संगठन बनाओ और संगठन में से लोग चुने जाएंगे. पवन घटवार, जीडी सीलम और कांग की कमेटी ने ऑस्कर फर्नांडिस से संगठन बनवाया, जो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बना. अब राहुल गांधी का दूसरा बयान आया कि टिकट उसी को दिए जाएंगे, जो साफ और स्वच्छ छवि के होंगे. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक बार फिर विश्वास जगा. नतीजा यह हुआ कि कार्यकर्ताओं ने फिर कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिया.

टिकट बंटवारे का समय आया, क्योंकि चुनाव की घोषणा होने वाली थी. चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी. अचानक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की टिकट बांटने में राहुल गांधी का घर और ऑफिस सबसे महत्वपूर्ण हो गया. वहां पर राहुल गांधी के दोस्त कहें, उनके सचिव कहें, उनके राजनीतिक सलाहकार कहें, उनके मैनेजर कनिष्क सिंह के नेतृत्व में एक ग्रुप का गठन हुआ. उस ग्रुप में पहला नाम मोहन प्रकाश, दूसरा नाम सलीम शेरवानी, तीसरा नाम राज बब्बर, चौथा नाम बेनी प्रसाद वर्मा, पांचवा नाम सलमान ख़ुर्शीद, छठा नाम श्रीप्रकाश जायसवाल और सातवां नाम रशीद मसूद का जुड़ा. इन सात लोगों ने मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों का बंटवारा किया. इन सात लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दो नंबर पर रखा और जो उनकी समझ से जीत सकते थे उन्हें एक नंबर एक पर रखा गया. दूसरी पार्टियों के हारे हुए उम्मीदवारों के नाम रखे और यह तर्क दिया कि अगर चुनाव नहीं जीते तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट देने से क्या फ़ायदा. इसलिए टिकट उसे दो, जो चुनाव जीत सके और इसके लिए इस टीम ने संदेश भेजने शुरू किए. समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पाटियों से जुड़े हुए लोगों को संदेश जाते थे कि राहुल गांधी आपसे मिलना चाहते हैं. वे लोग राहुल गांधी से मिलने आते थे, चाय राहुल गांधी पिलाते थे और जिस आदमी की चाय की प्याली में राहुल गांधी अपने हाथ से चीनी मिला दें, उसे माना जाता था कि उसका टिकट फाइनल हो गया. जिसकी चाय की प्याली में राहुल गांधी चीनी नहीं मिलाते थे, माना जाता था कि उस आदमी को राहुल गांधी ने अप्रूव नहीं किया है. जिसकी प्याली में राहुल गांधी के हाथों चीनी मिल गई, उसे कह दिया जाता था कि आपका टिकट पक्का है. जाइए आप चुनाव की तैयारी कीजिए. जिन लोगों ने दो साल अपने क्षेत्र में काम किया, पैसा ख़र्च किया, कांग्रेस के लिए माहौल तैयार किया, जो कांग्रेस के वफ़ादार थे उनकी टिकट इस टीम ने काट दी. इस टीम ने इसलिए टिकट काट दी, क्योंकि इस टीम में मोहन प्रकाश का कांग्रेस में कोई परिचय नहीं है. यह समाजवादी पार्टी से आए हैं, समझदार हैं, आंदोलनकारी हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नेता रहे हैं. राज बब्बर समाजवादी पार्टी से आए हैं, बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी से आए हैं, रशीद मसूद समाजवादी पार्टी से आए हैं. इसलिए इस टीम ने कनिष्क को और राहुल गांधी को यह समझा दिया कि उन्हीं को टिकट दो, जो जीत सकते हैं. एक बाहरी कांग्रेस तैयार हो गई. कांग्रेस में दो हिस्से हो गए, एक बाहरी कांगेस और एक अंदरूनी कंाग्रेस. लगा जैसे सिंडीकेट का ज़माना लौट आया है. फिर जो बाहरी कंाग्रेस

थी, उसके ख़िलाफ असली कांग्रेस का विद्रोह शुरू हो गया. टिकटें दी गईं, उन टिकटों का विरोध विपक्षी उम्मीदवारों ने उतने कारगर ढंग से नहीं किया, जितना विरोध कांग्रेस के अंदर के लोगों ने किा, जो ख़ुद को असली कांग्रेसी मानते थे. इसलिए राहुल गांधी जहां-जहां गए, वहां अधिकांश जगहों पर उनका विरोध करने वाले, उन्हें काला झंडा दिखाने वाले विपक्ष के लोग नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही लोग थे. तब दिग्विजय सिंह को कार्यकर्ताओं को फोन करना पड़ा कि जो भी हो गया, होने दीजिए. सरकार बनेगी, हमलोग सरकार में आएंगे. मिलीजुली सरकार बनेगी और आपका एडजस्टमेंट होगा. कार्यकर्ताओं ने उनसे बात करने से मना कर दिया. कार्यकर्ता कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने की बजाय उसके विरोध में लग गए.

अब टिकटें कैसे बटीं. स्क्रीनिंग कमेटी में उनकी मीटिंग से एक दिन पहले कनिष्क के दफ्तर से एक शीट जाती थी. जिसमें यह निर्देश होता था कि इन लोगों का टिकट क्लीयर कर दिया जाए. मेरी जानकारी यह बता रही है कि कनिष्क सिंह दिग्विजय सिंह को डिक्टेट करते थे. वह डिक्टेट ही नहीं करते थे, बल्कि डिक्टेट करने के साथ-साथ उनको अपमानित भी करते थे. दिग्विजय सिंह को सूची भेज दी जाती थी कि वह उस पर दस्तख़त करें और उसे स्क्रीनिंग कमेटी को भेज दें और कहा यह जाता था कि राहुल गांधी ऐसा ही चाहते हैं. कनिष्क जिस लिस्ट को भेजते थे उस लिस्ट को फाइनल करने वालों में मोहन प्रकाश, सलीम शेरवानी, राज बब्बर, बेनी प्रसाद वर्मा, सलमान ख़ुर्शीद, श्रीप्रकाश जायसवाल और रशीद मसूद होते थे. पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से टिकटों के बंटवारे हुए, उसने पूरी कांग्रेस पार्टी में अंदर ही अंदर भूचाल ला दिया और हमें यह दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस किसी भी क़ीमत पर 30 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली नहीं है, लेकिन कनिष्क सिंह और उनकी टीम ने सोचा की मीडिया को पैसे बांटकर और लोगों को बेवक़ूफ़ बनाकर चुनाव जीता जा सकता है. नैतिक रूप से कहें तो राहुल गांधी और उनकी टीम ने कांग्रेस पार्टी के सारे राजनीतिक दिमाग़ों को इस चुनाव से अलग रखा. अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी और मोतीलाल वोरा, जिन्होंने अभी तक कांग्रेस संगठन चलाया, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई भी उत्तर प्रदेश के बारे में राहुल गांधी से कुछ भी कह सकें. मैं इसका गवाह हूं. एक समारोह में मैं मौजूद था वहां एक बड़े पत्रकार ने जनार्दन द्विवेदी से कहा कि, जर्नादन द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश के बारे में विरोधाभास है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं. जनार्दन द्विवेदी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं कोई बात नहीं करूंगा. यह कैसा डर था जर्नादन द्विवेदी के मन में. दरअसल यह डर कनिष्क सिंह और उनकी नई टीम ने पैदा किया था. टिकटों के लिए जो शीट आती थी, कनिष्क सिंह के दफ्तर से उसके बारे में न दिग्विजय सिंह को, न परवेज़ हाशमी को, न भक्तचरण दास और न ही मधुसुदन मिस्त्री को पता होता था. भक्तशरण दास और मधुसुदन मिस्त्री स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होते थे, मोहन प्रकाश के साथ. मोहन प्रकाश को सिर्फ़ पता होता था, लेकिन इन दोनों को नहीं पता होता था और उस लिस्ट पर सिवाय हां करने के और कोई भी चारा नहीं होता था. दरअसल, स्क्रीनिंग कमेटी का जनाज़ा ख़ुद मोहन प्रकाश ने निकाल दिया था, क्योंकि वह कनिष्क सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, राज बब्बर, श्रीप्रकाश जायसवाल और सलीम शेरवानी के साथ बैठकर स्क्रीनिंग करते थे. इन सात लोगों का जुंटा चलता था. इस जुंटे ने हद तो तब कर दी, जब बुज़ुर्ग नेता रिज़वी को बेइज़्ज़त किया गया. सबसे आख़िर में उनका टिकट क्लीयर किया. इसलिए जब चुनाव हो गए तो रशीद मसूद के दिलाए सात टिकटों में सिर्फ़ एक जीता. बेनी प्रसाद वर्मा के यहां भी एक जीता. आरपीएन सिंह के यहां दो जीते, जितिन प्रसाद, सलमान ख़ुर्शीद, श्रीप्रकाश जायसवाल और राज बब्बर के इलाक़े में एक भी नहीं जीता.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 04 अंक 02
दिल्ली, 19 मार्च–25 मार्च 2012
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
सी–20, ट्रांस यमुना, एनएच–2, आगरा
फोन : 0526–4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर–440012
फोन नं : 0712–2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962, 0120–6450888, 0120–6452888, 0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999, +91 9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अन्ना के आंदोलन ने कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को प्रभावित किया. अन्ना का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जिसका मज़ाक़ सारे राजनीतिक दलों ने उड़ाया.



# कांग्रेस की हार की वजह राहुल के सेनापति हैं

कनिष्क सिंह

राहुल गांधी का प्रोग्राम किस तरह बनेगा, उनकी सभा कहां होगी, इसका फ़ैसला कनिष्क सिंह करते थे. किसको कितना पैसा जाना है, इसका फ़ैसला कनिष्क सिंह करते थे. मीडिया में किसको कितना दिया पैसा जाना है और किस मीडिया से क्या कहलवाना है, राज बब्बर तय करते थे. कैंपेन का मैनेजमेंट श्रीप्रकाश जायसवाल के हाथ में था. इस टीम को यह पता भी नहीं चला कि मीडिया के जिन लोगों को उन्होंने पैसा दिया, वे उनकी मीटिंग तो दिखा रहे हैं. ये टेलीविजन पर राहुल गांधी का चेहरा देखकर ख़ुश होते थे. ये मीडिया से सिर्फ़ यह अनुरोध करते थे कि सभा की भीड़ न दिखाई जाए, क्योंकि भीड़ नहीं होती थी. मीडिया वालों ने जमकर पैसा लिया, ऑफिशियली पैसा लिया. पैसा इस शर्त पर लिया कि ठीक है हम सिर्फ़ चेहरा दिखाएंगे, भीड़ नहीं. कनिष्क सिंह ने जो राहुल गांधी के आंख, कान और नाक हैं. उन्होंने ये सोचा कि भीड़ नहीं दिखाएंगे, राहुल गांधी के तेवर दिखाएंगे तो लोग राहुल गांधी को वोट दे देंगे. शायद ये ग़ैर राजनीतिक सोच की पराकाष्ठा थी और इस पराकाष्ठा ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उस जगह पहुंचा दिया, जहां से अगले साल होने वाले या इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को कांग्रेस जीत सकेगी, लगता नहीं है. उन राज्यों के कार्यकर्ताओं की हिम्मत उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नतीजों ने तोड़ दी. हद तो तब हो गई, जब राज बब्बर ने फ़िरोज़ाबाद में ज़िला कांग्रेस कमेटी पर अपने आदमी को नोमिनेट करवाया, लड़कर करवाया और वह चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी में चला गया.

बेनी प्रसाद वर्मा

लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सांसदों और विधायकों ने कहा कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए. रीता बहुगुणा की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस हाईकमान नहीं मानीं. दरअसल, रीता बहुगुणा का किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, न ही वह संगठन को मज़बूत कर पा रही थीं. कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं का इस्तेमाल नहीं किया, चाहे वह संजय सिंह रहे हों या प्रमोद तिवारी. सलमान ख़ुर्शीद और बेनी प्रसाद के बयानों ने लोगों को कांग्रेस से दिमाग़ी तौर पर दूर कर दिया उनको लगा कि केंद्र के ज़िम्मेदार मंत्री जिस तरह से बयानबाज़ी कर रहे हैं, उसे इस प्रदेश में ग़ैर ज़िम्मेदारी का बयान माना गया. मुसलमानों को लगा कि उन्हें लॉलीपॉप दिया जा रहा है. जो उन्हें 27 प्रतिशत में मिल रहा था, अब उससे भी कम मिलेगा. दूसरे वर्गों को लगा कि यह तो सिर्फ़ मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं. समाज में बाक़ी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं. जो पिछड़े नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं, लेकिन इसी प्रदेश में रहते हैं और वोटर हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं. इसलिए वे उनसे दूर चले गए. कांग्रेस ने बैकवर्ड कार्ड खेला और कांग्रेस ने यह नहीं समझा कि बैकवर्ड का अकेला सिंबल मुलायम सिंह हैं. बेनी प्रसाद वर्मा को उन्होंने सिंबल बनाने की कोशिश की, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा सिंबल नहीं बन सकते थे, क्योंकि बैकवर्ड के बारे में समझ कांग्रेस में नहीं थी. बेनी प्रसाद वर्मा बैकवर्ड की तमाम जातियों के बीच में एक जाति के हैं. वह भी अपनी जाति के अकेले नेता नहीं हैं. अपना दल, जिसके नेता सोने लाल पटेल थे, जिनका निधन हो गया है. अब उनकी बेटी और उनकी पत्नी उस समाज में घूमती हैं, जिस समाज से बेनी प्रसाद वर्मा आते हैं. नतीजा दिखाई पड़ा कि पिछड़ों को टिकट देना कांग्रेस के लिए महंगा पड़ गया. पिछले चुनाव में बैकवर्ड कांग्रेस की नाक के नीचे से भाजपा से निकलकर बसपा में चला गया. मज़े की बात यह है कि इस बार बसपा से निकलकर भाजपा में चला गया. कांग्रेस को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. कांग्रेस वहीं की वहीं खड़ी रही और अपने पुराने वोट बैंक को अपने पास लाने के लिए कुछ नहीं कर पाई. दरअसल, कांग्रेस के पास कोई सोच ही नहीं है.

श्रीप्रकाश जायसवाल

अन्ना के आंदोलन ने कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को प्रभावित किया. अन्ना का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जिसका मज़ाक़ सारे राजनीतिक दलों ने उड़ाया. एक तरफ़ उसने कांग्रेस का वोट कम किया और दूसरी तरफ़ बहुजन समाज पार्टी का वोट कम किया. ये वोट विकल्प की तलाश में चूंकि तीसरा विकल्प सिर्फ़ और सिर्फ़ समाजवादी पार्टी थी, उसके पास चला गया. कांग्रेस ने अपने भीतर कोई दलित या पिछड़ा नेता पैदा नहीं किया. बाहर से आए बेनी प्रसाद वर्मा को उसने बैकवर्ड चेहरा बना लिया. बाटला हाउस गोली कांड का जिस तरह फ़ायदा दिग्विजय सिंह उठाना चाहते थे, बाक़ी बयानबाज़ियों के बीच में वह तरीक़ा दिग्विजय सिंह के लिए भारी पड़ गया. दिग्विजय सिंह को जहां मुसलमानों की रोज़ी–रोटी के सवाल को उठाना चाहिए था, वहां उन्होंने मुसलमानों के भावनात्मक सवाल को उठाने की कोशिश की. मुसलमानों के मन में यह सवाल उठा कि अगर सोनियां गांधी रोईं, जैसा सलमान ख़ुर्शीद ने सबको बताया. क़ानून मंत्री और दिग्विजय सिंह बाटला हाउस कांड की निंदा करते हैं, तो जो लड़के बंद हैं, उन्हें क्यों नहीं छुड़वाते हैं. आपकी सरकार है, आपकी पुलिस ने केस किया है. ये सारे बयान कांग्रेस के लिए जानलेवा साबित हुए हैं.

मोहन प्रकाश

ऐसे क़िस्से भी सामने आए, जिनकी टिकट बदली, उन्होंने आकर कहा कि हमने पैसे दिए और हम टिकट लेकर चले आए. सबसे ज़्यादा आरोप रीता बहुगुणा पर लगे और उसके बाद कई नेताओं पर ऐसे आरोप लगे. इन आरोपों के बारे में किसी के पास सबूत नहीं हैं, सिर्फ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बातें हैं, जो यह कह रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट दिए गए. कुछ कांग्रेस नेताओं का तो यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 30 प्रतिशत टिकटें पैसे लेकर दी हैं. ये वे लोग हैं, जिन्हें चुनाव में कम वोट मिलें हैं, जिनकी ज़मानत ज़ब्त हुई है. कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि जिस पर मुझे कोई विश्वास नहीं है कि कनिष्क सिंह ने 50–50 लाख रुपये लेकर आख़िरी समय में कुछ टिकटें बदली हैं. इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ़ से जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी नज़र आया, वह न तो सोनिया गांधी थीं और न राहुल गांधी थे, वह कनिष्क सिंह थे. यहीं पर कनिष्क सिंह, अहमद पटेल और जनार्दन द्विवेदी जैसे लोगों के व्यक्तित्व को समझना चाहिए. जनार्दन द्विवेदी या अहमद पटेल राजनीति की नब्ज़ जानते हैं. ये लोगों की ताक़त जानते हैं, लोगों की कमज़ोरी जानते हैं. कौन कहां पर कांग्रेस नेता है, उसे जानते हैं. सिर्फ़ ये दोनों लोग कांग्रेस को ही नहीं जानते, बल्कि विपक्ष को भी जानते हैं. सालों साल उन्होंने विपक्षी नेताओं को हैंडल किया है. दूसरे शब्दों में कहें तो डील किया है. चुनाव का इतना महत्वपूर्ण मौक़ा और इन दोनों नेताओं को मोतीलाल वोहरा सहित किनारे बैठा देना सबसे बड़ी ग़लती थी और कनिष्क सिंह जैसे आदमी को जिस आदमी के पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, उसे सारी व्यवस्था सौंपकर कांग्रेस ने अपने लिए आत्महत्या का सामान ख़ुद इकट्ठा कर लिया.

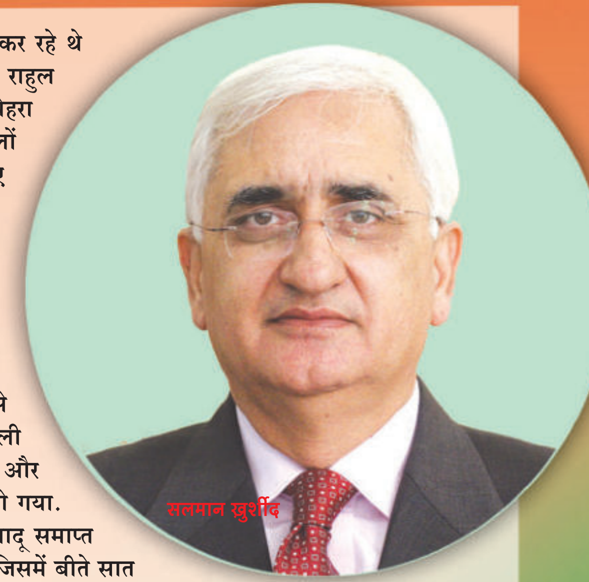

सलमान ख़ुर्शीद

सवाल यह है कि क्या कनिष्क सिंह ये सारे फ़ैसले ख़ुद कर रहे थे या सारे फ़ैसले राहुल गांधी की इच्छा अनुसार ही कर रहे थे. राहुल गांधी को शायद लगता था कि उत्तर प्रदेश में जनता उनका चेहरा देखकर उनके साथ खड़ी हो जाएगी. फिर एक झटके में सालों साल राजनीति में अपनी ज़िंदगी बिता चुके, कांग्रेस के लिए अपना ख़ून–पसीना एक कर चुके लोगों को एक साथ किनारे कर देंगे. जवाब कांग्रेस के लोग दे सकते हैं. लेकिन इस चुनाव में जो सबसे दुखद बात हुई, वह यह कि प्रियंका गांधी का तिलिस्म टूट गया. मैं दुखद इसलिए कहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के बीच में जो एक ध्रुव तारा था, लोगों को लगता था कि प्रियंका गांधी आएंगी और पार्टी को जादू की छड़ी से सत्ता में ले आएंगी. लेकिन प्रियंका गांधी इस चुनाव में जिस तरीक़े से विफल हुईं, उसकी मिसाल दूसरी नहीं मिलेगी. जब वह रायबरेली गईं तो महिलाओं ने पूछा कि अब तीन साल बाद आई हो, और तीन साल बाद ही आओगी. प्रियंका गांधी का चेहरा सफ़ेद हो गया. वह सभा पूरी नहीं कर पाईं. देश में प्रियंका गांधी नाम का जादू समाप्त हो गया. यहीं पर सोनिया गांधी के उस बयान की बात करेंगे, जिसमें बीते सात मार्च उन्होंने हार का कारण ग़लत टिकट वितरण बताया. यह ग़लत टिकट वितरण किसने किया. मुझे मेरा इंवेस्टिगेशन बताता है कि यह ग़लत टिकट वितरण राहुल गांधी ने किया. राहुल गांधी के हां करने के बाद कनिष्क सिंह अपने छह लोगों के साथ वह सूची स्क्रीनिंग कमेटी को भिजवाते थे, जो सिर्फ़ वाह–वाह करती थी. इतना ही नहीं रायबरेली, अमेठी और सुलतानपुर में जहां कांग्रेस 100 प्रतिशत हार गई. उसका ज़िम्मा किसके सिर है. अगर ग़लत टिकट वितरण हुआ है, तो अमेठी और रायबरेली में किसने टिकट बांटे. वे टिकट अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नहीं बांटे, तो किसने बांटे. हां, एक व्यक्ति हैं, जिनका नाम किशोरी शर्मा है. वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रतिनिधि है. यह वहां पर तभी जाते हैं, जब सोनिया गांधी या राहुल गांधी को अपने चुनाव क्षेत्र में जाना पड़ता है. इनके कहने का मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कहा होता है. जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र में सीटें हारी जा सकती हैं, तो इस हार का ज़िम्मा कांग्रेस अध्यक्ष लेंगी या रायबरेली का सांसद लेगा या अमेठी का सांसद लेगा, जो देश का होने वाला प्रधानमंत्री है. सोनिया गांधी का यह कहना कि महंगाई एक कारण है, भी ग़रीबों की तकलीफ़ का मज़ाक़ बनाना है. सोनिया गांधी को कोई यह नहीं बता पाया कि महंगाई और भ्रष्टाचार देश में कितना बड़ा सवाल बन गया है. राहुल गांधी के व्यवहार से सारे कांग्रेसी नेता परिचित हैं. बड़े से बड़ा नेता राहुल गांधी के पास जाता था और राहुल गांधी एक ही बात कहते थे कि कनिष्क इनकी बात सुन लो, कनिष्क नोट इट. कनिष्क सुन लेते थे और नोट करते थे. वह नेता वहां से गदगद या पिटा हुआ लौट जाता था. राजनीतिक व्यवहार कुशलता और राजनीतिक शैली का अभाव राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में हार का कारण बन गया. यही राजनीतिक कुशलता का अभाव मायावती के लिए भी हार का कारण बन गया. मायावती ने अपराध नियंत्रण किया, लेकिन वह लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल नहीं हो पाईं कि वह सर्वजन की नेता हैं. वह सर्वजन को अपमानित करने वाली नेता के रूप में लोगों के सामने आ गईं. मायावती से मायावती का वर्कर्स इन पांच सालों में मिल ही नहीं पाया. उनसे कॉ–ओर्डिनेटर्स मिलते थे, जिन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार को सांगठनिक रूप दिया. मायावती का व्यवहार उनकी गले की हड्डी बन गया. भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ़ इतना कहना चाहेंगे कि उसके पास अगर संजय जोशी नहीं होते तो, वह तीन सीटों की जगह और तीस सीटें कम पाती. चूंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने सवालों को, अपने नेताओं को, अपनी विचारधारा को, सामने नहीं रख पाई. सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक नहीं है, राम मंदिर है, राम मंदिर नहीं है. मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, आरक्षण है, आरक्षण नहीं है, वह इसी द्वंद्व में उलझ गई. हर पार्टी के लिए सोचने का समय है, लेकिन सारी पार्टियों में मुझे लगता है कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है, जो इस हार से सबक़ लेगी और इसे अपने संगठन को निखारने का शायद कारण बनाएगी. कांग्रेस कोई सीख लेती नज़र नहीं आती और बहुजन समाज पार्टी तो सीख लेगी ही क्या.

राज बब्बर

सलीम शेरवानी

आख़िर में कांग्रेस का आख़िरी कारनामा, बाटला हाउस कांड पर उर्दू सहारा के संपादक अजीज़ बर्नी द्वारा लिखी गई किताब चुनाव 2012 कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव में बांटती नज़र आई. कांग्रेस को लगा कि अगर वह अजीज़ बर्नी की किताब बांटेगी, तो उसे मुसलमानों का वोट मिल जाएगा. अकसर यह माना जाता है कि जो आपका विरोधी रहा है, अगर आप उसकी कोई चीज़ बांटते हैं तो लोग बिना पढ़े यह मान लेंगे कि वह आपके पक्ष में लिखा हुआ बयान है. अजीज़ बर्नी साहब ने भी इस किताब को बर्नी पब्लिकेशन हाउस के तहत हिंदी और उर्दू में छपवाया है. कांग्रेस ने इसकी लाखों प्रतियां ख़रीदी हैं. अजीज़ बर्नी साहब ने जो कांग्रेस के बाटला हाउस कांड में लगातार गालियां देने वालों में रहे हैं. उन्होंने क्यों इसकी इतनी प्रतियां छपवाईं और क्यों कांग्रेस को दीं. कांग्रेस खुलेआम कहती है कि इसकी लाखों प्रतियां ख़रीदी और लोगों में बांटीं. इसके पीछे क्या है, यह तो अजीज़ बर्नी साहब जानें और कांग्रेस जाने, पर इसका फ़ायदा कांग्रेस को बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि इसका नुक़सान ही हुआ. यह भी शायद राहुल गांधी और कनिष्क ने किया, क्योंकि इस किताब के तीस लफ्ज़ नामक पहले लेख में जिसे अजीज़ बर्नी साहब ने लिखा है कि 11 नवंबर, 2011 को 11 बजे यानी ग्यारह, ग्यारह, ग्यारह को उनकी राहुल गांधी से बारह तुग़लक लेन पर मुलाक़ात एक ऐसे मौक़े पर हुई, जब वह अपने परिवार के साथ ख्वाजा की दरगाह पर अजमेर जा रहे थे. उन्होंने दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि यह एक यादगार मुलाक़ात थी और कई लिहाज़ से अहम थी. उन्होंने बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि उसी मुलाक़ात में शायद इस किताब की लाखों प्रतियां ख़रीदने का फ़ैसला हुआ होगा. कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए ख़ुद को तैयार कर पाती या नहीं, यह लाख टके का सवाल है. इसका जवाब अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ज़्यादा देना है, क्योंकि कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता पहली बार नेतृत्व के ख़िलाफ आवाज़ उठाना न शुरू कर दें.

रशीद मसूद

**कनिष्क सिंह जैसे आदमी को जिस आदमी के पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, उसे सारी व्यवस्था सौंपकर कांग्रेस ने अपने लिए आत्महत्या का सामान ख़ुद इकट्ठा कर लिया. सवाल यह है कि क्या कनिष्क सिंह ये सारे फ़ैसले ख़ुद कर रहे थे या सारे फ़ैसले राहुल गांधी की इच्छा अनुसार ही कर रहे थे. राहुल गांधी को शायद लगता था कि उत्तर प्रदेश में जनता उनका चेहरा देखकर उनके साथ खड़ी हो जाएगी.**

editor@chauthiduniya.com

सरकार, राजनीतिक दलों एवं मीडिया, सबने मिलकर आंदोलन के इस पूरे दौर को कभी अन्ना बनाम सरकार तो कभी रामदेव बनाम सरकार का रूप दे दिया.

दिल्ली, 19 मार्च-25 मार्च 2012 चौथी दुनिया

# भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और चुनाव परिणाम के मायने

**भ्रष्टाचार को व्यवस्था का अंग मान लिया गया था, लेकिन अब जनता इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ग़ौर करें तो ऐसा ही लगता है. इस संकेत को समझने की ज़रूरत है. दिमाग़ के साथ, दिल से भी. बिना तर्क- कुतर्क के, ईमानदारी से. यह संकेत लोकतंत्र और अवाम के लिए ख़ुशनुमा है, तो नेताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी.**

शशि शेखर

आधी रात को सोए हज़ारों लोगों पर जब अपनी ही सरकार लाठी चलवाए, अपनी ही पुलिस गोलियां चलाए तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है. एक अदद क़ानून के लिए एक बूढ़े आदमी को तीन-तीन बार अनशन करना पड़े, लाखों लोग सड़क पर उतर आएं, फिर भी सरकार क़ानून बनाने के बजाय बार-बार वादाख़िलाफ़ी करे, तो जनता उसकी प्रतिक्रिया में क्या करेगी? जरा इस आंकड़े पर ग़ौर करें. उत्तर प्रदेश में इस बार 60 प्रतिशत मतदान हुआ. इसका अर्थ है कि 2007 के मुक़ाबले इस बार उत्तर प्रदेश में क़रीब 2 करोड़ या कहें कि 30 प्रतिशत ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया. इन 2 करोड़ मतदाताओं में ज़्यादातर युवा मतदाता शामिल थे, ख़ासकर महिला युवा मतदाता. अब इस आंकड़े को समझने की ज़रूरत है. आम तौर पर यह माना जाता था कि युवाओं की दिलचस्पी राजनीति में नहीं होती, वे वोट डालने नहीं जाते. फिर अचानक क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में युवा मतदाता न सिर्फ़ वोट डालने पहुंचे, बल्कि उन्होंने उन सियासी दलों का सूपड़ा साफ़ कर दिया, जिन पर भ्रष्टाचार करने, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ न लड़ने के आरोप थे.

सवाल उठता है कि मतदाताओं (ख़ासकर युवा मतदाताओं) के इस क़दम के पीछे कारण क्या है? कांग्रेस के युवा चेहरे के तौर पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की कमान ख़ुद संभाली. मीडिया से लेकर तमाम बुद्धिजीवियों तक ने भविष्यवाणी कर दी कि राहुल गांधी की मेहनत के अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे, लेकिन युवा मतदाताओं ने उन्हें अपना आईकॉन मानने से इंकार कर दिया. सत्ता में बैठकर भ्रष्टाचार करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोगों को युवा मतदाताओं ने साफ़ संकेत दे दिया कि अब भी वक़्त है, अपनी चाल, चरित्र, चिंतन एवं रीति-नीति बदल लो, अन्यथा हम कुछ और सोचेंगे. पांच राज्यों के इन चुनाव परिणामों को किसी पार्टी की जीत और हार से अलग संदर्भ में देखना होगा. यह जीत जनता की है, भ्रष्टाचार और सत्ता में मदमस्त नेताओं के ख़िलाफ़. अब चूंकि जनता के पास सीमित राजनीतिक विकल्प हैं, इसलिए उसने किसी एक को चुना, लेकिन उन्हें नहीं चुना, जो सीधे-सीधे इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री को जन्म देने के लिए ज़िम्मेदार हैं. अप्रैल 2011 से शुरू हुए आंदोलनों में, चाहे लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे का आंदोलन हो या काले धन के मुद्दे पर बाबा रामदेव का आंदोलन, जनता बार-बार सड़क पर उतरी, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इस जन अभियान को महज़ कुछ एनजीओ चलाने वालों का आंदोलन समझ बैठे. अन्ना या रामदेव के आंदोलन की अपनी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर ये लोग जनता के बीच गए, जिस ढंग से जनता को जागृत किया, लोकपाल आंदोलन में युवाओं की जो उल्लेखनीय भागीदारी रही, रामलीला मैदान सहित देश के तमाम हिस्सों में जो जन ज्वार उमड़ा, उसे देखकर भी कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दल जनभावना को समझ नहीं पाए.

सरकार, राजनीतिक दलों एवं मीडिया, सबने मिलकर आंदोलन के इस पूरे दौर को कभी अन्ना बनाम सरकार तो कभी रामदेव बनाम सरकार का रूप दे दिया, लेकिन इस सबके बीच जनता क्या सोच रही है, उसके मन में क्या है, इसकी चिंता करने की ज़रूरत किसी ने नहीं समझी. अन्ना हजारे उत्तर प्रदेश चुनाव में मतदाता जागरण के लिए नहीं गए, लेकिन उनकी टीम के कई सदस्यों ने वहां सैकड़ों रैलियां कीं, पर उनमें से किसी एक भी रैली की ख़बर मीडिया में नहीं आई. ख़बर नहीं आई, यह तो ख़बर थी ही, सबसे बड़ी ख़बर यह कि इन रैलियों का कोई असर होने से भी इंकार कर दिया गया. बाबा रामदेव गोवा में काफ़ी समय से अवैध खनन का मुद्दा उठा रहे थे. बहरहाल, इन चुनावों के परिणाम कांग्रेस सहित उन दलों को भी एक संदेश दे गए हैं, जिन्हें सत्ता मिली है कि अब जनता भ्रष्टाचार को व्यवस्था का स्वीकार्य अंग मानने को तैयार नहीं है. अभी चूंकि जनता के पास सीमित राजनीतिक विकल्प हैं, इसलिए सत्ता में आए और सत्ता से बेदख़ल हुए सभी दलों के पास आत्मचिंतन का मौक़ा है, अपनी ग़लती सुधारने का मौक़ा है. वे काम करने का मौक़ा है, जो जनता चाहती है. यह संकेत दिए जाने के बाद भी अगर देश की राजनीति चलाने वाले लोग नहीं चेतते हैं, तो शायद जनता कोई नया विकल्प भी तलाश लेगी.

shashishekhar@chauthiduniya.com

# मुसलमानों का वोट पाने में पार्टियां क्यों चूक गईं

**उत्तर प्रदेश में चुनाव के परिणाम आ चुके हैं. इस बार के चुनाव में लगभग सभी दलों ने मुस्लिम मुद्दों को जिस तरह उछाला, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था. बसपा, कांग्रेस और सपा ने मुसलमानों को रिझाने में अपनी तरफ़ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, फिर भी सपा को छोड़कर किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ. इसके पीछे क्या कारण रहे, देखते हैं इस रिपोर्ट में.**

डॉ. क़मर तबरेज़

मायावती की अध्यक्षता में बहुजन समाज पार्टी ने पिछले पांच सालों तक उत्तर प्रदेश पर राज किया. 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने मुलायम सिंह के हाथों से सत्ता छीनी थी. ज़ाहिर है, उसमें कहीं न कहीं मुलायम से मुसलमानों की नाराज़गी भी एक बड़ी वजह थी. मायावती ने जहां एक तरफ़ सतीश चंद्र मिश्र को अपने साथ बैठाकर सवर्णों का वोट हासिल करने की कोशिश की थी, वहीं दूसरी तरफ़ नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी को भी अपने साथ बैठाकर मुसलमानों को रिझाने की कोशिश में कामयाब हुई थीं. लेकिन जब किसी पार्टी की सरकार बन जाती है, तो जनता के प्रति उसका दायित्व भी बढ़ जाता है. सतीश मिश्र और नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी का संबंध जिन बिरादरियों से था, उनके अंदर यह आशा जगी थी कि बसपा सरकार उनके लिए कुछ अच्छे काम करेगी. ख़ासकर मायावती ने मुस्लिम विधायकों को जिस तरह महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए, उससे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लगा कि अब उनके दुख-दर्द दूर होने वाले हैं. लेकिन पांच साल गुज़रने के बाद उनकी हालत सुधरने की बजाय पहले जैसी ही दयनीय बनी रही. मायावती सरकार के दौरान जितने भी विकास के काम हुए, उनमें दलितों को ही प्राथमिकता दी गई. इसलिए ये दोनों बिरादरियां मायावती से दूर होती चली गईं. इतना ही नहीं, मायावती के शासनकाल में मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मुक़दमे दायर किए गए. वक़्फ़ की ज़मीनें वैसे ही लूटी जाती रहीं, मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि अदीब माहिर, अदीब कामिल और मोअल्लिम की डिग्रियों वाले जिन मुसलमानों को पिछली मुलायम सरकार ने उर्दू अध्यापकों की भर्ती के लिए मंज़ूरी दी थी, मायावती ने उस पर रोक लगा दी, पीएसी में पिछली मुलायम सरकार ने मुसलमानों को जो दस प्रतिशत का आरक्षण दिया था, मायावती ने उसे घटाकर चार प्रतिशत कर दिया. प्रदेश का मुसलमान जब भी अपना कोई काम कराने के लिए मायावती के पास गया, उन्होंने काम कराने के लिए रिश्वत मांगी और उनका मसला हल नहीं होने दिया. सरकारी आवासीय योजनाओं के अंतर्गत ग़रीब बस्तियों में पिछड़ों के लिए जो घर बनवाए गए, उनसे दलितों के अलावा किसी और का कोई फ़ायदा नहीं हुआ. मुस्लिम बस्तियों में सड़कों, नालियों और गंदगी का बुरा हाल ज्यों का त्यों बना रहा.

केंद्र सरकार की तरफ़ से बुनकरों और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए जो आर्थिक सहायता प्रदान की गई, उन्हें हक़दारों तक पहुंचने नहीं दिया गया और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी मायावती पर बराबर ये आरोप लगाते रहे कि हाथी इन पैसों को खा जाता है. कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रदेश के मुसलमानों के लिए मायावती ने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसे आधार बनाकर वह मुसलमानों के बीच जाकर उनके वोटों पर अपना हक़ जमा पातीं. इसलिए पूरे चुनाव के दौरान वह उनके बीच सभाएं करने से डरती रहीं, उनसे दूर भागती रहीं. चुनाव के परिणाम ने अब यह साबित कर दिया है कि मायावती ने मुसलमानों की तमाम आशाओं पर पानी फेर दिया, इसलिए उन्होंने इस बार बसपा से किनारा कर लिया.

जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो वह अपने फ़रेब और धोखाधड़ी की वजह से मुसलमानों में लंबे समय से बदनाम है. कांग्रेस ने हमेशा मुसलामानों को बेवक़ूफ़ समझा और भाजपा या इस जैसी दूसरी ताक़तों से उन्हें डरा धमका कर उनका वोट हासिल करने की कोशिश की. लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की यह पुरानी चाल उसके कोई काम न आ सकी. हद तो उस वक़्त हो गई, जब चुनावी तारीख़ों की घोषणा से ठीक पहले राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के बुनकरों और दलितों की याद आई और उन्होंने ग़रीब बुनकरों के क़र्ज़ माफ़ करने का ऐलान करने के साथ-साथ उनके बैंक खातों में सीधे केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता के तौर पर कुछ राशि जमा करने की घोषणा की. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही आचार संहिता लागू होने की वजह से यह सहायता राशि उन तक नहीं पहुंच सकी और बेचारे ग़रीब बुनकर इंतज़ार ही करते रह गए. इसी तरह केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण में से 4.5 प्रतिशत अलग से अल्पसंख्यकों को देने का ऐलान किया और ढिंढोरा पीटा कि यह आरक्षण केवल मुसलमानों के लिए है. हालांकि आचार संहिता के लागू होने की वजह से चुनाव आयोग ने प्रदेश में इसके लागू होने पर पहले ही पाबंदी लगा दी थी. लेकिन कांग्रेस का झूठ बोलने का सिलसिला तब भी नहीं रुका. उसने प्रदेश के अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी यह लिख दिया कि साढ़े चार प्रतिशत का ओबीसी के अंदर यह रिज़र्वेशन सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है. लेकिन जब चौथी दुनिया ने कांग्रेस के इस सबसे बड़े झूठ का पर्दाफ़ाश किया तो प्रदेश के मुसलमानों में कांग्रेस के प्रति जो थोड़ी बहुत हमदर्दी बची थी, वह भी समाप्त हो गई. इस झूठ से एक बार फिर यह बात साबित हो गया कि कांग्रेस अब भी मुसलमानों को मूर्ख ही समझती है और चाहती है कि उनका वोट उन्हें मूर्ख बनाकर ही हासिल किया जाए. लेकिन मुसलमानों ने सपा को बहुमत से जिताकर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस उन्हें भले ही मूर्ख समझती रहे, लेकिन वे बेवक़ूफ़ नहीं हैं. इसके अलावा देश के क़ानून मंत्री सलमान ख़ुर्शीद ने फ़र्रुख़ाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी अपनी पत्नी लुईस ख़ुर्शीद की एक चुनावी सभा में यह झूठी घोषणा कर दी कि सच्चर कमेटी की सारी सिफ़ारिशें लागू हो चुकी हैं. दिग्विजय सिंह और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने बाटला हाउस का मुद्दा उठाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की. भाजपा ने भी राम मंदिर का मुद्दा उठाकर ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रदेश के मतदाता अब सियासी पार्टियों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, उन्होंने इस प्रकार की तमाम राजनीतिक कोशिशों को नाकाम कर दिया.

**केंद्र सरकार की तरफ़ से बुनकरों और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए जो आर्थिक सहायता प्रदान की गई, उन्हें हक़दारों तक पहुंचने नहीं दिया गया और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी मायावती पर बराबर ये आरोप लगाते रहे कि हाथी इन पैसों को खा जाता है. कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रदेश के मुसलमानों के लिए मायावती ने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसे आधार बनाकर वह मुसलमानों के बीच जाकर उनके वोटों पर अपना हक़ जमा पातीं.**

भाजपा और कांग्रेस के इसी सांप्रदायिक कार्ड ने समाजवादी पार्टी को बहुमत से जिता दिया. सपा ने चुनाव प्रचार के दौरान कोई ऐसी बात नहीं की, जिसका मतदाताओं पर उल्टा असर पड़ता, बल्कि उसने अधिकतर बसपा सरकार की ख़राबियों को गिनवाने और सरकार बनने पर विकास के कार्य करने जैसे वादों तक ख़ुद को सीमित रखा, जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है. मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण देने के ऐलान से दूसरी पार्टियों की तरफ़ से उसे घेरने की कोशिश ज़रूर हुई, लेकिन इससे सपा पर मुसलमानों का भरोसा ख़त्म नहीं हुआ. लेकिन मुलायम सिंह की असल परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि अगर उन्होंने मुसलमानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए तो कांग्रेस की तरह उनसे भी मुसलमानों को दूर होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी.

tabrez@chauthiduniya.com

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पंजाब में कांग्रेस की हार के लिए पंजाब पीपल्स पार्टी को ज़िम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि पंजाब पीपल्स पार्टी ने कांग्रेस को 23 सीटों पर नुक़सान पहुंचाया.



पंजाब

# पंजाब पीपल्स पार्टी ने खेल बिगाड़ा

फ़िरदौस ख़ान

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल–भाजपा गठबंधन को दोबारा सत्ता दिलाने में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे एवं पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर पंजाब पीपल्स पार्टी का गठन किया और चुनावी मैदान में कूद पड़े. पंजाब पीपल्स पार्टी और सांझा मोर्चा के उम्मीदवारों ने यहां सबसे ज़्यादा कांग्रेस को नुक़सान पहुंचाया. कांग्रेस के इस नुक़सान का सीधा फ़ायदा शिरोमणि अकाली दल–भाजपा गठबंधन को मिला. यह सब हुआ मनप्रीत सिंह बादल की ग़लत रणनीति के कारण. दरअसल, वह फ़ैसला नहीं कर पाए कि उन्हें हासिल क्या करना है. वह यह तय नहीं कर पाए कि उन्हें शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन की सरकार से मुक़ाबला करना है या फिर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से. अपनी इसी ग़लती के कारण वह अपने सबसे बड़े दुश्मन शिरोमणि अकाली दल को ही जीत दिला बैठे.

चुनावी नतीजों पर ग़ौर करें तो यह बात सामने आ जाती है कि पंजाब पीपल्स पार्टी ने कांग्रेस को हराने और शिरोमणि अकाली दल को जिताने में अहम किरदार निभाया है. राज्य में दो दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं, जहां पंजाब पीपल्स पार्टी और सांझा मोर्चा के उम्मीदवारों को मिले वोट कांग्रेस उम्मीदवारों के खाते में जोड़ दिए जाएं तो वे जीत जाते हैं. पंजाब पीपल्स पार्टी को 5.7 फ़ीसदी वोट मिले, जो कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण बना. राज्य की तक़रीबन 27 सीटों पर उन्होंने शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के उम्मीदवारों को जीत दिलाई. हालत यह रही कि कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने पांच से 25 हज़ार वोट लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों को हराने का काम ही काम किया. तीन–चार सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाक़ी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत तय थी. कांग्रेस के आला नेता मान रहे हैं कि बाग़ियों की वजह से कांग्रेस ने नौ सीटें गंवाई हैं. राज्य में कांग्रेस कड़े मुक़ाबले में थी. कई सीटों पर तो कांटे की टक्कर थी.

फिल्लौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार संतोष सिंह चौधरी अकाली दल के प्रत्याशी अविनाश चंदर से महज़ 31 मतों के अंतर से हार गए. यहां पंजाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस के वोट काटे. इसी तरह पट्टी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार हरमिन्दर सिंह गिल अकाली दल के प्रत्याशी आदेश प्रताप सिंह से सिर्फ़ 45 वोटों से हार गए. यहां पंजाब पीपल्स पार्टी के प्रत्याशी ने 2208 वोट लेकर कांग्रेस को जीत से दूर कर दिया. इसके अलावा जालंधर ज़िले की शाहकोट, करतारपुर, जालधर कैंट और जालंधर सेंट्रल सीट पर पंजाब पीपल्स पार्टी के प्रत्याशियों के कारण कांग्रेस की हार हुई. नवांशहर ज़िले की बलाचौर सीट पर पंजाब पीपल्स पार्टी के प्रत्याशी ने 18988 वोट लेकर कांग्रेस उम्मीदवार को तीसरे पायदान पर पहुंचा दिया. रोपड़ सीट पर पंजाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 25024 वोट हासिल कर शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी दलजीत सिंह चीमा को जीत दिला दी. फ़तेहगढ़ साहिब ज़िले की बस्सी पठाना में तो शिरोमणि अकाली दल का उम्मीदवार बाहरी होने के बावजूद जीत गया. यहां पंजाब पीपल्स पार्टी के प्रत्याशी ने 11344 वोट लेकर कांग्रेस को हराने का काम किया. लुधियाना ज़िले की गिल, पायल और जगराओ सीट पर भी पंजाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की वजह से ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. मोगा ज़िले की निहाल सिंह वाला और धर्मकोट सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत में पंजाब पीपल्स पार्टी रोड़ा बनी. फ़िरोजपुर देहाती सीट पर पंजाब पीपल्स पार्टी के प्रत्याशी ने 7621 वोट लेकर कांग्रेस उम्मीदवार को हराने का काम किया. पंजाब पीपल्स पार्टी के प्रत्याशियों ने बठिंडा ज़िले की रामपुराफल सीट पर 23398, बठिंडा अर्बन सीट पर 10755, बठिंडा देहात सीट पर 17655 और मौड मंडी सीट पर 23398 वोट लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों को नुक़सान पहुंचाया. इसी तरह मानसा सीट पर पंजाब पीपल्स पार्टी का प्रत्याशी 30 हज़ार से ज़्यादा वोट लेकर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत में रुकावट बना. बुडलाडा सीट पर भी पंजाब पीपल्स पार्टी के प्रत्याशी ने 29 हज़ार से ज़्यादा वोट लेकर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत से दूर कर दिया. संगरूर और अमरगढ़ सीटों का भी यही हाल रहा. इसी तरह पटियाला ज़िले की घन्नौर और शुतराणा सीटों पर भी पंजाब पीपल्स पार्टी के प्रत्याशियों ने 17 से 20 हज़ार वोट लेकर कांग्रेस को जीत से दूर करने में अहम भूमिका निभाई.

बेटे के मोह ने भी कांग्रेस की एक सीट गंवाने का काम किया. कैप्टन अमरिन्दर सिंह की सांसद पत्नी परनीत कौर चाहती थीं कि बेटे रनिन्दर सिंह को सियासत में आगे बढ़ाया जाए. समाना सीट से रनिन्दर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया, जबकि यहां से कैप्टन के भाई मलविन्दर सिंह कांग्रेस टिकट के मज़बूत दावेदार थे. पार्टी की आंतरित कलह ने भी कांग्रेस को नुक़सान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. कैप्टन अमरिन्दर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री राजिन्दर सिंह भट्ठल के समर्थकों में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई थी. आलम यह था कि पार्टी के 18 लोग बाग़ी हो गए और इनकी वजह से महत्वपूर्ण सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा.

बहरहाल, अगर मनप्रीत सिंह बादल कांग्रेस को समर्थन दे देते या इससे गठजोड़ कर लेते तो वह अपनी पार्टी को सत्ता में देख पाते. ऐसा करने से उनकी पार्टी को फ़ायदा ही होता. कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन वह तो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की बजाय अपना दुश्मन बना बैठे.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पंजाब में कांग्रेस की हार के लिए पंजाब पीपल्स पार्टी को ज़िम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि पंजाब पीपल्स पार्टी ने कांग्रेस को 23 सीटों पर नुक़सान पहुंचाया. इस पार्टी ने वोट बांटने का काम किया. अगर यह पार्टी नहीं होती तो ये सभी सीटें कांग्रेस को ही मिलतीं. हालांकि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने हार की ज़िम्मेदारी लेते हुए चुनाव नतीजों को चौंकाने वाला क़रार दिया है. पहले उन्होंने कहा कि पार्टी के बाग़ियों की वजह से कांग्रेस को चुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई. बाद में उन्होंने यह भी माना कि पंजाब पीपल्स पार्टी से भी कांग्रेस को नुक़सान हुआ है.

पंजाब में कांग्रेस की हार से कैप्टन अमरिन्दर सिंह का सत्ता पर क़ाबिज़ होने का ख्वाब भले ही टूट गया हो, लेकिन चुनाव में वह अपने प्रतिद्वंद्वी को भारी मतों के अंतर से हराकर अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहे हैं. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार सुरजीत सिंह कोहली को 42318 मतों से हराकर पटियाला सीट जीत ली, लेकिन वह अपने बेटे रनिन्दर सिंह को नहीं जिता पाए. उधर, मनप्रीत सिंह बादल का कहना है कि इस चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया गया. शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने चुनाव में पांच से एक–एक उम्मीदवार पर पांच से दस करोड़ रुपये ख़र्च किए हैं. हमारी पार्टी की माली हालत अच्छी नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए, जिसके कारण हमें उम्मीद के मुताबिक़ कामयाबी नहीं मिल पाई.

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल–भाजपा गठबंधन सत्ता में फिर से क़ाबिज़ होने में तो कामयाब हो गया है, लेकिन दोनों ही दलों का जनाधार कम हुआ है. पंजाब में 117 सीटों वाली विधानसभा में शिरोमणि अकाली दल ने 56 सीटें हासिल की हैं. शिरोमणि अकाली दल के मत प्रतिशत में भी 2.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. इस चुनाव में शिरोमणि अकाली दल का वोट प्रतिशत घटकर 34.75 प्रतिशत हो गया है. पिछले चुनाव में यह दर 37.9 प्रतिशत थी. भाजपा का वोट भी 1.15 प्रतिशत घटा है. इस बार 7.13 प्रतिशत मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिए हैं, जबकि पिछली बार यह दर 8.28 प्रतिशत थी. कांग्रेस ने इस चुनाव में 46 सीटों पर जीत का परचम लहराया है. हालांकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि वह पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. मगर कांग्रेस के लिए यह बात राहत देने वाली है कि इसके वोट प्रतिशत में इज़ाफ़ा हुआ है. कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़कर 40.90 हो गया है, जो पिछले 2007 के विधानसभा चुनाव में 40.11 प्रतिशत था. इस तरह कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 0.79 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है. पिछली बार कांग्रेस ने 42 सीटें जीती थीं, जबकि इस बार इसे चार सीटों का फ़ायदा हुआ है.

firdaus@chauthiduniya.com

उत्तराखंड

# खंडूरी हारे, फिर भी कांग्रेस नहीं जीती

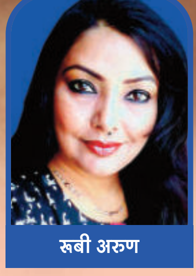

रूबी अरुण

जीतकर भी हारना क्या होता है, अगर आपको यह जानना है तो उत्तराखंड से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता. कमज़ोर नेतृत्व और आलाकमान में दूरदर्शिता की कमी क्या होती है, उत्तराखंड इसका भी नमूना पेश करता है. जिस राज्य में कांग्रेस की हवा बन चुकी थी, जहां की जनता कांग्रेस के हाथ राजपाट सौंपने का मन बना चुकी थी. उस राज्य में सरकार बनाने की ख़ातिर कांग्रेस के पसीने छूट गए. कांग्रेस को अपने तीन बाग़ी नेताओं को उनकी शर्तों पर मनाना पड़ा. उनके आगे गिड़गिड़ाना पड़ा. जिस राज्य में विपक्षी पार्टी भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीसी खंडूरी की करारी हार हुई हो और उत्तराखंड में खंडूरी है ज़रूरी का नारा भी भाजपा को नहीं बचा सका हो. वहां फिर भी कांग्रेस के पास इतनी सीटें न आ पाईं कि वह अपनी सरकार बग़ैर किसी मशक़्क़त या जोड़–तोड़ के बना सके, तो भला इससे बड़ी नीतिगत ख़ामी किसी भी राजनीतिक पार्टी में और क्या हो सकती है.

कांग्रेस के आला नेता इस बात से अनजान नहीं थे कि पिछली बार भी प्रदेश में उसे शिकस्त इसलिए खानी पड़ी, क्योंकि उसने समय रहते वहां मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की थी. इस बार भी सबसे बड़ा कारण यही रहा. यह बात सोनिया गांधी भी जानती थीं और राहुल गांधी भी कि राज्य के लोग हरीश रावत को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि हरीश रावत का सबसे मज़बूत पक्ष उनका बड़ा जनाधार है, जो पूरे उत्तराखंड में फैला हुआ है. इसके बावजूद कांग्रेस ने इस हक़ीक़त की अनदेखी की और हरीश रावत के नाम की घोषणा कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में नहीं की. इसका ख़ामियाज़ा कांग्रेस को भुगतना पड़ा. भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद, आपसी फूट, भीतरघात जैसी संगीनियों से जूझती भारतीय जनता पार्टी भी इतनी सीटें ले आई कि कांग्रेस के लिए सरकार बनाने की दावेदारी पेश करना मुश्किल हो गया. राज्य की कुल 70 सीटों में से कांग्रेस ने 32 सीटें जीतीं, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से चार कम थीं, तो भाजपा को 31 सीटें मिल गईं.

उत्तराखंड में पारंपरिक तौर पर ब्राह्मण और ठाकुर मतों का धुव्रीकरण होता आया है. हरीश रावत भी इससे बच न सके. हालांकि उन्होंने अपनी कट्टर ठाकुरवादी छवि से छुटकारा पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अभी भी उत्तराखंड में ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा उनकी इस छवि को न भुला पाने के चलते कांग्रेस को वोट देने से परहेज़ करता है. इसके बावजूद रावत जनप्रिय नेता हैं और उन्होंने अकेले अपने दम पर कांग्रेस को उत्तराखंड में मज़बूत किया. इस तथ्य को उनके विरोधी भी स्वीकारते हैं. भाजपा के भगत सिंह कोश्यारी की तरह ही हरीश रावत का प्रभाव क्षेत्र भी राज्य के ज़िलों में समान रूप से है. हरिद्वार से संसद की सीट भारी मतों से जीतकर रावत ने इसे प्रमाणित भी कर दिया है. इसके अलावा मुस्लिम समाज में भी उनकी ख़ासी पैठ है और ट्रेड यूनियन से लंबा जुड़ाव उन्हें श्रमजीवी एवं नौकरीपेशा वर्ग में भी लोकप्रिय बनाता है. अल्मोड़ा सीट से तीन बार सांसद रह चुके रावत पांच बार लगातार चुनाव हारे, लेकिन मतदाताओं पर उनकी मज़बूत पकड़ बनी रही. 2002 में राज्य विधानसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस को बहुमत दिलाने का श्रेय भी रावत को ही जाता है. उस समय भी विधायक दल का पूरा समर्थन होने के बावजूद रावत के दावे को नज़र अंदाज़ कर, एनडी तिवारी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस आलाकमान ने संगठन को दो फाड़ की स्थिति में ला खड़ा किया था. हालांकि मामले की गंभीरता देखते हुए हरीश रावत ने दूरदर्शिता का परिचय दिया और सरकार का गठन होने दिया, लेकिन उसके बाद उन पर यह भी आरोप लगते रहे कि पूरे पांच साल हरीश रावत ने एनडी सरकार की राह में कांटे बोये. रावत के समर्थक विधायकों ने एनडी सरकार के सामने हर रोज़ नई चुनौती खड़ी की और वह अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ काम करते नज़र आए, जिसका नतीजा यह रहा कि एनडी तिवारी ने हरीश रावत के कई कट्टर समर्थकों को अपनी तरफ़ मिला लिया और रावत को कमज़ोर करने का भी काम किया. एनडी तिवारी ने हरीश रावत के कई क़रीबी लोगों के मन में मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश जगा दी. यह एनडी तिवारी की ही माया है कि इस विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश कांग्रेस में तक़रीबन आधे दर्जन नेता ऐसे थे, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे. चूंकि वे दावेदार नेता नाराज़ न हो जाएं या फिर बाग़ी होकर पार्टी का नुक़सान न कर दें. इस डर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रदेश में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं कर पाईं, जबकि केंद्रीय नेतृत्व को यह अच्छी तरह पता था कि तमाम महत्वाकांक्षी नेताओं और विरोधियों के बावजूद मौजूदा वक़्त में हरीश रावत ही सबसे मज़बूत जनाधार वाले नेता हैं और सोनिया गांधी का यही डर प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुश्किलों का सबब बन गया.

आज भी ऐसा नहीं है कि हरीश रावत की राह आसान है, पर कभी उनकी घोर विरोधी और रावत विरोधियों की संरक्षणदाता इंदिरा हृदयेश भी बदले राजनीतिक परिदृश्य में रावत के साथ हो गई हैं. लेकिन इससे रावत की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं. अभी भी यशपाल आर्या को आगे करके रावत विरोधी गुट उन्हें कड़ी टक्कर देने की फ़िराक में है. वैसे चुनाव के पहले और परिणाम आने तथा सरकार बनाने तक हरीश रावत सतपाल महाराज, विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत आर्या के कंधे पर बंदूक़ रखकर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि यशपाल दलित हैं, इसलिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को वह सुहाते भी हैं. यही वजह रही कि सोनिया गांधी ने उत्तराखंड में दलित वोटरों के कम संख्या में होने के बावजूद यशपाल को कभी भी किनारे नहीं किया और उत्तराखंड के मतदाताओं में यह संदेश जाने दिया कि कांग्रेस यशपाल को भी मुख्यमंत्री बना सकती है. हालांकि कांग्रेस को अपनी इस लुका–छिपी से कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, बल्कि असंतुष्टों के क्षोभ का सामना ही करना पड़ा. सत्ता हासिल हो जाने के बाद भी हरीश इस ख़तरे को ख़ूब समझते हैं और फ़िलहाल वह डिफेंसिव मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि वह इस बात से ख़ूब वाक़िफ़ हैं कि किसी भी तरह यह सरकार बन तो गई, पर राह में अभी भी कांटे हैं, लिहाज़ा पहले की ग़लतियों से सबक़ लेकर संभल–संभल कर चलने की ज़रूरत है.

ruby@chauthiduniya.com

# कॉरपोरेट्स की सामाजिक ज़िम्मेदारी तय हो

यह आलेख कॉरपोरेट मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली द्वारा दिए गए एक भाषण और नए कंपनी बिल-2011 पर आधारित है. वीरप्पा मोइली ने बंगलुरु में हुए एक सम्मेलन, जिसका विषय था-भारत में कॉरपोरेट्स का भविष्य, में बोलते हुए नए कंपनी बिल-2011 और कॉरपोरेट्स की सामाजिक ज़िम्मेदारी यानी सीएसआर पर अपने विचार रखे थे.

## कॉरपोरेट स्वरूप के फ़ायदे

सीमित दायित्व, जिससे व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा और व्यापार बढ़ाने के अवसर मिलते हैं. अलग से लीगल स्टेट्स मिला हुआ है और अनवरत व्यापार चालू रखने के लिए उत्तराधिकार चुनने की स्वतंत्रता है. लघु एवं परिवार आधारित व्यापार और सार्वजनिक कंपनियों के बड़े ऑपरेशंस के लिए भी कॉरपोरेट स्वरूप अपनाने का विकल्प है. साथ ही शेयरों के हस्तांतरण की भी छूट है, ताकि तरलता बनी रहे. व्यापार के कॉरपोरेट फॉर्म के फ़ायदे उठाने के लिए ज़रूरी है कि लागू क़ानूनों मसलन, टैक्स लॉ, सेबी लॉ एवं कंपनीज एक्ट-1956 इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन हो. यह ज़रूरी है कि कॉरपोरेट्स पारदर्शी और ज़िम्मेदार होकर काम करें.

## कंपनी एक्ट-1956: कॉरपोरेट फ्रेंडली एक्ट

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कॉरपोरेट सेक्टर की बड़ी भूमिका है. कंपनियों की बढ़ती संख्या में उनका बड़ा योगदान है. कंपनी एक्ट-1956 कॉरपोरेट सेक्टर से संबंधित एक अहम क़ानून है. इसे समय-समय पर संशोधित किया गया है.

## वर्तमान आर्थिक परिदृश्य एवं चुनौतियां

बड़ी संख्या में कंपनियों के विलय एवं अधिग्रहण के मामले देखने को मिल रहे हैं. वैश्विक स्तर पर एक साझा कॉरपोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स एवं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की व्यवस्था पर सहमति बनती दिख रही है. ज्ञान, तकनीक एवं आविष्कार के माध्यम से कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा मिल रहा है. विश्व भर में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसे प्रयासों की रोकथाम के प्रति चिंता जताई जा रही है. अर्थव्यवस्था के दरवाज़े खुलने के बाद कॉरपोरेट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी हो गए हैं. इस वजह से भी कि कॉरपोरेट्स ने मुनाफ़े पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है. दूसरी तरफ़ कच्चे माल के बढ़ते दाम और बढ़ते श्रम मूल्य भी कुछ ख़ास सेक्टरों के लिए एक चिंता का विषय बन गए हैं. इसके अलावा वैश्विक मंदी, ज़्यादा मुनाफ़े का लालच एवं व्हाइट कॉलर क्राइम भी एक समस्या है.

## भाषण के मुख्य अंश

भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ ही अगर मज़बूत रेगुलेटरी सिस्टम विकसित कर लिया जाता तो पिछले कुछ समय में हमने कॉरपोरेट सेक्टर में जो बड़े-बड़े घोटाले होते देखे, वे नहीं होते. यदि कॉरपोरेट सेक्टर को लेकर एक मज़बूत व्यवस्था होती, क़ानून होते तो हमें यह सब नहीं देखना पड़ता. 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की घोषणा की, तब देश की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी. आर्थिक वृद्धि अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ और भी कई बातें जुड़ी हुई हैं. मसलन, सबको साथ लेना और रेगुलेशन. साथ ही एक बैलेंस्ड एवं सस्टनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए. कंपनी बिल-1956 बहुत पुराना अधिनियम है और जितनी जल्दी हो सके, इसकी जगह नया अधिनियम लाना चाहिए. अब कंपनी अधिनियम- 2011 की तैयारी की जा रही है. 1991 में आर्थिक उदारीकरण के तुरंत बाद ही हमें 1956 का अधिनियम समाप्त करके नया अधिनियम लाना चाहिए था. ऐसा होता तो आज कॉरपोरेट जगत से जो नकारात्मक ख़बरें हमें देखने-सुनने को मिलती हैं, उनसे बचा जा सकता था. प्रतिस्पर्धा अधिनियम बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, जबकि यह 2009 में आया. मुझे उम्मीद है कि प्रतिस्पर्धा नीति को मंज़ूरी दे दी जाएगी. इस नीति से आर्थिक वृद्धि एवं रोज़गार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी और मुद्रास्फीति पर लगाम लगाई जा सकेगी. एक राष्ट्रीय कॉरपोरेट गवर्नेंस नीति भी बनाई जाएगी. इसके लिए सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद इसे तैयार किया जाएगा.

## कॉरपोरेट सेक्टर के मुद्दे

मुनाफ़ा एक अहम हिस्सा है, लेकिन यह व्यापार का अकेला और एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता. टिकाऊ विकास और सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी पर भी अब ज़ोर-शोर से बात की जा रही है. लंबे समय तक बाज़ार में बने रहने के लिए यह ज़रूरी है कि शेयर होल्डर्स, कर्मचारियों, क़र्ज़दाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं एवं ज्वाइंट वेंचर के सहयोगियों इत्यादि सबके हितों की रक्षा हो. प्रतियोगिता से कैसे निपटना है, इस पर भी विचार करना होगा. सेक्टोरल रेगुलेटर्स की संख्या भी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि दिनोंदिन कॉरपोरेट्स नए-नए क्षेत्रों यानी फाइनेंस, फैक्ट्रिंग एवं रियल एस्टेट में क़दम बढ़ा रहा है. कॉरपोरेट्स हाउस का मालिकाना हक़ और उसका प्रबंधन अलग-अलग हो, इस पर भी विचार की ज़रूरत है. कॉरपोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स के अनुपालन की ज़्यादा ज़रूरत है. सीए, सीएस, एमबीए एवं एडवोकेट्स जैसे प्रोफेशनल्स का रोल भी अहम होने वाला है. कॉरपोरेट्स हाउस द्वारा ग़लत तरीक़े अपनाने एवं धोखाधड़ी जैसे कामों से समयबद्ध और मज़बूत क़ानूनी प्रावधानों के ज़रिए निपटने की ज़रूरत होगी.

## निष्कर्ष

कृषि क्षेत्र, जहां एक बहुत बड़ी आबादी लगी हुई है, के विकास की ज़रूरत है. कॉरपोरेट्स द्वारा अपना सीएसआर दायित्व निभाने की ज़रूरत है, जिससे कॉरपोरेट्स एवं लाभार्थियों यानी दोनों को फ़ायदा हो.

## कंपनी बिल-2011 की ख़ास बातें

वर्तमान राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र कंपनी एक्ट-1956 में बदलाव की ज़रूरत थी, इसलिए इसमें 25 संशोधन किए गए, ताकि एक बिजनेस फ्रेंडली कॉरपोरेट रेगुलेशन बनाया जा सके, कॉरपोरेट्स गवर्नेंस नॉर्म्स बनाया जा सके, कॉरपोरेट्स एवं ऑडिटर्स की ज़िम्मेदारी तय की जा सके, पारदर्शिता का स्तर बढ़ाया जा सके और निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके. साथ ही इस बिल की कुछ ख़ासियत भी है, जैसे कॉरपोरेट्स सोशल रेस्पोंसिबिलिटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वन पर्सन कंपनी (ओपीसी), सीरियस फ्रॉड इंवेस्टीगेशन ऑफिस, की-मैनेजेरियल पर्सन, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, निवेशक की भूमिका मज़बूत बनाना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एवं अपीलेट अथॉरिटी इत्यादि. 14 दिसंबर, 2011 को यह बिल लोकसभा में रखा गया, जिसे जांच के लिए स्टैंडिग कमेटी ऑन फिनांस के पास भेज दिया गया.

ई-गवर्नेंस (क्लॉज-120): कंपनियों को सारे दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देखने की सुविधा दी गई है. कॉरपोरेट्स सोशल रेस्पोंसिबिलिटी को शामिल किया गया है. कंपनियों की ज़िम्मेदारी बढ़ाई जा रही है. चेमोटर की परिभाषा को शामिल किया जा रहा है. सीएसआर, रिस्क मैनेजमेंट और कार्यक्षमता मूल्यांकन के संदर्भ में ख़ुलासा करने जैसे काम भी इसमें शामिल किए गए हैं. विदेशी सहयोगी के एकाउंट की जानकारी भी रजिस्ट्रार को देनी होगी. कंपनियों द्वारा धन इकट्ठा करने के संबंध में भी नियम बनाए गए हैं. सभी सूचीबद्ध कंपनियों को अपने प्रमोटरों एवं टॉप टेन शेयर होल्डरों में बदलाव की जानकारी अपने रिटर्न में रजिस्ट्रार को देनी होगी. ऑडिट के बारे में भी नियम बनाए गए हैं, जैसे एक ख़ास समय के बाद ऑडिटर्स एवं ऑडिटर्स फर्म में बदलाव लाना होगा. नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्स का नाम बदल कर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी करने का प्रस्ताव किया गया है. जो कंपनी मुनाफ़े में नहीं है, वह इस बिल में प्रस्तावित नए नियम के मुताबिक़ पारिश्रमिक का भुगतान करेगी. अगर इस नियम के मुताबिक़ कंपनी पारिश्रमिक देने में असमर्थ होगी तो उसे केंद्र सरकार से सहमति लेनी होगी. नए बिल के प्रावधानों के मुताबिक़, स्वतंत्र निदेशक को स्टॉक ऑप्शन नहीं, बल्कि तय शुल्क मिलेगा. यह शुल्क केंद्र सरकार तय कर सकती है. कंपनियों के विलय और अधिग्रहण के संबंध में भी नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिनके तहत ऐसा करने से पहले केंद्र सरकार को सूचित करना होगा. शेयर होल्डरों एवं निवेशकों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी. संगीन धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने के लिए जो कार्यालय होगा, उसे वैधानिक दर्जा मिलेगा. कम से कम एक महिला निदेशक का होना ज़रूरी होगा. नेशनल कंपनी लॉ के सदस्यों की योग्यता एवं अनुभव का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है. भारत विदेशी निवेशकों के लिए दूसरा सबसे पसंदीदा देश है. 2020 तक भारत के आईटी एवं बीपीओ सेक्टर 10 मिलियन प्रत्यक्ष और 20 मिलियन अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेंगे. रक्षा उद्योग भारत का उभरता बाज़ार है. पूंजी बाज़ार में 90 फ़ीसदी तरलता भारत के सिर्फ़ दस शहरों से आती है. सरकार और कॉरपोरेट्स में अनुचित कार्यों से हम जीडीपी का 2 फ़ीसदी खो देते हैं. यदि हमारे पास एक बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस हो तो हम 2 फ़ीसदी ज़्यादा जीडीपी पा सकते हैं.

## प्रभावी प्रतिस्पर्धा नीति की आवश्यकता

सिटी बैंक ग्रुप का एक अध्ययन बताता है कि 39 सालों के भीतर भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा. अभी सेकेंड जेनरेशन के सुधार के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है.

## चुनौतियां और उपाय

महंगाई एवं रोज़गार सृजन जैसे मुद्दों से कैसे निपटा जा सकता है. समग्र विकास के लिए ज़रूरी है कि यह देखा जाए कि क्या अर्थव्यवस्था ने लोगों के लिए नए अवसर पैदा किए, उनकी क्षमता बढ़ाने का काम किया, क्या अवसर एवं क्षमता को एक साथ मिलाने का काम किया गया और क्या उन्हें सुरक्षा दी गई?

## अप्रवासी भारतीय और निवेश

विदेशों में रहने वाले भारतीय आराम से, बिना किसी परेशानी के भारत में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि भारत विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी विकास दर काफ़ी तेज़ है. निवेश के लिए बेहतर विकल्प हैं. दवा से लेकर उपभोक्ता सामग्री, कृषि, ऊर्जा एवं शिक्षा जैसे सारे विकल्प खुले हुए हैं. सेवा क्षेत्र भी हैं, जैसे आईटी और सॉफ्टवेयर. भारत में शिक्षा का स्तर ऊंचा है. अंग्रेजी भाषा के जानकार युवा हैं. यहां का लोकतंत्र भी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में सहायक है. भारत में बचत की दर लगभग 37 फ़ीसदी है, जो निवेश के तौर पर काम आती है. भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका रही है. भारत में एक मज़बूत वित्तीय सेक्टर भी है, जो किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने में सहायक है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# पर्यावरण संबंधी मुकदमेबाज़ी का नया युग

भारत एक ऐसा देश है, जिसका पर्यावरण संबंधी आंदोलनों, ज़मीनी स्तर पर सक्रियता और उत्तरदायी उच्च न्यायपालिका का अपना समृद्ध इतिहास रहा है. ऐसे देश में 2011 का वर्ष पर्यावरण संबंधी मुकदमेबाज़ी का अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष अर्थात मील का पत्थर साबित हुआ है. यद्यपि पर्यावरण संबंधी मुक़दमेबाज़ी पिछले तीन दशकों में काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के कारण 2011 का वर्ष फिर भी काफ़ी विशिष्ट है. केवल यही एकमात्र तथ्य नहीं है कि इसकी स्थापना की गई, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ही एक अधिकरण की स्थापना की गई थी, जो इससे कम शक्तिशाली था. लेकिन जिस तरह से उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय को इस दिशा में सक्रियता से प्रेरित किया गया, वह इसकी विशेषता बन गई. राष्ट्रीय हरित अधिकरण का पहला क़दम और इसे पूरी तरह से स्थापित करने का निरंतर संघर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है. पर्यावरण संबंधी मामलों पर केंद्रित और गठित राष्ट्रीय हरित अधिकरण के क़ानून को जून, 2010 में राष्ट्रपति की स्वीकृति तो मिल गई थी, लेकिन इसे केंद्र सरकार की अधिसूचना के ज़रिये उस वर्ष के दौरान 18 अक्टूबर को ही लागू किया जा सका. उसी दिन भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एलएस पांटा को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया, हालांकि न तो किसी अन्य सदस्य को तब तक नियुक्त किया जा सका था और न ही इसके लिए बुनियादी ढांचा और स्टाफ मुहैया कराया जा सका था.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के लागू होने से दो वर्तमान क़ानून स्वतः ही भंग हो गए हैं. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 और इसी कारण राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण भी समाप्त हो गया, जिसे पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए दिए गए अनुमोदनों के ख़िलाफ़ सुनवाई करने के लिए एक अर्ध–न्यायिक निकाय के रूप में प्राधिकृत किया गया था. राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के सामने लंबित सभी मामलों की सुनवाई अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण करेगा. इसके बंद हो जाने से एक न्यायिक शून्य पैदा हो गया था और नए मामलों की सुनवाई के लिए कोई मंच नहीं रह गया था और सभी लंबित मामले अधर में लटक गए थे. अध्यक्ष के अलावा कम से कम एक और सदस्य की नियुक्ति के बिना राष्ट्रीय हरित अधिकरण काम ही नहीं कर सकता था. यद्यपि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने विनियामक अनुमोदन देना जारी रखा, लेकिन उन्हें चुनौती देने के लिए कोई न्यायिक निवारण तंत्र नहीं रह गया था. यह स्थिति अनिश्चित काल तक बनी रहती, यदि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश न दिया होता कि पर्यावरण और वन मंत्रालय नए अधिकरण की स्थापना के संबंध में की गई प्रगति से उन्हें नियमित रूप में अवगत कराता रहे. इसके परिणाम स्वरूप 5 मई, 2011 को तीन न्यायिक सदस्यों और चार विशेषज्ञ सदस्यों को नियुक्त किया गया और राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपनी पहली सुनवाई 25 मई, 2011 को शुरू की.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की न्याय–सीमा का दायरा अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण से कहीं अधिक व्यापक है. इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता सहित सात क़ानूनों के कार्यान्वयन से पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल उठने वाले मामले भी सुने जा सकते हैं. यह केवल अपीलीय निकाय ही नहीं है, बल्कि इसके मूल क्षेत्राधिकार में कुछ ख़ास कोटि के मामलों पर निर्णय देने का अधिकार भी आ जाता है. यह क्षतिपूर्ति के निर्णय दे सकता है और क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकीय और संपत्ति के फिर से बहाली के प्रत्यक्ष निर्णय भी दे सकता है.

आजकल नियमित सुनवाई की जाती है, लेकिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सामने बड़ी संस्थागत चुनौतियां भी हैं. राष्ट्रीय हरित अधिकरण दो अलग–अलग परिसरों से अपना काम करता है, क्योंकि इनके अपने परिसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस समय क़ाबिज़ है. कुल दस न्यायिक और दस विशेषज्ञ सदस्यों में से केवल दो न्यायिक और चार विशेषज्ञ सदस्यों की ही अब तक नियुक्ति की गई है और अध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दे दिया है. लगता है कि सरकार सदस्यों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने में असमर्थ है. पुणे, कोलकाता और चेन्नई की सर्किट बेंचों में अभी तक सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है, जबकि भोपाल बेंच में उद्घाटन के रूप में पहली सुनवाई पिछले नवंबर में ही हो गई थी. दिलचस्प बात तो यह है कि जब राष्ट्रीय हरित अधिकरण को पहले पहल संसद में पेश किया गया तो तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्री 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पहली बेंच की स्थापना भोपाल में ही कराने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अधिनियम के पारित होने से पहले ही यह प्रस्ताव त्याग दिया गया.

पिछले नौ महीनों में लगभग अस्सी मामले राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सामने आए हैं. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की व्यापक न्याय–सीमा के आधार पर अनेक प्रकार के मुद्दे उठाए गए. इन मुद्दों में बिजली परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी अनुमोदन प्रदान करने से जुड़े मामलों को चुनौती देने से लेकर वन्य भूमि के उपयोग के लिए सरकार द्वारा अनुमति देने तक और वायु एवं शोर प्रदूषण तक के मामले भी शामिल थे. जहां राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण में जाने वाले लोग मुख्यतः परियोजनाओं से प्रभावित लोग या समुदाय–आधारित संगठन ही होते थे, वहीं राष्ट्रीय हरित अधिकरण में जो आवेदक आते हैं, उनमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्णयों से प्रभावित छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों से लेकर उन पर थोपी गई नियामक स्थितियों को चुनौती देने वाली बड़ी कंपनियां भी शामिल होती हैं. इस प्रकार राष्ट्रीय

पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के विपरीत राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आवेदकों में व्यापक स्तर पर विविध प्रकार के आवेदक होते हैं. अपनी स्थापना से लेकर अब तक राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए हैं.

अधिकरण के सामने देरी से लाए गए मामलों के संबंध में भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उदार रुख़ अपनाया है, ताकि न्याय पाने के इच्छुक लोगों के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दरवाज़े लंबे समय तक खुले रखे जा सकें. क़ानून के अनुसार, यदि कोई सरकारी निर्णय को चुनौती देना चाहता है तो उसे निर्णय जारी होने की तारीख़ के तीस दिनों के अंदर ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संपर्क करना चाहिए. राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संपर्क करने का समय साठ दिनों तक तभी बढ़ाया जा सकता है, जब विलंब करने के पर्याप्त कारण मौजूद हों और अधिकरण इसे स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है, लेकिन नब्बे दिन बीत जाने पर इस अवधि को बढ़ाने का राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास कोई उपाय शेष नहीं बचता. हिमाचल प्रदेश में पन–बिजली परियोजना के निर्माण के लिए वन्य भूमि के दिशा–परिवर्तन को चुनौती देने वाले एक अपीलकर्ता ने निर्णय लिए जाने के 90वें दिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संपर्क किया था. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने विलंब के कारण को स्वीकार करते हुए उ च्च त म न्यायालय के इस निर्णय को मंज़ूर करते हुए कि यदि विवादी की तरफ़ से कोई लापरवाही या देरी नहीं की गई है और विवादी सदाशयी है तो ऐसे मामले में उदार रुख़ अपनाया जा सकता है, यह व्यवस्था दी कि विलंब की व्याख्या का कोई बना–बनाया सीधा फॉर्मूला नहीं हो सकता.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय इस बात पर था कि अधिकरण से कौन संपर्क कर सकता है अर्थात कौन इसके लिए क़ानूनी रूप से अधिकारी है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यह व्यवस्था दी कि कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के संबंध में अधिकरण से तब तक संपर्क कर सकता है, जब तक कि उसकी याचिका तुच्छ न हो. यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अधिक से अधिक हितधारक पर्यावरण के संबंध में क़ानूनी सवाल उठा सकते हैं और इससे उसका दायरा और भी बढ़ सकता है. ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संपर्क करने वाले लोग सरकार के किसी निर्णय (जैसे ताप बिजली घर या बांध बनाने के लिए अनुमोदन देना आदि) से सीधे प्रभावित या घायल हुए हों. कोई भी व्यक्ति जिसके पास यह मानने का कोई कारण हो कि सरकार के किसी निर्णय से प्राकृतिक पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है, अधिकरण से संपर्क कर सकता है.

खनन कार्य से संबंधित गुण–दोषों पर आधारित एक निर्णय पर परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन में हुई चूकों का पता लगाते समय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भारत में पर्यावरण संबंधी प्रभाव के मूल्यांकन की कमियों पर टिप्पणी की थी. पहली टिप्पणी थी, 10 किमी के अर्धव्यास के अंदर अन्य परियोजनाओं के संचयी प्रभाव के मूल्यांकन में कमी, दूसरी टिप्पणी यह है कि पर्यावरण संबंधी प्रभाव का मूल्यांकन उन सलाहकारों द्वारा किया जाता है, जिनका भुगतान परियोजना के समर्थकों द्वारा किया जाता है, हितों का टकराव होने लगता है और इस बात की भी संभावना बनी रहती है कि कुछ भीतरी सूचनाएं, जो समर्थकों के ख़िलाफ़ जा सकती हैं उन्हें प्रकट न किया जाए और तीसरी टिप्पणी यह है कि वे सलाहकार जिनकी पर्यावरण संबंधी प्रभाव के मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, वे अपनी सूचना के लिए किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं हैं. पर्यावरणविदों द्वारा ये मामले बार–बार उठाए जाते रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इन पर न तो किसी नीति की घोषणा की जाती है और न ही विधायी प्रतिक्रिया प्रकट की जाती है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अंततः यह निर्णय कर लिया है कि किसी भी अनुमोदन को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय परियोजना और पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर लेता. पर्यावरण संबंधी विधिवेत्ताओं ने इन मिसालों का स्वागत किया है और इन्हें प्रगतिशील कहा है और साथ ही साथ राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश बहुत सावधानी से लिए गए हैं. उदाहरण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मामलों के लंबित रहते हुए परियोजना–स्थलों पर काम रोकने से इंकार भी किया है और यह व्यवस्था भी दी है कि परवर्ती चरण में कपनियां इक्विटी के लिए दावा नहीं कर सकतीं या दूसरे शब्दों में अब बहुत देर हो गई है, इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता. परंतु दुख केवल इस बात का रह जाता है कि एक बार उजड़ी हुई जनजातियां और पर्यावरण को दोबारा नहीं बसाया या संवारा जा सकता.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन पर्यावरण और वन व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए किया गया था. यद्यपि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अभी मूल्यांकन करना कदाचित जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इतनी व्यापक शक्तियों और न्याय–सीमा के साथ ऐसे विशिष्ट अधिकरण के अस्तित्व से ही भारत में पर्यावरण संबंधी क़ानूनी मुद्दों का समय पर निपटारा किया जा सकता है.

**शिबानी घोष**
feedback@chauthiduniya.com

*(शिबानी घोष नई दिल्ली स्थित नीति अनुसंधान केंद्र में रिसर्च ऐसोसिएट हैं और सार्वजनिक हित के पर्यावरण संबंधी क़ानून की एक फर्म से जुड़ी हैं.)*

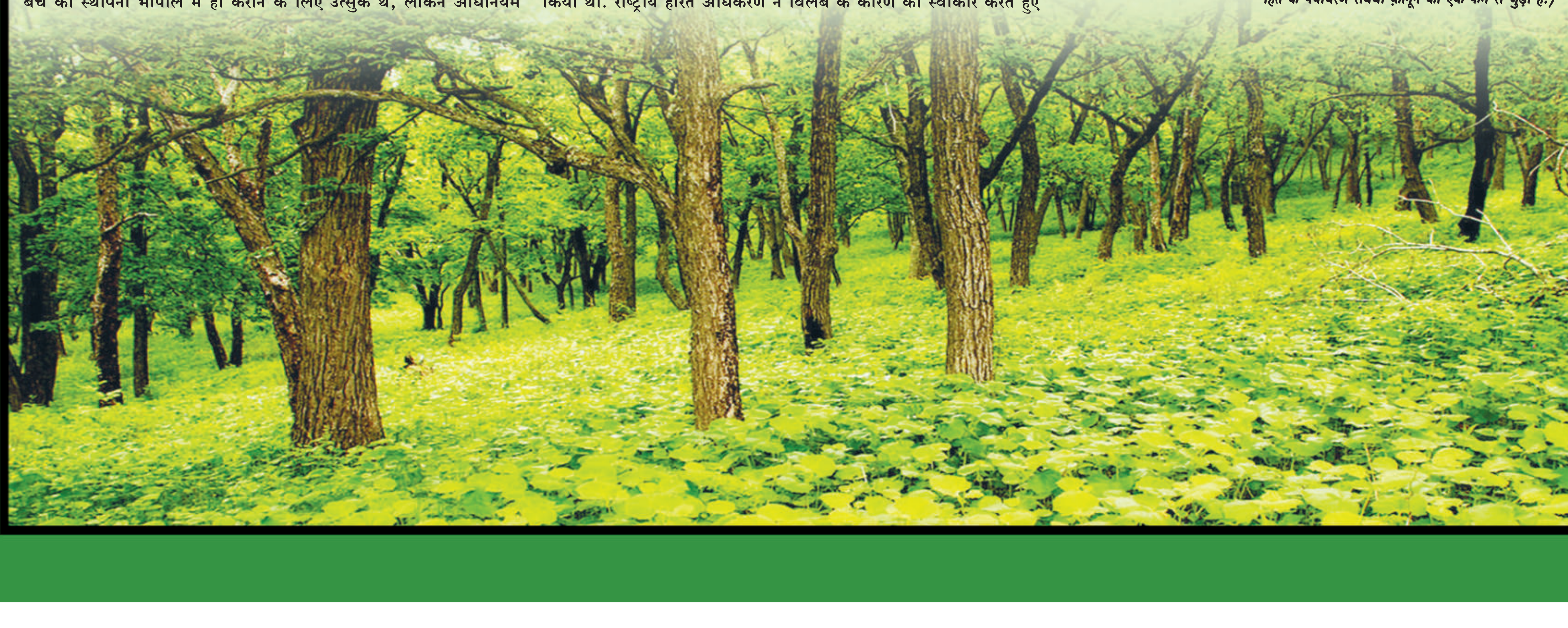

एक और काम भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र को करना चाहिए. इन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू सामाजिक विकास की योजनाओं में सहयोग करना चाहिए, ताकि भारत का संपूर्ण विकास हो सके.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

# काम रोको

यह सही है कि इससे जनता को कष्ट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. अभी हम श्रमिक संघ प्रणाली का विश्लेषण कर रहे हैं. इसके कई पहलू अभी तक बाक़ी रह गए हैं. मज़दूरों के किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए सविनय अवज्ञा के तरीक़े हैं, जैसे टूल्स डाऊन, स्टे-इन-स्ट्राइक आदि. हर श्रमिक संघ का पहला लक्ष्य तो यही रहता है कि हर मज़दूर या उस कार्य को कर सकने वाले जितने भी मज़दूर उस शहर में हों, सब उसके सदस्य होने चाहिए, जिससे कि मालिक लोग किन्हीं दूसरे व्यक्तियों को काम पर रखकर हड़ताल न तोड़ सकें, पर आदमी-आदमी में या एक मज़दूर का दूसरे मज़दूर से इतना सांघातिक वैमनस्य हो जाता है कि वे एक-दूसरे की जान लेने तक पर आमादा हो जाते हैं.

जो श्रमिक हड़तालकारियों की जगह भर्ती होने के लिए तत्पर हो जाएं, उन्हें उनकी भाषा में ग़द्दार, हरामख़ोर या पिट्ठू के नाम से पुकारा जाता है. मज़दूर समुदाय उन व्यक्तियों का सामाजिक और नैतिक बहिष्कार कर डालते हैं. श्रमिक संघ जब भी हड़ताल की घोषणा करते हैं, तुरंत उस कारख़ाने या फैक्टरी के द्वार पर उनके व्यक्तियों का धरना या पिकेटिंग चालू हो जाता है. किसी भी दूसरे श्रमिक को, जो काम करना चाहता हो और उनके संघ का सदस्य न हो, रोकने का वे यत्न करते हैं. भारत में अभी तक इन श्रमिक संघों के पतन की वह चरम सीमा नहीं आई है, जैसी दूसरे देशों में मौजूद है. ग्रेट ब्रिटेन में पहले तो कोई भी श्रमिक बिना संघ का सदस्य बने हो ही नहीं सकता. यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कोई भी मज़दूर बिना संघ का सदस्य हुए मज़दूरी कर भी सकता है. पर जहां-जहां हड़तालें होती हैं और मालिक लोग कहीं से प्रयत्न करके दूसरे मज़दूरों को भर्ती कर ले आते हैं, वहां उनके हाथ-पांव साबुत नहीं बच पाते. जब वे मील के बायलर के पास काम करने जाते हैं तो उन्हें वहां विस्फोटक बम मिलता है, जो उसी वक़्त फटकर नए भर्ती हुए श्रमिकों की मृत्यु या अंग भंग का कारण बन जाता है. वहां की मशीनों, इमारत और अन्य साधन सामग्रियों को पर्याप्त ख़तरा रहता है. हड़ताली मज़दूर इतने उपद्रवी हो जाते हैं कि जिस कारख़ाने या फैक्टरी पर हड़ताल हुई, वहां जान-माल कुछ भी सलामत नहीं. सैकड़ों ऐसे कार्य हैं, जिन्हें रोज़ाना करने वाला इस तरह से करके जाता है कि जो भी ग़द्दार या पिट्ठू उसकी जगह काम करने के लिए आए, उसे अपने जीवन के लाले पड़ जाएं.

इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन में श्रम संघों की जो भयानक ज़्यादती है, वह यह है कि किसी भी बाहरी श्रमिक को वे काम नहीं करने देंगे. हड़ताल के समय की बात ही नहीं है. यों साधारणतया भी अगर आपको एक बढ़ई या फिटर की आवश्यकता है तो आप अपने मनपसंद का अच्छा कारीगर नहीं रख सकते. आपको उसी संघ को ही प्रार्थनापत्र भेजना होगा और वही संघ अपनी शर्तों पर, जिसे चाहे भेजेगा. एक बढ़ई, फिटर, लोहार जो काम उसके ज़िम्मे है, उससे रंचमात्र भी ज़्यादा काम नहीं करेगा. अगर एक काम के पूरा होने में मान लीजिए, सिर्फ़ दो स्क्रू ही कसने बाक़ी रह गए और बढ़ई, राज या फिटर कोई भी आसानी से स्क्रू टाइट करा सकता है, पर चूंकि उनकी यूनियन के नियम हैं, इसलिए वह काम तब तक रुका रहेगा, जब तक स्क्रू फिटर आकर उन दोनों स्क्रू को कस न जाए.

अगर आपने किसी बाहरी अच्छे कारीगर को रख लिया तो संघ का कोई भी श्रमिक उसके साथ काम नहीं करेगा, तुरंत हड़ताल हो जाएगी. परिणाम होगा अशांति और उपद्रव. वहां के मालिक लोगों को ज़रा भी स्वतंत्रता नहीं है कि वे अपने मनपसंद कारीगर रख लें. न श्रमिक को छूट है कि उसे जहां नौकरी मिले, कर ले. लाख चाहकर, कोशिश करके भी वह किसी भी कारख़ाने में अपने आप नौकरी नहीं कर सकता. उसे पहले उसी संघ की शरण में जाना होता है जो उससे तगड़ी फी, पगड़ी या प्रवेश-फी वसूल करते हैं. बाद में 2-3 या 5 वर्षों तक संघ में ही अनेक शिक्षार्थियों के साथ काम करना पड़ता है, जहां वेतन न्यूनतम मिलता है. वहीं अखाड़े के पहलवानों की शागिर्दी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वह पूर्ण सदस्य बन पाता है. फिर वह संघ सूचित करता है कि उसका नाम, किसी कारख़ाने या फैक्टरी के लिए उपयुक्त हो गया है.

इस प्रथा को वाममार्गियों ने भैरवी चक्र की तरह बना रखा है, अंग्रेजी में इस क्लोज शॉप कहते हैं. भावार्थ यही है कि हमारे इस भैरवी चक्र के सदस्य के अलावा दूसरे श्रमिक को श्रम करने का या रोटी कमाकर खाने का अधिकार ही नहीं है. अमेरिका में इन संघों का रूप और भी ज़्यादा भयानक या वीभत्स है. हालांकि वहां उपरोक्त भैरवी चक्र नहीं है, पर बिना उस संघ की सदस्यता के कोई श्रमिक काम करने का साहस कर ले, यह स्वप्न में भी संभव नहीं है. संघ के अधिकारीगण बहुधा जरायम पेशावर गुंडे इस काम के लिए रखते हैं. उनको आदेश रहता है कि जो भी श्रमिक उनके बीच में आए या जो भी मज़दूर उनके विरुद्ध सभा में वोट देने का साहस करे, उसे मार्ग से हटा दो. कुछ ही घंटों बाद ऐसे श्रमिकों की लाशें नदी या समुद्र में ऊपर आई हुई मिलेंगी या कहीं सड़क के किनारे फेंकी हुई मिलेंगी. दूसरे भी तरीक़े हैं, जिनके द्वारा संघ के ये अवांछित श्रमिक राह से हटा दिए जाते हैं. दूसरे मज़दूरों द्वारा प्रयत्न करके व्यवस्थित ढंग से अनिच्छित श्रमिक का ख़ात्मा करा दिया जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी पर अभियोग न लगाया जा सके. मालिकों द्वारा जो वेतन दिया जाए या संघ द्वारा जो मांग पेश की जाए, इस मतभेद के अलावा श्रमिक को विशेष कठिनाई यह जानने में होती है कि उसे काम कितना करना है.

feedback@chauthiduniya.com

*महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.*

# सही प्रशिक्षण से सफलता मिलेगी

आज पूरा विश्व बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र में आई मंदी की मार झेल रहा है. यूरोप में इसका प्रभाव ज़्यादा दिखा, जबकि भारत इस मंदी से कुछ हद तक अपने को दूर रखने में कामयाब रहा है. भारत ने इसके लिए एक अच्छा रास्ता अपनाया. उसने अपनी घरेलू मांग को बढ़ाया. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों ने भी कॉरपोरेट क्षेत्र को मंदी से निपटने में सहयोग दिया, लेकिन सरकार का सहयोग और घरेलू मांगों को बढ़ाना ही वैश्वीकरण के इस दौर में मंदी से बचने के लिए काफ़ी नहीं है. इसके लिए कुछ और नए क़दम उठाने होंगे, ताकि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र और बैंक अपना विकास कर सकें. इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी व्यवसायिक गुणवत्ता को और अधिक बेहतर एवं प्रभावशाली बनाएं. व्यवसायिक गुणवत्ता बढ़ाने का एक मतलब यह भी है कि किसी भी संगठन में काम करने वाले लोगों को वैश्विक परिस्थितियों तथा घटने वाली घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए. कर्मचारियों की व्यवसायिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है. बिना प्रशिक्षण के गुणवत्ता में सुधार नहीं किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए विश्व की कई कंपनियों तथा कुछ भारतीय कंपनियों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं. उन्होंने मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में निवेश करना शुरू कर दिया है तथा अपनी कंपनी के भीतर भी मानव संसाधन विभाग की व्यवस्था करने लगे हैं. भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र ने देश के अंदर के संसाधनों ख़ासकर मानव संसाधन को तवज्जो देना शुरू किया है. हालांकि इस संसाधन को और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है, ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में ख़ुद को स्थापित किया जा सके. कई कंपनियों ने अपना विश्वविद्यालय भी खोल लिया है. ऐसे कुछ विश्वविद्यालय बंगलुरु

**हमारे पास एक उदाहरण है. बंगलुरु मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का काम पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छा रहा है. इसे हमने सार्वजनिक क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट की तरह बनाया. नई और आरामदायक बसों की व्यवस्था की गई. इसके कारण लोग अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करके बीएमटीएस की बसों में सफ़र करने लगे.**

में हैं. इन विश्वविद्यालयों में प्रोफेशनल स्किल बेहतर करने की शिक्षा दी जाती है, ताकि कॉरपोरेट क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा में स्थापित किया जा सके.

इसके अलावा एक और काम भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र को करना चाहिए. इन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू सामाजिक विकास की योजनाओं में सहयोग करना चाहिए, ताकि भारत का संपूर्ण विकास हो सके. जब भारत का विकास होगा तो इनके लिए बाज़ार उपलब्ध होगा. विकास के साथ ही बाज़ार का विकास किया जा सकता है. साथ ही राज्य की राजधानियों में उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है. अभी भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहां उद्योगों का संकेंद्रण बढ़ाया जा सके. भारत में अभी ढांचागत विकास तेज़ी से हो रहा है. सड़कों की अच्छी व्यवस्था करने के बाद उद्योगों को ज़िलों तक पहुंचाया जा सकता है. हालांकि कुछ राज्यों ने इसके लिए अच्छा काम किया है, जिसे उदाहरण बनाया जा सकता है तथा उससे प्रेरणा भी ली जा सकती है. हम कर्नाटक का उदाहरण ले सकते हैं. इस राज्य में सरकार ने सड़कों के विकास के लिए अच्छा काम किया है. इससे इस राज्य में ज़िला स्तर के शहरों का भी औद्योगीकरण हुआ है. यहां ज़िला स्तर के शहरों में उद्योग खोले जा रहे हैं. राज्य सरकार ने ग्लोबल इंवेस्टर मीट का आयोजन करके अच्छी पहल की है. इसके अलावा जो बात सबसे ज़रूरी है, वह है आर एंड डी में निवेश करना. रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करके हम अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं तथा अपनी वर्तमान विकास दर एवं औद्योगिक विकास को बरक़रार रख सकते हैं. सरकार को भी प्रयास करना होगा. सरकार मज़दूर क़ानून में तेज़ी से बदलाव लाए, ताकि उद्योगों के लिए रास्ता आसान हो सके. इसके लिए सरकार को आर्थिक और व्यवसायिक सोच अपनानी होगी. हम प्रतिस्पर्धा में तभी टिक पाएंगे, जब हमारे पास नए विचार होंगे तथा वैश्विक घटनाओं की जानकारी हमारे पास होगी. हमें अपने स्तर पर सुधार करना पड़ेगा. जब तक हम नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम प्रतिस्पर्धा के इस दौर में टिक नहीं पाएंगे. नए तरीक़े अपनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं. हमारे पास एक उदाहरण है. बंगलुरु मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का काम पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छा रहा है. इसे हमने सार्वजनिक क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट की तरह बनाया. नई और आरामदायक बसों की व्यवस्था की गई. इसके कारण लोग अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करके बीएमटीएस की बसों में सफ़र करने लगे. कई तरह की बसें लाई गईं, जिससे हर तरह के नागरिक इसमें सफ़र कर सकें. इससे बीएमटीसी को लगातार फ़ायदा हुआ. बीएमटीसी को कुल 675 करोड़ का लाभ हुआ. बीएमसी का नेट बर्थ बढ़कर 1500 करोड़ रुपये हो गया. बीएमटीसी पहली अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जिसने जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत मिले धन का उपयोग बसें ख़रीदने के लिए किया. यह पहली ऐसी बस सर्विस थी, जिसने लोगों को कई नई सुविधाएं दीं. इसने ट्रैफिक ट्रांजिट मैनेजमेंट सेंटर की व्यवस्था की, ताकि लोगों को गाड़ियों की स्थिति का पता चल सके. ऐसी व्यवस्था दूसरी जगहों पर भी की जानी है. इन नए उपायों ने बीएमटीसी की तस्वीर बदल दी. देश और विदेश के कई ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने बीएमटीसी की इस नवीन तकनीक को देखा और इसका अध्ययन किया. इस तरह से देख सकते हैं कि एक नवीन तकनीक के कारण किसी संस्था को कहां से कहां पहुंचाया जा सकता है. अब भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र को भी इसी तरह के काम करने होंगे, ताकि विकास को न केवल बढ़ाया जा सके, बल्कि इसे अपनी आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षित भी रखा जा सके.

**सैयद ज़मीर पाशा**
feedback@chauthiduniya.com

*(लेखक कर्नाटक सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव हैं.)*

# पाठकों की दुनिया
## सर्वश्रेष्ठ पत्र

### आंदोलन का उग्र रूप

भारत एक लोकतांत्रिक देश है. यहां अपनी मांगों को लेकर किसी को भी आंदोलन करने की स्वतंत्रता है. लेकिन जब आंदोलन, उग्र रूप धारण कर ले तो इसे क्या कहा जाए. हरियाणा के हिसार शहर में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण की मांग को लेकर जाट आंदोलनरत हैं. आंदोलनकारी धरने-प्रदर्शन से आगे बढ़कर चक्का जाम करते हैं. रेल की पटरियों पर बैठ जाते हैं. इसके कारण रेल व्यवस्था कई-कई दिन तक बाधित रहती है. हालत यह है कि बसें तक बंद हो जाती हैं. ऐसे में हिसार से आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतर आते हैं. सरकारी इमारतों और गाड़ियों को आग के हवाले कर देते हैं. इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है. हिसार ही नहीं अन्य जगहों की भी कमोबेश यही हालत है. आंदोलन के नाम पर हिंसा करना कहां तक उचित है, ज़रा सोचिए.

–*ज़की अहमद*, ओखला, नई दिल्ली

### सरकार लोक गायकों की सुध ले

चौथी दुनिया में लोकगीत चौपालों से ग़ायब हो रहे हैं, पढ़ा. यह हैरानी और अफ़सोस की बात है कि एक तरफ़ तो म्यूजिक कंपनियां गीत-संगीत के बूते करोड़ों रुपये कमा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ़ लोक गायक भुखमरी का शिकार हैं. इसमें कोई दो राय नहीं कि फिल्मों में भी लोक गायिकी को मान-सम्मान मिला है. लोक धुन पर आधारित गीतों ने फिल्मों को हिट कराने में अहम भूमिका तक निभाई है. सरकार को चाहिए कि वह लोक गायकों के कल्याण के लिए कारगर क़दम उठाए, ताकि वे भी समाज में सम्मान से जी सकें और अपनी गायिकी के हुनर का प्रचार-प्रसार भी कर सकें.

**असलम ख़ान,** *दिल्ली*

### खनन माफ़िया का आतंक

तमाम दावों के बाद भी सरकार खनन माफ़िया के ख़िलाफ़ कोई सख्त क़दम नहीं उठा पा रही है. इसके कारण खनन माफ़िया का आतंक दिनोदिन बढ़ता जा रहा है. मध्य प्रदेश के मुरैना में खनन माफ़िया का शिकार बने आईपीएस अफ़सर नरेंद्र कुमार के पिता केशव देव ने भी इस मामले में राजनेताओं और पुलिस पर आरोप लगाए हैं. देश के कई राज्यों में अमूल्य खनिज पदार्थों के भंडार हैं. अफ़सोस की बात तो यह है कि इनसे खनन माफ़िया ही लाभ कमा रहे हैं. अवैध खनन के कारण जहां सरकार को राजस्व का नुक़सान हो रहा है, वहीं पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है.

**–काशिफ़,** *दरियागंज, नई दिल्ली*

### दाल में कुछ तो काला है

बिहार में मीडिया की आज़ादी पर प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस काटजू के बयान पर जिस तरह से हंगामा मच रहा है, उसे स्वस्थ लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं कहा जा सकता है. देखा जाए तो मीडिया इस विषय पर मंथन करने की बजाय राजनीति को ज़्यादा हवा दे रही है. जस्टिस काटजू ने जो कुछ कहा वह कितना सच है, इसे बिहार के पत्रकार ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं. राजनीतिक दलों के लिए यह केवल आरोप-प्रत्यारोप का विषय है, लेकिन आम आदमी के लिए सच को जानना अति आवश्यक है. उसे यह पता होना चाहिए कि जिस विकसित बिहार की वह कहानी सुन रहा है, वह हक़ीक़त में है अथवा दबाव में लिखी गई है. बहरहाल, बात जो भी हो हमें जस्टिस काटजू की बातों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है. हो सकता है, उनकी बातों में ज़्यादा दम न हो, लेकिन दाल में कुछ तो काला है.

**–शम्स तमन्ना,** *नई दिल्ली*

### सांसद निधि ख़र्च हो

अगर सांसद अपनी भविष्य निधि को विकास कार्यों में लगाएं तो इससे जहां क्षेत्र का विकास होगा, वहीं इससे उनकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी. 2009-10 के आंकड़ों के मुताबिक़, अमेठी में राहुल गांधी की सांसद निधि की महज़ 35 फ़ीसदी रक़म खर्च हो पाई, वहीं रायबरेली में सोनिया गांधी की सांसद निधि की महज़ 58 फ़ीसदी रक़म ख़र्च हो सकी. अगर राहुल और सोनिया अपनी सांसद निधि को ही सलीक़े से ख़र्च कर देते तो अमेठी और रायबरेली की क़िस्मत संवर जाती. वहीं सुल्तानपुर, जिसमें अमेठी के दो विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जहां के सांसद भी कांग्रेस के हैं, वहां की हालत भी कम ख़राब नहीं है.

**–नेम सिंह,** *ईमेल*

राजकमल प्रकाशन समूह
1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002
फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
शाखा : अशोक राजपथ, पटना-800006 फोन 0612-2672280
पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001 फोन 0532-3293838, 2427274

लेखन विधा सम्मान 2011
'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपए की किताबें

देश के जाने-माने पत्रकार एवं 'चौथी दुनिया' के सम्पादक संतोष भारतीय के संपादन में प्रकाशित 'दलित अल्पसंख्यक सशक्तीकरण' के वैश्विक प्रयासों का तथ्यात्मक दस्तावेज। यह पुस्तक प्रमाणित करती है कि दुनिया भर के गरीब, दबे-कुचले और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग समूहबद्ध होकर यदि शक्तिसम्पन्न होने का संकल्प लें तो वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव सामने आएँगे।

मूल्य ₹ 1000 पृ. : 448
राजकमल प्रकाशन प्रा.लि.

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें
हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

## जब तोप मुक़ाबिल हो

# सेना के लिए ये एक अद्भुत अवसर है

भारतीय सेना देश का गौरव है. गौरव इसलिए है, क्योंकि देश का जवान मौत को चुनता है. सेना में जाने की एक ही क़ीमत है. जब भी युद्ध हो या देश में कहीं भी अशांति हो, सेना का जवान वहां हथियार लिए हुए मुस्तैद रहे. इस प्रोफेशन की यही एक मात्र शर्त है. इसका सीधा मतलब अपनी ख़ुशी से मौत को चुनना है. हमारे देश का वह जवान जो ख़ुशी-ख़ुशी देश की रक्षा के लिए, देश में अमन-चैन के लिए मौत को चुनता है. लेकिन जब वह नौकरी से रिटायर होता है, तो सेना और समाज उसे भटकने के लिए छोड़ देता है. होना यह चाहिए कि जो आदमी देश की रक्षा के लिए मौत को चुने, उसको पेंशन के साथ-साथ सेना या सरकार इस तरह का काम मुहैया कराए, जिससे वह अपनी समस्याओं का हल अपने आप कर सके. उसे किसी के दरवाज़े न जाना पड़े. उसके बच्चों को पढ़ने के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े. जितनी सरकार उसके प्रति उत्तरदायी हो, उतना ही समाज भी उसके प्रति उत्तरदायी हो, पर ऐसा होता नहीं है. अगर उसने कोई ट्रेनिंग कर ली, तो ट्रेनिंग करने के बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं. अगर उसने कोई काम सीखा तो उस काम से पैदा हुए उत्पाद की क़ीमत उसे मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है. नतीजे के तौर पर नौजवान जो चालीस साल की उम्र में सेना से रिटायर होता है, अपने बचे हुए चालीस साल वह अपनी ज़िंदगी के दोबारा मायने खोजने में बर्बाद करता है. चूंकि वह बीस साल सेना में लगाकर आता है, तो उसे समाज का कुछ भी पता नहीं होता है, या तो वो दूसरों को निराश कर देता है या फिर क्रोधित हो जाता है. क्रोधित होकर असामाजिक तत्वों को मदद देने लगता है. सेना के जवान में सबसे बड़ा गुण उसका अनुशासन और हथियारों के प्रति उसकी ट्रेनिंग होती है. इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा किस तरह से समाज को मिले, इसकी ज़िम्मेदारी सरकार और सेना दोनों की है. यह नौजवान समाज को दिशा दे सकता है. समाज में नए संदर्भ पैदा कर सकता है और उन सारे लोगों को जो सेना में नहीं गए हैं, बुनियादी ट्रेनिंग दे सकता है. लेकिन ऐसा होता नहीं है.

बीते सात मार्च को भारत की सेना ने एक नई पहल की. उसने मोरारका फाउंडेशन द्वारा जवानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग देने के प्रस्तावों को मान लिया. एडजुटेंट जनरल नेहरा की अनुपस्थिति में मेजर जनरल मज़ूमदार ने उस पर दस्तख़त किए. इस सहमति पत्र के अनुसार, सेना से रिटायर होने के बाद अगर जवान अपने यहां जैविक खेती करते हैं, तो उस जैविक खेती के उत्पादन को बेचने के लिए उन्हें मंडी नहीं जाना पड़ेगा. अगर वे उत्पादन करते हैं, तो उनके उत्पादन क्षेत्र से या उनके खेत से या उनके दरवाज़े से उस फ़सल को मोरारका फाउंडेशन ख़रीदेगा और उसे बाज़ार में बेचेगा. मोरारका फाउंडेशन बाज़ार दर से दस प्रतिशत ज़्यादा दाम उस जवान को देगा. अगर सेना इस सहमति पत्र के पक्ष में खड़ी रही और जवानों को मिलने वाले इस लाभ को रोकने की कोशिश नहीं की तो भारत की सेना को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने पहली बार अपने जवानों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम निर्धारित किया है. भारत की सेना में एक मोटे अंदाज़ के हिसाब से हर साल 60 से 70 हज़ार जवान रिटायर होते हैं, और उनके सामने बंदूक़ लिए शहर में घरों के आगे से सिक्योरिटी एजेंसिस के गार्ड के रूप में काम करने के अलावा और कोई विकल्प बचता ही नहीं है. कितनी बड़ी विडंबना है कि जो जवान हमारी रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए सीमा पर जाता है, वे जवान रिटायर होने के बाद हमारे दरवाज़े का दरबान बनता है. और उस दरबान को भी घर के सारे काम करने पड़ते हैं, ऐसा न करने पर उसकी नौकरी जा सकती है. अपने पेट के लिए वह रोज़ अपमानित होता है. सेना को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि सेना ने अपने जवानों के लिए एक बेहतर तरीक़ा सोचा. मोरारका फाउंडेशन जैविक खेती के क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन है, जो इस देश के लाखों किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन दे रहा है. इसमें लागत कम आती है और फ़ायदा ज़्यादा होता है. सबसे बड़ा फ़ायदा जैविक विधि से उपजाए गए उत्पाद ज़हर से मुक्त होते हैं, जिनमें अन्न, मसाले, तेल, घी शामिल है. सब्ज़ियां और फल शामिल हैं. देश का हर टेलीविज़न चैनल, हर अख़बार, हर रिसर्च इंस्टीट्यूट यह बता चुका है कि अब हमारे खेतों से आने वाला अन्न, सब्ज़ी ज़हरीली होती है. यह ज़हर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के ज़रिये से अन्न में आता है. हमारी बीमारी के साठ प्रतिशत कारण हमारे खाने में छिपे हुए हैं. अगर हमारा खाना अगर शुद्ध हो जाए. इन कीटनाशकों और ख़तरनाक खाद से मुक्त हो जाए, तो हम अपने स्वास्थ्य का, देश के स्वास्थ्य का साठ प्रतिशत ध्यान ख़ुद रख लेंगे, तो डॉक्टरों को फीस देने से बच जाएंगे. इसमें न्यूट्रिशंस भी हैं. मोरारका फाउंडेशन द्वारा किया जाने वाला यह अद्भुत काम एक आंदोलन के रूप में सारे देश में फैल रहा है. इस आंदोलन को चलाने के लिए ऐसे लोग चाहिए, जो अपना काम करते हुए जैविक उत्पादों के इस्तेमाल के लिए अपने पड़ोसी को प्रेरित कर सकें.

**सेना की यह पहल सेना से रिटायर होने वाले जवानों को सम्मानजनक जीवन देगी और शान से सिर उठाकर जीने का हौसला देगी, क्योंकि जवान जब अपने खेत में जैविक खेती करेगा तो बाज़ार भाव से दस प्रतिशत अधिक क़ीमत पर उसकी फ़सल बिकेगी और उसे बेचने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी.**

सेना की यह पहल सेना से रिटायर होने वाले जवानों को सम्मानजनक जीवन देगी और शान से सिर उठाकर जीने का हौसला देगी, क्योंकि जवान जब अपने खेत में जैविक खेती करेगा तो बाज़ार भाव से दस प्रतिशत अधिक क़ीमत पर उसकी फ़सल बिकेगी और उसे बेचने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी. वह ख़ुद भी स्वस्थ रहेगा और उसके परिवार के सदस्य भी स्वस्थ रहेंगे. अब तक गांव में जिस तरह कीटनाशक और खादों के ज़रिये खेती ज़हरीली होती चली जा रही थी, उसे रोकने का काम यह रिटायर हुआ सिपाही उसी जज़्बे के साथ करेगा, जिस जज़्बे के साथ वह दुश्मन को रोकता है. दरअसल, यह ज़हरीला खाना, यह मिलावटी खाना इतना ख़तरनाक है कि हम पेट से संबंधित, आंत से संबंधित, हाथ-पैर से संबंधित जितनी भी बीमारियां देखते हैं, वे सारी इन खानों की वजह से ही होती हैं. कैंसर का मुख्य कारण आज का खाना है. आज से पचास साल पहले हमारे यहां इतने क़िस्म के कैंसर नहीं थे, जितने आज हैं. इसकी जड़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ आज का खाद्यान्न है. इसलिए मैं इन जवानों को बधाई देता हूं और इन जवानों से पहले मैं सेना को बधाई देता हूं और इससे पहले मैं इन नौजवानों को बधाई देता हूं. सेना ने इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने के बारे में सोचा है. जवान अगर इसमें शामिल होंगे और उनके घरवाले उनके रिटायर होने से पहले ही इस प्रक्रिया को अपना लें तो उनके घरवालों को भी मोरारका फाउंडेशन वही सुविधा देना चाहता है, जो सेना से रिटायर होने वाले जवान को मिलने वाली है. इसलिए ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती को लेकर किसी संगठन ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सेना से हाथ मिलाया है. उसे यह आश्वासन दिया है कि वह सेना के सिपाही के रिहब्लिटेशन में अपना सौ प्रतिशत योगदान देंगे. सेना जितने लोगों को कहेगी, फाउंडेशन उतने लोगों को ट्रेनिंग देगा. इन लोगों द्वारा ऑर्गेनिक पद्धति से पैदा किए खाद्यान्नों को कसौटी पर कसेंगे और हर उत्पाद को ख़रीदेंगे. मोरारका फाउंडेशन ने दूसरा अद्भुत काम यह किया है कि सेना को उसने आश्वासन दिया है कि जिन सिपाहियों के पास ज़मीन नहीं है, उन्हें भी वह जैविक खेती की तकनीक बताएगा. इस अद्भुत तकनीक का नाम है ट्रे कल्टीवेशन. मोरारका फाउंडेशन ने ट्रे के भीतर कुछ ऐसी तकनीक अपनाई है कि उस ट्रे से सब्ज़ियां और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जा सकते हैं. अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है, लेकिन घर है, उसके घर में कोई बाल्कॉनी या छत है जो अक्सर गांव में होती है, तो वहां पर वह ट्रे में सब्ज़ियां और फल पैदा कर सकता है. वह उसे बाज़ार भेज सकता है. उसका भी माल उस दिन के बाज़ार भाव से दस प्रतिशत ज़्यादा क़ीमत देकर मोरारका फाउंडेशन द्वारा ख़रीद लिया जाएगा. यह भारतीय सेना के लिए एक ऐसा अद्भुत अवसर है, जिसका लाभ उठाकर सेना अपने जवान को नौकरी के बाद भी शान से ज़िंदगी बिताने का मौक़ा दे सकती है. मुझे लगता है, सेना अपने जवानों के हित में ज़रूर इसी तरह के क़दम उठाएगी, ताकि उनके जवान रिटायर होने के बाद समाज में अनुशासन क़ायम कर सेना की इज़्ज़त को क़ायम रखें. सेना के इक़बाल को, सेना के शौर्य को और सेना की गरिमा को क़ायम रखें, ताकि लोगों को लगे कि सेना में जाना बहुत ज़रूरी है. अगर सेना में जाएंगे तो अवश्य हमारे संपूर्ण भविष्य के लिए और हमारे परिवार के अच्छे भविष्य के लिए नए रास्ते खुलेंगे. सेना के उस अच्छे काम के लिए आख़िर में एक बार फिर बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि सेना से रिटायर हुए जवान इस सहमति पत्र के आधार पर सेना और मोरारका फाउंडेशन द्वारा उठाए गए क़दमों का फ़ायदा उठाएंगे और सम्मान के साथ अपने गांव में रहकर जीवन यापन करेंगे तथा समाज में एक नए नेतृत्व का विकास करेंगे, जो नेतृत्व अनुशसित भी होगा और कल्पनाशील भी.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

# मुस्लिम सियासत और पीस पार्टी

शफ़ीक़ आलम

एक महीने से अधिक समय तक चले उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया 6 मार्च को मतगणना और परिणामों की घोषणा के साथ समाप्त हो गई. इसके साथ ही समाप्त हो गया वह लंबा इंतज़ार जिसको लेकर हर कोई भविष्यवाणी करने में लगा हुआ था. बहरहाल, इन पांचों प्रदेशों में जिस प्रदेश के चुनाव को जनता और मीडिया ने सबसे अधिक महत्व दिया और जिसके चुनावी परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार किया गया, वह है उत्तर प्रदेश. क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहां से संसद में 80 नेता चुनकर आते हैं, जो केंद्र सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में दख़ल रखने वाली हर छोटी-बड़ी राजनीतिक पार्टी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताक़त झोंक दी थी. इस चुनाव में मायावती सरकार की असफलता और भ्रष्टाचार के बाद अगर कोई दूसरा मुद्दा था, जिसे राजनीतिक पार्टियों और मीडिया ने ख़ूब उछाला, तो वह था मुसलमानों का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन. आज़ाद भारत की राजनीति में शायद ही कोई चुनावी प्रक्रिया होगी, जिसमें मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को इतने ज़ोर शोर से उठाया गया हो. ऐसा क्यों हुआ? इसके अनेक कारण हैं, लेकिन हम अपनी बात पीस पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने तक ही सीमित रखेंगे.

पीस पार्टी ऑफ़ इंडिया का गठन फ़रवरी 2007 में गोरखपुर के प्रख्यात लीवर सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अयूब के नेतृत्व में हुआ था. पार्टी के राजनीति में उतरने की घोषणा कुछ इस तरह से की गई कि प्रदेश की राजनीति पर गहरी नज़र रखने वाला कोई भी विश्लेषक इसे नज़र अंदाज नहीं कर सकता था. 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कुल 21 प्रत्याशी मैदान में उतारे. हालांकि उनमें से कोई भी चुनाव जीतने में सफल नहीं रहा, लेकिन पीस पार्टी कुल वोट का 4.5 फ़ीसदी हिस्सा पाने में कामयाब हुई थी. वहीं दोमरियागंज के विधानसभा उपचुनाव में पीस पार्टी के प्रत्याशी सच्चिदानंद ने तीसरा स्थान हासिल किया था. इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की ज़मानत तक ज़ब्त हो गई थी. लखीमपुर खीरी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी शशिधर मिश्र दूसरे स्थान पर रहे थे. पीस पार्टी ने बहुत ही कम समय में यह जता दिया था कि मुसलमानों के वोटों पर भरोसा करने वाला कोई भी राजनीतिक दल उसे नज़र अंदाज़ नहीं कर सकता. इस तरह एक ख़ास सामाजिक फार्मूले के साथ पीस पार्टी 2012 के विधानसभा चुनाव में उतरी थी. यह वही सामाजिक फार्मूला था, जिसको प्रदेश की हर सियासी पार्टी अपनाती रही है. इसलिए पीस पार्टी के आने से सभी सेकुलर पार्टियों, ख़ासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में हलचल पैदा हो गई और पीस पार्टी को खेल ख़राब करने वाली और वोट कटुआ पार्टी तक कहा जाने लगा.

पीस पार्टी की नींव भी बहुजन पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरह ही मुस्लिम आरक्षण पर टिकी है. पार्टी का मानना है कि अब तक देश में आरक्षण की जो नीति अपनाई गई है, उसका फ़ायदा पहले से मज़बूत जातियां ही उठा रही हैं. जैसे ओबीसी आरक्षण का फ़ायदा अधिकतर यादव बिरादरी को ही मिलता रहा है, वहीं एससी आरक्षण का सारा लाभ जाटव बिरादरी के लोग उठा रहे हैं. पीस पार्टी ओबीसी की तरह दलित बिरादरी के लिए भी आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग कर रही है. साथ में महा दलित मुसलमानों को भी एससी श्रेणी में शामिल करने की मांग करती रही है. जहां तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात है, तो पीस पार्टी का हिसाब बिलकुल सीधा था. मुस्लिम, महा दलित और अति पिछड़ा वर्ग में राज्य के 54 फ़ीसदी मतदाता आते हैं, जिनके आधार पर पार्टी यह अंदाज़ा लगा रही थी कि उसे 50-60 फ़ीसदी मुस्लिम, 25-30 फ़ीसदी अति पिछड़ा वर्ग और महा दलित वोट मिल जाएंगे. अगर ऐसा हुआ तो पार्टी प्रदेश की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाने में कामयाब हो जाएगी. लेकिन अपने तमाम दावों के बावजूद पीस पार्टी मुस्लिम वोटों पर ही भरोसा किए हुए थी, जिसका पहला कारण यह है कि प्रदेश के कुल मतदाताओं में मुस्लिम मतदाताओं की भागीदारी 18 प्रतिशत है और यहां की 403 विधानसभा सीटों में से 130 क्षेत्र ऐसे हैं, जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी आंकड़ों को प्रभावित होने का दम-ख़म रखते हैं. इसलिए कांग्रेस के साथ बसपा और सपा को भी यह डर बराबर सताए जा रहा था कि कहीं पीस पार्टी उनका खेल न ख़राब कर दे. मुस्लिम वोटों की महत्ता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ा है, क्योंकि इस बार प्रदेश के 70 फ़ीसदी मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद सपा रही.

बहरहाल, पीस पार्टी ने इस चुनाव में कुल 204 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे और पार्टी का अंदाज़ा था कि वे 18 से 20 सीटें हासिल कर लेगी और त्रिशंकु विधानसभा की सूरत में सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगी. उसकी यह बेचैनी उस समय ज़ाहिर हो गई, जब वोटों की गिनती के दौरान ही पार्टी के एक लीडर ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी. यही नहीं, चुनाव जीतने के लिए पीस पार्टी ने समाज के हर वर्ग को भागीदारी दी. इसमें दूसरी पार्टियों के बाग़ी उम्मीदवारों के साथ अपराधी पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी भी शामिल थे, लेकिन उसकी यह सोशल इंजीनियरिंग कामयाब न हो सकी और उसे महज़ 4 सीटों पर ही सब्र करना पड़ा. पीस पार्टी से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी, लेकिन इस क्षेत्र से पार्टी के केवल 3 प्रत्याशी ही कामयाब हो सके और चौथा उम्मीदवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीत हासिल करने में कामयाब रहा. ज़ाहिर है, इसे कोई बड़ी राजनीतिक उपलब्धि नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसने कम से कम उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी तो दर्ज करा ही दी है. अब आगे मुस्लिम वोटों पर नज़र रखने वाली कोई भी पार्टी उसे नज़र अंदाज़ नहीं कर सकती है. चुनाव से पहले पीस पार्टी की रणनीति को बिहार में नितीश कुमार और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की शरुआती दिनों की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा था. जिस प्रकार से नितीश कुमार ने पसमांदा मुस्लिम कार्ड खेलकर लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम-यादव अर्थात एमवाई समीकरण को तोड़ने का सफल परीक्षण किया था, उसी तरह पीस पार्टी ने भी ओबीसी और एससी हिंदुओं में से ग़ैर यादव और ग़ैर जाटव समाज को टार्गेट करने की कोशिश की, लेकिन इसमें उसे कामयाबी नहीं मिली. इसकी एक वजह यह थी कि जदयू की बुनियाद बिहार में ज़मीनी सतह पर मज़बूत थी. उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी. लेकिन पीस पार्टी का बुनियादी ढांचा मज़बूत नहीं है. इसलिए वह अपने इस फार्मूला को पूरी तरह लागू करने में कामयाब नहीं हो पाई. उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का आगमन भी कुछ इसी अंदाज़ से हुआ था. 1989 में पहली बार प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाग लेते हुए पार्टी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी और वह मुस्लिम-दलित (और बाद में ब्राह्मण) गठबंधन के साथ 1989 से आज तक उत्तर प्रदेश की सियासत में एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ-साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई. बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद कांग्रेस और बीजेपी से उत्तर प्रदेश का मुसलमान दूर होता चला गया, अब उसके पास दो ही विकल्प बचे थे, बसपा और सपा. अब अगर पीस पार्टी को मुसलमानों का वोट चाहिए तो उसे प्रदेश में नई रणनीति बनानी होगी, पार्टी का बुनियादी ढांचा मज़बूत करना होगा, ऐसे लोगों को पार्टी से दूर रखना होगा जिनका अतीत दाग़दार है, नहीं तो अगले चुनाव में कोई भी पीस पार्टी को गंभीरता से नहीं लेगा और पार्टी का मिशन 2017 महज़ एक मिशन ही रह जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

स्कॉटलैंड में एक 19 वर्षीय युवक ने कुछ दिनों पहले लॉटरी का टिकट ख़रीदा था. वह उसे अपने बेडरूम में कहीं रखकर भूल गया.



सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

# सौ समस्याओं का एक समाधान : आरटीआई आवेदन

रिश्वत देना जहां एक ओर आम आदमी की मजबूरी बन गया है, वहीं कुछ लोगों के लिए यह अपना काम जल्दी और ग़लत तरीक़े से निकलवाने का ज़रिया भी बन गया है, लेकिन इन दोनों स्थितियों में एक फ़र्क़ है. एक ओर 2–जी स्पेक्ट्रम के लिए रिश्वत दी जाती है, तो दूसरी ओर एक आम और बेबस आदमी को राशन कार्ड बनवाने, सरकारी पेंशन, दवा एवं इंदिरा आवास पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है. वैसे रिश्वत किसी भी काम के लिए या किसी भी रूप में देना न सिर्फ़ ग़ैर क़ानूनी है, बल्कि अनैतिक भी है. बावजूद इसके व्यवस्था में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इस बीमारी से निजात पाना मुश्किल नज़र आता है. आप चाहे शहर में रहते हों या गांव में, सरकारी बाबुओं द्वारा फाइल दबाने और फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग से आप सभी का सामना ज़रूर हुआ होगा. गांवों में वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुज़ुर्गों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है. शहरों में भी लोगों को आयु, जन्म–मृत्यु एवं आवास प्रमाणपत्र बनवाने या इंकम टैक्स रिफंड लेने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं, साथ ही रिश्वत भी देनी पड़ती है. अब सवाल यह है कि जो आदमी रिश्वत देने की स्थिति में नहीं है तो क्या उसका काम नहीं होगा? ऐसा नहीं है, काम ज़रूर होगा, वह भी बिना रिश्वत दिए. ज़रूरत है, सिर्फ़ अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की और वह अधिकार है, सूचना का अधिकार. यह अधिकार एक क़ानून है. महज़ एक आवेदन देकर आप रिश्वतख़ोर अधिकारियों की नींद हराम कर सकते हैं. जैसे ही आप अपने रुके हुए काम से संबंधित एक आरटीआई आवेदन डालते हैं, भ्रष्ट एवं रिश्वतख़ोर अधिकारियों और बाबुओं की समझ में आ जाता है कि वे जिसे परेशान कर रहे हैं, वह आम आदमी तो है, लेकिन अपने अधिकारों और नियमों के प्रति जागरूक है. सरकारी विभागों में भी आम तौर पर उन्हीं लोगों को ज़्यादा परेशान किया जाता है, जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती. सूचना अधिकार क़ानून में इतनी ताक़त है कि छोटे–मोटे काम तो आवेदन देने के साथ ही हो जाते हैं. इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, बजाय घूस देकर काम कराने के. चौथी दुनिया आपके हर क़दम पर आपका साथ देने को तैयार है. कोई समस्या हो, कोई सुझाव चाहिए या आप अपने अनुभव हमसे बांटना चाहें तो हमें पत्र लिखें या ई–मेल करें. हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

**चौथी दुनिया**

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

## आवेदन का प्रारूप

किसी सरकारी विभाग में रुके हुए कार्य के विषय में सूचना के लिए आवेदन (राशन कार्ड, पासपोर्ट, वृद्धवस्था पेंशन, आयु–जन्म–मृत्यु–आवास आदि प्रमाणपत्र बनवाने या इन्कम टैक्स रिफंड मिलने में देरी होने, रिश्वत मांगने या बिना वजह परेशान करने की स्थिति में निम्न प्रश्नों के आधार पर सूचना के अधिकार का आवेदन तैयार करें)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

मैंने आपके विभाग में ............ तारीख़ को ..............के लिए आवेदन किया था (आवेदन की प्रति संलग्न है), लेकिन अब तक मेरे आवेदन पर संतोषजनक क़दम नहीं उठाया गया है. कृपया इस संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:–

1. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्रवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. मेरा आवेदन किन–किन अधिकारियों के पास गया एवं किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा और इस दौरान उसने उस पर क्या कार्रवाई की? पूरा विवरण उपलब्ध कराएं.

2. विभाग के नियम के अनुसार मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए थी? क्या मेरे मामले में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया?

3. कृपया उन अधिकारियों के नाम एवं पद बताएं, जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.

4. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी और यह कब तक की जाएगी?

5. अब मेरा काम कब तक पूरा होगा?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.......रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर..........है.
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.
भवदीय
नाम...................
पता..................
फोन नंबर.............
संलग्नक..........
(यदि कुछ हो तो)

# राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

**मेष** (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह आप कोई वैचारिक मतभेद न होने दें. अगर अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो स्थानांतरण के लिए तैयार हो जाएं. आर्थिक दृष्टि से शुभ समय रहेगा. व्यापारी ख़ुश रहेंगे. प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अध्ययनरत विद्यार्थी अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे और प्रदर्शन अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहेगा.

**वृष** (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह आप हर एक दृष्टिकोण से चुस्त महसूस करेंगे और ऊर्जावान रहेंगे. सहकर्मी और अधिकारी आपसे ख़ुश रहेंगे. व्यापारी थोड़े आर्थिक तौर पर सशक्त रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन अच्छा होगा. विद्यार्थी थोड़े विचलित रहेंगे. स्वास्थ्य मिलाजुला रहेगा. कोई साज–सज्जा और विलासिता से संबंधित वस्तु पर व्यय की संभावना है.

**मिथुन** (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह कोई क़ानूनी दस्तावेज़ को जांच परख कर हस्ताक्षर करें, अन्यथा उलझन बढ़ेगी. आमतौर पर कोई जीवन का बड़ा निर्णय लेने वाला सप्ताह होगा. व्यापारी ख़ुश रहेंगे. नौकरी पेशा वाले लोगों को प्रोन्नति की ख़बर मिलेगी. किसी शेयर और जुआ वाले बाज़ार से बचने की ज़रूरत. विद्यार्थी अच्छा करेंगे और कोई सफलता का समाचार प्राप्त होगा.

**कर्क** (21 जून से 20 जुलाई)
कोई नया व्यवसाय या नई नौकरी से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा. कोई पुराना तनाव भी इस सप्ताह ख़त्म हो जाएगा. आर्थिक दृष्टिकोण से इस सप्ताह थोड़ा उतार–चढ़ाव महसूस करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह थोड़ा तनाव रहेगा. तनाव की वजह से आपसी मतभेद न बढ़ने दें. लोगों की बातों को सुनने से ज़्यादा, स्वयं पर ध्यान दें.

**सिंह** (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह पारिवारिक विरोधी भी आपके साथ चलेंगे. पारिवारिक सामंजस्य से होने वाले किसी कार्य को इस सप्ताह निर्णय लेकर समाप्त करें. आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सख्त महसूस करेंगे. नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल पर अपने गुस्से को ज़ाहिर न होने दें. आमतौर पर सामाजिक रूप से पहचान बढ़ेगी. विद्यार्थी अपनी एकाग्रता बढ़ाएंगे.

**कन्या** (21 अगस्त से 20 सितंबर)
कोई बहुत दिनों से इंतज़ार वाला मांगलिक कार्य इस सप्ताह हो सकता है. अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा. व्यापारी आमतौर पर ख़ुशहाल रहेंगे. नौकरीपेशा लोग स्थानांतरण के साथ अच्छी ख़बर पा सकते हैं. आर्थिक रूप से इस सप्ताह सुदृढ़ होंगे. स्वास्थ्य में अस्थि विकार से बचें और चिकित्सक से सलाह लें.

**तुला** (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह आप भाग्यशाली साबित होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से की जा रही मेहनत अब रंग लाएगी. आर्थिक रूप से यह सप्ताह थोड़ा–उतार चढ़ाव वाला साबित होगा. केवल ज़मीन और भवन से संबंधित कार्यों में पैसा निवेश कर सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आप अपनी वाणी पर संयम रखें.

**वृश्चिक** (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह आपको अचानक धन लाभ की ख़बर प्राप्त हो सकती है. आमतौर पर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है. व्यापारी थोड़ा उतार–चढ़ाव महसूस करेंगे. नौकरी पेशा लोग थोड़े वित्तीय रूप से मज़बूत महसूस करेंगे. अपने खाने–पीने पर थोड़ा नियंत्रण रखें उदर विकार होने पर चिकित्सक से परामर्श लें.

**धनु** (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह थोड़े रोमांटिक रहेंगे और भावनात्मक रुप से कमज़ोर महसूस करेंगे. व्यापारी और नौकरीपेशा लोग आर्थिक रूप से संपन्न होंगे. ऐसे व्यापारी जो साझेदारी में कार्य कर रहे हैं, थोड़ी सतर्कता रखें, पारिवारिक दृष्टिकोण से आमतौर पर तनाव का माहौल रहेगा.

**मकर** (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह अपना ग़ुस्सा, शत्रु और विरोधी को दबाकर रखें या साधारणतः नज़र अंदाज़ करके चलें. वाहन सावधानी से चलाएं. दांपत्य जीवन में किसी तनाव को बढ़ावा न दें. आप नई–नई योजनाएं बनाएंगे और इसका क्रियान्वयन करने के लिए प्रयासरत रहेंगे. स्वयं को नियमित रखें और समय के महत्व को समझें. आर्थिक रूप से मज़बूत होंगे.

**कुंभ** (21 जनवरी से 20 फरवरी)
आप इस सप्ताह जोश में होश न खोएं. अपने मानसिक संतुलन को बनाकर चलें. आपकी विद्वता सामाजिक पहचान बनेगी. किसी बड़े सामाजिक कार्य में शामिल हो सकते हैं. किसी राजनीतिक व्यक्ति या प्रशासनिक अधिकारी के संपर्क में आएंगे. इस सप्ताह कोई वाहन ख़रीदने या बड़े ख़र्चे की योजना न बनाएं. आर्थिक रूप से मज़बूत रहेंगे.

**मीन** (21 फरवरी से 20 मार्च)
विलासिता से संबंधित किसी वस्तु पर व्यय हो सकता है. किसी संपत्ति का क्रय– विक्रय हो सकता है. किसी क़ानूनी उलझन में आपको समाधान मिलेगा. आर्थिक रूप से थोड़ा उतार–चढ़ाव वाला सप्ताह रहेगा. विद्यार्थी अध्ययनरत रहेंगे. प्रेम प्रसंग में अच्छा समाचार प्राप्त होगा. जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें. अपने स्वास्थ्य का आमतौर पर ख्याल रखें.

feedback@chauthiduniya.com

## ज़रा हट के

### कूड़े में ख़ज़ाना

आज के समय में व्यस्त होने के कारण लोग अपने बेडरूम की सफ़ाई नहीं करते, उसे नौकरों के भरोसे छोड़ देते हैं. स्कॉटलैंड में एक 19 वर्षीय युवक ने कुछ दिनों पहले लॉटरी का टिकट ख़रीदा था. वह उसे अपने बेडरूम में कहीं रखकर भूल गया. जब उसका बेडरूम काफ़ी गंदा हो गया तो मां ने उस पर दबाव डाला कि वह अपना बेडरूम साफ़ करे. काफ़ी टालने के बाद एक दिन उसने अपने अस्त–व्यस्त कमरे की सफ़ाई करनी शुरू की. सफ़ाई के दौरान उसे वही लॉटरी का टिकट मिल गया. पहले तो उसने टिकट को फ़ालतू का काग़ज़ समझ कर कूड़ेदान में फेंक दिया. तभी उसे ख्याल आया कि एक बार लॉटरी के विजेता के बारे में पता करने में कोई हर्ज नहीं है. यह सोचकर उसने टिकट को कूड़ेदान से निकाल कर लॉटरी के विजेता का पता लगाया तो यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसी ने लॉटरी का पहला पुरस्कार जीता है और उसे ईनाम स्वरूप 50 हज़ार रुपये की धनराशि मिली है.

### पेट में क़लम

रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ न कुछ नया होता दिखाई या सुनाई पड़ जाता है. दुनिया अजीबोग़रीब ख़बरों से भरी पड़ी है. ऐसी ही एक घटना लंदन में हुई, जहां एक 76 वर्षीय महिला के पेट से 25 सालों बाद पेन निकाला गया. कुछ दिनों पहले इस महिला के पेट में तेज़ दर्द उठा था. असहनीय दशा में यह महिला डॉक्टर के पास पहुंची. परीक्षण के दौरान जब महिला के पेट का सीटी स्कैन कराया गया तो मामला पकड़ में आया. डॉक्टर ने उस महिला को बताया कि उसके पेट में एक पेन पड़ा है, जिसके चलते उसे दर्द हो रहा है. तभी अचानक उस महिला को याद आया कि 25 साल पहले उसने ग़लती से एक पेन निगल लिया था. बहरहाल, डॉक्टरों ने ऑपरेशन द्वारा उस पेन को महिला के पेट से बाहर निकाल दिया. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पेट से निकली वह क़लम आज भी चालू हालत में है. जब डॉक्टरों ने उससे लिखकर दिखाया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए.

### यहां पैसा बंटता है

जर्मनी के एक शहर में लगातार घट रही एक घटना आजकल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. मसला यह है कि बर्लिन शहर के किसी न किसी घर में रोज़ ड्यूश मार्क (जर्मन मुद्रा) से भरा एक लिफ़ाफ़ा पाया जा रहा है. जिन्हें भी यह मिलता है, उन्हें ख़ुशी के अलावा हैरानी भी हो रही है. इस संबंध में लोगों के बीच कई कहानियां चल रही हैं. मसलन कुछ लोगों का मानना है कि किसी ने ग़लत तरीक़े से धन कमाया है और वह अपनी काली कमाई लोगों में बांटकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है. अभी तक पैसे बांटने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पुतिन चाहे जो कहें और उन्हें कहना भी चाहिए, लेकिन सच यही है कि राष्ट्रपति चाहे मेदवेदव रहे हों, लेकिन वास्तविक सत्ता पुतिन के हाथों में थी.

## रूस

# पुतिन की वापसी

राजीव कुमार

रूस की जनता ने ब्लादिमीर पुतिन को अपना राष्ट्रपति चुना है. विगत चार मार्च को रूस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें पुतिन को लगभग 64 फ़ीसदी मत मिले. उनके विरोधियों में से किसी ने बीस प्रतिशत मत नहीं पाए. कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार गेन्नादी ज्युगानोव को लगभग 18 फ़ीसदी मत मिले, जबकि अन्य उम्मीदवार दहाई के अंक तक नहीं पहुंच सके. रूस के एक बड़े उद्योगपति मिखाइल प्रोखोरोव को लगभग 7.9 फ़ीसदी मत मिले. लिबरल-डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता व्लादीमिर झिरिनोव्सकी को क़रीब 6.24 फ़ीसदी और न्यायशील रूस पार्टी के सर्गेई मिरोनोव को 3.8 फ़ीसदी मत मिले. चुनाव परिणाम पुतिन के पक्ष में रहे और उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का मौक़ा मिला. हालांकि उनके विरोधियों ने उन पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं, लेकिन इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता. उनके कुछ विरोधियों ने कहा है कि मतदाताओं को बसों में भरकर लाया गया. एक मतदाता ने कई-कई बार मतदान किया. वहीं इस चुनाव पर नज़र रखने के लिए आए विदेशी पर्यवेक्षकों ने चुनाव को निष्पक्ष बताया. ग़ौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव पर नज़र रखने के लिए विभिन्न संगठनों के लगभग 670 प्रतिनिधि रूस आए थे, जिनमें यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग संगठन के 219, स्वाधीन राज्य मंडल के 231, स्वाधीन राज्य मंडल की अंतरसंसदीय असेंबली के 44, यूरोपीय काउंसिल के 37 प्रतिनिधि एवं शंघाई सहयोग संगठन के 12 प्रतिनिधि शामिल थे. स्वाधीन राज्य मंडल की अंतरसंसदीय असेंबली के पर्यवेक्षकों ने कहा है कि चुनाव में कोई गंभीर उल्लंघन नहीं दिखाई पड़ा. इस पर्यवेक्षक दल के समन्वयक वादिम पोपोव ने कहा कि 11 क्षेत्रों के 350 मतदान केंद्रों का पर्यवेक्षक दल ने दौरा किया, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों के अलावा किसी तरह की बड़ी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है. ऐसी तकनीकी गड़बड़ियों से मतदाताओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता. सर्बिया के पर्यवेक्षक ने कहा कि सभी देशों को रूस के इस चुनाव से प्रेरणा लेनी चाहिए. इटली के प्रतिनिधि ने इस चुनाव को कमाल का लोकतांत्रिक चुनाव बताया. हंगरी के प्रतिनिधि ने यूरोपीय संसद को सलाह देते हुए कहा कि वह अपने संसदीय चुनाव में उन तकनीकों एवं उपायों का उपयोग करे, जैसा कि रूस के राष्ट्रपति चुनाव में अपनाया गया है. फिनलैंड के मानवाधिकार कार्यकर्ता आयोन हेल्विग का कहना था कि रूस को बदनाम करने का अभियान असफल हो गया है. योहन बेर्कमन ने पश्चिमी मीडिया को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह पश्चिमी मीडिया ने रूस के चुनाव में गड़बड़ी की ख़बरें चलाईं, पर्यवेक्षकों ने स्थिति उससे बिल्कुल उल्टी पाई.

ग़ौरतलब है कि रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में काफी सावधानी बरती गई थी. मतदान के लिए बनाए गए 95,000 मतदान केंद्रों पर वेब कैमरे लगाए गए थे. कैमरों को मतपेटियों पर केंद्रित किया गया था, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो. हालांकि इतना होने के बावजूद मतदान में गड़बड़ी के आरोप विपक्षियों ने लगाए हैं, लेकिन विदेशी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद ऐसे आरोपों का कोई वजन नहीं रह जाता. बीते दिसंबर माह में हुए संसदीय चुनाव में पुतिन पर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे. पश्चिमी मीडिया ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया था. अमेरिका ने भी संसदीय चुनाव में गड़बड़ी के आरोप को ख़ूब उछाला था. रूस में भी पुतिन के विरोध में प्रदर्शन हुए थे और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की गई थी, लेकिन इस चुनाव परिणाम और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट से यही लगता है कि संसदीय चुनाव में धांधली के आरोप निराधार थे. परिणामों पर नज़र डालें तो भी यही लगता है. पुतिन के नेतृत्व वाली यूनाइटेड रसिया पार्टी को संसदीय चुनाव में 50.2 फ़ीसदी मत मिले थे, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को 19.12 फ़ीसदी और जस्ट रसिया पार्टी को 13.3 फ़ीसदी मत मिले थे. राष्ट्रपति के चुनाव में भी कम्युनिस्ट नेता को 18 फ़ीसदी मत मिले. इससे तो यही लगता है कि चुनाव में उस समय भी कोई ऐसी धांधली नहीं हुई थी, जिसे मुद्दा बनाया जा सके. यह पुतिन की लोकप्रियता कम करने और उन्हें बदनाम करने की साजिश थी. पश्चिमी देशों ने पुतिन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाना शुरू किया और मीडिया ने भी उन्हीं का साथ दिया. विरोधियों ने अपने समर्थकों से पुतिन विरोधी प्रदर्शन कराए और यह दिखाने की कोशिश की कि पुतिन लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिनों पहले भी पुतिन विरोधी प्रदर्शन किए गए थे और 34 किलोमीटर लंबी मानव शृंखला बनाई गई थी, लेकिन अब लगता है कि रूस में पुतिन विरोधी प्रदर्शन का आधार समस्या नहीं थी, बल्कि विपक्षी दलों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए उक्त प्रदर्शन कराए थे. चुनाव से कुछ दिनों पहले पुतिन को मारने की साजिश का पर्दाफाश किया गया था. सच्चाई क्या है, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन रूस के ख़ुफ़िया विभाग ने तो यही जानकारी दी कि पुतिन को मारने की साजिश की जा रही थी. जिन लोगों को पकड़ा गया, उनके पास पुतिन के काफिले का एक वीडियो भी मिला.

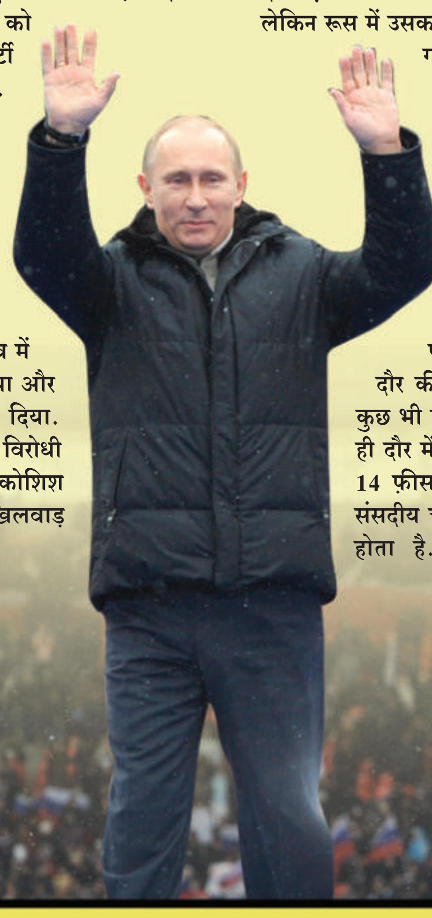

पुतिन को 64 फ़ीसदी मत मिले हैं, जबकि संसदीय चुनाव में उनके दल को 50.2 फ़ीसदी मत मिले थे. संसदीय चुनाव के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतना पुतिन के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन विरोध प्रदर्शनों को यूरोपीय देशों और अमेरिका का सहयोग मिलना पुतिन के लिए फ़ायदेमंद हो गया. पुतिन की छवि एक मज़बूत नेता की रही है. उन्होंने कई मौक़ों पर अमेरिका का विरोध किया है. अभी सीरिया के मुद्दे पर रूस ने वीटो किया था और अमेरिका के मंसूबे पर पानी फेर दिया था. ईरान के मामले में भी रूस अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है. पुतिन बहुध्रुवीय विश्व की बात करते हैं और अमेरिका की सुपरमेसी का विरोध करते हैं. बीते चार महीनों के दौरान अमेरिका, उसके सहयोगी देशों एवं मीडिया ने पुतिन को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन रूस में उसका उल्टा असर हुआ. पुतिन का समर्थन बढ़ गया और लोगों को लगा कि पुतिन ही सही मायनों में रूस को नई दिशा दे सकते हैं. अगर अन्य देश पुतिन का विरोध न करते और प्रतिद्वंद्वी अन्य मुद्दों को उनके विरोध का आधार बनाते, तो हो सकता है कि दूसरे दौर की मतगणना करने की नौबत आ जाती. संसदीय चुनाव में पचास फ़ीसदी का आंकड़ा किसी तरह पार किया गया था. अगर इस चुनाव में पचास फ़ीसदी से कम वोट मिलते तो दूसरे दौर की मतगणना मजबूरी बन जाती और फिर कुछ भी हो सकता था, लेकिन पुतिन को तो पहले ही दौर में 64 फ़ीसदी मत मिल गए. चार महीने में 14 फ़ीसदी मत उन्हें ज़्यादा मिल गए. हालांकि संसदीय चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव में थोड़ा अंतर होता है. दोनों के मुद्दे अलग होते हैं और मतदाताओं की अपेक्षाएं भी भिन्न होती हैं.

बहरहाल, पुतिन अगले 6 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बन गए हैं. अब देखना यह है कि आगे उनकी नीति क्या होती है. वैसे जब आगे की रणनीति के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वह रूस में लोकतंत्र को मज़बूत करेंगे, आर्थिक सुधारों द्वारा रूस को आर्थिक ताक़त बनाएंगे और रोज़गार सृजन के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि युवाओं को काम मिल सके. उनकी विदेश नीति वर्तमान विदेश नीति से भिन्न नहीं होगी, क्योंकि भले ही रूस के राष्ट्रपति दीमीत्री मेदवेदेव थे, लेकिन नीति निर्धारण में पुतिन की अहम भूमिका रही. जब यह कहा गया कि पिछले 12 सालों से आप सत्ता में हैं तो उनका कहना था कि पिछले चार सालों से वह प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति नहीं. उन्होंने कहा कि संविधान ने प्रधानमंत्री को जो अधिकार दिए हैं, वह उन्हीं के दायरे में रहकर काम कर रहे थे और मेदवेदेव के कामों में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहा.

पुतिन चाहे जो कहें और उन्हें कहना भी चाहिए, लेकिन सच यही है कि राष्ट्रपति चाहे मेदवेदव रहे हों, लेकिन वास्तविक सत्ता पुतिन के हाथों में थी. पुतिन संवैधानिक अवरोध के कारण तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, इसलिए मेदवेदव को राष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन बाद में जब रूस के संविधान में संशोधन किया गया तो साफ हो गया कि ऐसा पुतिन को राष्ट्रपति बनाने के लिए किया गया है. पुतिन के राष्ट्रपति बनते ही पश्चिमी देशों को यह आशंका होने लगी है कि कहीं रूस की विदेश नीति में कोई परिवर्तन न हो. इसीलिए ऐसे बयान आ रहे हैं कि विदेश नीति नहीं बदलेगी. भारत को भी पुतिन का स्वागत करना चाहिए और रूस को अपना अच्छा मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए. वैसे तो रूस भारत का परंपरागत मित्र रहा है, लेकिन जब भारत अमेरिका की ओर ज़्यादा झुकाव दिखाने लगा तो रूस भी अपनी रणनीति बदलने लगा और पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करने लगा. संकेत साफ है कि भारत अगर रूस को तवज्जो देना कम करता है तो वह पाकिस्तान के नज़दीक जा सकता है. अभी चीन भारतीय सीमा पर जिस तरह की हरकतें कर रहा है, वैसे में भारत का रूस के साथ मज़बूत संबंध बनाना बेहद ज़रूरी हो गया है. पुतिन ने भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए समर्थन दिया है, जबकि अमेरिका इस मुद्दे पर परोक्ष रूप से भारत का विरोध कर रहा है. भारत के लिए यह अच्छा मौक़ा है कि वह पुतिन की वापसी पर रूस को फिर से अपना वैसा मित्र बनाए, जैसा सोवियत संघ के समय था.

rajiv@chauthiduniya.com

# साईं तेरी महिमा अनंत

## साईं तेरी महिमा अनंत

हे साईं तू मन में है
हे साईं तू तन में है
हे साईं तू आत्मा में है
हे साईं तू रोम-रोम में है
हे साईं तू नैनो में है
हे साईं तू धरती में है
हे साईं तू आसमां में है
हे साईं तू जल में है
हे साईं तू सब में है
हे साईं तू मां के दुलार में है
हे साईं तू पिता की डांट में है.

हे साईं तू दोस्त में है
हे साईं तू दुश्मन में है
हे साईं तू जिव्हा पे है
हे साईं तू सपने में है
हे साईं तू दिल में है
हे साईं तू सुख में है
हे साईं तू दुःख में है
हे साईं तू जन्म में है

हे साईं तू मौत में है
हे साईं तू अपने में है
हे साईं तू पराए में है
हे साईं तू गीता में है
हे साईं तू पुराण में है
हे साईं तू वेद में है
हे साईं तू रामायण में है.

हे साईं तू पलकों पे है
हे साईं तू सिर-आंखों पे है
हे साईं तू लोक में है
हे साईं तू परलोक में है
हे साईं तू मेरी इस कविता में है
हे साईं तू हर कविता में है
हे साईं तू हर भावना में है
हे साईं तू हर जगह है
हे साईं तू जल का स्वाद है
हे साईं तू फूलों की ख़ुशबू है
हे साईं तू सच्चा दोस्त है.

## सेवानिवृत जवानों के पुनर्वास के लिए

# भारतीय सेना का ऐतिहासिक क़दम

**सरहद पर तैनात बहादुर जवानों के बेहतर भविष्य के लिए भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक क़दम उठाया है. दिल्ली के कंस्टीच्यूशन कल्ब में भारतीय सेना और मोरारका फाउंडेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया. इसके तहत दोनों ही संगठन रिटायर होने वाले सैनिकों के लिए जैविक खेती के अवसरों की जांच करेंगे. इस क़दम से लाखों जवानों को फ़ायदा पहुंचेगा. मोरारका फाउंडेशन देश के 19 राज्यों में विकास के काम कर रहा है. सेना के साथ इस पहल के ज़रिये फाउंडेशन जवानों को आर्थिक रूप से मज़बूत करेगा, ताकि रिटायरमेंट केबाद उन्हें नौकरी के लिए दर-दर ठोकरें नहीं खाना पड़ें.**

शहरों और गांवों में शांति से रहने वाले हम आप जैसे लोगों को शायद ही कभी यह ध्यान में आता है कि यह शांति और आज़ादी एक ही झटके में ख़त्म हो जाए, अगर देश के लाखों बहादुर जवान बॉर्डर पर तैनात न रहें. हम इंडियन आर्मी और सीमा पर तैनात लाखों जांबाज़ों को सलाम करते हैं, जो अपने परिवार से दूर, अपने गांव से दूर, अपने दोस्तों से दूर, हिमालय की ऊंचाइयों और रेगिस्तान की गर्मी में रहकर देश की सुरक्षा करते हैं. आज हम ऐसे लाखों जांबाज़ों की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात करेंगे. यह समस्या ऐसी है जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया. दरअसल, ये जवान लगभग चालीस साल की उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं. कुछ चालीस से पहले भी रिटायर होते हैं. रिटायर होने के बाद भी उनके सामने पूरा जीवन होता है. उन्हें पेंशन भी मिलती है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होती है. इसलिए वे रिटायर होने के बाद भी नौकरी तलाशते हैं. कुछ को नौकरी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलती है. सरकार के पास इन जवानों के पुनर्वास की कोई पुख्ता पॉलिसी नहीं है. इसलिए उन्हें मजबूर होकर छोटी-मोटी नौकरियों से गुज़ारा करना पड़ता है. बुधवार यानी बीते सात मार्च को इंडियन आर्मी ने जवानों के भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक फ़ैसला लिया, जो सरहद पर तैनात जवानों के लिए एक अच्छी ख़बर है. इंडियन आर्मी के एडजूटैंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जयप्रकाश नेहरा की उपस्थिति में मेजर जनरल के. मज़ूमदार ने मोररका फाउंडेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिग साइन किया है. देश में हर साल चालीस से पचास हज़ार जवान रिटारयर होते हैं. मोरारका फाउंडेशन इन सैनिकों को जैविक खेती करने की ट्रेनिंग देगा. मोरारका ऑर्गेनिक फूड लिमिटेड के ज़रिये जवानों द्वारा उपजाए गए खाद्य पदार्थों को बाज़ार तक पहुंचाया जाएगा. जवानों को उनके उत्पाद के लिए बाज़ार से ज़्यादा क़ीमत दी जाएगी. इंडियन आर्मी की तरफ़ से मेजर जनरल के. मज़ूमदार ने इस क़रार पर दस्तख़त किए. इस मौक़े पर लेफ्टिनेंट जनरल रवि प्रकाश नेहरा ने इस पहल को सराहा और कहा कि इस स्कीम के ज़रिये उन जवानों को भी फ़ायदा होगा जिनके पास कम ज़मीन है.

समझने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ़ से सेवानिवृत सैनिकों को जो मदद मिलती है, वह पर्याप्त नहीं है. जितनी पेंशन मिलती है, उससे परिवार नहीं चल सकता है. सरकार की योजनाओं का फ़ायदा कुछ आर्मी अफ़सरों को मिलता है, लेकिन रिटायर होने के बाद जवानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. यह बात भी जानना ज़रूरी है कि जबसे जनरल वीके सिंह इंडियन आर्मी के चीफ बने हैं, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि रिटायरमेंट के बाद देश के जवान अच्छी ज़िंदगी बिता सकें. सेना की तरफ़ से आज कई स्कीमें हैं, जिससे जवानों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. जवानों की पढ़ाई-लिखाई ज़्यादा नहीं होती है, न ही उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होती है, जिससे उन्हें कोई नौकरी मिल सके. इसलिए अब नौकरी के दौरान सैनिकों को अलग-अलग प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है. कोर्स कराया जा रहा है, ताकि जब वे रिटायर होकर बाहर की दुनिया में आएं तब उन्हें कोई परेशानी न हो. इंडियन आर्मी की इस पहल से सैनिकों को फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन इससे जवानों की समस्या का समाधान निकलना मुश्किल होगा.

आज़ादी के बाद अब तक जवानों को सरकार ने बेसहारा छोड़ा दिया था. सेना से रिटार्यरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी दूभर हो जाती है. अभी होता यह है कि रिटायरमेंट के बाद नौकरी की तलाश में शहर जाना पड़ता है. उन्हें बड़ी मुश्किल से दस से पंद्रह हज़ार रुपये की नौकरी मिल पाती है. ज़्यादातर जवान सिक्योरिटी गार्ड्स बन जाते हैं, जिनकी हालत सचुमच दयनीय है. क्योंकि यह स्थायी नौकरी नहीं है, इसलिए हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं. शहर में परिवार के साथ रहने में ख़र्च भी ज़्यादा होता है. अगर वे अपनी खेती करने लग जाएं, उनकी पूरी फ़सल बाज़ार से ज़्यादा दाम पर ख़रीद ली जाए और उनकी आमदनी बढ़ जाए, तो उन्हें अपने घरवालों को छोड़कर शहरों में दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा. साथ ही वे अपनी मेहनत और अनुशासन से गांव वालों में एक नई ऊर्जा और आदर्श क़ायम कर पाएंगे. हम जिस तरह का मान-सम्मान अपने सैनिक भाइयों को देना चाहते हैं, वह उन्हें मिल पाएगा.

कई सैनिकों के पास ज़मीनें होती हैं, लेकिन खेती में फ़ायदा नहीं होता है. इसलिए वे खेती नहीं करते हैं. फ़ायदा न होने की सबसे बड़ी वजह है कि खेती में पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बीज से लेकर खाद तक सबकुछ महंगे हो गए हैं. इसके अलावा पानी की कमी सबसे ज़्यादा है. मोरारका फाउंडेशन सेवानिवृत सैनिकों को जैविक खेती की ऐसी ट्रेनिंग देगा, जिसमें फ़सलों में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें वे स्वयं पैदा कर सकेंगे. इससे किसानों को कम लागत पर ज़्यादा फ़ायदा होता है. साथ ही मोरारका रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े वैज्ञानिक सेना के जवानों को इस बात की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें पानी का कम से कम प्रयोग करके अधिक से अधिक फ़सल उगाई जा सके. ये वैज्ञानिक हाइड्रोपोनिक तकनीक, ट्रे कल्टीवेशन, ड्रिप सिस्टम आदि द्वारा खेती करना सिखाएंगे, जिनमें पानी का कम से कम इस्तेमाल होता है. हाइड्रोपोनिक तकनीक के ज़रिये सैनिकों को मिट्टी के बिना और पानी के कम से कम इस्तेमाल से सब्ज़ियां उगाना सिखाया जाएगा. इस तकनीक की दूसरी विशेषता यह है कि इसके लिए आपको खेत की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं तो अपने मकान की छत पर भी बड़ी आसानी से सब्ज़ियां उगा सकते हैं. हाइड्रोपोनिक तकनीक द्वारा लगातार पैदावार की जा सकती है और इसमें सभी सब्ज़ियां किसी भी ऋतु में पैदा की जा सकती हैं. साथ ही जल और एग्री इनपुट्स की बर्बादी भी कम होती है. यह तकनीक पत्ते वाली सब्ज़ियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है. मोरारका फाउंडेशन सैनिकों को ट्रे कल्टीवेशन के गुण सिखाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन सौनिकों को होगा, जिनके पास बहुत कम ज़मीन है. इन तकनीकों से टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, करेला, ककड़ी, ग्वारफली को उपजाया जा सकता है, जिसकी मांग बाज़ार में ज़्यादा है. इस तरह रिटायर होने के बाद ट्रे कल्टीवेशन द्वारा कम लागत पर ज़्यादा सब्ज़ियां उगाकर अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं. अच्छी बात यह है कि मोरारका फाउंडेशन उनकी उपज को बाज़ार से 10 से 25 फ़ीसदी ज़्यादा क़ीमत पर ख़रीदने को तैयार हो गया है. समझने वाली बात यह है कि जैविक खेती के लिए पहले तीन सालो में थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बार मिट्टी और किसान तैयार हो जाते हैं तो तीन साल के बाद जैविक किसानों की आय में 40 से 60 फ़ीसदी की बढ़त हो जाती है. इस स्कीम का फ़ायदा यह होगा कि देश के बहादुर जवान रिटायर होने के बाद अपने घर वापस जा सकते हैं. अर्थिक तौर पर ख़ुद को मज़बूत कर सकेंगे और सेना के प्रति और देश के प्रति लोगों में सद्भावना और समाज में देशप्रेम को फैलाने वाले सबसे बड़े माध्यम बन सकते हैं.

इस पहल से देश की जनता को भी फ़ायदा होने वाला है. देश में जिस तरह से खाने-पीने के सामान में ज़हर घुलता जा रहा है. सब्ज़ियां, तेल, मसाले यहां तक कि दूध और घी में भी ज़हर है. खेतों में हम इतना केमिकल और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों में तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं. मोरारका फाउंडेशन जिस तरह की खेती की ट्रेनिंग सेना के जवानों को देगा, उसमें न तो केमिकल का इस्तेमाल होता है, न ही पेस्टिसाइड और न ही किसी इनसेक्टिसाइड का और मुनाफ़ा भी ज़्यादा होता है. इस तरह इस स्कीम से सेना के जवानों को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही बाज़ार में हमें शुद्ध और स्वादिष्ट सामान भी उपलब्ध होगा. इस क़रार के ज़रिये सेना के जवानों के सामने रिटायर होने के बाद जैविक खेती करने का विकल्प होगा. ज़्यादातर जवान गांवों से आते हैं. मेहनती होते हैं और सेना में रहने की वजह से अनुशासित होते हैं. हमारे जवानों की ये ख़ूबियां देश में जैविक खेती को एक आंदोलन का रूप दे सकती हैं. देश से ज़हरीली सब्ज़ियां और खाने पीने के सामनों को बाज़ार से हमारे जवान बाहर कर सकते हैं. पहली बार किसी संगठन ने ये कमाल किया है, जिससे सेना से रिटायर होने वाले जवान न सिर्फ़ आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाएंगे साथ ही वे अपने गांवों में एक नए आंदोलन का नेतृत्व कर सकेंगे. आइये अब हम आपको बताते हैं कि इस स्कीम के ज़रिये कैसे जवानों को आर्थिक और समाजिक रूप से सुरक्षित और मज़बूत किया जाएगा. मोरारका फाउंडेशन एक स्वयंसेवी संस्था है, जो 1993 से ग्रामीणों और ग़रीबों के विकास के लिए काम कर रही है. इसकी स्थापना समाजसेवी कमल मोरारका ने गैनन एंड डंकरेली कंपनी लिमिटेड के समाजिक दायित्व के तहत अपने पिता स्वर्गीय एमआर मोरारका की स्मृति में की. मोरारका फाउंडेशन अब तक डेढ़ लाख से ज़्यादा किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग दे चुका है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अनंत विजय

# ताबड़तोड़ विमोचनों का मेला

कुछ दिनों पहले दिल्ली में बीसवां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला समाप्त हुआ. दरअसल यह मेला एक साहित्यिक उत्सव की तरह होता है, जिसमें पाठकों की भागीदारी के साथ–साथ देशभर के लेखक भी जुटते हैं और परस्पर व्यक्तिगत संवाद संभव होता है. इस बार के मेले की विशेषता रही किताबों का ताबड़तोड़ विमोचन और कमी खली राजेंद्र यादव की, जो बीमारी की वजह से मेले में शिरकत नहीं कर सके. एक अनुमान के मुताबिक़, इस बार के पुस्तक मेले में हिंदी की तक़रीबन सात से आठ सौ किताबों का विमोचन हुआ. हिंदी के हर प्रकाशक के स्टॉल पर हर दिन किसी न किसी का संग्रह विमोचित हो रहा था. इस बार फिर से नामवर सिंह और अशोक वाजपेयी ने सबसे ज़्यादा किताबें विमोचित की होंगी, ऐसा मेरा अमुमान है. इस अनुमान का आधार प्रकाशकों से मिलने वाले विमोचन के एसएमएस रूपी निमंत्रण हैं. मेले में इस बार शिद्दत से हंस के संपादक राजेंद्र यादव की कमी महसूस हुई. राजेंद्र यादव एक छोटे से ऑपरेशन के बाद से ठीक होने की प्रक्रिया में हैं और इस प्रक्रिया में उनका बिस्तर से उठ पाना मुश्किल है. लिहाज़ा, वह पुस्तक मेले में नहीं आ पाए. सिर्फ़ मेला ही क्यों दिल्ली का हिंदी समाज हंस के दरियागंज दफ्तर में उनकी अनुपस्थिति को महसूस कर रहा है. हिंदी साहित्य का एक स्थायी ठीहा आजकल उनकी अनुपस्थिति की वजह से वीरान ही नहीं, उदास भी है. हम सब लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, ताकि दिल्ली के हिंदी जगत की ज़िंदादिली वापस आ सके.

वापस लौटते हैं पुस्तक मेले पर. पुस्तक मेले में इतनी बड़ी संख्या में किताबों के विमोचन को देखते हुए लगता है कि हिंदी में पाठकों की कमी का रोना नाजायज़ है. अगर पाठक नहीं हैं तो फिर इतनी किताबें क्यों छप रही हैं. मेरा मानना है कि सिर्फ़ सरकारी ख़रीद के लिए इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकें नहीं छप सकती हैं. एक बार फिर से हिंदी के कर्ता–धर्ताओं को इस पर विचार करना चाहिए और डंके की चोट पर यह ऐलान भी करना चाहिए कि हिंदी सिर्फ़ पाठकों के बूते ही चलेगी भी और बढ़ेगी भी. इससे न केवल लेखकों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि पाठकों की कमी का रोना रोने वालों को भी मुंहतोड़ जवाब मिल पाएगा. छात्रों की परीक्षा के बावजूद मेले में लोगों की सहभागिता के आधार पर मेरा विश्वास बढ़ा है. मेले में जो किताबें विमोचित या जारी हुईं, उनमें कवि–संस्कृतिकर्मी यतींद्र मिश्र के निबंधों का संग्रह विस्मय का बखान (वाणी प्रकाशन), कवि तजेन्दर लूथरा का कविता संग्रह अस्सी घाट पर बांसुरीवाला (राजकमल प्रकाशन), हाल के दिनों में अपनी कहानियों से हिंदी जगत को झकझोरने वाली लेखिका जयश्री राय का उपन्यास औरत जो नदी है (शिल्पायन, दिल्ली) अशोक वाजपेयी के अख़बारों में लिखी टिप्पणियों का संग्रह–कुछ खोजते हुए के अलावा झारखंड की उपन्यासकार महुआ माजी का नया उपन्यास मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ (राजकमल प्रकाशन) और पत्रकार एवं कहानीकार गीताश्री की शोधपरक पुस्तक सपनों की मंडी प्रमुख है. हिंदी में शोध के आधार पर साहित्यिक या ग़ैर साहित्यिक लेखन बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है. जो हुआ है, उसमें विषय विशेष की सूक्ष्मता से पड़ताल नहीं गई है. विषय विशेष को उभारने के लिए जिस तरह से उसके हर पक्ष की सूक्ष्म डिटेलिंग होनी चाहिए थी उसका अभाव लंबे समय से हिंदी जगत को खटक रहा था. अपने ज्ञान, प्रचलित मान्यताओं, पूर्व के लेखकों के लेखन और धर्म ग्रंथों को आधार बनाकर काफ़ी लेखन हुआ है. लेकिन तर्क और प्रामाणिकता के अभाव में उस लेखन को बौद्धिक जगत से मान्यता नहीं मिल पाई. लेखकों की नई पीढ़ी में यह काम करने की छटपटाहट लक्षित की जा सकती है. इस पीढ़ी के लेखकों ने श्रमपूर्वक ग़ैर साहित्यिक विषयों पर बेहद सूक्ष्म डीटेलिंग के साथ लिखना शुरू किया. नई पीढ़ी की उन्हीं चुनिंदा लेखकों में एक अहम नाम है गीताश्री का. कुछ दिनों पहले एक के बाद एक बेहतरीन कहानियां लिखकर कहानीकार के रूप में शोहरत हासिल कर चुकीं पत्रकार गीताश्री ने तक़रीबन एक दशक तक शोध और यात्राओं और उसके अनुभवों के आधार पर देह व्यापार की मंडी पर यह किताब लिखी है. गीताश्री ने अपनी इस किताब में अपनी आंखों से देखा हुआ और इस पेशे के दर्द को झेल चुकी और झेल रही महिलाओं से सुनकर जो दास्तान पेश की है, उससे पाठकों के हृदय की तार झंकृत हो उठती है. उम्मीद की जा सकती है कि हिंदी में जो एक कमी महसूस की जा रही थी वह गीताश्री की इस किताब से पूरी होगी. कवि तजेन्दर लूथरा के कविता संग्रह का नाम अस्सी घाट पर बांसुरीवाला चौंकाने वाला है. संग्रह के विमोचन के बाद जब मैंने नामवर सिंह से इस कविता संग्रह के शीर्ष के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि जब तक वह बनारस में थे, तब तक उन्होंने अस्सी घाट पर बांसुरी वाले को नहीं देखा था. लेकिन नामवर सिंह ने तजेन्दर की कविताओं को बेहतर बताया. हालांकि कवि का दावा है कि उन्होंने अस्सी घाट पर बजाप्ता बांसुरी वाले को बांसुरी बजाते देखा है और वहीं से इस कविता को उठाया है. मैंने भी तजेन्दर की कई कविताएं पढ़ी और सुनी हैं. उनकी कविताओं की एक विशेषता जिसे हिंदी के आलोचकों को रेखांकित करना चाहिए, वह यह है कि वहां कविता के साथ–साथ कहानी भी समांतर रूप से चलती है. तजेन्दर की कविताएं ज़्यादातर लंबी होती हैं और उसमें जिस तरह से समांतर रूप से एक कहानी भी साथ–साथ चलती है, उससे पाठकों को दोनों का आस्वाद मिलता है. तजेन्दर की कविताओं के इस पक्ष पर हिंदी में चर्चा होना शेष है. मैं आमतौर पर कविता संग्रहों पर नहीं लिखता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज की ज़्यादातर कविताएं सपाट बयानी और नारेबाज़ी की शिकार होकर रह गई हैं. लेकिन तजेन्दर की कविताओं में नारेबाज़ी या फैशन की क्रांति नहीं होने से यह थोड़ी अलग है. कभी विस्तार से इस कविता संग्रह पर लिखूंगा.

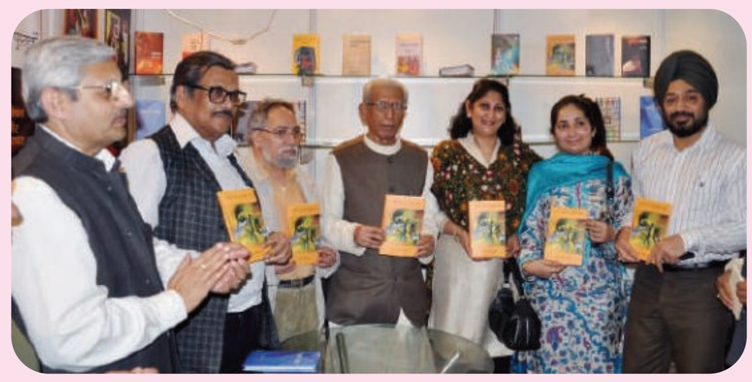

महुआ माजी का पहला उपन्यास मैं बोरिशाइल्ला ठीक–ठाक चर्चित हुआ था. अब एक लंबे अंतराल के बाद उनका जो दूसरा उपन्यास आया है, उसे लेखिका ने विकिरण, प्रदूषण और विस्थापन से जुड़े आदिवासियों की गाथा बताया है. लेखिका के मुताबिक़, इसमें द्वितीय विश्वयुद्ध से हुए विध्वंस से लेकर वर्तमान तक को समेटा गया है. विजय मोहन सिंह इसे जंगल जीवन की महागाथा बताते हैं, लेकिन देखना होगा कि हिंदी के पाठक इस उपन्यास को किस तरह से लेते हैं. रचनाओं को परखने की आलोचकों की नज़र पाठकों से इतर होती है और बहुधा उनकी राय भी अलग ही होती है. पुस्तक मेले के आयोजक नेशनल बुक ट्रस्ट के नए और युवा निदेशक एमए सिकंदर से भी लंबी बातचीत हुई. दरअसल, मेले में कुछ प्रकाशकों ने आयोजन की तिथि और व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे. एनबीटी के निदेशक ने साफ़ तौर पर यह स्वीकार किया कि बच्चे कम संख्या में आ पाए, लेकिन जिस तरह से ट्रस्ट ने दिल्ली के कॉलेजों में एक अभियान चलाया, उससे पुस्तक मेले में छात्रों की भागीदारी बढ़ी. बातचीत के क्रम में सिकंदर साहब ने जो एक अहम बात कही वह यह कि एनबीटी विश्व पुस्तक मेले को हर साल आयोजित करने की संभावनाओं को तलाश रहा है. अगर यह हो पाता है तो हिंदी समेत अन्य भाषाओं के लिए भी बेहतरीन काम होगा.

*(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)*

anant.ibn@gmail.com

# न्याय याचना के ज्वलंत सवाल

भारतीय साहित्यकार संघ के अध्यक्ष डॉ. वेद व्यथित का खंड काव्य न्याय याचना एक अनुपम कृति है. जैसा नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें न्याय पर सवाल उठाए गए हैं. वह कहते हैं, यह ठीक है कि जानबूझ कर किया गया अपराध अनजाने में हुए अपराध से कहीं भयावह है, लेकिन लापरवाही में किया गया अपराध भी कम भयावह नहीं है. ज़रूर कहीं उसके अवचेतन में व्यवस्था और अनुशासन की अवहेलना है. ठीक है, गंधर्व ने जानबूझ कर ऋषि की अंजलि में नहीं थूका, लेकिन क्या कहीं भी थूक देना उचित है? क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? यह उसकी मदमत्तता और अभिमान नहीं तो क्या है? दूसरा सवाल पश्चाताप का उठाया गया है. गंधर्व चित्रसेन ने ख़ूब पश्चाताप किया है. इसलिए उसे क्षमा कर देना चाहिए. क्यों कर देना चाहिए? पश्चाताप करना उसका व्यक्तिगत मामला है. अपराधी को पश्चाताप तो करना ही चाहिए, लेकिन मात्र पश्चाताप के बाद वह क्षम्य है तो व्यक्ति कुछ भी अपराध करके पश्चाताप कर लेगा. ऐसे में न्यायालय या व्यवस्था का क्या महत्व रह जाएगा? इन्हीं सवालों को इस पौराणिक कथा के ज़रिए उठाने की कोशिश की गई है. विषय तो इसका उत्कृष्ट है ही, भाषा शैली भी सौंदर्य से परिपूर्ण है.

**खंड काव्य के प्रथम सर्ग में वह लिखते हैं:–**

*कब होती है तृप्त देह यह*
*राग रंग भोगों से*
*जितना करते यत्न शांत*
*करने का इस तृष्णा को*
*वह तो और सुलग जाती,*
*ऐसी ही प्रतिपल ज्वाला सी*
*धधक रही थी उनमें*
*उसी आग को लेकर दोनों*
*उड़े चले जाते हैं.*

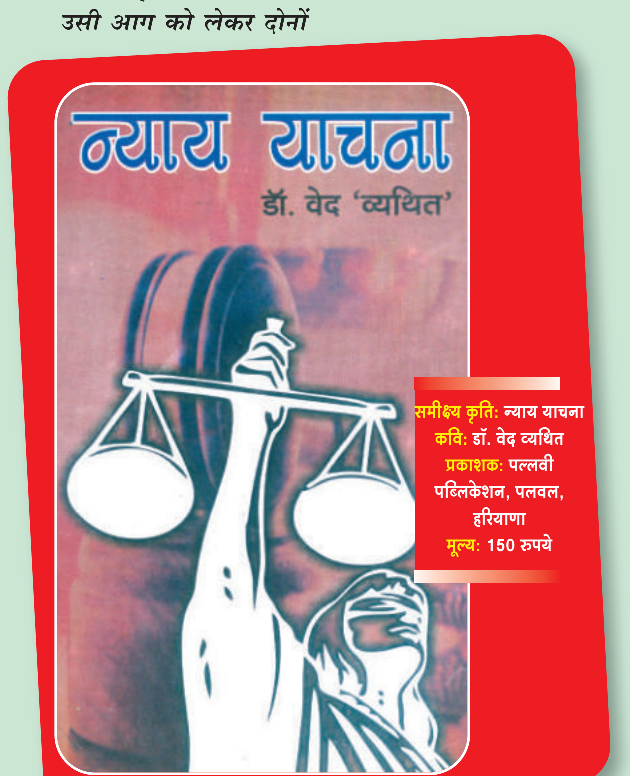

समीक्ष्य कृति: न्याय याचना
कवि: डॉ. वेद व्यथित
प्रकाशक: पल्लवी पब्लिकेशन, पलवल, हरियाणा
मूल्य: 150 रुपये

द्वितीय सर्ग में भी सुंदर शब्दों से वह वातावरण का मनोहारी वर्णन करते हैं:–

*पूरब रंगा सुहाग सूर्य की*
*सिंदूरी आभा लेकर*
*विकसे कमल हुआ हर्षित मन*
*ऊषा का रूपवरण,*
*अनुकंपा हे ईश! तुम्हारी*
*तुमको है शत–शत बार नमन*
*प्रकटो अनंत ज्योति के स्वामी*
*अंजलि करो स्वीकार प्रवर.*

डॉ. वेद व्यथित की कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं. इनमें मधुरिमा (काव्य नाटक), आख़िर वह क्या करें (उपन्यास), बीत गए वे पल (संस्मरण), आधुनिक हिंदी साहित्य में नार्गाजुन (आलोचना), भारत में जातीय सांप्रदायिकता (उपन्यास) और अंतर्मन (काव्य संग्रह) शामिल हैं. उन्होंने व्यक्ति चित्र नामक नवीन विधा का सृजन किया है. इसके अलावा त्रिपदी काव्य की नवीन विधा के सृजन का श्रेय भी उन्हीं को जाता है. पंजाबी और जापानी भाषा में उनकी कई रचनाओं का अनुवाद हो चुका है.

बक़ौल डॉ. मनोहर लाल शर्मा, यह युग प्रबंध काव्यों का युग नहीं रह गया है. निराला जी की पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा और अज्ञेय की असाध्य वीणा जैसी लंबी कविताएं उक्त विवशता के स्वीकरण का पूर्वाभास देती हैं. ऐसी कविताओं में कवि जीवन के समग्रत्व का समावेश करने की केवल चेष्टा कर सकता है. लंबी कविताओं में फिर भी वह बात नहीं आ पाती, जो प्रबंध काव्यों में जीवन के अनेक विषयों, नानाविध मनोभावों, क्रिया–व्यापारों, दृश्यों एवं प्रसंगों की उपस्थिति द्वारा सहज देखने को मिल जाती है. इसी बिंदू से प्रबंध काव्यों की अपरिहार्यता सिद्ध हो जाती है. युग की बेबसियां चाहे कितना ही दबाव रचनाकारों और सहृदयों के मानस पटल पर बनाती रहें, यदि हमें अपने समशील मानव प्राणियों, मानवेतर प्राणियों के मनोभावों, क्रियाकलापों और नानाविध प्रकरणों में अपनी दिलचस्पी को व्याहत नहीं होने देना है तो हमें अंतत: ऐसे प्रबंधों की प्रयोजनीयता को हृदयंगम करना होगा. डॉ. वेद व्यथित का खंड काव्य न्याय याचना इसी मांग की पूर्ति और प्रतिपूर्ति का साहसपूर्ण उपक्रम है. वह जानते होंगे कि धारा के विपरीत किश्ती को तैरा देना कितना विवेकसम्मत है, पर हिम्मती लोग ऐसा कर दिखाते हैं. प्रस्तुत खंड काव्य आज के प्रतिकूल वातावरण, परिवेश और विषम प्रतिक्रियाओं के होते हुए भी एक स्वागत योग्य क़दम है. यह खंड काव्य नए रचनाकारों के लिए भी प्रेरणादायी है.

डॉ. व्यथित कहते हैं:–

तुम न्याय के मंदिर की कहानी लिखना
सूली पे चढ़ू उसकी ज़ुबानी लिखना,
तुम ख़ून को मेरे ही बनाना स्याही
अस्थि को क़लम मेरी बनाकर लिखना.

निस्संदेह, यह खंड काव्य अपने विषय और प्रस्तुति की रोचकता के कारण पठनीय है.

फ़िरदौस ख़ान
firdaus@chauthiduniya.com

## किताब मिली

पुस्तक का नाम
मैक्सिम गोर्की की लोकप्रिय कहानियां

लेखक
मैक्सिम गोर्की

प्रकाशक
राधाकृष्ण प्रकाशन

मूल्य
250 रुपये

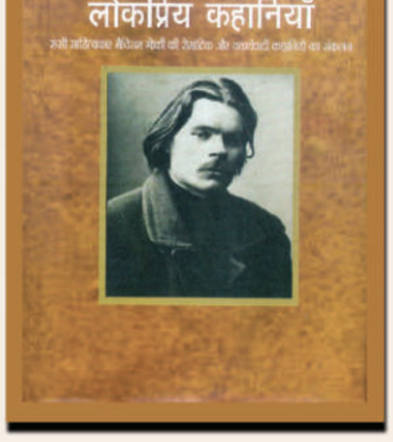


यह किताब प्रख्यात रूसी साहित्यकार मैक्सिम गोर्की की कहानियों का संग्रह है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

# किताबों की दुनिया और बच्चे

दौड़ती–भागती दुनिया और तेज़ी से होता आधुनिकीकरण. बच्चों की तो दुनिया ही बदल गई है. टीवी और इंटरनेट ने उन्हें किताबों और साहित्य से कोसों दूर कर दिया है. ऐसे में केंद्र सरकार ने बच्चों की साहित्यक रूचि का मंच प्रदान करने और वरिष्ठों के बीच बिठाकर उनकी प्रतिभा को निखारने की योजना बनाई है. इसकी शुरुआत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कर भी दी है. इसके लिए सभी प्रदेशों और उसके सभी ज़िलों में साहित्य मेलों का आयोजन भी किया जाएगा. इस आयोजन को विद्यालय स्तर तक जोड़ा जाएगा, ताकि प्रतिभाएं सामने आ सकें. हर साल फरवरी माह में होने वाले इन मेलों में देश के प्रतिष्ठित प्रकाशकों को आमंत्रित किया जाएगा यानी बच्चे किताबों की स्वप्नमय दुनिया से रूबरू हो सकेंगे. इस दौरान ही विभिन्न साहित्यक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए ज़िला स्तरीय कमेटी भी गठित की जा रही है, जिसके संरक्षक ज़िला कलेक्टर होंगे. मेले का आयोजन ऐसे स्थान पर किए जाने के निर्देश हैं, जो सांस्कृतिक एवं पुरातत्व महत्व का हो, ताकि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को सांस्कृतिक धरोहरों की बेहतर जानकारी मिल सके और उनमें कला, साहित्य एवं संस्कृति के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके. इसलिए इन मेलों में शिक्षक, विद्यार्थी, लेखक, वरिष्ठ नागरिक और कलाकार शामिल किए जाएंगे.

शैक्षिक भ्रमण अभियान के तहत प्रतिभावान विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण भी कराया जाएगा. इसके तहत सरकार ने बजट भी आवंटित किया है. राज्य स्तर पर आयोजित शैक्षिक भ्रमण में प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा. साहित्य मेले में मूल रूप से पुस्तक मेला तो लगेगा ही, जिसमें नेशनल बुक ट्रस्ट सहित देश के सभी प्रतिष्ठित प्रकाशकों को आमंत्रित किया जाएगा. इसमें बच्चे ही नहीं, शहर के लोग भी दुर्लभ पुस्तकों को पढ़ सकेंगे. वैसे बच्चों से संबंधित किताबों पर ज़ोर अधिक रहेगा, लेकिन शिक्षा सहित दर्शन, आध्यात्म, इतिहास, उपन्यास, कहानी, समाज, व्यवस्था, प्रबंधन विषय से संबंधित पुस्तकें भी आएंगी. मेले से बच्चों को जोड़ने के लिए सभी स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इसमें साहित्य प्रतियोगिताओं के तहत सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए निबंध, कहानी, कविता लेखन स्पर्धा का भी आयोजन किया जाएगा.

साहित्य मेले का मक़सद बच्चों में साहित्य के प्रति जागरूकता लाना है. मेले के माध्यम से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को साहित्यक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे. हर सूबे की सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे स्थानीय साहित्यकारों, कलाकारों के साथ संवाद क़ायम होगा. सामुदायिक गतिशीलता से शिक्षा एवं समुदाय के बीच समन्वय बनेगा और साहित्यक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही सृजनात्मक वातावरण तैयार होगा, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# व्यूसोनिक का नया टैबलेट

**टैब की स्क्रीन 1024/600 रेज्योलूशन को सपोर्ट करती है, जिससे यूजर को शानदार वीडियो और पिक्चर क्वालिटी मिलती है.**

टैबलेट पीसी की रेंज में व्यूसोनिक ने भारत में एक नया टैबलेट लांच किया है. अन्य टैबलेट्स के मुक़ाबले व्यूसोनिक टैबलेट में 10 इंच की स्क्रीन है, जो यूजर को बड़ा पिक्चर व्यू प्रोवाइड करती है. व्यूसोनिक व्यूपैड में दमदार सीपीयू के साथ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म मौजूद है. टैब की स्क्रीन 1024/600 रेज्योलूशन को सपोर्ट करती है, जिससे यूजर को शानदार वीडियो और पिक्चर क्वालिटी मिलती है. इसके अलावा टैब में कई मल्टीमीडिया फीचर दिए गए हैं. व्यूसोनिक ने इस टैबलेट को भारतीय बाज़ार में 17,000 रुपये की अनुमानित क़ीमत में लांच किया है.

# क्यूब टच माउस

कंप्यूटर एक्सेसरीज की कई वैरायटी बाज़ार में आने के बाद अब माउस के डिजाइन को लेकर नए-नए इनोवेशन हो रहे हैं. लॉजिटेक ने पीसी बाज़ार में एक नया माउस लांच किया है. साधारण माउस के मुक़ाबले लॉजिटेक का नया क्यूब माउस देखने में अलग लगता है. इसकी डिजाइन ही इसकी खासियत है. अपने नाम के अनुरूप क्यूब का शेप देखने में क्यूब जैसा है. इस माउस में टच तकनीक का प्रयोग किया गया है. राइट और लेफ्ट क्लिक के लिए यूजर को सिर्फ़ माउस के ऊपर हल्का सा टच करना होगा. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में इसकी क़ीमत 2,941 रुपये है.

नई दिल्ली में एएसयूएस का नया नोटबुक लॉन्च करते विशाल धुपर (दाएं) एमडी एनवीआईडीआईए, एशिया-साउथ, एएसयूएस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और एलेक्स हांग (बाएं) एमडी, सिस्टम बिजनेश ग्रूप, एएसयूएस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

फोटो–*सुनील मल्होत्रा*

# निसान-370 जी

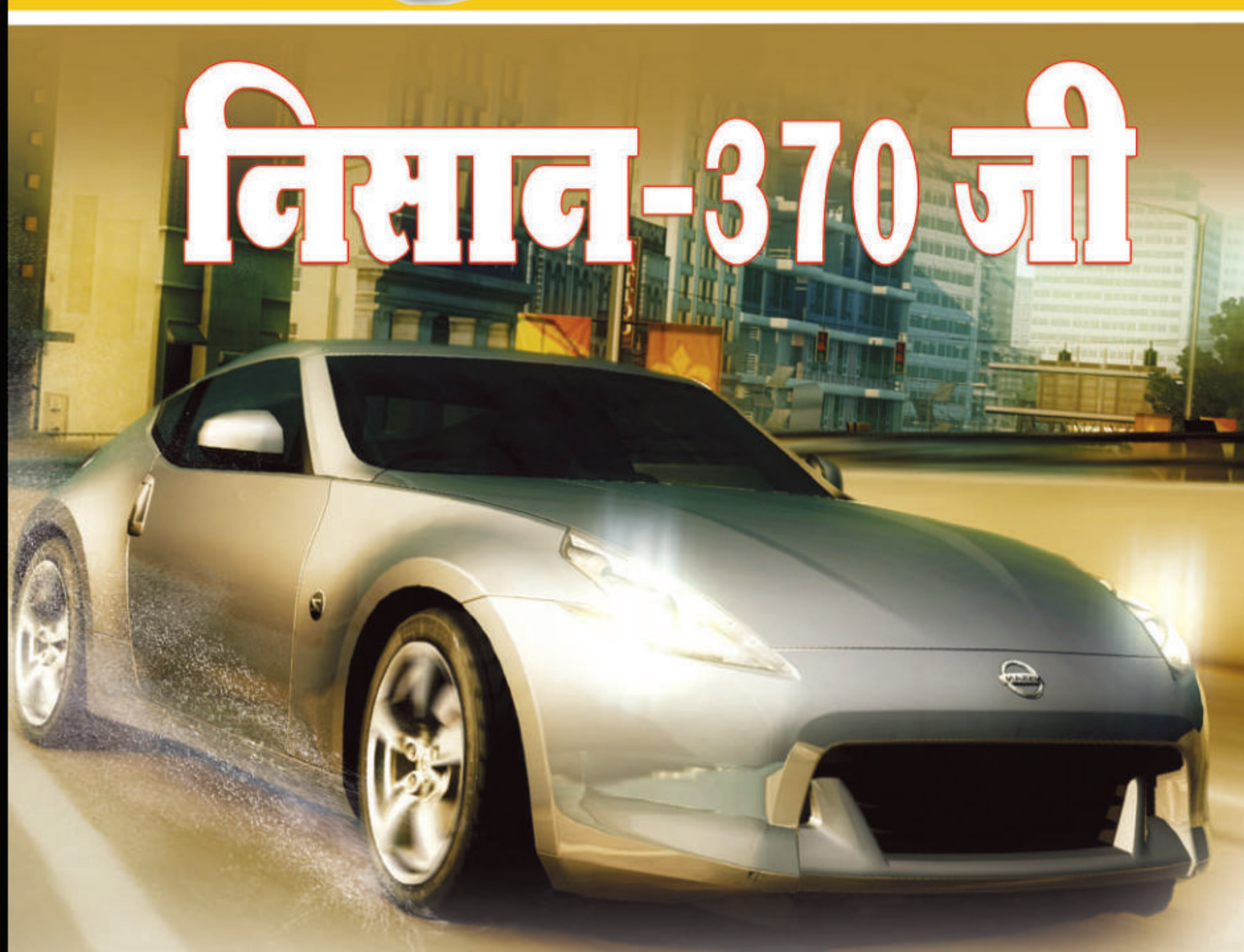

यदि बात की जाए निसान–370 जी के एक्सटीरियर की तो यह एक बेहद आकर्षक लुक वाली स्पोर्ट कार है. इस कार में कंपनी ने 3.7 लीटर का डीओएचसी इंजन प्रयोग किया है. निसान–370 एक बेहतरीन ढंग से तैयार की गई सुगठित कार है. आकर्षक डिजाइन, स्पोर्टी लुक और बेहतरीन तकनीक इसे खास बना देती है. भारतीय बाज़ार में इस कार की क़ीमत 55 लाख रुपये से शुरू होती है. निसान ने भारतीय बाज़ार में इस कार के दो वैरिएंट पेश किए हैं 370–जीएटी और 370–जीएमटी. निसान 370–जीएटी में 7–स्पीड ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही गियर ट्रांसमिशन का प्रयोग किया गया है. वहीं 370–जीएमटी मॉडल में 6–स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का प्रयोग किया गया है.

कंपनी ने इस कार में बेहद शानदार बी–जेनॉन एचआईडी हेडलैंप का प्रयोग किया है. इस कार की टेल लाइट भी बेहद शानदार और आकर्षक है. कंपनी ने अपनी जी सीरीज के लोगो को कार में बतौर साइड इंडिकेटर प्रयोग किया है. शानदार टायरों और आधुनिक फीचरों से लैस इस कार में बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस, इबीडी को शामिल किया गया है. निसान–370 जी जब अपनी अधिकतम गति से दौड़ती है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन और तेज कार के साथ राइड का अनुभव होता है. बाहर सड़क पर आपका इंतज़ार करने वाले इस कार की आवाज़ दूर से ही सुन लेंगे.

**भारतीय बाज़ार में इस कार की क़ीमत 55 लाख रुपये से शुरू होती है. निसान ने भारतीय बाज़ार में इस कार के दो वैरिएंट पेश किए हैं 370-जीएटी और 370-जीएमटी. निसान 370-जीएटी में 7-स्पीड ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही गियर ट्रांसमिशन का प्रयोग किया गया है.**

# सोनी का स्टाइलिश कैमरा

**सोनी ने यह नया कैमरा साइबर शॉट डीएससी टीएक्स-66 के नाम से लांच किया है. ट्रैवलिंग के हिसाब से सोनी डीएससी टीएक्स-66 काफी अच्छा है.**

सोनी ने बाज़ार में ग्राहकों के रुख़ को ध्यान में रखते हुए नया स्लिम लुक कैमरा लांच किया है. मात्र 13 एमएम पतला यह कैमरा किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है. सोनी ने यह नया कैमरा साइबर शॉट डीएससी टीएक्स-66 के नाम से लांच किया है. ट्रैवलिंग के हिसाब से सोनी डीएससी टीएक्स-66 काफी अच्छा है.

यह 18.2 मेगापिक्सल कैमरा है, जिसमें बीएसआई-सीएमओएस सेंसर और बीआईओएनजेड इमेज प्रोसेसर है. ऑप्टिकल इमेज स्टैबलाइजेशन के साथ इसमें फोकल लेंथ 26-130 एमएम है. इसमें फेस डिटेक्शन दिया गया है. 3.3 इंच एलसीडी स्क्रीन पर बेहतरीन दिखने के लिए इसमें 1920/1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है. इसकी इंटरनल मेमोरी 19 एमबी है और इसमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए 2.0 यूएसबी पोर्ट है.

इस कैमरे में आप फुल हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. इसके कैमरे में दिया गया ऑटो फोकस काफी फास्ट काम करता है. अगर आपका बजट 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच है तो सोनी डीएससी टीएक्स-66 डिजिटल कैमरा आपको ज़रूर पसंद आएगा. सोनी डीएससी टीएक्स-66 डिजिटल कैमरा 17,500 रुपये में उपलब्ध है.

# न्यू लुक स्पीकर

ऑडियो बाज़ार में सैटेची नामक कंपनी ने स्मार्ट फोन के लिए न्यू लुक स्पीकर लांच किए हैं. इन स्पीकरों में पावर बैकअप के लिए रिचार्जेबल बैटरी दी गई है, जिसकी मदद से इन्हें कहीं भी फोन से कनेक्ट कर म्यूजिक का मज़ा लिया जा सकता है. इन स्पीकरों का साइज़ काफी पोर्टेबल है. सैटेची ऑडियो मूवी एसडी स्पीकरों में हाई बास तकनीक दी गई है, जो दमदार म्यूजिक का मज़ा देती है. स्टीरियो साउंड वाले इस स्पीकर में दिए गए फीचर्स काफी खास हैं. इसमें 32 जीबी एक्सपेंडेबल मेमोरी के लिए माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है, जिसमें 600 गाने स्टोर करने की क्षमता है. 17 घंटे बैटरी बैकअप के साथ 5 वोल्ट यूएसबी पॉवर एडॉप्टर भी है. यूजर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्पीकरों की मेमोरी माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट की मदद से 32 जीबी तक एक्सपेंड कर सकते हैं. मतलब यह कि वे स्पीकरों में 600 से अधिक गाने सेव कर सकते हैं. स्पीकरों को स्मार्ट फोन से कनेक्ट करने के लिए 3.5 एमएम का ऑडियो जैक दिया गया है. इनबिल्ड बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने पर क़रीब 17 घंटे तक म्यूजिक सुना जा सकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# जेडटीई का किस मोबाइल

ढेर सारे फीचरों के अलावा हैंडसेट कंपनियां अपने प्रोडक्ट के नाम भी ऐसे रख रही हैं, जिन्हें सुनकर ही उपभोक्ता आकर्षित हो जाएं. मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में जेडटीई ने किस नामक एक नया फोन लांच किया है. जेडटीई के इस नए हैंडसेट को खास तौर पर युवाओं के लिए बनाया गया है.

इस फोन में 2.3 जिजरब्रेड के साथ हॉट लुक दिया गया है. हालांकि जेडटीई किस में अन्य एंड्रॉयड फोन की तरह ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स मौजूद नहीं हैं, मगर इसका लुक यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा. किस में 800 मेगाहर्ट का प्रोसेसर और 256 रैम है. इसमें 3.5 की टच स्क्रीन दी गई है, जो 320/480 रेज्योलूशन को सपोर्ट करती है. फोन में थ्री जी कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है, इससे फास्ट नेट स्पीड चाहने वालों को निराशा हो सकती है. यूजर्स फोन की मेमोरी को माइक्रो कार्ड स्लॉट की मदद से 32 जीबी तक एक्सपेंड कर सकते हैं.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

# दुबई ओपन भूपति-बोपन्ना के नाम

भारतीय टेनिस स्टार महेश भूपति एवं रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने हाल में एटीपी दुबई ओपन के खिताबी मुक़ाबले में पोलैंड के मारियूस्ज फ्रीस्टनबर्ग एवं मार्सिन मातकोवस्की की जोड़ी को हराकर अपना पहला खिताब जीता. चौथी वरीयता प्राप्त भूपति एवं बोपन्ना ने 17,00475 डॉलर की ईनामी राशि वाले हार्डकोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में कड़ी चुनौती से उबरते हुए 6–4, 3–6, 10–5 से जीत दर्ज की. ये दोनों भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में एक साथ खेलने की योजना बना रहे हैं और 2012 के सत्र में बतौर जोड़ीदार शुरुआत करने के बाद इन दोनों ने यहां खिताब जीतने से पहले दो टूर्नामेंट्स के सेमी फाइनल में प्रवेश किया. भूपति के लिए यह चौथा दुबई खिताब है. इससे पहले उन्होंने लिएंडर पेस के साथ 1998 में, फैब्रिस सांतोरो के साथ 2004 में और मार्क नोल्स के साथ 2008 में यह ट्रॉफी जीती थी. बोपन्ना के करियर का यह छठवां एटीपी खिताब है. लिएंडर पेस एवं यांको टिप्सारेविच की जोड़ी शुरुआती राउंड में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी.

**चौथी वरीयता प्राप्त भूपति एवं बोपन्ना ने 17,00475 डॉलर की ईनामी राशि वाले हार्डकोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में कड़ी चुनौती से उबरते हुए 6-4, 3-6, 10-5 से जीत दर्ज की.**

# कोहली की विराट पारी

पूर्व आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ डीन जोंस ने विराट कोहली की श्रीलंका के ख़िलाफ़ 86 गेंदों पर नाबाद 133 रनों की पारी को एकदिवसीय क्रिकेट की सर्वोत्तम पारी क़रार दिया. उनका मानना है कि इस युवा बल्लेबाज़ को इस प्रारूप में तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी के लिए भेजा जाना चाहिए. जोंस ने कहा कि विराट कोहली की पारी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की सर्वकालिक सर्वोत्तम पारियों में से एक थी. कोहली की पारी को विव रिचर्ड्स की 1984 में इंग्लैंड में खेली गई पारी के बराबर आंका जा सकता है. एक समय वेस्टइंडीज का स्कोर सात विकेट पर 102 रन था और विव ने नाबाद 189 रन ठोक कर स्कोर 272 रनों पर पहुंचाया था. कोहली को वन डे में नंबर तीन पर भेजा जाना चाहिए, लेकिन टेस्ट मैचों में नहीं. उन्हें टेस्ट क्रिकेट में नंबर तीन पर उतरने के लिए रक्षात्मक तकनीक पर काम करना होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# मंडेला कप की तैयारी

भारत ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के बसने के 150 वर्ष पूरे होने के मौक़े पर आगामी 30 मार्च को जोहांसबर्ग में होने वाले एकमात्र टी–20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने की तैयारी कर ली है. जानकारी के अनुसार, दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड इस पर सहमत हो गए हैं और इसे मंडेला कप नाम दिया गया है. भारतीय टीम 28 मार्च को दक्षिण अफ्रीका रवाना होगी. सचिन तेंदुलकर की जगह कर्नाटक के रोबिन उथप्पा को दक्षिण अफ्रीका भेजे जाने की संभावना है. यह टी–20 मैच अंतरराष्ट्रीय वांडरर्स मैदान पर खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका की टीम भी न्यूजीलैंड में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलकर स्वदेश पहुंचेगी.

# ब्रॉड का दोहरा शतक

क्रिस ब्रॉड 200 वन डे मैचों में मैच रेफरी की भूमिका निभाने वाले दूसरे आईसीसी अधिकारी बन गए. उन्होंने आस्ट्रेलिया और श्रीलंका के ख़िलाफ़ ट्राई सीरीज के बेस्ट ऑफ थ्री फाइनल्स के पहले मुक़ाबले में उतरने के साथ ही यह उपलब्धि हासिल की. इंग्लैंड के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज़ ने मैच रेफरी के रूप में अपनी शुरुआत 2004 में न्यूजीलैंड एवं पाकिस्तान के बीच डुनेडिन वन डे मैच के साथ की थी. क्रिस श्रीलंका के रंजन मदुगुले के बाद 200 या इससे अधिक मैचों में रेफरी की भूमिका निभाने वाले दूसरे अधिकारी हैं. आईसीसी के बयान के मुताबिक़, ब्रॉड ने 200 वन डे मैचों के अलावा 51 टेस्ट मैचों में भी रेफरी की भूमिका निभाई. वह सर्वाधिक टेस्ट मैचों में अधिकारी की भूमिका निभाने वाले मैच रेफरियों की सूची में मदुगुले (132 टेस्ट) एवं क्लाइव लॉयड (53 टेस्ट) के बाद तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 41 टी–20 मैचों में भी यह भूमिका निभाई. इस सूची में वह मदुगुले (46) के बाद दूसरे स्थान पर हैं. ब्रॉड ने कहा, मेरे पास ख़ुश होने का एक अतिरिक्त कारण है, आठ साल पहले मेरे करियर की शुरुआत के बाद से 1180 वन डे मैच खेले गए. ब्रॉड ने कहा कि मैच रेफरी के रूप में उनका सबसे यादगार वन डे 2006 का वांडरर्स का मैच था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने एक गेंद और एक विकेट शेष रहते आस्ट्रेलिया के 434 रनों का लक्ष्य हासिल किया था.

# महिला मुक्केबाज़ों के लिए बदले नियम

इस साल लंदन में होने वाले ओलंपिक खेलों के दौरान महिला मुक्केबाज़ों को स्कर्ट पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ (एआईबीए) ने यह घोषणा की है. स्कर्ट अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर एआईबीए को महिला मुक्केबाज़ों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसके तकनीकी और प्रतियोगिता नियमों में बदलाव देखने को मिला है, जिसे संघ की वेबसाइट पर दिया जा चुका है. एआईबीए ने कहा कि महिलाएं अपनी पसंद के अनुरूप शॉर्ट या स्कर्ट कुछ भी पहन सकती हैं. नए निर्देशों में कहा गया है कि एआईबीए से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रतियोगिता में महिला मुक्केबाज़ों को लाल या नीले रंग की बनियान वेस्ट एवं अपनी पसंद के हिसाब से शॉर्ट या स्कर्ट पहननी होगी.

# विश्व कप कबड्डी पर भारत का क़ब्ज़ा

भारत ने हाल में प्रथम महिला विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता में अपना परचम लहराते हुए खिताब पर क़ब्ज़ा जमाया. रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने ईरान की टीम को 25–19 से मात दी. जापान और एशियाड रजत पदक विजेता थाईलैंड को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा. सेमी फाइनल में भारत ने जापान को 59–20 और ईरान ने थाईलैंड को 45–26 से हराकर खिताबी मुक़ाबले में प्रवेश किया था. फाइनल मुक़ाबला काफी रोमांचक रहा. ग्वांग्झू एशियाड खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम ने पूरे मैच में दो लोना और दो बोनस अंक हासिल किए. जवाब में ईरान ने छह बोनस अंक तो जुटाए, लेकिन लोना न मिलने का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा. भारत की कप्तान स्टार रेडर ममता पुजारी निर्णायक मुक़ाबले में भी छाई रहीं. सेमी फाइनल में जापान के ख़िलाफ़ 19 अंक बटोरने वाली ममता का जवाब ईरानी टीम के पास नहीं था. ममता ने आठ महत्वपूर्ण अंक जुटाए. उप कप्तान दीपिका हेनरी जोसेफ से उन्हें पूरा सहयोग मिला. प्रियंका नेगी ने डिफेंस में अपनी भूमिका बख़ूबी निभाई, जिससे मध्यांतर तक भारत ने 19–11 की बढ़त हासिल कर ली. दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने रक्षात्मक रवैया अपनाया. भारतीयों को रक्षात्मक होते देखकर ईरान की लंबी कद की रेडर गजला ने ज़बरदस्त आक्रमण किया और लगातार चार अंक बटोर कर अपनी टीम को वापसी दिलाने की कोशिश की, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और भारत को जीत हासिल हो गई.

# छोटा टायसन सुरंजय

छोटा टायसन के नाम से मशहूर भारतीय मुक्केबाज़ एम सुरंजय सिंह (52 किग्रा) अप्रैल में होने वाले ओलंपिक क्वॉलीफायर में लंदन ओलंपिक–2012 का टिकट कटाने के अंतिम मौक़े को हाथ से नहीं गंवाना चाहते और इसके लिए उन्हें आक्रामकता अपनाने से भी कोई गुरेज नहीं है. 5 से 12 अप्रैल तक कजाकिस्तान के अस्ताना में होने वाले एशियाई महाद्वीपीय ओलंपिक क्वॉलीफाइंग टूर्नामेंट में 52 किग्रा वर्ग में चार मुक्केबाज़ों को ओलंपिक कोटा मिलेगा. सुरंजय की भी निगाहें कांस्य पदक हासिल कर लंदन ओलंपिक के लिए क्वॉलीफाई करने पर लगी हैं. पूर्व एशियाई चैंपियन सुरंजय ने कहा कि हर कोई ओलंपिक कोटा हासिल करने की कोशिश में है और मैं भी वही करना चाहता हूं, इसलिए मेरे लिए सबसे पहला क़दम ओलंपिक क्वॉलीफायर में कांस्य पदक हासिल करना होगा. सेमी फाइनल में पहुंचने से मुझे कोटा मिल जाएगा.

# आमिर का अपील से इंकार

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज़ मोहम्मद आमिर स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण में अपनी भूमिका के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध को चुनौती नहीं देंगे. आमिर ने अपनी वकील साजिदा मलिक के ज़रिए आईसीसी को लिखित में सूचित किया है कि खेल पंचाट में अपील करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है. आईसीसी ने इसकी पुष्टि की कि आमिर ने लिखित रूप में कहा है कि वह प्रतिबंध के ख़िलाफ़ खेल पंचाट में अपील नहीं करेंगे.

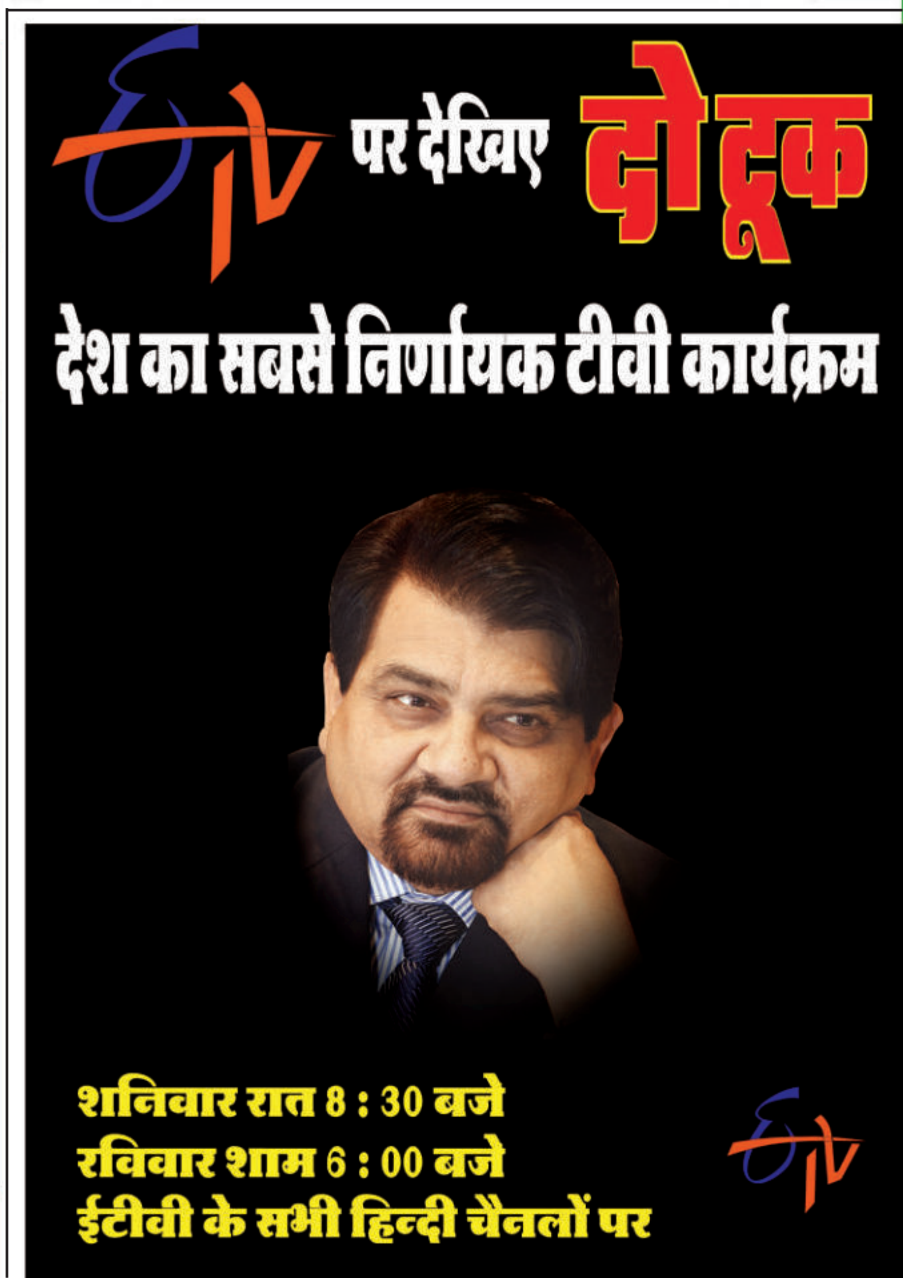

डायरेक्टर साजिद ख़ान के इस फ़ैसले के कई कारण हैं. पहले तो वह फिर से एक इतिहास बनाना चाहते हैं.

# हिम्मतवाला की रीमेक में अजय देवगन

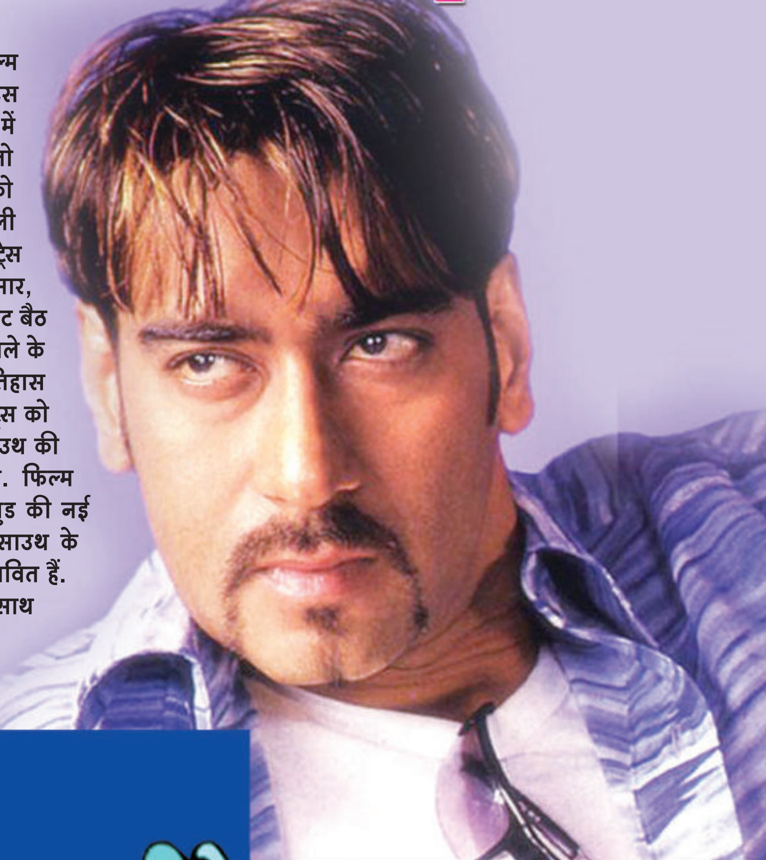

बॉलीवुड फिल्म मेकर साजिद ख़ान फिल्म हिम्मतवाला की रीमेक बना रहे हैं. इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में हैं. जहां तक बात फिल्म की हीरोईन की है तो इस फिल्म में साजिद किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को कास्ट नहीं कर रहे हैं. साजिद ने अपनी अगली फिल्म के लिए साउथ इंडियन फिल्म की एक्ट्रेस को कास्ट करने का मन बनाया है. उनके अनुसार, इस रोल के लिए साउथ की ही कोई एक्ट्रेस फिट बैठ सकती है. डायरेक्टर साजिद ख़ान के इस फ़ैसले के कई कारण हैं. पहले तो वह फिर से एक इतिहास बनाना चाहते हैं. वह साउथ की एक हिट एक्ट्रेस को लेना चाहते हैं, इसकी मूल फिल्म के लिए साउथ की सुपरस्टार रही श्रीदेवी को लिया गया था. फिल्म हिम्मतवाला के हिट होते ही श्रीदेवी बॉलीवुड की नई सनसनी बन गई थीं. इसके अलावा वह साउथ के कलाकारों के प्रोफेशनलिज्म से भी बहुत प्रभावित हैं. हाल में साजिद ने हाउसफुल 2 में असिन के साथ काम किया है और उनका यह विचार उनके साथ काम करने के बाद ही बना है.

# चित्रांगदा उत्साहित

**मुंबई में अकेली रहती हैं. वह कहती हैं कि घर और करियर दोनों संभालना आसान नहीं है. उनके पति ज्योति अपने खेल के सिलसिले में साल में 30 हफ्ते तो बाहर ही रहते हैं, जबकि उनका बेटा उनके माता-पिता के साथ रहता है. चित्रांगदा मानती हैं कि इंडस्ट्री सेफ नहीं है. हालांकि उन्हें अभी तक इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा. या हो सकता है कि मैं इस तरह की किसी बात को समझ ही नहीं पाई. चित्रांगदा की आने वाली फिल्म जोकर और इंकार है.**

चित्रांगदा सिंह ने कुछ ही फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी ख़ास बात यह है कि छोटी सी भूमिका में भी वह अपनी पहचान छोड़ जाती हैं. चित्रांगदा ने अपनी शुरुआती फिल्म हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के तुरंत बाद गोल्फर ज्योति रंधावा से शादी कर ली थी. चित्रांगदा मानती हैं कि भले ही उनका करियर दूसरों की तरह आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इस बात से चह ख़ुश हैं कि वह सेटल हैं. शादी सिक्योरिटी देती है और कम से कम एक तरफ़ से तो वह सिक्योर हैं. उन्हें फिल्मों में काम करना पसंद है. हालांकि फिल्मों से ज़्यादा उन्हें विज्ञापन के ऑफर मिलते हैं.

वह मुंबई में अकेली रहती हैं. वह कहती हैं कि घर और करियर दोनों संभालना आसान नहीं है. उनके पति ज्योति अपने खेल के सिलसिले में साल में 30 हफ्ते तो बाहर ही रहते हैं, जबकि उनका बेटा उनके माता-पिता के साथ रहता है. चित्रांगदा मानती हैं कि इंडस्ट्री सेफ नहीं है. हालांकि उन्हें अभी तक इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा. या हो सकता है कि मैं इस तरह की किसी बात को समझ ही नहीं पाई. चित्रांगदा की आने वाली फिल्म जोकर और इंकार है. फिल्म जोकर में जहां चित्रांगदा सिंह आइटम डांस करने वाली हैं, वहीं फिल्म इंकार यौन उत्पीड़न पर आधारित है. निर्देशक सुधीर मिश्रा की आने वाली फिल्म इंकार में चित्रांगदा अभिनेता अर्जुन रामपाल के साथ नज़र आएंगी. फिल्म में चित्रांगदा एक कॉरपोरेट महिला की भूमिका में हैं, जिसे कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है. चित्रांगदा को फिल्म इंकार से बहुत उम्मीदें हैं.

# मेरिल को ऑस्कर अवॉर्ड मिला

किसी फिल्म कलाकार को 17 बार ऑस्कर पुरस्कार मिले तो यह वाक़ई हैरत की बात होगी. लेकिन यह सच है कि 62 वर्ष की हॉलीवुड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप को पिछले दिनों आयरन लेडी के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला. 17 ऑस्कर अवॉर्ड्स में कई उन्हें 40 और 50 की उम्र के बाद मिले. एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा 17 बार नामांकित हुई स्ट्रीप ने फिल्म द आयरन लेडी में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के किरदार के लिए पिछले 30 सालों में अपना पहला और कुल तीसरा ऑस्कर जीता. मेरिल इससे पहले 1979 में फिल्म क्रमेर वर्सेज क्रमेर और 1982 में सोफिज च्वायस के लिए ऑस्कर जीत चुकी हैं. स्ट्रीप ने पुरस्कार ग्रहण करते हुए कहा, हे भगवान! बहुत-बहुत शुक्रिया. जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे लगा कि आधा अमेरिका सोच रहा होगा, ओह, एक बार फिर यह?

**एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा 17 बार नामांकित हुई स्ट्रीप ने फिल्म द आयरन लेडी में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के किरदार के लिए पिछले 30 सालों में अपना पहला और कुल तीसरा ऑस्कर जीता. मेरिल इससे पहले 1979 में फिल्म क्रमेर वर्सेज क्रमेर और 1982 में सोफिज च्वायस के लिए ऑस्कर जीत चुकी हैं.**

# शेट्टी बहनें एड फिल्मों में

बॉलीवुड में परिवारीजनों का साथ-साथ रील लाइफ में काम करना कोई नई बात नहीं है. बॉलीवुड की हॉट शेट्टी सिस्टर्स एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन शमिता शेट्टी बहुत जल्द एक विज्ञापन में एक साथ नज़र आएंगी. दोनों बहनें इससे पहले फिल्म फरेब में साथ नज़र आई थीं. इस बारे में शिल्पा शेट्टी ने ट्विटर पर लिखा है कि बहन शमिता के साथ विज्ञापन की शूटिंग करना बहुत उत्साहजनक है. उन्होंने यह भी लिखा है कि वह अभी नहीं बता सकती कि कौन से ब्रांड का विज्ञापन वह शमिता के साथ कर रहीं हैं. शिल्पा, आर सारथ की आने वाली फिल्म द डिजायर में मुख्य किरदार निभा रही हैं. वह मां बनने वाली हैं और फ़िलहाल वह अपने पहले बच्चे के जन्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है. हालांकि शिल्पा बॉलीवुड की हॉटेस्ट अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, वहीं उनकी बहन ने कुछेक गिनी चुनी फिल्मों में काम किया है, जो नहीं चलीं.

**चौथी दुनिया ब्यूरो**
feedback@chauthiduniya.com

## फिल्म प्रीव्यू

### एजेंट विनोद

एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म एजेंट विनोद ने सैफ़ अली ख़ान का काफ़ी समय लिया. यह काफ़ी बड़े बजट की फिल्म है. यह फिल्म सौ करोड़ रुपये की लागत से बनी है. फिल्म के प्रोमो पहले से ही दर्शकों में उत्सुकता जगा रहे हैं. इस फिल्म की कहानी एजेंट विनोद के इर्दगिर्द घूमती है, जो कई देशों द्वारा खेले जा रहे गेम से भली-भांति परिचित है. विनोद (सैफ़ अली ख़ान) के काम करने का अंदाज़ अलग है. वह पहले दरवाज़ा खोलता है फिर देखता है कि उसके पीछे क्या है. अपनी इसी आदत के चलते विनोद कई बार ख़तरों से घिरा है. उसके पास कई जानकारियां हैं. पूरी दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं श्रृंखलाबद्ध तरीक़े से घटती हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं लगता है. उज्बेकिस्तान में एक्स केजीबी ऑफिसर को टॉर्चर करने के बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है. केपटाउन में इस ऑफिसर की मौत के बारे बिज़नेस टॉयकून्स बात कर रहे हैं.

उनका मानना है कि केजीबी ऑफिसर के पास न्यूक्लियर बम के सारे राज़ थे. मॉस्को में एक इंडियन सीक्रेट एजेंट का राज़ खुल जाता है और उसे गोली मार दी जाती है, क्योंकि वह कोड मैसेज भारत भेज रहा था. भारत में रॉ के हेड के हाथ अधूरा मैसेज लगता है, जिसमें 242 नंबर रहता है. फिल्म में कई दिलचस्प मोड़ सामने आते हैं. इस फिल्म में पुराने और नये स्टाइल का सम्मिश्रण है और इसे अलग तरीक़े से बनाया गया है. फिल्म की मुख्य अभिनेत्री करीना कपूर का मुजरा काफ़ी ताज़गी देने वाला और रोमांचक है. यह फिल्म 23 मार्च को सिनेमा घरों में प्रदर्शित होगी.

**चौथी दुनिया ब्यूरो**
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 19 मार्च-25 मार्च 2012
www.chauthiduniya.com

## अब इंडिया बुल्स ने छीना

# नासिक के किसानों का पानी

**सिंचाई विभाग से क़रार होने से पहले तक यह संभावना थी कि इंडिया बुल्स का मनपा प्रशासन के साथ पानी आपूर्ति का क़रार हो जाएगा. इस प्लांट को मंज़ूरी दिए जाने के दौरान यह तय हुआ था कि सिंचाई विभाग द्वारा जो पानी दैनंदिन ज़रूरतों के लिए मनपा प्रशासन को उपलब्ध कराया जाता है, उससे निकलने वाले मलजल (दूषित पानी) को फिल्टर कर पुनः बिजली उत्पादन के लिए इंडिया बुल्स के पॉवर प्लांट को दिया जाएगा.**

प्रवीण महाजन

महाराष्ट्र में जहां एक ओर इंडिया बुल्स का जलवा बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर किसानों पर आफ़त आ रही है. इंडिया बुल्स अमरावती के किसानों के हक़ के पानी पर डाका डालने के बाद अब नासिक के खेतों के पानी पर भी डाका डालने जा रही है. यह सब सरकारी स्तर पर हो रहा है. सरकार कहती ज़रूर है कि पानी पर पहला हक़ किसानों और नागरिकों का है, लेकिन उसकी कथनी-करनी में ज़मीन और आसमान का अंतर है. इंडिया बुल्स के नासिक के निकट स्थापित हो रहे पॉवर प्लांट को पानी मुहैया कराने के लिए सिंचाई विभाग के साथ क़रार भी कर लिया है. सिंचाई विभाग को यह क़रार करने पर जहां 72 करोड़ रुपये मिले हैं, वहीं इससे नासिक महानगर पालिका को करारा झटका लगा है. इसकी वजह यह है कि इंडिया बुल्स के पॉवर प्लांट को पहले पानी मुहैया कराने का क़रार मनपा से होना तय हुआ था और शहर से निकलने वाले निस्तारित पानी को पुनः बिजली उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाना था. मगर इंडिया बुल्स के मनपा को ठेंगा दिखाकर सिंचाई विभाग से क़रार कर लिए जाने से निस्तारित पानी के पुनः प्रयोग की योजना भी खटाई में पड़ गई है.

उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसंबर माह में इंडिया बुल्स कंपनी उस समय चर्चा में आई थी, जब राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री छगन भुजबल के भुजबल फाउंडेशन को करोड़ों रुपये का चंदा देने के मामले का ख़ुलासा हुआ था. भुजबल के फाउंडेशन को जो चंदा दिया गया था, वह नासिक में 2700 मेगावॉट के पॉवर प्लांट को स्थापित करने में सहयोग देने के बदले में दिया गया था. हालांकि भुजबल ने बताया था कि यह चंदा नासिक फेस्टिवल के नाम पर लिया गया था. मगर इस मामले के उजागर होने के पहले भी इंडिया बुल्स राज्य में तब भी चर्चा में थी, जब अमरावती ज़िले के किसानों ने अपने खेतों के हक़ के पानी पर सोफिया पॉवर प्लांट द्वारा पी जाने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और उग्र आंदोलन किया था. मामला अदालत में भी गया था और अदालत में सुनवाई के लिए निलंबित है. अमरावती का खेल अब नासिक और अहमदनगर में इंडिया बुल्स द्वारा सिंचाई विभाग की मिलीभगत से खेला जाना है. इससे आने वाले दिनों में नासिक के आसपास के किसानों को अपनी फ़सलों की सिंचाई के लिए पानी की बूंद-बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है. इसकी वजह यह है कि नासिक मनपा को ठेंगा दिखाकर इंडिया बुल्स ने सिंचाई विभाग के साथ जो क़रार किया है, उसको पूरा करने के लिए सिंचाई विभाग को नासिक और अहमदनगर ज़िले के तक़रीबन 10 हज़ार हेक्टेयर सिंचन क्षेत्र में कटौती किया जाना तय माना जा रहा है. इंडिया बुल्स ने इस क्षेत्र को पुनर्स्थापना हेतु लिए जाने के एवज में सिंचाई विभाग को 72 करोड़ 65 लाख रुपये का भुगतान किया है.

विशेष बात यह है कि छगन भुजबल नासिक के पालकमंत्री हैं और इंडिया बुल्स के दो चरणों में स्थापित होने वाले पॉवर प्लांट को लाने का पूरा श्रेय भी वही लेते हैं. सिंचाई विभाग से क़रार होने के पहले तक यह संभावना थी कि इंडिया बुल्स का मनपा प्रशासन के साथ पानी आपूर्ति का क़रार हो जाएगा. इस प्लांट को मंज़ूरी दिए जाने के दौरान यह तय हुआ था कि सिंचाई विभाग द्वारा जो पानी दैनंदिन ज़रूरतों के लिए मनपा प्रशासन को उपलब्ध कराया जाता है, उससे निकलने वाले मलजल (दूषित पानी) को फिल्टर कर पुनः बिजली उत्पादन के लिए इंडिया बुल्स के पॉवर प्लांट को दिया जाएगा. प्लांट के लिए पानी का आरक्षण किए जाने की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भी कंपनी ने मनपा प्रशासन से पिछले तीन साल में क़रार करने में कोई रुचि नहीं दिखाई. उलटे मनपा प्रशासन उससे संपर्क कर पानी उपलब्ध कराने को तैयार था. जिस मलजल का उपयोग इंडिया बुल्स के पॉवर प्लांट में किया जाना था, उसकी रॉयल्टी पर सिंचाई विभाग एवं मनपा प्रशासन ने हक़ जताया था. इस मामले में उच्चाधिकार समिति ने हस्तक्षेप करके अपना फ़ैसला सिंचाई विभाग के पक्ष में दिया. इससे रॉयल्टी पाने का सिंचाई विभाग का रास्ता साफ़ हो गया. इस पर इंडिया बुल्स के प्रबंधन का मानना था कि रॉयल्टी भुगतान की प्रक्रिया से उसके लिए आरक्षित पानी पर विपरीत असर पड़ सकता है, जिसके कारण उसने सिंचाई विभाग से ही क़रार करने का मन बना लिया. सिंचाई विभाग से जो क़रार इंडिया बुल्स ने किया है, उसमें मनपा का कहीं भी किसी भी संदर्भ में कोई ज़िक्र तक नहीं किया गया है. आख़िर मनपा प्रशासन की क्या भूमिका रहेगी? इसका साफ़ अर्थ यह निकलता है कि इंडिया बुल्स ने मनपा प्रशासन को अपने रास्ते से पूरी तरह हटा दिया है. इसका कारण अब तक कंपनी द्वारा नहीं बताया गया है कि आख़िर मनपा को क़रार से बाहर करने का राजनीतिक कारण है या आर्थिक या अन्य कोई.

बहरहाल, दो चरणों में साकार होने वाले इंडिया बुल्स के नासिक पॉवर प्लांट के पहले चरण के लिए 43.80 और दूसरे चरण के 36.50 लाख घनमीटर पुनः उपयोग के लिए पानी दिया जाना है. अब यदि क़रार पर अमल होता है तो गोदावरी नहर से 9,749 हेक्टेयर खेती को सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी पर कटौती किया जाना है. इसका मतलब यह है कि सिंचन क्षेत्र में पानी की कटौती के लिए पहले चरण के लिए 26.36 करोड़ रुपये और दूसरे चरण के लिए 46.29 करोड़ मिलाकर कुल 72 करोड़ 65 लाख रुपये इंडिया बुल्स ने सिंचाई विभाग के खाते में अग्रिम रूप से जमा कर दिए हैं. इसी तरह प्रारंभ के दो माह की पानीपट्टी के लिए 78 लाख रुपये महाराष्ट्र जलसंपत्ति नियामक निर्णय के आधार पर पहले से ही भुगतान कंपनी द्वारा किया जा चुका है. हालांकि वर्तमान में 10 रुपये 70 पैसे प्रति 10 हज़ार लीटर की दर से पानीपट्टी का भुगतान किया गया है, लेकिन कंपनी ने निस्तारित पानी के पुनः उपयोग के लिए दिए जाने के कारण जलसंपत्ति प्राधिकरण से दर कम करने का अनुरोध किया है. इस मामले में प्राधिकरण का निर्णय प्रलंबित है और इसी दरम्यान मनपा प्रशासन ने रॉयल्टी में कुछ हिस्सा दिलाने के लिए प्राधिकरण के सामने अपना दावा पेश कर दिया है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि कंपनी ने सिंचाई विभाग से सीधे क़रार करने का वह समय चुना, जब मनपा प्रशासन चुनाव में व्यस्त था. इससे क़रार किए जाने के दौरान इंडिया बुल्स को मनपा प्रशासन से किसी तरह का विरोध नहीं करना पड़ा. चुनाव संपन्न होने के बाद जब क़रार के संबंध में पता चला तो मनपा प्रशासन की आंख खुली. वहीं पानी का मोल पहचानें, की सीख जनता को देने वाले सिंचाई विभाग ने इंडिया बुल्स के पॉवर प्लांट को हरी झंडी दिखा दी. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब सिंचाई विभाग ने नासिक मनपा प्रशासन की अनदेखी की है. इसके पहले भी शहर के आसपास पांच प्रकल्पों को पानी देने के मामले में मनपा प्रशासन को पूरी तरह किनारे किया गया है. इससे ऐसा लगता है कि इंडिया बुल्स के पॉवर प्लांट को पानी आपूर्ति का मामला सैद्धांतिक या नीतिगत कम और राजनीतिक अधिक लगता है.

feedback@chauthiduniya.com

## किसान पिसेंगे

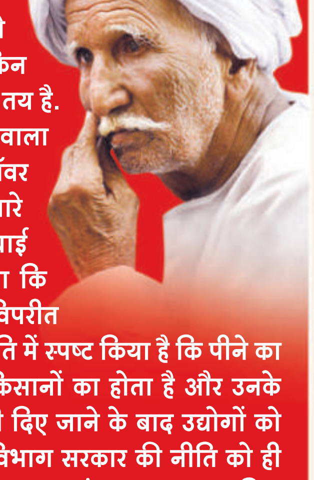

इंडिया बुल्स पॉवर प्लांट को पानी आपूर्ति को लेकर सिंचाई विभाग से क़रार चाहे जिस वजह से हुआ हो, लेकिन इसमें बेचारे किसानों पर आफ़त आनी तय है. आख़िर 9,749 हेक्टर क्षेत्र को मिलने वाला सिंचाई का पानी जब इंडिया बुल्स के पॉवर प्लांट को दिया जाएगा तो किसान बेचारे क्या करेंगे? क़रार करने से पूर्व सिंचाई विभाग को यह तय करना चाहिए था कि किसानों के हित पर किसी तरह का विपरीत प्रभाव न पड़े. सरकार ने भी अपनी नीति में स्पष्ट किया है कि पीने का पानी दिए जाने के बाद पहला हक़ किसानों का होता है और उनके खेतों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी दिए जाने के बाद उद्योगों को दिया जाएगा. मगर यहां तो सिंचाई विभाग सरकार की नीति को ही उलटता दिखाई दे रहा है. सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन यहां वह तमाशबीन बनी नज़र आ रही है. अब इस क़रार का कारण राजनीति एवं नीतिगत जो भी हो, लेकिन यहां सबसे अधिक नुक़सान किसानों को होने वाला है. यदि यह क़रार राजनीतिक बिसात पर किया गया है, तो बेचारे किसान राजनीतिक लड़ाई में पिस जाएंगे. इसके कारण नासिक में भी आने वाले समय पर यदि मावल और अमरावती जैसा उग्र किसान आंदोलन हो तो आश्चर्य की बात नहीं होगी. इसलिए सरकार को नासिक को दूसरा मावल और अमरावती बनने से रोकने के लिए किसानों एवं कृषि के हितों की रक्षा के लिए स्वतः आगे आना चाहिए. विशेषकर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को किसानों की रक्षा राजनीति से ऊपर उठकर करनी चाहिए.

पहले तो भाई देश में मौजूद कालेधन को ही सामने लाने की ज़रूरत है, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए और जब देश में कालाधन नहीं होगा तो वह विदेश क्यों भेजा जाएगा.

इन नियुक्तियों को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने ग़ैर क़ानूनी घोषित कर दिया है. मज़े की बात यह है कि इस मामले की भनक तक मुख्यमंत्री को नहीं लगने दी गई.



# महाराष्ट्र हलचल

उपराजधानी नागपुर में निर्माणाधीन मिहान में आईटी कंपनी इंफोसिस के साथ क़रार होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक, नितिन राऊत, अन्न एवं नागरी आपूर्ति मंत्री अनिल देशमुख, इंफोसिस के सीईओ एसडी शिबुलाल, एमएडीसी के उपाध्यक्ष यूपीएस मदान, कंपनी के उपाध्यक्ष चंद्रकेतु झा, पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे, राज्यमंत्री राजेंद्र मुलक.

बुलढाणा ज़िले के खामगांव में सकल जैन समाज द्वारा आचार्य देव विजयरत्न सुंदर सुरीश्वरजी महाराज के आयोजित प्रवचन के दौरान निकाली गई रैली और प्रवचनमाला का दीप प्रज्जवलित कर उद्‌घाटन करते विधायक दिलीप कुमार सानंदा, नरेंद्र सकलेचा व अन्य.

अकोला महानगर पालिका के लिए महापौर और उपमहापौर चुनाव के लिए कांग्रेस-राकांपा के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की नेताओं के साथ बैठक में चर्चा करते हुए.

केंद्र सरकार द्वारा कपास निर्यात पर पाबंदी लगाने की घोषणा से अमरावती ज़िले की वरुड तहसील में आंदोलन करते कपास उत्पादक.

चंद्रपुर ज़िले में पंचायत समिति शिक्षण विभाग, सिंदेवाही द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के तहत आयोजित एक सुर एक ताल कार्यक्रम को संबोधित करते सभापति अरविंद राऊत एवं अन्य मंचासीन अतिथिगण.

यवतमाल ज़िले के धानोरा में केंद्रीय स्कूल में आयोजित शिक्षणोत्सव समारोह का फ़ीता काटकर उद्‌घाटन करती सरपंच वर्षा ताई सुरकार एवं उनके साथ अन्य शिक्षकगण.

गोंदिया ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक शाखा अर्जुनी/मोरगांव में हुए घोटाले के गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किए जाने के दौरान हज़ारों की संख्या में जमा आक्रोशित नागरिक.

सेवाग्राम स्थित महात्मा गांधी आश्रम में आश्रम के पदाधिकारियों और अपने समर्थकों के साथ चरखे पर कपास कातते हुए प्रख्यात मानस प्रवचनकार मुरारी बापू.

# बोगस डॉक्टरों पर नकेल कसने की तैयारी

## पंजीयन नहीं तो घर बैठो

डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन जिस तरह छोटे शहरों और गांवों में बोगस डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे ग्रामीण स्वास्थ्य के विषय में चिंताएं बढ़ा दी हैं. इन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन आगे आया है. डॉक्टरों को व्यवसाय की अनुमति देने वाली इस संस्था के तहत जिन डॉक्टरों ने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया है, उन पर घर बैठने की नौबत आ सकती है. ग्रामीण क्षेत्रों में बोगस डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है. स्वास्थ्य के संबंध में लोगों को अधिक जानकारी नहीं होने का फ़ायदा बोगस डॉक्टर उठा रहे हैं. ज़रूरत नहीं होने पर भी मरीज़ को इंजेक्शन और सलाइन लगाना ग्रामीण क्षेत्रों में आम बात हो गई है. कहीं-कहीं तो एक ही मरीज़ के दोनों हाथों में सलाइन लगाई जाती है. इसके लिए ग्रामीणों से मोटी रक़म वसूली जाती है. ज़रूरत नहीं होने पर भी एक्स-रे, सीटी स्कैन या एमआरआई जैसे महंगे टेस्ट करवाए जाते हैं. इन डॉक्टरों की टेस्ट करने वाली पैथलैब से मिलीभगत होती है और टेस्ट की राशि में उनका कमीशन बंधा होता है. ऐसे में बोगस डॉक्टर मरीज़ों को लूटने का काम कर रहे हैं. जानकारों की मानें तो इनमें से कई डॉक्टर बड़े-बड़े डॉक्टरों के कम्पाउंडर रह चुके हैं. कुछ फार्मासिस्ट ही दवाखाना खोलकर बैठे हैं. ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं और डॉक्टरों के अभाव में लोग निजी दवाख़ानों में जाते हैं. हालांकि बोगस डॉक्टरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने और उन्हें जेल में डालने का प्रावधान है, लेकिन प्रशासन इस दिशा में क़दम नहीं उठाता. यही कारण है कि कुकुरमुत्ते की तरह गांवों और तहसीलों में दवाखाने खुलते जा रहे हैं.

**विदर्भ में अपंजीकृत डॉक्टर**

| | |
|---|---|
| नागपुर | 1398 |
| अमरावती | 750 |
| वर्धा | 183 |
| अकोला | 574 |
| भंडारा | 333 |
| बुलढाणा | 462 |
| चंद्रपुर | 208 |
| गढ़चिरोली | 47 |
| गोंदिया | 101 |
| वाशिम | 144 |
| यवतमाल | 509 |

### अब नकेल कसेगी

किसी भी डॉक्टर को व्यवसाय शुरू करने के लिए महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के पास लाइसेंस का पंजीयन कराना अनिवार्य है. साथ ही हर पांच वर्ष में इस लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है, लेकिन बताया जाता है कि राज्य में ऐसे हज़ारों डॉक्टर हैं, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है. इसे देखते हुए महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने यह निर्णय लिया है कि जिन डॉक्टरों ने अब तक इस संबंध में कार्यवाही नहीं की है, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही हर तहसील स्तर पर बोगस डॉक्टरों से निपटने के लिए विशेष मुहिम शुरू की जाएगी.

### आयुर्वेद-यूनानी डॉक्टरों ने 1961 से पंजीयन नहीं कराया

महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट 1961 की धारा 23 (ए) के तहत सभी आयुर्वेद एवं यूनानी डॉक्टरों को भी महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के तहत पंजीयन करवाना अनिवार्य होता है, लेकिन इन डॉक्टरों ने वर्ष 1961 से अब तक पंजीयन ही नहीं कराया. काउंसिल का गठन होने के पूर्व बोर्ड ऑफ फैकल्टी के ज़रिये पंजीयन करवाया जाता था. वर्ष 1981 के बाद काउंसिल का गठन किया गया. आयुर्वेद एवं यूनानी डॉक्टरों द्वारा वर्ष 1961 से अपने व्यवसाय का पंजीयन नहीं कराया जाना, काफ़ी गंभीर स्थिति को दर्शाता है. कई बोगस डॉक्टर आयुर्वेद एवं यूनानी डॉक्टरों का बोर्ड लगाकर ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसमें भी बीएएमएस की डिग्री का बोर्ड लगाकर प्रैक्टिस करने वालों की संख्या सबसे अधिक है. यह सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है. ऐसे कई मामले हैं, जिनमें सही उपचार नहीं मिलने के कारण मरीज़ की मौत तक हो गई है. इसी संबंध में सतर्क होते हुए काउंसिल ने तय किया है कि राज्य में बोगस डॉक्टरों की खोज कर उन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी. जानकारों की मानें तो काउंसिल अकेले बोगस डॉक्टरों के नेटवर्क से नहीं लड़ सकता. ऐसे में उसे हर ज़िले के प्रशासन और पुलिस की मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन हालत यह है कि प्रशासन इसे गंभीरता से ही नहीं ले रहा है. इसी कारण काउंसिल की ओर से क़दम उठाने के बाद भी उसके सही परिणाम नहीं मिल पाते.

### बोगस डॉक्टर नागपुर में अधिक हैं

आंकड़ों पर ग़ौर करें तो विदर्भ में ऐसे 4709 डॉक्टर हैं, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से अपने लाइसेंस का पंजीयन काउंसिल के पास नहीं कराया है. इसमें भी नागपुर ज़िले के डॉक्टरों की संख्या सर्वाधिक है. यहां 1398 डॉक्टर ऐसे हैं, जो बिना पंजीयन के डॉक्टरी कर रहे हैं. दूसरे स्थान पर अमरावती ज़िला है. यहां 750 डॉक्टरों ने लाइसेंस का पंजीयन नहीं कराया है. विदर्भ में हज़ारों डॉक्टर बिना पंजीयन के व्यवसाय कर रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में मरीज़ों की जान पर बन आती है. ऐसे में ज़रूरी है कि राज्य सरकार कठोर क़दम उठाकर बोगस डॉक्टरों पर नकेल कसे.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

## ये क्या हो रहा है...

# काला हवाला

देश का कालाधन विदेशों में होने पर ख़ूब चर्चा हो रही है. राजनीतिक बतंगड़बाज़ी हो रही है. आंदोलन हो रहे हैं, सरकार मुस्करा रही है और हमारे नेता कालेधन को राजनीतिक मोहरा बनाकर ख़ूब आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. लेकिन जब जो सत्ता में रहता है, वह इस मुद्दे को अपने वादों-आश्वासनों के पिटारे में बंद करके ही रखना चाहता है. एक समय काले के भाई हवाले से भी नेता घबराते थे. एक डायरी में हवाला के माध्यम से देश के नामी-गिरामी राजनीतिक हस्तियों को धन देने का मामला सामने आया था, लेकिन आज देश के अंदर ही कालेधन का हेर-फेर करने वाले व्यवसाय हवाला पर कोई नहीं बोलता है. कालेधन का देश के बाहर जाने का सबसे बड़ा मार्ग भी हवाला ही है. फिर भी इस पर सरकार रोक लगाने में नाकाम रही है. हवाला कारोबारियों को यदि कोई लूट भी लेता है तो उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखाई जाती है. जिसका पैसा जाता है वह इस ग़म को सहता है और अपने स्तर पर लुटेरे का पता लगाकर उससे रक़म वसूल करने की रणनीति पर काम करता या फिर लुटेरे को सबक़ सिखाने के लिए उसका गेम बजा देता है. मगर हवाला में हुई गड़बड़ी ग़बन आदि की शिकायत पुलिस से नहीं की जाती है. इसकी वजह यह बताई जाती है कि हवाला कारोबार ग़ैर क़ानूनी होने के बाद भी ईमानदारी से किया जाने वाला कारोबार है. हां, इसमें अधिकांश वही लोग शामिल होते हैं, जो आर्थिक कदाचार करने में माहिर होते हैं, क्योंकि इसमें दो नंबर के धन को सफ़ेद बनाने का काम किया जाता है. अब देखिए पिछले दिनों एक हवाला कारोबारी का कर्मचारी नागपुर के सर्राफ़ा बाज़ार से 20 लाख रुपये लेकर जा रहा था, जिसे कुछ बदमाशों ने रास्ते में पिस्तौल की नोंक पर लूट लिया. इस लूट की वारदात की शिकायत न हवाला कारोबारी ने और न उसके कर्मचारी ने पुलिस थाने में दर्ज कराना उचित समझा. इसका मतलब यह है कि हवाला कारोबारियों को पुलिस पर विश्वास नहीं है और पुलिस है कि इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेती है. पुलिस वालों का कहना है कि जब शिकायत दर्ज होगी तब कार्रवाई करेंगे. आख़िर पुलिस कमिश्नर सहित उपराजधानी में पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों की फ़ौज के होते हुए ये हो क्या रहा है? पुलिस इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? क्या उसे याद नहीं कि वर्ष 2008 में हवाला कारोबार में लखोटिया बंधुओं की किस तरह हत्या कर दी गई थी. अब फिर से हवाला कारोबारी के कर्मचारी से हवाला के 20 लाख रुपये लूटे जाने की घटना के बाद किसी बड़े धमाके की आशंका व्यक्त की जा रही है. अपने स्तर पर हवाला कारोबारी ज़रूर लुटेरे का पता लगाकर उसका गेम बजाने का प्रयास करने की चर्चा बाज़ार में है यानी उपराजधानी में आगे हवाला कारोबार में गैंगवार होने की आशंकाएं मंडरा रही हैं. अब जब देश के अंदर कालेधन का अरबों का हवाला व्यवसाय संचालित है जिस पर अंकुश

लगाने में हमारी सरकारें, आयकर विभाग, पुलिस सहित अन्य एजेंसियां नाकाम हैं, वे भला विदेशों से कालाधन लाने की चिंता में क्यों पड़ेंगे. पहले तो भाई देश में मौजूद कालेधन को ही सामने लाने की ज़रूरत है, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए और जब देश में कालाधन नहीं होगा तो वह विदेश क्यों भेजा जाएगा. इसलिए कालेधन के हवाला कारोबार को रोकना ज़रूरी है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# कपास निर्यात पर पाबंदी से किसान परेशान

केंद्र सरकार द्वारा कपास निर्यात पर पाबंदी लगाने की घोषणा से राज्य के कपास उत्पादकों को करारा झटका लगा है. एक तो पहले से कपास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य कम है. ऊपर से निर्यात पर पाबंदी लगाए जाने से कपास के दाम आधे से भी कम हो गए हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कपास की मांग में तेज़ी बनी हुई है. पाबंदी की घोषणा के बाद राज्य में कपास का दाम घटकर 3000 रुपये से लेकर 2900 रुपये पर आ गया है. वहीं आज की स्थिति में राज्य के कपास उत्पादकों के पास अभी भी कपास की क़रीब 25 लाख गांठे पड़ी हुई हैं. इस तरह कपास के दामों में गिरावट आने से कपास उत्पादक किसानों को भारी नुक़सान उठाना पड़ रहा है. इससे किसानों में आक्रोश है. इस बार कपास उत्पादकों के लिहाज़ से प्रकृति का चक्र उल्टा घूमने से किसान पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मौसमी कपास की फ़सल नहीं ले पाए. इस बार कपास उत्पादन में 15 लाख गांठों की कमी दर्ज की गई. केंद्र सरकार के कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फ़ैसले से आगामी सीजन में कपास के उत्पादन में और कमी आने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं. कपास का उत्पादन कम होने और लागत बढ़ने से किसान को उपज का अधिक भाव मिलना चाहिए. कम से कम समर्थन मूल्य इतना होना चाहिए कि उसकी लागत तो निकले. लेकिन राज्य में एक तो कपास ख़रीदी में देरी और ऊपर से कम समर्थन मूल्य होने से किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर व्यापारियों को बेचनी पड़ती है. अब कपास निर्यात बंदी से व्यापारी भी कपास की क़ीमत आधी करके दे रहे हैं. व्यापारी किसी भी स्थिति में 3000-2800 रुपये से अधिक भाव देने को तैयार नहीं हैं. राज्य में इस पर कपास की खेती क़रीब 50 लाख हेक्टेयर में की गई है, जिसमें सबसे अधिक विदर्भ में यानी 28 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई की गई. इतनी अधिक कपास की खेती का कारण यह था कि पिछले साल कपास का भाव 7000 रुपये प्रति कुंतल तक था. इसके बावजूद कपास की पैदावार इस बार कम हुई. जिन कपास उत्पादकों ने इस आस में अपनी कपास व्यापारियों को अब तक यह सोचकर नहीं बेची थी कि भाव में वृद्धि होगी. उनके उत्पाद के भाव अच्छे मिलेंगे. मगर अब केंद्र सरकार के फ़ैसले के कारण उन्हें कपास कौड़ी के भाव में बेचना पड़ रहा है. बाज़ार के विश्लेषकों का कहना है कि राज्य में अब तक 225 लाख कुंतल कपास की ख़रीदी की गई है. बाज़ार में 45 लाख कुंतल कपास मौजूद है. इसके अलावा अभी भी 25 लाख कपास की गांठे उत्पादकों के घरों में मौजूद हैं.

### किसान संगठनों ने विरोध जताया

राज्य के किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस रद्द कर कपास निर्यात प्रतिबंध लगाने पर आक्रोश व्यक्त किया है. किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि विश्व बाज़ार में भारतीय कपास की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है. कपास का विश्व बाज़ार भारतीय कपास पर निर्भर है और उसकी मांग आज भी बनी हुई है. यह इस बात से ही पता चलता है कि 23 देशों की कपास की मांग को भारत पूरा करता है. कपास की निर्यात बंदी से विश्व बाज़ार में अपनी साख बनाने का अवसर भारत को गंवाना पड़ सकता है. इन स्थितियों में कपास निर्यात पर प्रतिबंध लगाना कहां तक उचित है. इसको लेकर राज्य में कई जगहों पर कपास उत्पादकों और किसान संगठनों चक्का जाम आंदोलन भी शुरू कर दिया है. किसान संगठनों का कहना है कि यह समझ से परे है कि केंद्र सरकार ने यह प्रतिबंध क्यों लगाया है? प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ख़ुद एक अर्थशास्त्री हैं. क्या उनको विश्व बाज़ार में कपास की स्थिति की समझ नहीं है. यह तो सरासर सरकार का किसान विरोधी क़दम है. यदि सरकार इस फ़ैसले को जल्द ही वापस नहीं लेती है तो राज्य में किसानों का आंदोलन और भड़क सकता है. इस बीच कृषि मंत्री शरद पवार ने स्पष्ट किया है कि कपास निर्यात पाबंदी का मुद्दा मंत्रियों के समूह के पास पुनर्विचार के लिए भेजा गया है. सरकार इस फ़ैसले की समीक्षा कर अंतिम निर्णय लेगी.

राजेश नामदेव
feedback@chauthiduniya.com

## हज़ारों करोड़ के गृह निर्माण प्रकल्प अधूरे

# महंगे क़र्ज़ ने रोका गृह प्रवेश

आलोक मिश्रा

यह ख़बर उन लोगों को ज़रूर चिंता में डाल सकती है, जिन्होंने अपना ख़ुद का घर ख़रीदने के लिए किसी गृह निर्माण स्कीम में बुकिंग की है. राज्य में वर्ष 2008 में कुल 2693 गृह निर्माण प्रकल्पों का भूमि पूजन कर काम शुरू किया गया था. इन प्रकल्पों को वर्ष 2012 में पूरा होना था. यह आश्वासन ख़ुद इससे जुड़े बिल्डरों ने ग्राहकों को दिया था, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इनमें से केवल 773 प्रकल्प ही पूरे हो पाए हैं, जबकि 1920 प्रकल्प अभी भी अधूरे हैं. अधूरे प्रकल्पों की सबसे अधिक संख्या मुंबई में है. यहां 43 फ़ीसदी प्रकल्प ऐसे हैं, जिन्हें पूरा होने में अभी और समय लगेगा. इसके बाद पुणे में 30 फ़ीसदी, नासिक में 28 फ़ीसदी और नागपुर में 20 फ़ीसदी गृह निर्माण प्रकल्प अधूरे हैं. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण महंगे हुए क़र्ज़ को बताया जा रहा है. ऐसे में साफ़ है कि वर्षों से अपने घर का सपना संजोए बैठे हज़ारों परिवारों को गृह प्रवेश के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा.

राज्य में शहरीकरण के कारण मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद आदि शहर तेज़ी से बढ़ रहे हैं. इसके कारण बड़ी संख्या में राज्य के गांवों और अन्य राज्यों से लोग नौकरी तथा अन्य व्यवसायों के लिए इन शहरों की ओर रुख़ कर रहे हैं. हर वर्ष इन शहरों की जनसंख्या में लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं. इनमें से अधिकतर लोग किराये के घरों में अपना बसेरा बनाते हैं. अच्छा वेतन मिलने के कारण हर व्यक्ति शहर में अपना ख़ुद का आशियाना बनाने की चाहत रखता है. इन शहरों में जगह की कमी के कारण यहां फ्लैट सिस्टम की संकल्पना तेज़ी से विकसित हो रही है. इसी कारण कई गृह निर्माण प्रकल्पों में बिल्डरों ने हज़ारों करोड़ रुपये का निवेश किया है. मुंबई और पुणे में इसकी संख्या सबसे अधिक है. इसके साथ-साथ नासिक, नागपुर और औरंगाबाद में भी फ्लैट सिस्टम की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन प्रोपर्टी कॉर्नर संस्था की ओर से देश के निर्माण उद्योग के समक्ष खड़ी समस्याओं के संबंध में जब सर्वेक्षण किया गया, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. संस्था की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2008 में राज्य में 2693 गृह निर्माण प्रकल्प शुरू किए गए. इन प्रकल्पों में फ्लैट बेचते समय संबंधित बिल्डरों ने ग्राहकों को वर्ष 2012 में इन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इनमें से केवल 773 ही पूरे हो पाए हैं, जबकि 1920 प्रकल्प अधूरे हैं. पिछले 4 वर्षों से प्रकल्प पूरा नहीं होने के कारण इनमें से कई प्रकल्पों के ग्राहकों ने बिल्डरों से पैसा वापस लेना शुरू कर दिया है. ऐसे में कई बिल्डर समूहों पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है.

> **शहरों में जगह की कमी के कारण यहां फ्लैट सिस्टम की संकल्पना तेज़ी से विकसित हो रही है. इसी कारण कई गृह निर्माण प्रकल्पों में बिल्डरों ने हज़ारों करोड़ रुपये का निवेश किया है. मुंबई और पुणे में इसकी संख्या सबसे अधिक है. इसके साथ-साथ नासिक, नागपुर और औरंगाबाद में भी फ्लैट सिस्टम की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन प्रोपर्टी कॉर्नर संस्था की ओर से देश के निर्माण उद्योग के समक्ष खड़ी समस्याओं के संबंध में जब सर्वेक्षण किया गया, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. संस्था की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2008 में राज्य में 2693 गृह निर्माण प्रकल्प शुरू किए गए.**

### महंगा क़र्ज़ कारण बना

संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रकल्पों के रुकने के पीछे का सबसे बड़ा कारण महंगा क़र्ज़ है. साथ ही लिए गए क़र्ज़ को वापस नहीं करना और कोर्ट में ज़मीनों को लेकर चल रहे मामले भी इन प्रकल्पों के पूरा नहीं होने का कारण है. अधूरे प्रकल्पों में सबसे अधिक संख्या टाउनशिप संकल्पना से बन रहे प्रकल्पों की है. कई स्थानों पर इनका निर्माण कार्य 40 से 70 फ़ीसदी तक पूरा हो चुका है. बिल्डर एसोसिएशन के एसएम मीरचंदानी ने बताया कि बिल्डर प्रकल्पों के लिए बैंकों से क़र्ज़ तो लेते ही हैं, उसके साथ-साथ मार्केट से भी अधिक ब्याज़ पर क़र्ज़ लेते हैं. इसके पीछे की उनकी सोच होती है कि जल्द से जल्द प्रकल्प को पूरा कर उसे बेचकर मुनाफ़ा कमाना, लेकिन पिछले तीन वर्षों से छाई मंदी और महंगाई के कारण उन्हें ग्राहक ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में उन्हें राशि की कमी का सामना करना पड़ता है. प्रकल्पों के अधूरे होने का यह सबसे बड़ा कारण है.

### कमज़ोर क़ानून

ऐसा नहीं है कि प्रकल्प अधूरा होने से केवल बिल्डर को ही नुक़सान होता है, बल्कि ग्राहक को आर्थिक नुक़सान के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है. जिन लोगों ने इन प्रकल्पों में फ्लैट की बुकिंग की है, उन्हें इसके लिए उठाए गए क़र्ज़ की मासिक क़िस्तें और घर का किराया, ऐसी दोतरफ़ा मार झेलनी पड़ रही है. जानकारों की मानें, तो इस संबंध में क़ानून कमज़ोर है. इसके कारण बिल्डरों पर अधिक दबाव नहीं आ पाता. बुकिंग के समय बिल्डर और ग्राहक के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत बिल्डर को तय समयावधि में ग्राहक को प्रकल्प पूरा कर फ्लैट सौंपना होता है. यदि वह यह करने में नाकाम रहा, तो एक फुट के पीछे बिल्डर को 5 से 10 रुपये नुक़सान भरपाई के रूप में ग्राहक को हर महीने देने होते हैं. मुंबई में यदि 2 हज़ार चौरस फुट घर की क़ीमत 1 करोड़ रुपये है और उसके क़र्ज़ की अदायगी के पीछे ग्राहक को 1 लाख रुपये देने पड़ते हैं. यदि घर समय पर नहीं मिलता, तो बिल्डर को ग्राहक को केवल 20 हज़ार रुपये महीने ही देने होंगे. ऐसे में प्रकल्प के रुकने का सबसे अधिक नुक़सान ग्राहक को उठाना पड़ता है. इसे देखते हुए ज़रूरी है कि निर्माण उद्योग से जुड़े नियम और क़ानूनों को ग्राहकों के पक्ष में अधिक से अधिक मज़बूत बनाया जाए, जिससे बिल्डरों पर दबाव बढ़ेगा और प्रकल्प समय पर पूरे होंगे.

feedback@chauthiduniya.com

# मंज़ूरी के बिना सीईओ की नियुक्तियां

स्थानीय निकाय संस्थाओं में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर आईएएस अधिकारियों की गुटीय लॉबी इतनी ताक़तवर हो गई है कि उसे नियम-क़ायदों की भी कोई परवाह नहीं है. मराठी-ग़ैर मराठी का विवाद इन अधिकारियों में इस क़दर व्याप्त है कि बिना केंद्रीय कार्मिक विभाग की मंज़ूरी के राज्य की आठ ज़िला परिषदों और दो महानगर पालिका में सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) की नियुक्तियां किए जाने का मामला उजागर हुआ है. इन नियुक्तियों को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने ग़ैर क़ानूनी घोषित कर दिया है. मज़े की बात यह है कि इस मामले की भनक तक मुख्यमंत्री को नहीं लगने दी गई. यह पूरा मामला राज्य के आईएएस अधिकारियों की मराठी-ग़ैर मराठी लॉबी की आपसी खींचतान के कारण अंजाम तक पहुंचा. अधिकारियों की मराठी और ग़ैर मराठी लॉबी के बीच चल रही खींचतान आज की बात नहीं है. दोनों में लंबे समय से यह विवाद जारी है. जानकारों का कहना है कि राज्य में ग़ैर मराठी आईएएस अधिकारियों की लॉबी काफ़ी मजबूत स्थिति में है. इसके कारण अधिकतर महत्वपूर्ण पदों पर उसका क़ब्ज़ा है और जो कम महत्व के पद एवं विभाग हैं, उनमें मराठी अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है. कहा तो यहां तक जाता है कि यह लॉबी इतनी सशक्त है कि मंत्रियों तक की परवाह नहीं करती है. इसी विवाद के कारण राज्य में छह ज़िला परिषदों और दो मनपाओं में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में न केवल क़ानून का उल्लंघन किया गया है, बल्कि ऐसा लगता है कि यूपीएससी के नियमों को भी राज्य मंत्रालय में बैठे अधिकारियों ने कचरे की टोकरी के हवाले कर दिया है. इस मामले से पता चलता है कि मंत्रालयों में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की कार्य पद्धति किस तरह संचालित होती है.

दरअसल, नियमों को देखा जाए तो ज़िला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के कैडर का होता है. इसलिए क़ानूनन एवं यूपीएससी नियमों के आधार पर ज़िला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर आईएएस अधिकारी की ही नियुक्ति की जानी चाहिए थी. उनके उपलब्ध न होने पर ही जिन पदाधिकारियों की पदोन्नति की सूची तैयार हो, उसमें से वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त की जानी चाहिए थी. इस सूची के तैयार न होने पर विशेष स्थिति में ज़िला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में केवल राज्य प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जा सकती है, पर सिर्फ़ 6 माह के लिए. मगर इस मामले में गुटीय खींचतान के चलते सारे नियम-क़ायदों की अनदेखी की गई और यह अनदेखी अनजाने में नहीं जानबूझकर किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है. इसकी वजह यह है कि राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के होने के बावजूद अन्य सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति ज़िला परिषद और महानगर पालिका के वरिष्ठ पदों पर की गई. यदि नियमों को ध्यान में रखकर नियुक्तियां की जातीं तो वर्ष 2010 एवं 2011 के लिए अपर संवर्ग जिलाधिकारी स्तर से भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी मिल सकते थे. इस संबंध में प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मंत्रालय के पास लंबित पड़ा है.

अब सवाल यह उठता है कि इस गड़बड़ी को अंजाम देने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं? हालांकि इस मामले में कुछ अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने जिन अधिकारियों की नियुक्ति को ग़ैर क़ानूनी बताया है उन्हें बदल दिया जाएगा. इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है. इन नियुक्तियों से राज्य की आईएएस अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है. पूरे राज्य में आईएएस अधिकारियों के 61 पद रिक्त पड़े हैं. ऐसी स्थिति में यदि सामान्य प्रशासन विभाग में धूल खा रहा प्रस्ताव मुख्य सचिव के ज़रिये मुख्यमंत्री के पास भेजा जाए तो वहां से यूपीएससी के पास जाने का उसका मार्ग खुल सकता है. अब विचारणीय यह है कि वर्ष 2009 की चयनित सूची को तीन साल के बाद 2012 में क्लियर किया जाएगा तो पिछले दो वर्ष में यानी वर्ष 2010 एवं 2011 के चयनित अधिकारियों के बैच को कब न्याय मिलेगा? इसके साथ ही राज्यसेवा के मराठी अधिकारियों के साथ कब न्याय हो सकेगा? शासन की इस

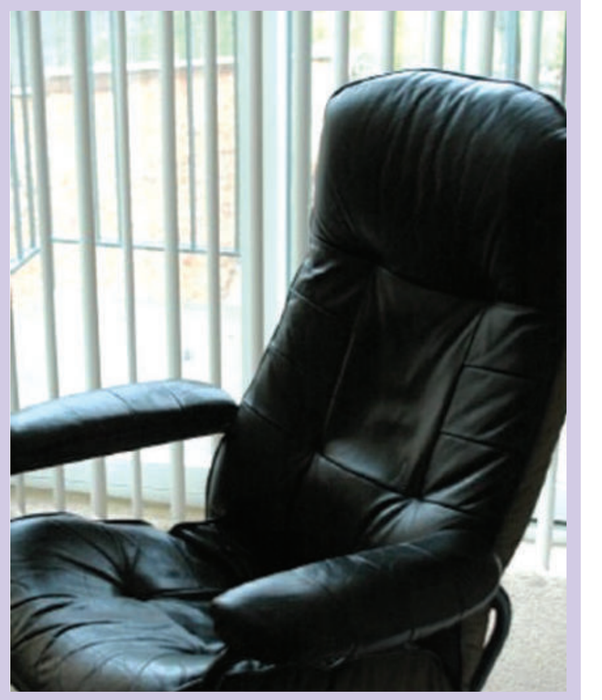

कोताही के कारण कई अधिकारियों की वरिष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है. सरकार को चाहिए कि प्रशासन की इस जड़ता को तोड़ने के लिए समय से क़दम उठाकर सभी बैच के चयनित अधिकारियों को उचित पद पर नियुक्त कर प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करे, जिससे वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों पर काम का बोझ कम हो और वे कार्य को सही तरीक़े से क्रियान्वित कर सकें.

> **मुख्यमंत्री को भी गुमराह किया**
>
> कार्मिक विभाग की मंज़ूरी के बिना ज़िला परिषद और महानगर पालिका में की गई ग़ैर क़ानूनी नियुक्तियों के प्रति मुख्यमंत्री को भी भनक नहीं लगने दी गई. मंत्रालय में चर्चा है कि इस कार्य को अंजाम देने वालों ने मुख्यमंत्री को भी गुमराह करने में कोई कोर-कसर बाक़ी नहीं रखी. उनको अंधेरे में रखकर यह कार्य किया गया. इससे यह पता चलता है कि राज्य में अधिकारियों की गुटीय लड़ाई से किस तरह प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है. सरकार को समय रहते वरिष्ठ अधिकारियों की गुटबाज़ी पर अंकुश लगाने के उपाय करने होंगे.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# संक्षिप्त समाचार

## विद्यार्थी एक नहीं, फिर भी शाला शुरू

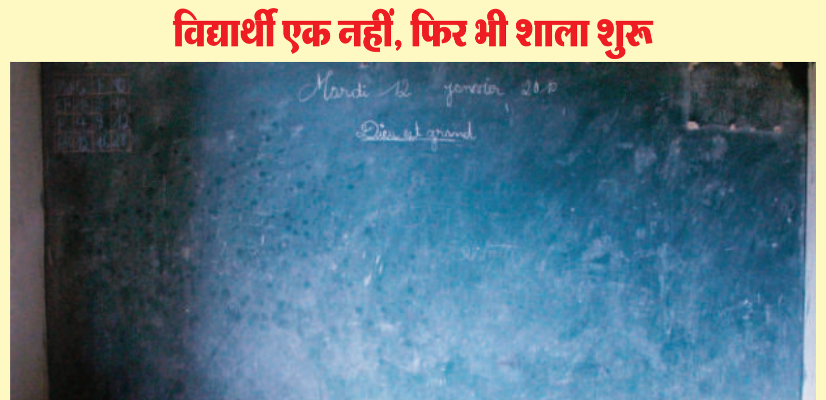

राज्य के नागपुर ज़िले की भिवापुर तहसील में एकता बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा संचालित हिमांशी मतिमंद आवासीय शाला और रतन चहांदे मतिमंद कर्मशाला में एक भी विद्यार्थियों ने प्रवेश नहीं लिया है. इसके बावजूद दोनों शालाएं सरकारी रिकॉर्ड में सुव्यवस्थित रूप से संचालित हैं और यह हो रहा है समाज कल्याण विभाग के आशीर्वाद से. यह तथ्य हाल में संस्था की जांच रिपोर्ट से सामने आया है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक में कम से कम 40 विद्यार्थियों का होना ज़रूरी है. एकता बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था की असलियत का ख़ुलासा पिछले साल की जांच रिपोर्ट से हुआ है. पिछले साल समाज कल्याण विभाग के डीएम गेटमे ने इस संस्था की निवासी शाला एवं मतिमंद कर्मशाला का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि वहां शाला एवं कर्मशाला होते हुए भी एक भी विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया है. इसी तरह शाला एवं कर्मशाला के रिकॉर्ड के अनुसार, वहां 19 शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन निरीक्षण के दरम्यान वहां सिर्फ़ 9 शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित पाए गए. विद्यार्थियों के न होने पर वहां स्थित मेस के बंद होने का उल्लेख भी रिपोर्ट में किया गया है. इन दोनों में से रतन चहांदे मतिमंद कर्मशाला क़ायम बिना अनुदानित होने पर भी वहां एक भी विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया है, लेकिन रिकॉर्ड पूरा बनाकर रखा जा रहा था. इसमें विशेष बात यह है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद भी समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने संस्था संचालकों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की. इस तथ्य से तो यही पता चलता है कि समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा से ही उक्त संस्थाएं सरकारी रिकॉर्ड में व्यवस्थित रूप से संचालित होती रही हैं और रिकॉर्ड को सही व्यवस्थित दर्शा कर अनुदान प्राप्त करना ही संस्था संचालकों का बहु-उद्देश्य रहा है. वहीं अब स्थानीय संगठन समाज कल्याण विभाग के ग़ैर ज़िम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.

## शराबी महिला टीसी का हुड़दंग

मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के यात्री पिछले दिनों उस समय दंग रह गए, जब एक महिला टीसी शराब के नशे में सवार होकर न केवल हुड़दंग किया, बल्कि यात्रियों के साथ भी बदतमीज़ी की. ड्यूटी पर न होने पर भी टिकट चेक किया. स्टेशन आने पर यात्रियों ने आरपीएफ के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, तब जाकर नशे में धुत महिला टीसी को ट्रेन से उतारा गया. आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि इस 34 वर्षीय महिला टीसी का नाम राधा तोमर है. पिछले दिन नाइट ड्यूटी करने के बाद उसने अपने पति सीएस भामरा (रेलवे का पूर्व अधिकारी) के साथ उल्हासनगर के एक होटल में जमकर शराब पी. शराब पीने के पश्चात उल्हासनगर से अंबरनाथ जा रही लोकल ट्रेन में दोनों चढ़ गए. नशे में धुत राधा जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ी, जबकि भामरा किसी और डिब्बे में सवार हो गए. अंबरनाथ स्टेशन आने के पहले उसने ड्यूटी न होते हुए भी यात्रियों के टिकट चेक करने शुरू कर दिए. टिकट चेक करने के साथ ही यात्रियों को गालियां देने लगी और कुछ को गाड़ी के बाहर फेंकने की धमकी भी दी. इसके बावजूद महिला टीसी की ज़्यादतियां यात्री इसलिए बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि वह एक महिला है. अंततः अंबरनाथ स्टेशन में यात्रियों की शिकायत पर आरपीएफ के जवानों ने उसे नीचे उतारा और उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ने जाया गया, जहां उसके शराब पीने की पुष्टि हुई. आरपीएफ के अधिकारियों का कहना है कि टीसी राधा तोमर के ख़िलाफ़ दर्ज शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेज दिया गया है. अब देखना यह है कि शराबी महिला टीसी के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है.

## आबा पालकमंत्री पद छोड़ेंगे

राज्य के गृहमंत्री आरआर पाटिल उर्फ़ आबा ने पार्टी के अंदर हो रही आलोचनाओं के कारण नक्सल समस्याग्रस्त गड़चिरोली ज़िले के पालकमंत्री की ज़िम्मेदारी छोड़ने का मन बनाया है. उल्लेखनीय है कि 30 वर्षों से नक्सली हिंसा से त्रस्त होने के कारण गड़चिरोली ज़िला हमेशा से चर्चा में रहा है और तीखी आलोचनाएं होने पर आबा ने गृहमंत्री होने के नाते गड़चिरोली ज़िले के पालकमंत्री की ज़िम्मेदारी चुनौती के रूप में स्वीकार की थी. इसी के साथ उन पर ज़िले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मज़बूत करने की भी ज़िम्मेदारी स्वतः ही आ गई. मगर उनके पालकमंत्री रहते हुए न गड़चिरोली में नक्सलियों की गतिविधियों में कमी आई और न पार्टी मज़बूत हुई. पिछले तीन माह में गड़चिरोली ज़िले में नगर पालिका और ज़िला परिषद के चुनाव संपन्न हुए. इन चुनावों में पार्टी को कोई अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हुई. अपना पालकमंत्री होने पर भी गड़चिरोली में पार्टी की हुई हार पर राकांपा के नेताओं ने आबा के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए. ज़िले में संपन्न दोनों चुनावों में मिली असफलता का ठीकरा आबा के सिर मढ़ दिया गया. अब कहा जा रहा है कि पार्टी में हो रही आलोचनाओं से तिलमिलाये आबा ने गड़चिरोली का पालकमंत्री पद छोड़ने का मन बना लिया है. इस संबंध में उन्होंने पार्टी के राज्य नेतृत्व को भी सूचना दे दी है.

## पार्टी में सीबीआई का ख़लल

पिछले दिनों उपराजधानी नागपुर में यूनियन बैंक में हुई करोड़ों की अफ़रा-तफ़री का पता लगाने के लिए सीबीआई ने तीन बैंक अधिकारियों और व्यापारियों के यहां छापा मारा. जिन तीन बैंक अधिकारियों के यहां छापा मारा गया, उनमें यूनियन बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक वीके कोलते, सह प्रबंधक गोंविद राजन और एसजी पवार शामिल थे. इन तीनों के ख़िलाफ़ सीबीआई को गुप्त शिकायत मिली थी कि उन्होंने ने कुछ व्यापारियों को करोड़ों का लोन जिस कार्य के लिए दिलाया था, उसमें उस धन का उपयोग नहीं किया गया. साथ ही वर्ष 2007 में क़र्ज़ लेने वाले व्यापारी लोन की अब तक एक भी क़िस्त नहीं भर पाए हैं. शिकायत पर सीबीआई ने पिछले दिनों उपराजधानी के 6 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की. जिन तीन बैंक अधिकारियों के यहां सीबीआई का छापा पड़ा, उनमें से सह प्रबंधक गोंविद राजन छापे पड़ने के एक दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए थे. जब सीबीआई के अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे तो गोंविद राजन के घर बैंक से सेवामुक्त होने की ख़ुशी में पार्टी की तैयारियां चल रही थीं. पार्टी में शामिल होने के लिए रिश्तेदार, परिचित और बैंक के सहयोगी भी आए हुए थे. सीबीआई अधिकारियों को सामने देखकर गोविंद राजन के होश उड़ गए. उन्होंने जांच अधिकारियों से हाथ जोड़कर अनुरोध किया, गिड़गिड़ाए कि वे अपनी कार्रवाई को एक दिन के लिए टाल दें. मगर सीबीआई तो ठहरी सीबीआई, वह भला कहां मानने वाली. एकदिन में तो सारा वारा-न्यारा हो जाता है. सो बैंक प्रबंधक की सेवानिवृत्त पार्टी में सीबीआई ने ख़लल डाल ही दिया और पार्टी का पूरा मज़ा किरकिरा हो गया.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

किसानों को राहत मिल रहा है या नहीं, इसकी सुध लेने की किसी को याद नहीं आई. छह-सात साल बाद केंद्र सरकार को अपने पैकेज के बेअसर होने की याद आई है.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467



## करोड़ों के पैकेज के बावजूद किसान बदहाल

# पैकेज का खेल फेल

**चुनावों में वोट की फ़सल काटने वाले सत्ताधीशों ने किस तरह से विदर्भ के किसानों का मज़ाक़ बनाकर रख दिया है. किसानों को राहत पहुंचाने के बदले पैकेज का उनके साथ खेल खेला जा रहा है. दूसरी ओर किसानों की आत्महत्या का सिलसिला बदस्तूर जारी है. आत्महत्या करने वाले किसानों का आंकड़ा 2500 के पार चला गया है और आए दिन राज्य के किसी न किसी ज़िले एवं गांव के किसान द्वारा क़र्ज़ से तंग आकर विष पीने या फांसी पर लटक कर मौत को गले लगाने की ख़बरें समाचार पत्रों की सुर्ख़ियां बनती रहती हैं.**

राजेश नामदेव

विदर्भ के बदहाल किसानों को राहत पहुंचाने के लिए अब तक केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी पैकेज नकारा साबित हुए हैं. यह हम नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के किसानों की बदहाली और उनके लिए घोषित पैकेज की समीक्षा करने आई 30 सदस्यीय संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद वासुदेव आचार्य ने मीडिया के सामने स्वीकार किया है. इससे यह पता चलता है कि पैकेज घोषणा करने का शोर मचाकर चुनावों में वोट की फ़सल काटने वाले सत्ताधीशों ने किस तरह से विदर्भ के किसानों का मज़ाक़ बनाकर रख दिया है. किसानों को राहत पहुंचाने के बदले पैकेज का उनके साथ खेल खेला जा रहा है. दूसरी ओर किसानों की आत्महत्या का सिलसिला बदस्तूर जारी है. आत्महत्या करने वाले किसानों का आंकड़ा 2500 के पार चला गया है और आए दिन राज्य के किसी न किसी ज़िले एवं गांव के किसान द्वारा क़र्ज़ से तंग आकर विष पीने या फांसी पर लटक कर मौत को गले लगाने की ख़बरें समाचार पत्रों की सुर्ख़ियां बनती रहती हैं. पिछले साल दिसंबर माह में भी राज्य सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक नए पैकेज की घोषणा की और जनवरी–फरवरी में हुए महानगर पालिका एवं ज़िला परिषद के चुनावों में वोटों की फ़सल काटने की क़वायद की. ऐसा लगता है कि जब भी चुनाव का मौसम नज़दीक होता है, सरकारें पैकेज का दाना फेंक कर मतदाता को रिझाने का प्रयास करती हैं. सबसे गंभीर बात यह है कि किसानों को राहत पहुंचाने के

नाम पर हज़ारों करोड़ों रुपये का पैकेज घोषित तो किया गया, लेकिन उनको किसी तरह की राहत तो मिली नहीं. दस्तावेज़ों में दर्ज आंकड़ों में बाक़ायदा ख़र्च, किसानों को वितरित रक़म का हिसाब–किताब है. फिर पैकेज का पैसा गया तो कहां गया?

ग़ौरतलब है कि वर्ष 2006 में राज्य सरकार ने राज्य में किसान आत्महत्या रोकने के लिए पैकेज की घोषणा की थी. इस पैकेज में उस वक़्त किसानों की क़र्ज़ माफ़ी के साथ ही विविध योजनाएं शुरू करने का दावा शासन–प्रशासन कर रहा था, लेकिन विदर्भ किसानों का सुसाइड जोन बना ही रहा. किसानों द्वारा आत्महत्याएं लगातार की जाती रही हैं. इस पर राज्य सहित पूरे देश में किसानों की आत्महत्याओं को लेकर राज्य एवं केंद्र सरकार की कृषि नीति की तीखी आलोचना होने पर प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के उपरांत एक और पैकेज की घोषणा किसानों को राहत पहुंचाने के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा की गई थी. इस पैकेज में यह माना गया कि महाराष्ट्र के अमरावती संभाग के पांच ज़िले बुलढाना, वाशिम, यवतमाल, अकोला, अमरावती और नागपुर संभाग का वर्धा ज़िला किसान आत्महत्या की दृष्टि से सबसे प्रभावित ज़िलों में शामिल है. प्रधानमंत्री ने इन छह ज़िलों के किसानों को राहत पहुंचाने के लिहाज़ से 3700 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया था, जिसका लक्ष्य था कि इन ज़िलों में विकास की गंगा बहाकर और किसानों को पूरक रोज़गार के अवसर प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनाना. मगर इस पैकेज से भी किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुका. इन पैकेजों के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी संभालने वाले वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशन के दस्तावेज़ी आंकड़े भी यही दर्शाते हैं कि इन पैकेजों से किसानों को किसी तरह की प्रत्यक्ष राहत नसीब नहीं हुई है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि किसानों को पूरक व्यवसाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पैकेज में प्रावधान किए गए थे. इसके लिए पैकेज में 135 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने मात्र 100.12 करोड़ रुपये जारी किए, जिनमें से 99.44 करोड़ रुपये ख़र्च हुए. इसके तहत किसानों को 25298 मवेशी बांटे गए, जिसमें जमकर धांधली होने की ख़बर है. वहीं राज्य सरकार के पैकेज के तहत तीन सालों में इन छह ज़िलों में पूरक व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए अलग से प्रावधान किया गया था. मगर उससे भी कोई पूरक व्यवसाय किसानों को उपल्ब्ध नहीं कराया जा सका. मिशन से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि राज्य एवं केंद्र सरकार के पैकेज के तहत किसानों को मवेशी तो उपलब्ध कराए गए, लेकिन चारे की कोई व्यवस्था न होने से यह योजना पूरी तरह से फेल हो गई. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आत्महत्या करने वाले अधिकांश किसान कपास उत्पादक हैं. हालांकि तीन वर्षों में कपास उत्पादकों को राहत पहुंचाने के लिए 134 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जिसमें से मात्र 129.77 करोड़ रुपये ख़र्च हुए. उक्त प्रावधान सिर्फ़ राज्य सरकार के पैकेज में किया गया था. केंद्र सरकार के पैकेज में कपास उत्पादकों के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं दी गई थी. इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के 3750 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा करने के बाद भी किसान आत्महत्या रोकने के लिए जारी पैकेज के 150.14 फ़ीसदी यानी 5630.22 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए. इसमें क़र्ज़ ब्याज़ माफ़ी पर 837.56 करोड़ रुपये, लघु सिंचाई पर 113.19 करोड़ रुपये, गारंटी सिंचाई योजना पर 3983.81 करोड़ रुपये, चेक डैम पर 192.66 करोड़ रुपये, सिंचित क्षेत्र विकास पर 103.39 करोड़ रुपये, कृषि तकनीक पर करोड़ एवं वॉटर हारवेस्टिंग पर 6 करोड़ रुपये और बीज वितरण 119.83 करोड़ रुपये ख़र्च करने की बात कही गई. इसी तरह राज्य सरकार के पुराने पैकेज के तहत करोड़ों रुपये ख़र्च करने के आंकड़ें वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशन के दस्तावेज़ों में दर्ज हैं.

जब इन पैकेजों की राशि जारी की गई और पैकेज की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, तब किसी ने इस पर ग़ौर नहीं किया कि जारी करोड़ों की रक़म कहां और किस तरह ख़र्च की जा रही है. किसानों को राहत मिल रहा है या नहीं, इसकी सुध लेने की किसी को याद नहीं आई. छह–सात साल बाद केंद्र सरकार को अपने पैकेज के बेअसर होने की याद आई है. हालांकि इसके पहले केंद्र सरकार के युवराज राहुल गांधी यवतमाल ज़िले का दौरा करके ख़ूब सुर्ख़ियां बटोर चुके हैं. लेकिन विदर्भ के किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस एक कलावती की चर्चा यवतमाल से लेकर संसद तक हुई. मगर विदर्भ के किसानों की हालत में कोई बदलाव नहीं आया. अब जब लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए दो वर्ष बचे हैं, तब तीस सदस्यीय संसदीय समिति को दौरा करने के लिए भेज दिया. ऐसा लगता है कि चुनाव आते–आते नया पैकेज घोषित करने की पुनः तैयारी शुरू हो गई है. परंतु समिति ने दौरा कर जो समीक्षा की, उसका प्रतिफल यह निकला कि अब तक राज्य सरकार ने किसानों के साथ जो पैकेज–पैकेज का खेल खेला है, वह पूरी तरह विफल रहा है. संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद वासुदेव आचार्य ने भी माना कि पैकेजों के बाद भी राज्य में किसान आत्महत्याओं का दौर रुक नहीं रहा है. देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र में सिंचाई सुविधाएं काफ़ी कम हैं. यहां केवल 10 प्रतिशत कृषि क्षेत्र की सिंचाई हो पाती है. खाद की समस्या भी है. आचार्य ने यह भी बताया कि यहां के किसान बीटी कॉटन नहीं लगाना चाहते हैं. उनको देसी बीज पर अधिक विश्वास है. साथ ही यह भी आश्चर्य जताया कि करोड़ों की राशि ख़र्च करने के बाद भी विदर्भ के किसानों की हालत जस की तस है. समिति केंद्र सरकार को अपनी समीक्षा रिपोर्ट देकर यहां के किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अपनी सिफ़ारिशें देगी. वहीं बैठक में शामिल राज्य के कृषि एवं फलोत्पादन विभाग के प्रधान सचिव सुधीर गोयल ने बताया कि संसदीय समिति से फ़सल बीमा योजना में सुधार करने, सिंचाई योजनाओं के लिए 13000 करोड़ रुपये एवं विदर्भ के आत्महत्याग्रस्त ज़िलों के लिए और 7500 करोड़ रुपये का पैकेज देने की मांग की गई है. दो पैकेजों की विफलता के बाद और पैकेज देने की बात की जा रही है, लेकिन यहां यह कोई बताने को तैयार नहीं है कि अब तक के पैकेजों के तहत जो करोड़ों रुपये ख़र्च हुए वे कहां गए? किसको राहत मिली और किसकी जेबें भरी गईं? क्यों किसान पहले भी क़र्ज़ से डूबा था और हज़ारों करोड़ों की रक़म ख़र्च होने के बाद भी क़र्ज़दार है?

feedback@chauthiduniya.com

### राज्य सरकार के नए पैकेज का क्या हुआ

**पिछले वर्ष राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 2000 करोड़ रुपये का नया पैकेज विधानसभा में घोषित किया था. उस पैकेज के तहत अब तक मात्र 100 करोड़ रुपये ही किसानों के लिए जारी किए जा सके हैं. इस 100 करोड़ रुपये को 31 मार्च तक वितरित किए जाने के आदेश हैं, जो ऊंट के मुंह में ज़ीरे के समान साबित हो रहे हैं. यदि विभागों की दृष्टि से देखें तो विदर्भ के अमरावती विभाग के 9,762 हेक्टेयर कृषि भूमि को 410 करोड़ रुपये की मदद की ज़रूरत है और उसे मिले हैं मात्र 33 करोड़ रुपये. इसी तरह विदर्भ के नागपुर विभाग में 3, 217 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र के लिए 128 करोड़ रुपये चाहिए, पर मात्र 9 करोड़ रुपये मिले. इसी तरह राज्य के अन्य विभागों में से नासिक विभाग के 7,885 हेक्टेयर के लिए 315 करोड़ चाहिए, पर सिर्फ़ 22 करोड़ रुपये ही मिले हैं. औरंगाबाद विभाग की 14,177 हेक्टेयर भूमि के लिए 567 करोड़ रुपये की ज़रूरत है, जबकि मात्र 40 करोड़ रुपये मिले हैं. इसी तरह पुणे विभाग को 32 हेक्टेय क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रुपये मिलने की अपेक्षा थी, पर 9 लाख रुपये मिले. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार की पैकेज नीति किस तरह से क्रियान्वित हो रही है. किसानों को जितनी मदद की ज़रूरत रहती है, सरकार उतनी मदद देने में असमर्थ साबित हुई है. इससे साबित होता है कि पैकेज क्यों बेकार साबित होते हैं.**

### बड़े की बजाय छोटे बांधों की ज़रूरत है

**राज्य में सिंचाई के लिए बड़ी परियोजनाओं का निर्माण हज़ारों करोड़ रुपये ख़र्च करने के बाद भी अधूरा है. उनसे अब तक अपेक्षित सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला है. इसके साथ ही बड़े बांधों में पानी का संग्रहण किए जाने से नदियां सूख रहीं हैं और राज्य में भू-जल स्तर तेज़ी से नीचे जा रहा है. इन तथ्यों के मद्देनज़र राज्य में छोटे-छोटे चेक डैम हर ज़िले में बनाकर सिंचाई के लिए पानी उपल्ब्ध कराने की ज़रूरत है. इन चेक डैमों से न केवल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सकता है, बल्कि नदियों के अस्तित्व को बचाया जा सकता है. साथ ही तेज़ी से गिर रहे जलस्तर को भी रोका जा सकता है.**

### शासन-प्रशासन की अनास्था

**पैकेजों को समयबद्ध चरण से क्रियान्वयन करने में राज्य का शासन-प्रशासन हमेशा असंवेदनशील रहा है. सत्त-ाधीशों व प्रशासनिक अधिकारियों की अनास्था की वजह से पैकेजों केतहत केन्द्र व राज्य शासन द्वारा जारी की गई राशि का उपयोग नहीं किया जाता है. रकम खजाने में पड़ी रहती है. किसान बीज-खाद केलिए तरसते रहते हैं. इसकेअलावा कर्ज वसूली में बरती जाने वाली सख्ती से किसान परेशान हो उठता है और जब उसे कोई राह नही सुझती तो वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है. शासन-प्रशासन की यह अनास्था राज्य में आत्महत्या की घटनाओं में अंकुश न लगा पाने की सबसे बड़ी वजह है. यदि मंत्री, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी संवेदनशीलता केसाथ पैकेजों को किसानों की जरूरत के अनुसार क्रियान्वयन करें तो किसान आत्महत्या पर अंकुश लगाया जा सकता है.**

चौथी दुनिया
बिहार झारखंड

दिल्ली, 19 मार्च–25 मार्च 2012
www.chauthiduniya.com

## स्कूलों में कंप्यूटर

# बस देखने की चीज़

सरोज सिंह


बिहार के मध्य और उच्च विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने की योजना के तहत सरकार द्वारा करोड़ों रुपये ख़र्च किए गए, लेकिन इसका नतीजा निराश करने वाला है. विभागीय मंत्री और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों का दावा जो हो, पर ज़मीनी सच्चाई यह है कि राज्य में कंप्यूटर शिक्षा योजना का कबाड़ा निकलता जा रहा है. हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करोड़ों रुपये की लागत से ख़रीदे गए कंप्यूटर और जेनरेटर अधिकांश स्कूलों की बस शोभा बढ़ा रहे हैं. या यूं कहें कि कंप्यूटर और संबंधित उपकरण कबाड़ख़ाने में जाने को बेताब दिख रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह शिक्षकों की कमी के साथ बिजली की अनुपलब्धता कही जा रही है, पर मामला यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है. बिजली उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण कंप्यूटर और संबंधित उपकरण महज़ कांच के बक्से बनकर रह गए हैं. किसी–किसी विद्यालय की स्थिति तो यह है कि गुरुजी बच्चों को यह कहकर कंप्यूटर छूने से मना कर देते हैं कि कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा. अब ऐसे गुरुजी को कौन समझाए कि जनाब! बच्चे जब कंप्युटर छुएंग ही नहीं, तो उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान कैसे मिल सकेगा! अगर शिक्षा का ज्ञान आईसीटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई इस योजना की ज़मीनी पड़ताल की जाए तो शायद आंखें फटी की फटी रह जाएं. वैसे तो लगभग सभी ज़िलों की स्थिति कमोबेश एक ही जैसी है, लेकिन अगर नालंदा ज़िले की बात की जाए तो इस ज़िले के 15 उच्च विद्यालयों (प्लस–2) में ग्यारह–ग्यारह कंप्यूटर सेट लगाए गए है. कंप्यूटर सिस्टम की आपूर्ति बेल्ट्रान नामक कंपनी द्वारा कराई गई है. ज़िले के 10 मध्य विद्यालयों में भी स्पीड यानी राज्य प्रारंभिक शिक्षा विकास कार्यक्रम द्वारा तीन–तीन कंप्यूटर सेट लगाए गए हैं. लेकिन बिजली और संसाधन के अभाव में कंप्यूटर बेकार पड़े हैं. बक्सर ज़िले में भी आईसीटी प्रोजेक्ट के तहत कंप्यूटर शिक्षा के लिए चौदह उच्च विद्यालयों का चयन किया गया था. स्कूलों में कंप्यूटर भी लगा दिए गए. लेकिन संसाधन और बिजली के अभाव में लगभग सभी जगह इनका वास्तविक रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है. जेनरेटर की व्यवस्था रहने पर कुछ विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा का संचालन हो पा रहा है. बात अलग है कि माध्यमिक शिक्षा के डीओ डॉ. ओमप्रकाश लगभग सभी विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई होने का जी भरकर दावा कर रहे हैं. एसएम बालिका उच्च विद्यालय बिहारशरीफ़ की नौवीं की छात्रा सुमन कुमारी ने कहा कि कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, लेकिन मास्टर की–बोर्ड या मॉनीटर ख़राब होने का डर दिखाकर छूने नहीं देते हैं. उधर, आरा ज़िला प्रशासन कार्यालय की नाक के नीचे अर्थात महज़ सौ मीटर दूरी पर स्थित ज़िला स्कूल में लगे पचास कंप्यूटर बेकार पड़े हैं. विद्यालय के प्रभारी उमेश प्रसाद ने बताया कि एक ही कमरे में 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पचास कंप्यूटर लगाए गए हैं. शुरुआती दौर में कंप्यूटर शिक्षा लेने के लिए छात्रों की होड़ लग गई थी. लेकिन बिजली के अभाव में कंप्यूटर की पढ़ाई बंद हो गई. कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए सरकार ने एक लाख रुपये भी आवंटित किए, लेकिन आज तक एक जेनसेट तक की ख़रीददारी नहीं हो सकी. कैमूर ज़िले के महज़ सात मध्य विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर से इन विद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा छह और सात के छात्र कंप्यूटर सीख रहे हैं. मोहनियां प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी अरूण प्रकाश का कहना है कि तीन मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर तो उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन ऑपरेटर एवं स्थान के अभाव में छात्र इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. भभुआ स्थित इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के कंप्यूटर कक्ष में रखे सात कंप्यूटर बीते वर्ष 2005 के सितंबर माह में जल गए थे. इसके बाद से कंप्यूटर शिक्षा ठप है. चैनपुर मध्य विद्यालय के कक्षा सात के छात्र मोहन सिंह, राकेश, अरविंद आदि ने बताया कि सप्ताह में सिर्फ़ दो दिन कंप्यूटर के की–बोर्ड पर सीखने का अवसर इन लोगों को मिलता है. अररिया ज़िले में भी प्रशिक्षक और संसाधन के अभाव में कंप्यूटर शिक्षा योजना फेल हो गई है. शेखपुरा में तो केवल कंप्यूटर का स्थान बदलने में सत्तर हज़ार का बिल बना दिया गया.

**बिहार में कंप्यूटर शिक्षा योजना का कबाड़ा निकलता जा रहा है. लगभग सभी जगह बिजली और संसाधन के अभाव में छात्र-छात्राएं कंप्यूटर शिक्षा से वंचित हैं. कहीं-कहीं सभी व्यवस्था उपलब्ध है, भी तो गुरुजी यह कहकर बच्चों को कंप्यूटर छूने से मना कर देते हैं कि ख़राब हो जाएगा. यही कारण है कि कई ज़िलों में कंप्यूटर या तो रखे-रखे ख़राब हो रहे हैं या गुरुजी या संबंधित पदाधिकारी के घर की शोभा बढ़ा रहे हैं.**

दरअसल, कंप्यूटर शिक्षा के इस हाल के पीछे के कारणों से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि इसके पीछे मंशा क्या थी? बिहार में बिजली के हाल से सभी वाक़िफ़ हैं. जेनसेट के सहारे इसे चलाने की पेचीदगियों का आकलन पटना में भी बैठकर आसानी से किया जा सकता है. प्रशिक्षकों की क़िल्लत के आंकड़े भी सरकार के पास थे. लेकिन सब कुछ जानते समझते करोड़ों रुपये इस योजना में झोंक दिए गए तो सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाज़िमी है. नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीक़ी कहते हैं कि सरकार ब्लैक बोर्ड पर तो बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं पा रही है, तो कंप्यूटर की पढ़ाई तो दूर की बात है. राजद प्रवक्ता रामबिहारी सिंह कहते हैं कि यह कंप्यूटर शिक्षा योजना वास्तव में सरकार की खाओ, पकाओ योजना थी और इस योजना के अमल में नीतीश सरकार पूरी तरह सफल रही है. उनके अनुसार जहां बच्चों को स्कूलों में छत भी उपलब्ध नहीं है, वहां कंप्यूटर भेजकर राज्य के पैसे की बस बंदरबाट की गई है. सांसद उपेंद्र कुशवाह मानते हैं कि यह सरकार की ग़लत नीतियों का परिणाम है कि करोड़ों के कंप्यूटर स्कूलों में धूल फांक रहे हैं. अगर सही योजना बनाकर इसे अमल में लाया जाता है, तो सूबे के बच्चों का काफ़ी भला होता और राज्य को इसका फ़ायदा मिलता, लेकिन इसमें केवल बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला. देखा जाए तो तकनीकी शिक्षा में बच्चों को आगे ले जाने की जो चुनौती है, उसे देखते हुए सरकार को काफ़ी गंभीरता से दोबारा सोचना होगा, ताकि ग़रीब छात्रों को कंप्यूटर की दुनिया से रूबरू कराया जा सके.

feedback@chauthiduniya.com

स्कूल में कंप्यूटर तो लगा है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि आख़िर बगहा डीएम एकेडमी सहित अन्य चार स्कूलों में कंप्यूटर क्यों नहीं लगाए गए.

# कंप्यूटर शिक्षा ख़स्ता हाल

प्रो. अरविंद नाथ तिवारी

बिजली के अभाव तथा अन्य कारणों से बगहा ज़िले में आईसीटी योजना के तहत माध्यमिक स्तर पर शुरू की गई कंप्यूटर शिक्षा योजना दम तोड़ती नज़र आ रही है. विद्यालय प्रबंधन का रोना है कि जेनरेटर में तेल की आपूर्ति करना कंप्यूटर संचालन कराने वाली बेल्ट्रान कंपनी की ज़िम्मेदारी है. इसके बावजूद कई विद्यालयों द्वारा तेल संबंधित बिल जमा करने के बाद भी भुगतान आज तक संभव नहीं हो पाया है. छात्र-छात्राओं की बातों पर अगर भरोसा करें तो छात्र-छात्राओं से ही रुपये लेकर कभी-कभार कंप्यूटर कक्षा का संचालन किया जाता है. कहने को तो पश्चिम चंपारण ज़िले के सौ विद्यालयों में यह योजना विगत तीन वर्षों से चल रही है, लेकिन कई विद्यालयों के संदर्भ में बताया जाता है कि कंप्यूटर लगा भी नहीं और कंप्यूटर का आवंटन दिखला दिया गया है. बात अलग है कि बीस में से चिह्नित 15 विद्यालयों में कंप्यूटर लगा दिया गया है, लेकिन कंप्यूटर शिक्षा महज़ छलावा साबित हो रही है. शेष पांच विद्यालयों के लिए कंप्यूटर की ख़रीद होना, गंभीर जांच का विषय है. बेतिया स्थित राज इंटर हाई स्कूल, विपिन हाई स्कूल, राज संपोषित कन्या उच्च विद्यालय, बैरिया स्थित उच्च विद्यालय बथना, हाई स्कूल पखनाहा, साठी स्थित राजाराम प्रजापति हाई स्कूल, नरकटियागंज स्थित उच्च विद्यालय, मतिसरा हाई स्कूल, बगहा स्थित प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, राधेश्याम हाई स्कूल परसौनी, योगापट्टी हाई स्कूल, लौरिया स्थित बागड़ कुंअर कन्या उच्च विद्यालय, गौनहा स्थित नंदकेश्वर उच्च विद्यालय, रामनगर पकड़ी स्थित गुड्डीलाल कन्या उच्च विद्यालय, सिकटा स्थित जनता हाई स्कूल तथा मझौलिया स्थित जानकी प्रोजेक्ट हाई स्कूल में कंप्यूटर तो लगा है. लेकिन चर्चा इस बात की है कि आख़िर बगहा डीएम एकेडमी सहित अन्य चार स्कूलों में कंप्यूटर क्यों नहीं लगाए गए. चर्चा इस बात की भी है कि योजना के तहत आईसीटी योजना का कंप्यूटर आख़िर गंतव्य तक पहुंचा क्यों नहीं. बगहा कन्या गर्ल्स प्रोजेक्ट के कंप्यूटर शिक्षक चंद्रकिशोर राम ने डीज़ल के अभाव में कंप्यूटर बंद रहने का रोना रोते हुए कहा कि कभी-कभी शिक्षक और छात्राओं से पैसा लेकर कंप्यूटर चलाया जाता है. तीन-तीन बार बेल्ट्रान प्रबंधन को बिल बनाकर दिया गया, किंतु अभी तक भुगतान नहीं हुआ है. विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रद्युम्न पांडेय ने बताया कि बेल्ट्रान के ज़िला प्रबंधन अमित कुमार के साथ-साथ ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी जयशंकर ठाकुर को पत्रांक संख्या 127/11 दिनांक 8.11.11 के माध्यम से कंप्यूटर बंद रहने की जानकारी दे दी गई है. हालांकि अब तक इस मसले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. उधर, इस संदर्भ में बार-बार कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश के बाद भी उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ सकी.

बगहा

feedback@chauthiduniya.com

# हवा में कंप्यूटर शिक्षा

मोतिहारी

इंतज़ारुल हक़

कंप्यूटर आधारित शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा की गई अब तक की तमाम कार्रवाई मोतिहारी में हवा हवाई साबित हुई है और कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर केवल राशि का दुरुपयोग हुआ है. भले ही विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र कंप्यूटर सीखने से वंचित रह गए, किंतु विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सरकार की यह योजना काफ़ी लाभदायक साबित हुई. ज़िले के 15 मध्य विद्यालयों में बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से कंप्यूटर सेट की आपूर्ति की गई थी, जा लगने के साथ ही ख़राब हो गया. एक विद्यालय में कंप्यूटर सेट की चोरी होने का मामला दर्ज है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2004-05 में ज़िला स्तर पर क्रय समिति द्वारा कंप्यूटर की ख़रीदारी की गई थी और सभी विद्यालयों को तीन-तीन कंप्यूटर दिए गए थे. मध्य विद्यालय सेमरा, गौरी शंकर मध्य विद्यालय मोतिहारी, मध्य विद्यालय ढाका बालक, मध्य विद्यालय पकड़ी दयाल बालक, मध्य विद्यालय चकिया बालक, मध्य विद्यालय सरोतर केसरिया, मध्य विद्यालय रक्सौल व मध्य विद्यालय सुगौली मेंलगा कंप्यूटर लगने के साथ ही ख़राब हो गया और आज तक ठीक नहीं कराया गया. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से सीधे भेजे गए सात विद्यालयों के कंप्यूटर भगवान भरोसे चल रहे हैं. इसमें मंगलापुर संग्रामपुर मध्य विद्यालय का कंप्यूटर चोरी हो गया है. मध्य विद्यालय आदापुर बालक, मध्य विद्यालय रामगढ़वा, मध्य विद्यालय जमुआ ढाका, मध्य विद्यालय परसौनी देवाजीत मेहसी मेंलगा कंप्यूटर सही हालत में है और इन विद्यालयों में परियोजना द्वारा सीधे कंप्यूटर की आपूर्ति की गई है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच इस मामले मं बेहतर तालमेल भी नहीं है, जिस कारण सरकार की यह महत्वकांक्षी योजना ज़मीन पर उतरने से पहले दम तोड़ने लगी है. भ्रष्टाचार के कारण पूरे ज़िले में चर्चा में रहने वाला सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षा विभाग इन दिनों रैंकिंग में आई गिरावट को लेकर फिर चर्चा में है. पूरे बिहार में सर्वशिक्षा अभियान 90 करोड़ रुपये ख़र्च होने के बावजूद मोतिहारी 32वें स्थान पर पहुंच गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2011-12 में सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय ने 459 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया था और प्रस्ताव पारित कर विभाग को भेजा था, किंतु 90 करोड़ रुपये ही मिले. चम्पारण ज़िले में विद्यालयों के भवन निर्माण में सबसे अधिक गड़बड़ी हुई है और राशि का दुरुपयोग किया गया है. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के संचालन का मामला हो या फिर भवन का, या फिर अन्य योजनाओं का. तमाम योजनाओं में लूट मची हुई है. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बदतर हालत सुधारने व कुव्यवस्था को समाप्त करने के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी बिमल की खिंचाई हमेशा होती है, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला. सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी बिमल से डीआरजी भी काफ़ी परेशान हैं और उनका मानदेय नहीं मिल रहा है. यहां बता दें कि इसकी शिकायतें भी लगातार अधिकारियों के यहां पहुंचती हैं और जनता दरबार में भी मामला पहुंचता है, किंतु जांच के नाम पर मामले को उलझा कर रख दिया जाता है.

कई विद्यालय बनने के साथ ही ध्वस्त हो गए हैं. ज़िले के बंजरिया, आदापुर, रामगढ़वा, रक्सौल, कल्याणपुर समेत कई प्रखंडों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय भवन बनाए गए हैं, जो प्राकलन के विपरीत है. इन तमाम मामलों की अगर गहनता से जांच हो तो अनेक मामले सामने आएंगे. ज़िले में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से विद्यालयों के प्राचार्य अब कोई कंप्यूटर लेने से सीधे इंकार कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर विभाग द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, तभी वे कंप्यूटर लेंगे. उधर, सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम पदाधिकारी ने स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है, किंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है.

feedback@chauthiduniya.com

**शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच इस मामले मं बेहतर तालमेल भी नहीं है, जिस कारण सरकार की महत्वकांक्षी यह योजना ज़मीन पर उतरने से पहले दम तोड़ने लगी है. भ्रष्टाचार के कारण पूरे ज़िले में चर्चा में रहने वाला सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षा विभाग इन दिनों रैंकिंग में आई गिरावट को लेकर फिर चर्चा में आया गया है. पूरे बिहार में सर्वशिक्षा अभियान 90 करोड़ रुपये ख़र्च होने के बावजूद मोतिहारी 32वें स्थान पर पहुंच गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2011-12 में सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय ने 459 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया था और प्रस्ताव पारित कर विभाग को भेजा था, किंतु 90 करोड़ ही रुपये मिले. पूर्व चम्पारण ज़िले में विद्यालयों के भवन निर्माण में सबसे अधिक गड़बड़ी हुई है और राशि का दुरुपयोग किया गया है.**

# सर्जरी से डरें नहीं

डॉ. निर्मल कुमार सिन्हा

पटना के जाने माने जनरल सर्जन डॉ. निर्मल कुमार सिन्हा का कहना है कि सर्जरी से मरीज़ों को डरने की ज़रूरत नहीं है. अब तो विशेषज्ञ बड़ी आसानी से मरीज़ों की सर्जरी कर उन्हें रोगमुक्त कर देते हैं. पटना स्थित जानकी चिकित्सा केंद्र में व्यस्त डॉ. सिन्हा का कहना है कि पहले ज़माने की तुलना में अब लोग अपनी सेहत के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए हैं. इसलिए यह देखा जा रहा है कि सर्जरी कराने वाले मरीज़ों की संख्या भी बढ़ी है.

इसके साथ ही साथ बीमारियों की जांच सुविधा में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है. इस कारण बीमारियां पकड़ में आने में सुविधा हो रही है. उनका कहना है कि मरीज़ों को विशेषज्ञ सर्जन से ही सर्जरी करानी चाहिए. झोला छाप डॉक्टर पूरे केस को बिगाड़ देते हैं और मरीज़ को इसकी क़ीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है. डॉ. निर्मल सिन्हा का मानना है कि सर्जरी भी अच्छा विकल्प है, लेकिन सही वक़्त पर ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए. बेहतर खान-पान और अनुशासित दिनचर्या लोगों को स्वस्थ्य रखने में मदद करती है. इसलिए लोगों को हर हाल में इसका पालन करना चाहिए.

राजेश सिन्हा
feedback@chauthiduniya.com

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
ASRFEN-P
Aceclofenac + paracetamol Serratiopeptidase Tab.
ECTALOPAM
Escitalopram Oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalamin,Lycopene,Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxidant
Carbo-XT
Ferrous Ascorbate With Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan,Guaiphenesine Ammonium Chloride Cough Syp.
MENSOSET
Her Tonic With Ashoka 1800mg.
MUSTAL
Levocetirizine Hydrochloride Montelukast Sodium Tab.

विनय कुमार पटेल
नगर उपसभापति
मनोहर कुमार यादव
नगर सभापति
महेश्वर प्रसाद सिंह
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
BIHAR
बिहार दिवस शताब्दी समारोह
खगड़िया नगरवासियों को बिहार दिवस के शताब्दी वर्ष पर हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर घरों में दीपक जलाएं एवं परिवेश को साफ-सुथरा रखने का संकल्प लें।
नगर परिषद, खगड़िया

बिहारवासियों को रंगों का त्योहार होली की अनन्त शुभकामनायें आपसी सौहार्द रहे कायम यही ईश्वर से प्रार्थना है।
रिजनिंग सर्किल में आई.बी.पी.एस. क्लर्क की मुफ्त साक्षात्कार की तैयारी करायी जा रही है
निवेदक
बी. बिहारी
राज्य सदस्य
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ
सह निदेशक
रिजनिंग सर्किल मोतिहारी
मो. 9852943572

ISO 9001 : 2008 CERTIFIED HOSPITAL
कोशी का गौरव
सूर्या हॉस्पीटल
गांधी पथ (सत्संग मंदिर रोड) सहरसा, बिहार
सुविधाएं
डॉ. विजय शंकर
डॉ. करुणा शंकर
भविष्य में दी जाने वाली सुविधायें
मो. 9334999421, 7631243693

BRIGHT CAREER SCHOOL
Affiliated to C.B.S.E. (Up to X) Affiliation No. : 330246
Careers' Colony, Purnea
Phone No. : 9334474858, 9835133209, 9304158682
ADMISSION NOTICE
NUR TO IX
Registration Open
Admission will be taken only against vacant seats
Last date for Registration : 24.03.12
Date for Admission Test : 25.03.12

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Authorised Study Centre of EIILM University. Code-CIIP/101683
Diploma/PG Diploma/Bachelor Degree/PG Degree in the following Subjects :
Fire Safety Management • Industrial Safety Management
FREE
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
YEAR GUARANTY
WINNER OF NATIONAL AWARD
Contact : 9386595926, 9334115955



दो दर्जन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के बाबत कंप्यूटर लगाए गए, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रशिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकी.

# करोड़ों के कंप्यूटर भगवान भरोसे

अरूण साथी

विद्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए अख़बारों में विज्ञापन दिए गए. प्रमुखता के साथ मीडिया में इस ख़बर को उछालकर शाइनिंग बिहार की छवि भी बनाई गई. इसके बावजूद कंप्यूटर शिक्षा योजना धरातल पर उतर नहीं सकी. विभागीय जानकारी के मुताबिक़, ज़िले के कुल 18 उच्च विद्यालयों को लगभग दो करोड़ की राशि से कंप्यूटरीकृत किया गया. विद्यालय में प्रतिनियुक्त कंप्यूटर शिक्षक को कंप्यूटर प्रशिक्षण के नाम पर वेतन से लेकर अन्य ख़र्च भी दिए जा रहे हैं. लेकिन फलाफल शून्य है. प्रतिनियुक्त शिक्षक घरों में आराम फ़रमाते हैं और बच्चों को बिना पढ़े ही प्रमाण पत्र मिल जाते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाओं की विडंबना इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि कंप्यूटर लगाने में करोड़ों रुपये ख़र्च कर दिए गए, लेकिन इसकी सुरक्षा भगवान भरोसे है.

सुरक्षा को लेकर उच्च विद्यालय बरबीघा के प्राचार्य डॉ. लाखपति शर्मा कहते हैं कि जर्जर भवन में कंप्यूटर रखा गया है. सुरक्षा की दृष्टिकोण से हटाने को लेकर (पत्रांक 7/11, दिनांक 08/09/2011) बेल्ट्रोन कंपनी को पत्र लिखा गया. इसके आलोक में सरकार की ओर से 70,000 हज़ार रुपये ख़र्च करने की स्वीकृति भी मिल गई, लेकिन आज तक वहां से सिस्टम नहीं हटाया गया. सुरक्षा व्यवस्था का हाल यह है कि कबाड़ को छिपाने के लिए बेंच-डेस्क का सहारा दिया गया है. कमरे की जर्जरता, कंप्यूटरों पर जमी धूल, दीवारों पर उग आए पेड़-पैधे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षा का यहां क्या हाल है. हद तो तब दिखती है जब कंप्यूटर शिक्षा के बाबत जनरेटर भी ख़रीद लिए गए, लेकिन जनरेटर शायद चलता ही नहीं है. इस संबंध में बेलाव उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक कहते हैं कि डीजल की व्यवस्था नहीं की गई है और बिजली की उपलब्धता भी नहीं है, तो फिर कंप्यूटर चलेगा कैसे. विद्यालय के छात्र सोनू कुमार, राजू कुमार आदि का कहना है कि कंप्यूटर तो दे दिया गया है, लेकिन सिर्फ़ देखने के लिए. कंप्यूटर सीखने की इच्छा तो होती है, लेकिन किया क्या जाए. इस्लामिया विद्यायल की छात्राओं की प्रबल इच्छा के बाद भी उनकी तमन्नाएं कभी-कभी पूरी हो पाती हैं.

कोसरा उच्च विद्यालय में कंप्यूटर का दर्शन भी विद्यार्थियों ने नहीं किया है. यह विद्यालय सुदूरवर्ती गांव में है. लोगों को इस बात की आशंका है कि यहां से कभी भी कंप्यूटर की चोरी हो सकती है. अभी तक इस ओर किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी का ध्यान नहीं जाना लोगों के लिए आकाश कुसुम बना हुआ है. बिहार नवनिर्माण मंच के प्रदेश प्रवक्ता शिवकुमार की मानें तो यह सब हाई लेवल मैनेजमेंट का फंडा है. दूसरी ओर प्रखंड के चयनित दो मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर लगाया गया है. विद्यालयों में लगाया गया कंप्यूटर चोरी हो गया, जबकि अन्य विद्यालयों के कंप्यूटर हेडमास्टर के घर की शोभा बढ़ा रहे हैं. हालांकि एक मात्र टाउन मध्य विद्यालय में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा अवश्य दी जा रही है. इस संबंध में जिलाधिकारी बिरेंद्र प्रसाद का कहना है कि कंप्यूटर आधुनिक दुनिया का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस योजना को नज़रअंदाज़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में ज़िला शिक्षा पदाधिकारी ठाकुर मनोरंजन प्रसाद कुछ भी कहने से कन्नी काट गए.

feedback@chauthiduniya.com

शेखपुरा

**विद्यालय के छात्र सोनू कुमार, राजू कुमार आदि का कहना है कि कंप्यूटर तो दे दिया गया है, लेकिन सिर्फ़ देखने के लिए. कंप्यूटर सीखने की इच्छा तो होती है, लेकिन किया क्या जाए.**

समस्तीपुर

# बस नाम की कंप्यूटर शिक्षा

समस्तीपुर ज़िले में भी कंप्यूटर शिक्षा योजना ख़स्ताहाल है. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए लाखों रुपये के कंप्यूटर विभिन्न विद्यालयों में रखे पड़े हैं, लेकिन छात्र-छात्राओं को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है. कहीं साधन संसाधन के अभाव में कंप्यूटर रखे पड़े हैं, तो कहीं कंप्यूटर प्रशिक्षक नहीं रहने के कारण कंम्यूटर शिक्षा से छात्र-छात्राएं वंचित हैं. अगर किसी विद्यालय में प्रशिक्षक की नियुक्ति हुई भी है, तो उन्हें स्वयं ही कंप्यूटर संचालन की वास्तविक जानकारी नहीं है. जानकारों का कहना है कि पैरवी पुत्रों की प्रतिनियुक्ति बतौर प्रशिक्षक होने के कारण यहां कंप्यूटर शिक्षा योजना दम तोड़ती नज़र आ रही है. समस्तीपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हसनपुर, कल्याणपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय जितवरिया, विद्यापतिनगर के मध्य विद्यालय वाजिदपुर, मोहनपुर के मध्य विद्यालय रसलपुर, मोहिद्दीनगर के मध्य विद्यालय कल्याणपुर बस्ती, सरायरंजन मध्य विद्यालय, मोरवा के मध्य विद्यालय अमृतपुर, उजियारपुर कन्या मध्य विद्यालय, पूसा के मध्य विद्यालय बैनी, राजकीय मध्य विद्यालय दलसिंहसराय, पटोरी के मध्य विद्यालय चकसलेम सहित लगभग दो दर्जन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के बाबत कंप्यूटर लगाए गए, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रशिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकी. नतीजतन, इस ज़िले में कंप्यूटर शिक्षा योजना का हश्र काफ़ी बुरा दिख रहा है. कई विद्यालय के छात्र-छात्राओं का कहना था कि इस हाईटेक युग में भी कंप्यूटर का ज्ञान बच्चों को नहीं दिया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार की कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का अंतर है. राज्य सरकार द्वारा स्कूली बच्चों को सरकारी स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा से लैस करने की घोषणा तो की गई, लेकिन इसके लिए ईमानदार प्रयास नहीं किया गया. हालांकि यह अलग बात है कि सरकारी घोषणा के अनुसार विभिन्न विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध ज़रूर कराए गए, परंतु कंप्यूटर संचालन के लिए साधन संसाधन की व्यवस्था नहीं की गई. कहीं जेनरेटर नहीं रहने के कारण कंप्यूटर ऑन तक नहीं किया गया तो कहीं प्रशिक्षक नहीं रहने के कारण कंप्यूटर शिक्षा से बच्चों को जोड़ा नहीं गया.

प्रकाश कुमार
feedback@chauthiduniya.com

# एक नज़र

## साहित्य और पौधों के बीच गहरा रिश्ता

साहित्य और पौधों के बीच चोली दामन का रिश्ता है. जिस प्रकार एक पौधा पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, उसी प्रकार साहित्य भी समाज की बुराइयों और अच्छाइयों को उजागर कर एक दिशा एवं दशा तय करता है. उक्त बातें हनुमानशरण कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विमल नारायण आर्य ने पटना के बोरिंग कैनाल रोड स्थित पंचमुखी हनुमान के पास शिवम् क्लासेज कुर्जी पटना के सौजन्य से आयोजित एक दिवसीय पर्यावरण सह पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहीं. प्रदर्शनी के मौक़े पर कथाकार डॉ. लालजी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित 36 शीर्षकों में उपलब्ध पुस्तकें रखी गई थीं. महज़ तीस रुपये में मिलने वाली पुस्तकों के साथ पाठकों को उनकी पसंद का एक पौधा नि:शुल्क दिया गया. प्रो. बीके राय, प्रो. सीडी सिंह, मनोज कुमार, प्रो. नवीन कुमार, गणितज्ञ प्रो. पंकज कुमार, प्रो. भूपेंद्र कुमार, डॉ. शारदा झा, डॉ. पवन कुमार झा, युवा नेता अरूण कुमार सिंह, चितरंजन नारायण आर्य, प्रो. संजय ठाकुर, हरिद्वार सिंह, रीना सिन्हा, मीरा कुमार, प्रो. रूपराधा, डॉ. उर्मिला कुमार, प्रो. मधु, प्रो. सरिता सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र सिंह, सुबोध कुमार सिंह आदि की मौजूदगी में डॉ. लालजी प्रसाद सिंह ने कहा कि रोड शो और नुक्कड़ नाटक के ज़रिये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को शिक्षित एवं जागरूक करना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है.

## जमालपुर रेल कारख़ाने को लेकर आंदोलन

मुंगेर ज़िले के जमालपुर रेल इंजन कारख़ाने की बदतर स्थिति से नाराज़ लोगों का ग़ुस्सा धीरे-धीरे परवान चढ़ता जा रहा है. जमालपुर रेल निर्माण कारख़ाना संघर्ष मोर्चा द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है. इसी क्रम में बीते दिनों जमालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह मोर्चा सदस्य पप्पू यादव के नेतृत्व में धरना दिया गया. धरनार्थियों को संबोधित करते हुए राजद जिलाध्यक्ष मोहन यादव, टीएमसी जिलाध्यक्ष दीपक सिन्हा, जदयू के वरीय नेता विजय आज़ाद, छात्र राजद के प्रदेश महासचिव विनोद यादव, सपा के वरीय नेता राकेश गोप, सुनील कुमार पिंटू, युवा जदयू के वरीय नेता राणा सिंह, युवा जदयू के प्रदेश सचिव सह मोर्चा प्रवक्ता आदि ने कहा कि गोल्फ मैदान में हो रहे निर्माण कार्य के नाम पर मची लूट की उच्चस्तरीय जांच कराने, आउट सोर्सिंग पर अविलंब रोक लगाने, आरपीएफ की मिलीभगत से रेलवे की संपत्ति की हो रही चोरी पर रोक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई सार्थक क़दम नहीं उठाया जाना लोगों को उद्धेलित करने के लिए काफ़ी है.

## जेईई क्लासेज की नई स्टडी सेंटर का उद्घाटन

जेईई क्लासेज को रोल मॉडल बनाए बग़ैर सरकार द्वारा बनाई गई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं आधुनिक तकनीक की कोचिंग व्यवस्था का हाल सुधर नहीं सकता है. उक्त बातें पटना के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने सगुना मोड़ स्थित शशिधर कुंज में जेईई क्लासेज की नई स्टडी सेंटर का उद्घाटन करते हुए कही. मुंबई आईआईटी से आए प्रो. टीएन सिंह ने भावुक शब्दों में कहा कि एएन सिंह की इच्छा माईग्रेशन को रोकने की थी. बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार के निर्माण में जो भूमिका निभाई, उसकी सराहना सभी कर रहे हैं. संस्थान के सचिव इंजीनियर एएन सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहारी बच्चों का भविष्य सुधारना उनकी पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर को उठाने में वह अपना योगदान देते रहेंगे. मौक़े पर विधायक प्रेमरंजन पटेल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे.

*-चौथी दुनिया ब्यूरो*

## सड़क की जर्जरता से परेशानी

खगड़िया ज़िले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत रामपुर उर्फ़ रहीमपुर पंचायत स्थित मोजाहिदपुर गांव के समीप जर्जर सड़क के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन संबंधित विभाग के पदाधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण लोगों में आक्रोश पनपने लगा है. पूर्व सरपंच योगेंद्र साह का कहना है कि उनके घर के पास सड़क बनाने के समय भंवरा बनाया गया था. एक बार डैमेज होने के बाद विभागीय स्तर से मरम्मत तो कराई गई, लेकिन इसके बाद विभागीय पदाधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया. नतीजतन, लोगों को इस सड़क के पार करने में काफ़ी परेशानी होती है. उधर, स्थानीय मुखिया कैलाश शर्मा का कहना है कि ध्वस्त हुए भंवरे का निर्माण पहले किया गया था. जल्द ही इस भंवरे का निर्माण होना चाहिए. दूसरी तरफ़ विभाग के कार्यपालक अभियंता सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि वह अभी अवकाश पर हैं. अवकाश से वापस लौटते ही मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

*-गीता कुमार*

# सारण एक नज़र

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India
Relationships beyond banking.

## रोट्रेक्ट क्लब का सम्मान समारोह

रोट्रेक्ट और छपरा सिटी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन अनूप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ. इस अवसर पर सभी सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं. पटना में आयोजित जनसंख्या अभिशाप विषयक वाद-विवाद प्रतियोगिता में रोट्रैक्ट के संस्थापक अध्यक्ष ने बिहार के कोने-कोने से आए हुए प्रतियोगिताओं को मात देकर छपरा शहर का नाम रौशन किया और इस प्रतियोगिता के विजेता हुए. आइडियल आइज द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में बहुत सारे धुरंधरों ने अपनी प्रतिभा दिखाई. इसी ख़ुशी के अवसर पर रोट्रक्ट परिवार ने सीताराम सिंह को सम्मानित किया. रोट्रेक्ट अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव ने आइडियल आइज प्रबंधक, अध्यक्ष पंकज कुमार, सचिव शकील अख्तर, राजू कुमार सहित समस्त आइडियल आइज परिवार को धन्यवाद दिया. इस अवसर पर रोट्रेक्ट सचिव तरुण प्रकाश विशाल गौरव, पंकज कुमार, अर्चना सिंह, आलोक कुमार, हेमांत सोनी, शब्द राज श्रीवास्तव, अमन कुमार आदि उपस्थित थे.

## छात्र ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे

एकमा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विधालय, गाजीपुर के वर्ग सात एवं आठ के छात्र-छात्राएं मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत विभिन्न ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का परिभ्रमण करेंगे. यह जानकारी प्रधानाध्यापक वेदप्रकाश प्रसाद ने दी. उन्होंने बताया कि छात्रों के साथ शिक्षक मनोज कुमार, अवधेश कुमार सिंह, संतोष कुमार यादव, विक्रमा सिंह एवं सविता देवी भी रहेंगे.

## बैंक की फ्रेंचाइजी शुरू

दरियापुर प्रखंड क्षेत्र के बेला गांव में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की फ्रेंचाइजी का उद्घाटन प्रदेश प्रमुख चितरंजन शर्मा ने किया. इस मौक़े पर क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने खाता खोलकर शुरुआत की. उद्घाटन समारोह में फ्रेंचाइजी संचालक मोहम्मद अंसारी, मनोज कुमार, पूर्व मुखिया रामनाथ ठाकुर समेत अन्य उपस्थित थे.

## फगुआ में उडेला अबीर

छपरा के नगरपालिका चौक पर होली के गीत गाते हुए राज्य के सुख्यात गायक रामेश्वर गोप के गीत फगुआ में उडेला अबीर, जोगिरा शारारार..., और बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर के फगुआ गीत सुनकर छपरावासी झूम उठे. इस अवसर पर मॉरिशस-भारत सांस्कृतिक संगठन की प्रतिनिधि सरिता बुद्धू, प्रोफेसर लालबाबू यादव आदि ने भी कार्यक्रम में सहयोग किया. थाना परिसर में होली के मद्देनज़र शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. कार्यक्रम की अध्यक्षता थानाध्यक्ष कमलेश्वर कुमार सिंह ने की.

## विश्व संवाद केंद्र का प्रशिक्षण संपन्न

छपरा शहर के कचहरी रोड स्थित बाबेज इंस्टीट्यूट में विश्व संवाद केंद्र द्वारा आयोजित सात दिवसीय पत्रकारिता प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ. समापन समारोह को संबोधित करते हुए संवाद केंद्र के ज़िला संयोजक-सह प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर के रामदयाल शर्मा ने कहा कि पत्रकारिता समाज का दर्पण है. संस्था के निदेशक रविशेखर कुशवाहा ने धन्यवाद ज्ञापन किया. समारोह के उपरान्त रंग अबीर एक दूसरे को लगाकर बधाई दी. इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से प्रो. राजू कुमार, जयशंकर, इरशाद आलम, प्रियंका, आस्था, सुभम, बिनय राजेश, दिलीप, मनोरंजन, संतोष , देवेंद्र , रमेश, मुकेश, तपन, उज्जवल, अवलोक,ट्विंकल ,मुन्ना, सत्येंद्र , रविशंकर इत्यादि उपस्थित थे.

## सरकार सभी मोर्चों पर विफल : क़ैसर

क़ौमी एकता समिति के तत्वाधान में आयोजित होली मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि चौधरी, महबूब अली क़ैसर ने छपरा के एकता भवन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि होली का त्योहार सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है. नज़रे हसन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सारण में एकता की मिसाल क़ायम करेगा. सूबे की सरकार हर मोर्चे पर विफल है. सभा को संबोधित करने वालों में जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह भारद्वाज, नज़रे हसन, डॉ. कामेश्वर सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह, नरेंद्र मिश्र, नूरुद्दीन ख़ां, अनूप श्रीवास्तव, रविशंकर सिंह मुन्ना, अनिल कुमार सिंह, मनोज पांडेय, नदीम अख्तर अंसारी, प्रितम यादव, राकेश सिन्हा, चंद्रावती देवी, रंभा देवी, मोहम्मद सुल्तान, अमित मनु पांडेय, मिलन कुमार सिन्हा, शौकत ख़ां, आलोक कुमार, जयराम राय आदि प्रमुख थे.

## हुजरा शाह का उर्स मनाया

पानापुर प्रखंड के उधवा सारंगपुर स्थित दरगाह हुजरा शाह का सालाना उर्स मनाया गया. इसमें मुसलमानों के साथ हिंदू भाइयों ने भी शिकरत की. इस मौक़े पर मदरसा कादरिया चिश्तिया सारंगपुर से इमाम मौलाना ज़ियाउद्दीन की निगरानी में जुलूस निकाला गया. इसमें अक़ीदतमंदों ने शिरकत कर जोश व जज्बे के साथ चादरपोशी की. इस मौक़े पर आयोजित समारोह में उलेमाओं ने हुजरा शाह की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और मुल्क के अमन के लिए दुआएं कीं. महफ़िल में शायर आज़म, मोहम्मद मिराज शिवानी, शाहिद रज़ा, ईद मोहम्मद भी मौजूद थे. इस मौक़े पर मोहम्मद शबीब पूर्व प्रमुख मोहम्मद कलाम, सचिव बाबूजान मियां, मक़बूल मियां, मोहम्मद ज़ाहिद हुसैन उपस्थित थे.

प्रस्तुति-शुभम् रानी चौहान, मनीष कश्यप, जयनाथ सिंह

यह संगठन हज़ारीबाग़ में बैठकर दिल्ली और मुंबई को दहलाने की योजना बनाता था. हालांकि स्थानीय पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण पर जानकारी जुटाकर दोषियों के ख़िलाफ़ कारवाई की जाएगी.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

# नक़ली तेल का काला कारोबार

नीरज कुमार सिंह

सुशासन की सरकार सेहत और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है, वहीं सीमांचल के बाज़ारों में पड़ोसी राज्य बंगाल के साथ-साथ अन्य प्रांतों से आने वाले अमानक खाद्य तेलों की बिक्री जारी है. इससे लोगों की सेहत प्रभावित हो रही है. जहां एक ओर बिहार सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्रसिद्ध मंडी गुलाबबाग़ समेत सीमांचल के अन्य शहरों के शुद्ध तेल का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है. गुलाबबाग़ समेत अररिया, किशनगंज, कटिहार आदि जगहों में खाद्य तेल की आपूर्ति मुख्यत: मध्य प्रदेश के मुरैना, राजस्थान के जयपुर एवं भरतपुर, हरियाणा के हिसार एवं बंगाल से होती है. मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान में तिलहनी फ़सलों की अधिक पैदावार होने के कारण तेल मिलों की संख्या अधिक है. पश्चिम बंगाल के मिल बहुत हद तक दूसरे राज्यों से आनेवाली तिलहनी फ़सलों पर निर्भर करते हैं. सीमांचल से सटे बंगाल के कलियागंज, रायगंज, दालकोला, कानकी, इस्लामपुर, सोनापुर, सिल्लीगुड़ी में मिलों के साथ सरसों तेल के डिब्बों, बोतलों एवं टीनों में पैकिंग करने के व्यवसाय ने उद्योग का रूप ले लिया है, जिसमें डीजल, पेट्रोल ढोने वाले टैंकरों से ब्राउन ऑयल (धान के भूसे का तेल) पाम ऑयल, हल्दिया (कोलकाता) से मंगाए जाते हैं, जबकि सरसों तेल, पाम आयल एवं एसेंस मिलाकर एक नए मार्का का सरसों का तेल तैयार किया जाता है. बिक्री हेतु बंगाल के अलावा किशनगंज का चप्पा-चप्पा, पूर्णिया के बायसी अनुमंडल, कटिहार के बारसोई, अनुमंडल अररिया के सिकटी पलासी जो, सिक्किम तथा नेपाल तक भेजा जाता है. ऐसे तैयार ब्रांडों में पीएस (सिल्लीगुड़ी), कमल (सोनापुर), कलश (रामगंज), क्रांति (इस्लामपुर), कमल फूल (कानकी), प्रिया गोल्ड एवं एके मार्का कलियागंज, दालकोला, रायगंज में तैयार होने वाले कई और नाम भी हैं. बंगाल के तेल पेकिंग व्यवसाय से प्रेरित होकर सीमांचल के व्यवसायियों ने भी बाज़ारों की प्रतिस्पर्धा से टक्कर लेने के लिए गुलाबबाग़, फारबिसगंज, कटिहार, सहरसा, किशनगंज जैसे शहरों में सरकारी लाइसेंस लेकर सरसों तेल के इस व्यवसाय को चालू किया है. वैसे बंगाल में कुछ नामी ब्रांडों के सरसों तेल तथा डालडा की डुप्लीकेसी होती है. यही कारण है कि सीमांचल के व्यवसायियों की प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ गई है. सीमांचल में तेल मिल चालू होने से जहां बिहार सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिला. 4 दिसंबर, 2010 को पूर्णिया के गुलाबबाग़ में एक तेल मिल रीफीलिंग प्रतिष्ठान पर पूर्णिया अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में मालिक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराया गया. इस छापेमारी के बाद सीमांचाल के 10 उद्योग व्यवसायी भयवश प्रभावित तो हुए ही, हज़ारों लोग बेरोज़गार भी हो गए. छापेमारी के बाद स्थानीय लोगों का कहना था कि तीन वर्षों के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस की नज़र प्रतिष्ठान पर आख़िर कैसे गई. माना कि प्रतिष्ठान में गड़बड़ी हो रही थी तो फिर स्वास्थ्य विभाग एवं फूड इंस्पेक्टर विगत तीन वर्षों से हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे. सवाल यह उठता है कि बिना प्रयोगशाला परीक्षण के कोई कैसे कह सकता है कि बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही थी? कुछ लोगों का यहां तक भी कहना था कि मुरैना (मध्य प्रदेश) के तेल कारोबारी को बिहार में फैलते तेल मिल एवं रीफीलिंग का धंधा उनकी आंखों में कांटे चुभो रहा था. गुलाबबाग़ में इस मामले के बाद सरकार ने सीमांचल में अमानक खाद्य तेल एवं खाद्य पदार्थों की जांच के लिए तीन सदस्यीय खाद्य निरीक्षकों की टीम भेजी, जिसने जांच के नाम पर पूरे सीमांचल के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में व्यवसायियों से उगाही की. इसकी जांच की कोई भी रिपोर्ट आज तक जनता के सामने नहीं आ सकी. साथ ही इतना तो ज़रूर हुआ कि तेल रीफीलिंग मिल से मिलने वाला सरकारी राजस्व जहां बंद हो गया, वहीं हज़ारों लोग बेरोज़गार भी हो गए. जानकारों का कहना है कि जहां उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार उद्योगपतियों को प्रोत्साहन के साथ राज्य में आने के लिए आमंत्रित कर रही है, वहीं प्रशासनिक चूक से छोटे-मोटे उद्योग बंद होते जा रहे हैं. इस धंधे का दूसरा पहलू यह है कि विभिन्न राज्यों में खाद्य तेलों पर लगने वाले टैक्स में व्यवसायी टैक्स चोरी के विभिन्न उपाय अपनाते हैं. इसका कारण भी है, विभिन्न राज्यों में खाद्य तेलों पर लगने वाला सीएसटी पूरे भारत में 2 प्रतिशत है, जबकि विभिन्न राज्यों में लगने वाले वैट में काफ़ी अंतर है. बंगाल में वैट 2 प्रतिशत है, जबकि बिहार में वैट 3 प्रतिशत है. बंगाल में उत्पादित खाद्य तेलों को बंगाल में बेचने पर कुल टैक्स 4 प्रतिशत लगता है, वहीं बिहार में बेचने पर कुल 7 प्रतिशत टैक्स लगता है. हिसार, मुरैना तथा जयपुर से चलने वाले सरसों तेल पर बंगाल में 6 प्रतिशत टैक्स लागू होता है. बंगाल की बिल्टी (काग़ज़ात) पर चलने वाले सरसों तेल के ट्रक का माल रातों-रात गुलाबबाग़, फारबिसगंज, अररिया, कटिहार, किशनगंज में ख़ाली हो जाता है. जनवरी 2012 में पूर्णिया सदर पुलिस ने गुलाबबाग़ पोलोग्राम के समीप रात्रि में खाद्य तेलों से लदा ऐसा ही एक ट्रक को पकड़ा था. इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि यह माल बाज़ार समिति प्रांगण स्थित गणेश ट्रेडिंग एवं वर्तमान अजित ट्रेडिंग का था.

**बंगाल में कुछ नामी ब्रांडों के सरसों तेल तथा डालडा की डुप्लीकेसी होती है. यही कारण है कि सीमांचल के व्यवसायियों की प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ गई है. सीमांचल में तेल मिल चालू होने से जहां बिहार सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिला. 4 दिसंबर, 2010 को पूर्णिया के गुलाबबाग़ में एक तेल मिल रीफीलिंग प्रतिष्ठान पर पूर्णिया अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व के मालिक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराया गया.**

इन प्रतिष्ठानों का तेल गोदाम सिल्लीगुड़ी-पूर्णिया मार्ग पर दमका चौक पर स्थित है और यह माल सिल्लीगुड़ी में लादा गया था. वर्तमान स्थिति यह है कि सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया का बायसी अनुमंडल, अररिया एवं कटिहार के बारसोई अनुमंडल में बंगाल का खाद्य तेल धड़ल्ले से बिकता है, वहीं बिहार को वाणिज्य कर की क्षति भी हो रही है. इस संबंध में पूर्णिया प्रमंडल के वाणिज्यकर आयुक्त अरुण कुमार वर्मा का कहना है कि जब तक सभी राज्यों में वाणिज्य कर को लेकर समानता नहीं आएगी, तब तक इस तरह का व्यापार चलता रहेगा. जब उनसे पूछा गया कि बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाणिज्य कर की चोरी रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि विभागीय लोग वाणिज्य कर की अधिक से अधिक वसूली को लेकर सक्रिय हैं.

feedback@chauthiduniya.com

# झारखंड आतंक के साये में

आतंकी तौशिफ

चंद्रेश शर्मा

झारखंड राज्य के गठन को 11 साल 4 माह हुए हैं. इन 11 वर्षों में राज्य का कितना विकास हुआ, इसका लेखा -जोखा सरकार के अगुआ रहे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री एनोस एक्का, कमलेश सिंह सरीखे राजनेताओं के बैंक खातों में जमा हज़ारों करोड़ रुपये के वारे न्यारे को जनता ने देखा. राज्य में सक्रिय नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों से राजनेताओं की मिलीभगत भी समय-समय पर सामने आती रही. राज्य में शायद ही कोई राजनीतिक संगठन होगा, जिससे माओवादियों के संबंध जगज़ाहिर नहीं हुए हों, लेकिन सरकारी मशीनरी ने कभी इस दिशा में कोई ठोस क़दम नहीं उठाया. इसका लाभ झारखंड में सक्रिय कट्टरपंथियों ने भी उठाया. लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों ने भी राज्य में अपने पांव पसार लिए हैं और इन्हें भी राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है. हाल में दिल्ली में जिन दो आतंकियों को पकड़ा गया था, उनमें से एक एहतेशाम का ममेरा भाई तौशिफ़ अहमद पीर को दिल्ली पुलिस के सहयोग से हज़ारीबाग़ में पकड़ा गया. पकड़े गए लश्कर के आतंकी तौशिफ़ अहमद पीर के मामले ने राज्य में जड़ जमाए आतंकी नेटवर्क का ख़ुलासा किया है, जिसने यह बताया कि स्थानीय नेटवर्क के सहारे कश्मीर के निवासी ने किस प्रकार से हज़ारीबाग़ के पेलावल थाना क्षेत्र में ज़मीन ख़रीदकर पहले तो कश्मीर हाउस नाम का आलीशान भवन बनवाया और फिर हज़ारीबाग़ में बैठकर लश्कर-ए-तैयबा का नेटवर्क चलाया. यह संगठन हज़ारीबाग़ में बैठकर दिल्ली और मुंबई को दहलाने की योजना बनाता था. हालांकि स्थानीय पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण पर जानकारी जुटाकर दोषियों के ख़िलाफ़ कारवाई की जाएगी.

पुलिस अधीक्षक पंकज कंबोज की मानें तो जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठा दिया जाएगा और इसमें संलिप्त सफ़ेदपोशों के चेहरों से नक़ाब उठाया जाएगा. पुलिस के मुताबिक़, इस बात की जांच की जा रही है कि कैसे एक कश्मीरी को हज़ारीबाग़ में मकान बनाने की इजाज़त दी गई. झारखंड से पकड़े गए आतंकवादी तौशिफ़ अहमद पीर का पूरा परिवार ही आतंकी संगठन के लिए काम करता है. इसके मामा और मौसा भी आतंकी हैं. तौशिफ़ ने पूछताछ में यह भी ख़ुलासा किया कि वह लश्कर कमांडर अबु बदर को क़रीब से जानता है. उसने लश्कर में शामिल अपने पांच सहयोगियों के नाम भी बताएं, जिनमें उसका मौसेरा भाई कश्मीर का सौपोर निवासी ज़ुबैर अहमद मलिक, सोपोर के फ़ैज़ल अहमद ग़ज़ाली, शौकत अहमद, एहतेशाम एवं हाजी महरजापुरा का नाम शामिल है. मूलत: कश्मीर के बादामीबाग़ सौपोर निवासी तौशिफ़ 2008 में ऐहतेशाम के साथ लश्कर से जुड़ा था. हालांकि झारखंड के लिए यह कोई नया मामला नहीं था. इसके पूर्व भी 28 जनवरी, 2002 को हज़ारीबाग़ के खिरगांव मुहल्ले में दिल्ली पुलिस के सहयोग से हज़ारीबाग़ पुलिस ने दो आंतकियों को मार गिराया था. मारे गए आतंकियों में पाकिस्तान के मुल्तान निवासी इदरीस उर्फ़ वाजिद उर्फ़ जाहिद एवं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत निवासी मोहम्मद सलीम शामिल था. उस वक़्त इस मामले ने भी काफ़ी तूल पकड़ा था. पुलिस द्वारा की गई जांच में यह ख़ुलासा हुआ था कि बिहार के गया ज़िले का सदाक़त तथा हज़ारीबाग़ का एक बस व्यवसायी के सहयोग से आतंकियों को स्थानीय स्तर पर संरक्षण था. उस वक़्त हज़ारीबाग़ में पुलिस अधीक्षक के तौर पर दीपक वर्मा पदस्थापित थे. पुलिस को जांच के दौरान यह स्पष्ट तौर पर पता चल गया था कि हज़ारीबाग़ का उक्त आरोपी बस व्यवसायी कौन था? आपको यहां बताते चलें कि आरोपी बस व्यवसायी मूल रूप से झारखंड के चतरा ज़िले का निवासी है, जो अपने व्यवसाय के सिलसिले में हज़ारीबाग़ में ही सैटल हो गया है. इसके बावजूद उसके नाम का ख़ुलासा नहीं किया गया.

आश्चर्य की बात यह रही कि घटना के बाद जो वस्तुस्थिति सामने आई, उसे बड़े ही नाटकीय तरीक़े से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. उस वक़्त यह चर्चा ज़ोरों पर रही कि राज्य के सत्ताधारी दल के एक राजनेता ने पुलिस को मैनेज करने के लिए ऊपर से दबाव डलवाने में अहम भूमिका निभाई. राजनेताओं और पुलिस की दरियादिली का ही नतीजा रहा कि आंतकी अपनी गतिविधियां चलाते रहे और सरकार को कानो-कान ख़बर नहीं हुई. आपको यह बता दें कि अगर 2002 में ही पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाकर आंतकियों के संरक्षक सदाक़त और बस व्यवसायी के ख़िलाफ़ गंभीरता पूर्वक कारवाई की होती तो शायद आतंकी घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय पटल पर झारखंड की छवि शायद इतनी ख़राब नहीं होती.

feedback@chauthiduniya.com

# चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 19 मार्च-25 मार्च 2012

www.chauthiduniya.com

# फिर कसौटी पर होगा मुलायम राज

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश के नतीजे राजनीतिक पंडितों को भले ही चौंकाने वाले लग रहे हों लेकिन जनता ने कहीं कोई ग़लती नहीं की. जनता ने वर्ष 2007 में समाजवादी पार्टी से तंग होकर बहुजन समाज पार्टी को सत्ता पर बैठाया था तो इस बार बहुजन समाज पार्टी को उसकी करनी की सजा देते हुए समाजवादी पार्टी को गद्दी दिला दी. कांग्रेस और भाजपा का जब आधार ही नहीं था, तो फिर मतदाता उन्हें वोट क्यों करता. कांग्रेस और भाजपा को वोट देने का साफ़ मतलब था कि राज्य में एक बार फिर खिचड़ी सरकार का बुरा दौर शुरू होना. खिचड़ी सरकार मायने लूटने-खसोटने वाले सब, जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं. जनता नहीं चाहती थी कि जिसको गद्दी मिले वह कोई बहानेबाज़ी कर पाए. मिली-जुली सरकारों में ऐसा नहीं हो पाता है, यह सच्चाई अतीत और वतर्मान दोनों में देखी जा सकती है. उत्तर प्रदेश का दस साल से पहले का इतिहास उठा कर देखा जाए या फिर वतर्मान में केंद्र की खिचड़ी सरकार की कार्यशैली सभी जगह हुक़ूमत कमज़ोर और लाचार नज़र आती है. गठबंधन में शामिल दल फ़ायदा तो उठाते रहते हैं लेकिन सरकार की दुश्वारियों की उन्हें कोई चिंता नहीं होती. फलस्वरूप भ्रष्टाचार पनपता है, क़ानून व्यवस्था बिगड़ती है. जनता के हित में कड़े फ़ैसले लेने की हिम्मत शीर्ष पर बैठे लोग जुटा नहीं पाते हैं. दबाव की राजनीति चरम पर पहुंच जाती है. अगर मायावती सरकार बहुमत के साथ सत्ता में न होती तो उनके ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना सशक्त नहीं हो पाता. वह अपनी कर्मों का घड़ा दूसरे पर आसानी से फोड़ देती, जैसा दिल्ली में हो रहा है. जनता नहीं चाहती थी कि राज्य में ऐसे हालात पैदा हों. उसे पता था कि पिछले पांच सालों में सपा को छोड़कर किसी भी दल ने जनता के लिए संघर्ष नहीं किया. चाहें राहुल हों या फिर भाजपा नेता. राहुल गांधी ने दलितों के घर ख़ूब खाना खाया, गांवों में चौपाल लगाई, लेकिन कभी भी लखनऊ आकर मायावती सरकार के ख़िलाफ़ धरना-प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं जुटाई. जनता की समस्याओं से उनका कोई नाता नहीं रहा. वह वहां पहुंचते थे, जहां उन्हें लगता था कि उन्हें राजनीतिक फ़ायदा होगा. चाहें भट्टा पारसौल हो या फिर बुंदेलखंड. राहुल ने जनता से अपने लिए तो बहुत कुछ मांगा, लेकिन जनता को उनसे क्या मिल रहा है, यह नहीं सोचा. केंद्र के मंत्री प्रदेश का हिस्सा छिनने की कोशिश करते रहे. राहुल की जुबान पर कुछ रहता था और दिल में कुछ. जिस जनता को वह बेवकूफ समझते थे, उसी जनता ने यह बात पढ़ ली. कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं थी. कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे वह कांग्रेस की बजाए गांधी परिवार के प्रति ज़्यादा निष्ठावान दिखाई पड़ रहे थे. चाहें सलमान हों या फिर जायसवाल, रीता बहुगुणा या अन्य कोई नेता. यही हाल भाजपा का था. भाजपा नेता भी ज़मीनी लड़ाई से काफ़ी दूर थे. वह बयानबाज़ी से चुनाव जीतना चाहते थे. भाजपा नेताओं के बीच अंतरविरोध हमेशा बड़ी समस्या बना रहता है, इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला. भाजपा दूर-दूर तक लड़ाई में नहीं थी, लेकिन भाजपा में मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं की कोई कमी नहीं थी. भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अलग से प्रयोग पर प्रयोग करता रहा. उमा भारती को खोज कर निकाला गया तो बाबू सिंह कुशवाहा जैसे भ्रष्टाचारियों से भी उसे हाथ मिलाने में परहेज नहीं हुआ. जिनके कंधों पर अपने दल के प्रत्याशियों को जिताने का दारोमदार था, वह अपनी ही सीट नहीं बचा पाए. इसके विपरीत सपाइयों ने कई बार बसपा सरकार को चुनौती दी. बसपा सरकार की शह पर पुलिस ने सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कई बार जुल्म ढाए. उन पर लाठी भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े, जेलों में बंद कर दिया गया. कुछ मौक़ों पर तो मुलायम सिंह यादव स्वयं अगुवाई करते हुए दिखे. मुलायम का अनुभव और अखिलेश के जोश ने इस सपा को आंख का तारा बना लिया जिसे पांच वर्ष पहले जनता ने आंख की किरकिरी समझ कर फेंक दिया था.

सपा क्यों जीती इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल अखिलेश का रहा. अखिलेश ने न तो राहुल की तरह बड़ी-बड़ी बातें की न कहीं गुस्सा दिखाया. अपने विरोधियों का भी वह सम्मान करते दिखे. उन्होंने उन नेताओं के ख़िलाफ़ भी कुछ जुबान नहीं खोली जो सपा के साथ व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे थे. राहुल को बात-बात पर गुस्सा आता लेकिन अखिलेश को कोई बच्चा कह देता तो भी वह बात को हंस कर टाल देते. अखिलेश ने भी राहुल की तरह विदेश में शिक्षा ग्रहण की लेकिन उनका गांव-देहात से जुड़ाव कभी ख़त्म नहीं हुआ, जिसका उन्हें फ़ायदा भी मिला. उन्हें कभी आलू के खेत में जाकर राजनीति नहीं करनी पड़ी. समाजवादी पार्टी में प्रदेश की जनता को मायावती सरकार का विकल्प नज़र आया और उसने उसे सत्ता सौंप दी. न उससे मुसलामान दूर हुआ न युवा. अन्य वर्गों ने भी उसमें विश्वास जताया.

बहरहाल, सपा की ताजपोशी हो चुकी है. वायदों का दौर समाप्त हो चुका है. अभी सपा के सामने ज़मीनी हक़ीक़त समझने और इसका मुक़ाबला करने की चुनौती है. वहीं उसे उन ख़ामियों से भी दूर रहना होगा जिसके चलते वर्ष 2007 में सत्ता उसके हाथों से खिसक गई थी. ख़ासकर गुंडागर्दी पर लगाम लगाना होगा. सपा सरकार के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा. यह बात उसके शीर्ष नेतृत्व को समझनी होगी. इस बात का अहसास सपा की जीत तय होते ही हो भी गया. उत्तर प्रदेश में राजपाठ बदलते ही सपाईयों ने अपना आपा खोना शुरू कर दिया. पहले ही दिन कई ज़िलों में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ख़ूब हुड़दंग मचाया. सपा के नए नायक अखिलेश यादव को नहीं पता था कि वह जिस समय प्रेस से कह रहे थे कि क़ानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक उसी समय सपाई कहीं फायरिंग कर रहे थे तो कहीं किसी को बंधक बनाए हुए थे. पहली घटना फ़िरोज़ाबाद में घटी. जिसमें विधानसभा परिणाम को लेकर सपा समर्थक सड़क पर उतर आए, पथराव किया. एक बाइक में आग लगा दी. दूसरी घटना संभल में सामने आई. यहां सपा प्रत्याशी की जीत के जुलूस में अवैध असलहों से फायरिंग हुई. एक गोली बसपा समर्थक के 13 वर्षीय पुत्र की कनपटी पर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई. इसी ज़िले में सपा प्रत्याशी की जीत का ऐलान होने के बाद उनकी प्रतिद्वंदी बसपा सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क से झड़प हो गई. सपा समर्थकों ने फायरिंग कर दी एक गोली बच्चे को लग गई. फ़िरोज़ाबाद में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला. यहां सपा के अजीम भाई की जीत की अफवाह फैल गई. बाद में जब पता चला कि भाजपा प्रत्याशी मनीष असीजा विजई हुए हैं तो सपा समर्थक भड़क उठे. झांसी में सपा समर्थित भीड़ ने मतगणना केंद्र पर बवाल काटा, पथराव किया. उसके निशाने पर विशेष रूप से मीडियाकर्मी रहे. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मूकदर्शक बने रहे. एक पत्रकार का सिर फट गया. उससे पहले बबीना विधानसभा की गिनती के दौरान मतगणना कक्ष में अंदर ही कुछ लोगों ने बसपा प्रत्याशी कृष्ण राजपूत और उनके एजेंट से हाथापाई की, जिस कारण भगदड़ जैसा माहौल भी हो गया. अंबेडकर नगर में मतगणना स्थल पर लगी बैरी कैटिंग को सपाइयों ने तोड़ दिया. क़रीब चार सौ सपाई जबरदस्ती मतगणना स्थल पर पहुंच गए. कहीं अर्ध सैनिक बलों ने तो कई जगह चुनाव आयोग ने सपाईयों के हुड़दंग को रोका.

सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फ़िरोज़ाबाद और झांसी में हुई घटनाओं की निंदा तो की, लेकिन वह कोई ऐसा मैसेज जनता को नहीं दे पाए जिससे जनता को लगता कि सपा राज में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी. गौरतलब हो, 2007 में जब बसपा जीती थी तो इस दिन में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला था, तब बसपा नेताओं ने हुड़दंग मचाया था. बसपा के एक नेता ने लखनऊ में एक आवास पर क़ब्ज़ा कर लिया, यह बात जब मायावती को पता चली तो उन्होंने शपथ बाद में ग्रहण की पहले इस नेता से मकान खाली करा कर इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की. मायावती ने सत्ता हासिल करने के हफ्ते भर के भीतर अपने आवास से अपने ही सांसद उमाकांत को गिरफ्तार करा कर भी ख़ूब नाम कमाया था. सपा को नहीं भूलना चाहिए की अगर उसने समय रहते गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ सख्त क़दम नहीं उठाए तो उसकी छवि न केवल दाग़दार होगी, बल्कि उनकी बातों से विश्वास भी उठ जाएगा. समाजवादी पार्टी को नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 2014 में आम चुनाव होने है, उसके पास दो साल का समय अपनी साख बढ़ाने और अपने आप को साबित करने का है. यदि वह जनता की कसौटी पर ख़री नहीं उतरी तो उसे भी ठीक वैसे ही जनता के कोपभाजन बनना पड़ सकता है, जैसे जनता ने मायावती को बनाया है. समाजवादी पार्टी को गुंडागर्दी पर लगान लगाने के अलावा समाजवादी संस्कृति को भी पहचानना होगा. उसे इस फाइव स्टार कल्चर से बाहर निकलना होगा जिसमें अमर सिंह जैसे नेता उसे ले गए थे. अमर के कारण ही मुलायम ज़मीनी नेता की जगह आसमानी नेता कहलाए जाने लगे थे. अब अमर तो नहीं हैं लेकिन अन्य कई नेता हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए समाजवादी विचारधारा को ठेंगा दिखा सकते हैं. पिछली बार मुलायम से जो सबसे बड़ी ग़लती हुई थी, वह उनका चापलूस अधिकारियों और नेताओं से घिर जाना था. अबकी संभवतया मुलायम ऐसी ग़लती नहीं दोहराएंगे.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

फिल्मी चेहरे समाजवादी पार्टी के साथ क़दम से क़दम मिला कर चलते थे. इस बार बुखारी के साथ मुलायम एक टेबल पर बैठे नज़र आए.

कौवे को पितृ पक्ष में आमंत्रित करने के पीछे एक और मान्यता है. यह पक्षी कागभुसुंड समाज से है.





# समाजवादी पार्टी घोषणापत्र

- प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा.
- कक्षा 6 तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा, इंटर तक बिना सरकारी अनुदान के विद्यालयों में शिक्षकों को मानदेय.
- स्नातक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, पिछड़े मुस्लिम इलाकों में विद्यालयों की स्थापना.
- कक्षा 8 तक छात्राओं को 2 साल में दो बार स्कूल ड्रेस मुफ्त दी जाएगी.
- कक्षा आठ तक सभी को पुस्तकें मुफ्त और गरीब छात्रों के लिए छात्रावास और नि:शुल्क कोचिंग.
- इंटर पास छात्रों को लैपटॉप और दसवीं पास छात्रों को मुफ्त में टैबलेट दिए जाएंगे.
- बेरोजगारों को 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता.
- रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा.
- प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती की आयु सीमा 35 वर्ष होगी.
- 35 वर्ष की उम्र के बाद भी नौकरी न मिलने पर 12 हजार रुपये सालाना बेरोजगारी भत्ता.
- प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव होंगे.
- कृषि के क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों को कृषि कार्य के लिए चार प्रतिशत पर ऋण.
- सिंचाई के जितने भी साधन हैं, उनसे किसानों को पानी मुफ्त.
- 65 साल की उम्र के छोटी जात के किसानों को पेंशन.
- किसान की किसी आपदा में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पांच लाख रुपये मिलेंगे.
- किसानों को उत्तम किस्म के बीज और खाद समय पर उपलब्ध कराने का पुख्ता इंतजाम.
- नकली खाद बेचने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
- उपजाऊ ज़मीन का उद्योग एवं बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए अधिग्रहण पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा.
- अगर अधिग्रहण आवश्यक हो किसानों को सर्किल रेट से छह गुना अधिक क़ीमत दी जाएगी.
- मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों की रोशनी में सभी मुसलमानों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा मानते हुए दलितों की तरह जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा.
- रंगनाथ मिश्र आयोग एवं सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार पर पूरा दबाव बनाया जाएगा.
- जो सिफ़ारिशें राज्य सरकार के ज़रिए लागू हो सकती हैं, उन्हें प्रदेश में अतिशीघ्र लागू कराया जाएगा.
- आतंकवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम युवकों को जेलों में डाला गया है, उन्हें फौरन रिहा कराया जाएगा.
- उन मुसलमानों को मुआवज़े के साथ इंसाफ़ दिया जाएगा.
- सरकारी कमीशन, बोर्ड और कमेटियों में कम से कम एक अल्पसंख्यक प्रतिनिधि को सदस्य नियुक्त किया जाएगा.
- इसके साथ कक्षा दस पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा प्रदान की जाएगी.
- मुस्लिम बालिकाओं के विवाह हेतु 30 हज़ार रुपये के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा.
- व्यापारी वर्ग को खुदरा व्यापार में एफडीआई प्रदेश में नहीं आने दिया जाएगा.
- साइकिल तथा रिक्शा बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जाएगा.
- विशेष योजना के तहत उनके रिक्शों को बैटरी, सोलर चार्ज से चालित बनाया जाएगा.
- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पिछले पांच साल के भ्रष्टाचार की जांच के एक आयोग का गठन किया जाएगा.

# भाजपा में फिर वही ढाक के तीन पात

उत्तर प्रदेश में क़दम रखते ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने सोचा था कि भाजपा को वर्ष 2012 के चुनाव में ख़ासी सफ़लता दिलाकर रहेंगे, उनके आने के बाद पार्टी में कुछ जान आई, लेकिन प्रत्याशियों के चयन को लेकर खींचतान मची रही. इसका ख़ामियाजा चुनाव परिणाम में देखने को मिला. भाजपा अन्य पार्टियों की तरह तेजी नहीं दिखा सकी. जब सपा और बसपा तथा कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट देकर विधानसभा क्षेत्रों में भेज चुकी थी. तब भाजपा हाथ पर हाथ धरे बैठी थी. कुछ दिन तो यही सुनने में आता रहा कि भाजपा प्रत्याशियों की सूची अभी गडकरी के लैपटॉप में बंद है. मुख्यमंत्री को लेकर भी पार्टी में अंदरूनी उठापटक बनी रही. आख़िरकार चुनाव के दिन नजदीक आते गए, सिर आई चुनाव तारीखों को देखकर जल्दी से भाजपा प्रत्याशियों की सूची निर्गत की गई. जिसमें परिवारवाद की बू भी आई, इन सबसे हटकर बिना मुख्यमंत्री के टारगेट के बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वह भी एक विभीषण के बल पर. कुशवाहा को पाकर भाजपाई इसलिए खुश रहे कि पिछड़ा वोट तो उनकी झोली में अब आ ही जाएगा, लेकिन कुशवाहा के आने पर भाजपा की बनी बनाई साख़ को धक्का लगा, जिससे पार्टी दो धड़ों में बंटती नज़र आई. योगी आदित्य भी रूठ गए. उन्होंने पार्टी के चुनाव प्रचार से ही हाथ खींचने शुरू कर दिए. इसी प्रकार आपसी तालमेल न बना पाने में भाजपा पीछे रह गई. युवा नेता वरूण गांधी का चुनाव में हिस्सा न लेना, साध्वी और गडकरी के बल पर चुनाव लड़ना, हिंदुत्व की अलख जगाने वाले गुजरात के सफ़ल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक के रूप में सिरकत न करना, बिहार की तर्ज पर जनता दल यूनाइटेड के साथ भाजपा का आपसी समझौता न होना, इत्यादि बातें भाजपा को बुरी तरह हराने वाले फैक्टर हैं. इन्हीं वजहों से पार्टी ऊपर बढ़ने के बजाए नीचे लुढ़क गई. जीत का आंकड़ा वहां तक नहीं पहुंच सका, जहां भाजपा 2007 में रूकी थी. उसे 51 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार यह गिनती 4 सीट घटकर 47 पर आ गई. प्रदेश भाजपा आत्ममुग्ध थी, इसका यही कहना रहा कि नतीजे अप्रत्याशित होंगे. भाजपा अंडर करेंट चल रही है. इसके सारे दावे धरे रह गए. इसके उल्टे भाजपा को करारी शिकस्त मिली. भाजपा के गढ़ में साइकिल ने कुछ ऐसी रफ्तार पकड़ी कि भाजपा के धुरंधर विधायक बुरी तरह पराजित हो गए. रामजी की नगरी पांच बार से जीत रहे लल्लू सिंह भी सपा की आंधी में नहीं बच सके. लगातार जीत रहे पार्टी विधानमंडल दल के नेता ओमप्रकाश सिंह भी अपनी हार बचा नहीं पाए. भाजपा के बड़े बड़े नेता ही नहीं हारे, वरन आधे विधायक जीत से हाथ धो बैठे. लगभग बीस विधायक ऐसे रहे जो विधानसभा की दहलीज लांघने में सफ़ल रहे. कई ऐसे दिग्गज भी हारे जो लगातार जीत दर्ज करा रहे थे.

पार्टी के चुनाव अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष कलराज मिश्र और सूबे में संगठन की नैया पार लगाने आई उमा भारती भी पार्टी को संजीवनी देने में नाक़ामयाब रहीं. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही पथरदेवा से चुनाव हारकर इस्तीफ़े की पेशकश कर चुके हैं. उन्होंने पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली है. उन्होंने कहा कि जनता ने जो फ़ैसला किया है, उसे वह स्वीकार करते हैं. चर्चा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है, लेकिन नितिन गडकरी ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया है, उनका कहना है कि शाही पूर्व की तरह पार्टी के लिए काम करते रहेंगे. भाजपा के जीतने वाले विधायकों में कैराना से हुकुम सिंह, आगरा से जगन गर्ग, कानपुर से सलिल विश्नोई, सतीश महाना, जौनपुर की मुगरा बादशाहपुर से सुरेश खन्ना, वाराणसी से श्यामदेव राय चौधरी, ज्योत्सना श्रीवास्तव, मेरठ कैंट से सत्यप्रकाश अग्रवाल, सहारनपुर से राघव लखनपाल है. नए विधायकों में गोविंदनगर कानपुर से सत्यदेव पचौरी, मेरठ शहर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मेरठ दक्षिण से रवींद्र भड़ाना, सरधना से संगीत सोम, हमीरपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, झांसी से रवि शर्मा, थाना भवन से सुरेश कुमार, वाराणसी उत्तर प्रदेश से रवींद्र जायसवाल, ठाकुर द्वारा से सर्वेश कुमार सिंह, सिराथू से केशव प्रसाद, सिकंदराबाद से विमला सोलंकी, सवाइजपुर सरोजनी तिवारी, रूदौली से रामचंद्र यादव, नूरपुर से लोकेंद्र सिंह, निघासन से अजय, मेरठ दक्षिण से रवींद्र भड़ाना, खजनी से संतप्रसाद, खागा से कृष्णा पासवान, कानपुर कैंट से रघुनंद भदौरिया, देवरिया से जनमेजय सिंह, विसालपुर से रामसरन, नोएडा से महेश कुमार शर्मा, बरेली से अरूण कुमार, कैसरगंज से मुकुट बिहारी वर्मा, बाल्हा से सावित्री बाई फूले शामिल हैं.

भाजपा के हारने वाले विधायकों में फतेहपुर से राधेश्याम गुप्ता, विधायक धुन्नी सिंह, बाराबंकी के जैदपुर से रामनरेश रावत, मिलक से काशीराम, धनौरा से हरपाल सिंह, छर्रा से राम सिंह, मुजफ्फरनगर से अशोक कंसल, वीरेंद्र सिंह सिरोही जैसे भाजपा दिग्गज चुनाव हार गए. वहीं इलाहाबाद की बारा सीट से उदयभान करवरिया, लखीमपुर खीरी के कस्ता से कृष्णाराज, बहराइच के महसी

से विधायक सुरेश्वर सिंह अपनी हार नहीं बचा सके. भाजपा के दाग़ी और दलबदलुओं में हारने वाले अवधेश वर्मा, दद्दन प्रसाद वर्मा, को पराजय का मुंह देखना पड़ा है. वहीं सपा से भाजपा में आए विधायक लोखूलाल, महोबा से विधायक बादशाह सिंह, भाजपा सांसद रमाकांत यादव हैं. रमाकांत यादव अपनी पत्नी रंजना यादव और विधायक पुत्र अरूण यादव को भी विजयश्री नहीं दिला पाए. कुशवाहा का करिश्मा भी कोई काम नहीं कर पाया. भाजपा फिर हाशिए पर आ गई है.

हालांकि भाजपा ने उमा भारती को प्रदेश की कमान सौंप रखी थी, माना यह जाने लगा था कि साध्वी एक बार फिर वर्ष 1991 वाली आक्रामकता दिखाकर भाजपा को जिताने में सफ़ल होंगी. भाजपाई यह भी मान बैठे थे, कि इस बार सवर्ण मतदाता ज़रूर उनके पक्ष में वोट करेगा, क्योंकि सपा और बसपा को उसने पहले आजमाया है. इस बार भाजपा की ही बारी है. साध्वी का हिंदुत्ववादी चेहरा काम न आया. नितिन गडकरी की तरफ़ से भाजपा के संकट मोचक संजय जोशी का करिश्मा काम नहीं कर पाया. उमा का चुनाव लड़ने से आगा पीछा करना, ऐसे में हिंदुत्व का लाभ नहीं मिला, वहीं पिछड़ों का साथ भी नहीं मिल सका. बहरहाल इस जबर्दस्त हार के बाद भाजपा नेताओं को एक बार फिर आत्म परीक्षण करने की नौबत आ गई है कि सेमीफाइनल में इतनी बड़ी शिकस्त क्यों मिली.

## सपा की आंधी में ढहा अटल का किला

वर्ष 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी का गढ़ भी सपा की आंधी में ढह गया. लखनऊ पूर्व की एक सीट कलराज मिश्र बचा पाए हैं. उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा की जूही सिंह को 20818 मतों से हराया. अटल के सखा लालजी टंडन अपने पुत्र की हार को बचा न पाए. पहली बार बनी सीट लखनऊ उत्तर प्रदेश से लालजी टंडन के पुत्र आशुतोष टंडन गोपालजी 45245 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे. लखनऊ मध्य विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विद्या सागर गुप्ता को 22732 मतों से हराया. लखनऊ कैंट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र तिवारी को हराकर अपनी जीत दर्ज की. सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर सपा के प्रत्याशी शारदा प्रताप शुक्ल विजई हुए. भाजपा के वीरेंद्र तिवारी 29510 मत पाकर चौथे स्थान पर पहुंच गए. बक्शी का तालाब विधानसभा सीट भी सपा के पक्ष में गई. इस सीट से भाजपा से सपा में गए गोमती यादव को सफ़लता मिली. भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह चौथे स्थान पर खिसक गए. मलिहाबाद में भाजपा को छठे स्थान पर रहकर संतोष करना पड़ा. यहां भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार को सिर्फ़ 3300 वोट हासिल हो सके. मोहनलालगंज सीट पर भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा वर्मा सातवें स्थान पर चली गईं. उन्हें 7710 मत ही मिले. लखनऊ पश्चिम सीट पर सपा के मुहम्मद रेहान ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के सुरेश कुमार को हराकर शिकस्त दी. भाजपा ने लखनऊ मध्य, पश्चिम और कैंट से हैट्रिक लगा चुके विधायकों को ही इस बार मैदान में उतारा था.

## जनता ने बाहुबलियों को किया किनारे

उत्तर प्रदेश 2012 का चुनाव सपा के पक्ष में प्रचंड बहुमत लेकर पेश हुआ. दो बार से बहुमत की सरकार बनाकर प्रदेश के मतदाताओं ने जागरूकता का परिचय देकर जहां त्रिशंकु की साया को रोका, वहीं अपराधियों को विधानसभा में घुसने से रोक दिया. अतीक अहमद, डीपी यादव, अशोक सिंह चंदेल, जितेंद्र सिंह उर्फ़ बबलू, मदन भैया, मुन्ना बजरंगी जैसे बाहुबली खेत रहे. इस चुनाव में सपा के 199, बसपा के 131, कांग्रेस के 120, भाजपा के 144, रालोद के 16, जदयू के 46, अपना दल के 22, पीस पार्टी के 55, बुंदेलखंड कांग्रेस के पांच, कौमी एकता दल के 13 ऐसे ऐसे प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था. जिनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज थे. निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतरे आपराधिक छवि के लोगों पर भी जनता ने लगाम लगा दी. बसपा के टॉप टेन के प्रत्याशियों में इंद्र प्रताप, पुष्पा शर्मा, मनीष पांडेय, मुहम्मद अहमद अंसारी, महेश चंद्र मिश्र, जावेद इकबाल, असलम, पुष्पेंद्र सिंह, चंद्र कुमार मिश्र, मुहम्मद ताहिर खां को जनता ने पवेलियन लौटा दिया. वहीं कांग्रेस के उत्पल राय, अजय कुमार, कलावती, केशव बाबू, सर्वेश कुमार, ब्रजेंद्र कुमार व्यास, मोहम्मद नई, वीरेंद्र कुमार को भी नकार दिया. भाजपा में जिताऊ बाहुबलियों की सूरत रखने वाले केशव प्रसाद, देवेंद्र सिंह भोले, उपेंद्र, सुरेश्वर सिंह, रामफेर, राम इकबाल, अरूण कुमार सिंह, स्वामी सच्चिदानंद, रामवीर सिंह एवं प्रेम नारायण की तरफ़ से जनता ने मुंह फेर लिया और वे विधानसभा की दहलीज का दीदार नहीं कर सके. इसी प्रकार पीस पार्टी से उम्मीदवार जितेंद्र सिंह उर्फ बबलू, अजय प्रकाश सिंह, प्रदीप, अशोक सिंह चंदेल, यश बहादुर सिंह उर्फ मोनू, जय भगवान, बिल्लू उर्फ जय सिंह, जमई ख़ान तथा अनिल कुमार भी चारों खाने चित हो गए. लेकिन अपवाद स्वरूप 8 आपराधिक मुक़दमों वाले रायबरेली के अखिलेश कुमार सिंह को जनता ने जिताकर विधानसभा पहुंचा दिया. वहीं 15 आपराधिक मुक़दमों वाले मऊ से मुख्तार अंसारी चुनाव जीत गए, लेकिन घोसी की जनता ने उन्हें बैरंग लौटाया. उन्होंने कौमी एकता दल से दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था. इसी दल के रविकांत सिंह, इमरान, हीरावती, गुलफाम, अतहर, जमाल लारी, मनोहर लाल, अरविंद सिंह और मेराज ख़ान चुनाव हारे. इन पर आपराधिक मुक़दमें दर्ज हैं. इसी प्रकार खूंखार आपराधिक छवि के बृजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी से मतदाता दूर रहे. चंदौली ज़िले की सैयदराजा सीट से चुनाव लड़ रहे बृजेश सिंह अहमदाबाद जेल में बंद है. वह प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से उम्मीदवार थे. बृजेश सिंह का अनुमान था कि इस सीट पर बिंद वोटरों की संख्या तक़रीबन 40 हज़ार और क्षत्रिय वोटरों की संख्या क़रीब 30 हज़ार है. चूंकि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की बिंद बिरादरी में अच्छी पैठ मानी जाती रही है. उम्मीद थी यह सारा जोड़–तोड़ उनकी चुनावी नैया पार लगा देगा, लेकिन इस सीट से स्वच्छ छवि के मनोज कुमार ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करा दी है. वहीं भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड से ही चर्चा में आए तिहाड़ जेल में बंद प्रेमप्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी ने भी अपने गृह जनपद जौनपुर की मड़ियाहूं सीट से अपना दल के टिकट पर दांव आजमाया था. मुन्ना बजरंगी पर गंभीर मामले दर्ज हैं. वर्ष 2009 में मुंबई में गिरफ्तार हुए गैंगेस्टर मुन्ना बजरंगी पर मकोका समेत कई मामले चल रहे हैं. इस सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार श्रद्धा यादव ने उन्हें बुरी तरह मात दी है. बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड समेत कई मामलों में चर्चा में रहे अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद अतीक अहमद इस बार अपना दल से ही इलाहाबाद पश्चिम सीट से प्रत्याशी थे. उन्हें राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने बुरी तरह हरा दिया है. बदायूं की सहसवान सीट पर राष्ट्रीय परिवर्तन दल से प्रत्याशी और देश भर में नीतीश कटारा हत्याकांड से चर्चा में आए डीपी यादव भी चुनाव हार गए हैं. डीपी यादव पिछली विधानसभा चुनाव में बसपा की शरण में थे. इस बार उन्होंने सपा का दामन थामने की कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पर सपा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी में प्रवेश देने के लिए साफ़ मना कर दिया था. डीपी यादव को सपा के ओंकार सिंह ने हराकर विजयश्री प्राप्त की. बहरहाल दबंगई के बल पर राजनीति करने वाले इन नेताओं को सपने में भी अहसास न रहा होगा, कि जनता उन्हें इस तरह खारिज कर देगी. राजनीतिक पंडित मानते हैं कि राजनीति में दख़ल रखने वाले ऐसे बाहुबलियों को राजनीतिक पार्टियां इसलिए चुनाव में टिकट देती रही हैं कि वे निश्चित ही जिताऊ साबित होंगे. ऐसा पिछली सरकारों में हुआ भी, लेकिन इस बार जनता ने साफ़ सुथरी छवि के लोगों को ही चुनकर विधानसभा भेजा है. जागरूक युवाओं और महिलाओं ने दबंगों को दरकिनार कर अच्छे लोगों को चुनने में गुरेज नहीं किया है. दो दशकों बाद ऐसा अवसर आया है, जब मतदाताओं ने दबंगों को नकारकर साफ़ सुथरी छवि के लोगों को विधानसभा में भेजा है. यह प्रदेश के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है.

दर्शन शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

# बसपा की सीटों पर सपा की जीत

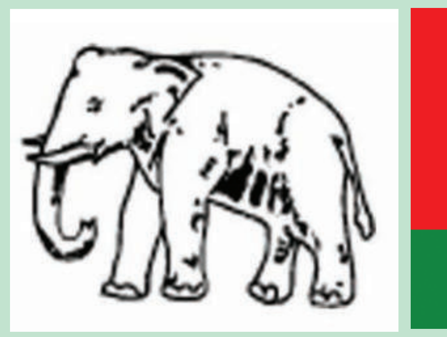

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सरकार के ज़्यादातर मंत्रियों को मुंह की खानी पड़ी. मायावती सरकार के कई मंत्री अपना गढ़ तक बचाने में नाक़ाम रहे. मायावती मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य लालजी वर्मा बहुजन समाज पार्टी के गढ़ समझे जाने वाले अंबेडकरनगर ज़िले की कटेहरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे. पिछला चुनाव उन्होंने इसी ज़िले के टांडा सीट से लड़ा था. परिसीमन की वजह से उन्होंने कटेहरी को सुरक्षित समझा, लेकिन कटेहरी के मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया. वर्मा समाजवादी पार्टी के शंखलाल माझी से क़रीब 17 हज़ार मतों से पराजित हो गए. जौनपुर के जफराबाद सीट से कपड़ा मंत्री जगदीश नारायण राय चुनाव हार गए हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी के शचींद्र नाथ त्रिपाठी ने 4000 से अधिक मतों से पराजित किया. राजस्व मंत्री फागू चौहान को भी हार का मुंह देखना पड़ा है. चौहान को समाजवादी पार्टी के सुधाकर त्रिपाठी ने 21 हज़ार से अधिक मतों से पराजित किया. फागू चौहान घोसी सीट से चुनाव मैदान में थे. प्रदेश के नगर विकास व संस्थागत वित्त मंत्री नकुल दुबे बक्शी का तालाब सीट से चुनाव हार गए, उन्हें सपा के गोमती यादव ने हराया. दुबे मुख्यमंत्री मायावती के नजदीकी सतीश चंद्र मिश्रा का ख़ास माना जाता है. शाहगंज सीट से मत्स्य मंत्री धर्मराज निषाद बुरी तरह चुनाव हारे हैं, वह तीसरे नंबर पर चले गए, उन्हें सपा के शैलेंद्र दुबे ने हराया. होम्योपैथ मंत्री नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से चुनाव हार गए हैं. समाजवादी पार्टी के हाज़ी परवेज ने उन्हें एक हज़ार से अधिक मतों से पराजित किया. पर्यटन मंत्री विनोद सिंह भी बुरी तरह पराजित हुए हैं. किठौर सीट से चुनाव लड़ रहे लखीराम नागर को समाजवादी पार्टी के शाहिद मंजूर ने 12 हज़ार से अधिक मतों से पराजित कर दिया. हरदोई ज़िले के संडीला सीट से चुनाव लड़ रहे मंत्री अब्दुल मन्नान को भी हार का मुंह देखना पड़ा है. मायावती मंत्रिमंडल के सदस्य रामपाल वर्मा हरदोई ज़िले के बालामऊ सीट से चुनाव हार गए हैं. हारने वालों प्रमुख मंत्रियों में जयवीर सिंह भी शामिल हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी के सोबरन ने तीस हज़ार से अधिक मतों से पराजित किया. वरिष्ठ मंत्रियों में शुमार चौ. लक्ष्मी नारायण भी चुनाव हार गए हैं. बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय बमुश्किल अपनी प्रतिष्ठा बचा सके. समाज कल्याण मंत्री इंद्रजीत सरोज मंझनपुर से मात्र तीन हज़ार मतों से जीते हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के शिवमोहन चौधरी को पराजित किया है. पंचायतीराज मंत्री और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य भी जीत गए हैं. उन्होंने कांग्रेस के राजेश जायसवाल को आठ हज़ार मतों से पराजित किया. जीतने वाले मंत्रियों में वेदराम भाटी भी शामिल हैं. खाद्य एवं रसद मंत्री राम प्रसाद चौधरी बस्ती ज़िले की कप्तानगंज सीट से चुनाव जीत गए हैं. उन्होंने समाजवादी पार्टी के त्रयंबक पाठक को पराजित किया है. इन मंत्रियों के हारने के से जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल को जनता से सिरे ने ख़ारिज कर दिया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# फिर कसौटी पर होगा मुलायम राज

पृष्ठ 1 का शेष

मुलायम का पिछला शासन गुंडागर्दी के अलावा तबादला उद्योग और पुलिस भर्ती में धांधली के लिए भी काफ़ी बदनाम हुआ था. ट्रांसफॉर्मर–पोस्टिंग में सपा नेताओं ने ख़ूब कमाई की थी. अच्छा होगा सपा नौकरशाहों की तैनाती में योग्यता का मापदंड तय कर दे और इसी आधार पर नए अधिकारियों की नियुक्ति करे. इससे वह अपनी साख़ पर बट्टा लगाने से बच सकती है. यह काम तब ही हो सकता है जब सपा नेता जनसंवाद करते रहेंगे. मायावती ने जनसंवाद पूरी तरह से बंद कर रखा था, वह अपने मंत्रियों और विधायकों की भी नहीं सुनती थीं. मुट्ठी भर नौकरशाहों ने उन्हें घेर रखा था. उनके ही कहे अनुसार वह फ़ैसले लेने लगी थीं. समाजवादी पार्टी पहली बार बहुमत के साथ सत्ता में आई है. उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है. ऐसे में उसे काम करने की आज़ादी होगी तो उसको अपने ऊपर स्वयं ही नियंत्रण भी रखना होगा. बहुमत मिलने के कारण मायावती तानाशाह जैसी हो गईं थीं. उन्होंने मीडिया का गला घोंटने की कोशिश की तो विपक्ष की जुबान बंद करने का प्रयास. बसपा राज में कई ऐसे फ़ैसले भी लिए गए जो ग़ैर–ज़रूरी थे. चाहें मूर्तिंया लगाने की बात हो या फिर सपा शासनकाल में शुरू किए गए अच्छे कामों को भी रोक देने की बात. मायावती ने बदले की राजनीति की तो जनता ने उनसे बदला ले लिया. मायावती राज में कुछ नाम ऐसे भी रहे जो कभी मुलायम के क़रीबी हुआ करते थे, लेकिन सत्ता बदली तो वह भी बदल गए. वाइन किंग पोंटी और जेपी ग्रुप इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं. मुलायम सिंह के लिए अपने ही कुछ नेताओं को संतुष्ट रखने की भी चुनौती है. ख़ासकर आजम खां जैसे नेताओं को जिनकी महत्वाकांक्षा सत्ता में आते ही हिलोरे मारने लगती है.

## अगड़े वोट बंटने से हारे: मायावती

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों के बाद लखनऊ में अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि समाजवादी पार्टी उनके कल्याण कार्यक्रमों को रोक देगी और प्रदेश को पीछे ले जाएगी. मायावती ने कहा कि प्रदेश में चुनाव परिणाम पार्टी के पक्ष में नहीं रहे, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से सदन को भंग करने की सिफ़ारिश की है और अपना इस्तीफ़ा दे दिया है. मायावती ने अपनी पार्टी की चुनावी हार के लिए अगड़ी जातियों के वोटों में विभाजन को ज़िम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा उनके कल्याण कार्यक्रमों को रोक देगी और उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाएगी. मायावती ने कहा कि कांग्रेस के कमजोर दिखने के कारण मुसलमानों के 70 प्रतिशत मत सपा के पक्ष में गए.

## बुंदलेखंड : नहीं चला सपा का सिक्का

उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा के चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी बुंदेलखंडियों का दिल नहीं जीत पाई. वहां बसपा एक बार फिर अपना दबदबा बनाए रखने में सफ़ल रही, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि बाबू सिंह कुशवाहा फैक्टर इसे नुक़सान पहुंचा सकता है. बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों के नतीजों पर नज़र डालें तो इनमें से सात पर बसपा ने क़ब्ज़ा किया है. सपा को सिर्फ़ पांच सीटों पर ही जीत मिल सकी. भाजपा ने बुंदेलखंड में पिछड़ों को लुभाने के लिए उमा भारती को वहां से लड़वाया तो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे बाबू सिंह कुशवाहा को भी गले लगाया. इस करसत से पार्टी का खाता तो खुला, लेकिन आंकड़ा तीन सीटों से आगे नहीं बढ़ पाया. कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की लगभग तीन–चार वर्षों की सक्रियता और विशेष आर्थिक पैकेज का असर ज़रूर यहां थोड़ा–बहुत दिखा. कांग्रेस की सीटें दोगुनी होकर चार हो गई. प्रदेश में चौथे स्थान पर रहने वाली कांग्रेस यहां तीसरे स्थान पर रही. रूपहले पर्दे से राजनीति के मैदान में भाग्य आजमाने उतरे राजा बुंदेला ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अन्ना हजारे की मुहिम को काफ़ी आगे बढ़ाया. पहली बार क्षेत्र के विकास के लिए पृथक बुंदेलखंड का नारा दिया. बुंदेलखंड कांग्रेस के नाम से पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़ा, लेकिन उनकी यह कोशिश मतदाताओं का अपेक्षित समर्थन पाने में विफल रही और सभी 19 सीटों पर उसे पराजय देखनी पड़ी.

feedback@chauthiduniya.com

# अखिलेश पलटे, नहीं हटेंगी मूर्तियां

बसपा सुप्रीमो मायावती और पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की क़ीमती मूर्तियां सुरक्षित रहेंगी. सपा के स्टार प्रचारक अखिलेश सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में नतीजे आने के कुछ देर बाद मीडिया से यह बात कही. उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद इन मूर्तियों को हटाया नहीं जाएगा. अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी ताकि पिता एवं सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को फिर से सत्ता पर काबिज होने में मदद मिल सके. चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश ने कई मौक़ों पर कहा था कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद उन मूर्तियों का नामोनिशान नहीं मिलेगा. इंजीनियर से राजनेता बने 39 वर्षीय अखिलेश से जब संवाददाताओं ने पूछा कि क्या मायावती की ओर से लगाई गई मूर्तियों को हटाया जाएगा, उन्होंने कहा कि दलित नेताओं की मूर्तियों और स्मारकों को कोई ख़तरा नहीं है. अखिलेश ने पिछले साल कहा था कि उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद मायावती की मूर्तियां इसी तरह हटा दी जाएंगी, जैसा हाल में दुनिया के कुछ देशों में तानाशाहों के मामले में हुआ है. उन्होंने समाजवादी क्रांति रथ यात्रा के दौरान बुंदेलखंड में कहा था कि हाल के दिनों में कुछ देशों में तानाशाहों की मूर्तियां हटाई गई हैं. वर्ष 2012 में जिस दिन समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में आई, मायावती की भारी भरकम मूर्तियों का नामोनिशान नहीं होगा. उन्होंने कहा था कि जिन पार्कों और जगहों पर स्मारक बनाए गए हैं और जहां भारी भरकम राशि ख़र्च की गई है, इन जगहों का इस्तेमाल अस्पताल और शैक्षिक संस्थानों के निर्माण के लिए किया जा सकता था. गौरतलब है कि चुनाव आयोग के आदेश के बाद क़रीब 52 दिन परदे में रहने वाली मायावती की 11 प्रतिमाएं और लखनऊ एवं नोएडा में 200 से अधिक प्रतिमाओं से चार मार्च को परदा हटा लिया गया.

संजय सक्सेना
feedback@chauthiduniya.com

# कौवे की पूजा

बुंदेलखंड में आज अब भी पूर्वजों के श्राद्ध में कौवे को आमंत्रित करने की परंपरा है. यहां पितृ पक्ष में इस पक्षी को दाई–बाबा के नाम से पुकारा जाता है. लोगों का मानना है कि पूर्वज कौवे का भी जन्म ले सकते हैं. बुंदेलखंड में लोग पूर्वज के श्राद्ध की पूर्व संध्या पर ऊंची आवाज़ में कौवे को दाई–बाबा कह कर आमंत्रित करते हैं. श्राद्ध के दिन पूर्वजों के नाम हवन–पूजा के बाद बनाए गए पकवान घरों के छप्पर पर फेंके जाते हैं, जिन्हें कौवे झुंड में आकर खाते हैं. इस इलाक़े में आमतौर पर दो प्रजाति देसी व गंगापारी कौवे पाए जाते हैं, लेकिन कभी–कभार यहां सफ़ेद रंग के कौवे भी दिखाई पड़ते हैं. यदि पितृ पक्ष में सफ़ेद रंग का कौआ किसी के खपरैल में नज़र आए तो उसे स्वर्ग से आया पूर्वज माना जाता है. एक पखवारे तक चलने वाले पितृ पक्ष में कौआ चार बार आमंत्रित किए जाते हैं. बांदा के लोगों का कहना है कि पितृ पक्ष के प्रथम दिन यानी परीवा को पहला न्योता, फिर पूर्वज की मृत्यु की तिथि पर, तीसरा आमंत्रण नवमी तिथि यानी नवें डोकरिया और अंतिम बार पितृ विसर्जन के दिन इन पक्षियों को आमंत्रित कर भोजन कराने की सदियों पुरानी परंपरा है. तेंदुरा गांव के एक बुजुर्ग का कहना है कि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं. मृत्यु के बाद जीव किसी भी योनि में जन्म ले सकता है. कौवे को पितृ पक्ष में आमंत्रित करने के पीछे एक और मान्यता है. यह पक्षी कागभुसुंड समाज से है. कागभुसुंड भगवान शिव का परम भक्त था, धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है. इसलिए कौवे को आमंत्रित कर परिवार के लोग भगवान शिव से अपने कल्याण और अनिष्ट से बचने की कामना करते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# कांग्रेस में कई खलनायक हैं

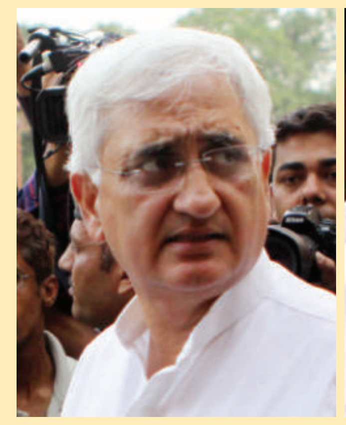

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार की जिम्मेदारी केवल राहुल गांधी ने ही नहीं ली है. कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी दिग्विजय सिंह ने भी इस हार के लिए अपने को कसूरवार बताते हुए इस्तीफ़े की पेशकश कर दी है. दिग्गी राजा वह शख्स हैं जिन्होंने अपने युवराज को काफ़ी सपने दिखाए थे. वैसे चर्चा इस बात की भी है कि राहुल के सारथी बने दिग्विजय सिंह को सजा के तौर पर हासिए पर डाला जा सकता है. हो सकता है कि वह 2014 के लोकसभा चुनाव में लाइमलाइट में न रहें. हाईकमान ने उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने का भी मन बना लिया है. वैसे दिग्गी ही नहीं कांग्रेस के कई और नामी चेहरे केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, श्रीप्रकाश जासयवाल, सपाई से कांग्रेसी बने बेनी प्रसाद वर्मा, सांसद राजब्बर, किक्रेटर से सांसद बने अजहरूद्दीन, हाल में ही सपा छोड़कर आने वाले रशीद मसूद जैसे कुछ नेताओं के वर्चस्व वाले क्षेत्र में कांग्रेस को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा इसकी भी समीक्षा कांग्रेस आलाकमान कर रहा है. कांग्रेस में हार का खलनायक कौन है, इस बात पर नज़र दौड़ाई जाए तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का चेहरा सबसे आगे आता है, लेकिन सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद वर्मा, दिग्गी राजा और जायसवाल ने भी अपनी बदजुबानी से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी. सलमान खुर्शीद और बेनी बाबू अपने को बहुत बड़ा नेता समझते थे, लेकिन जब सलमान अपनी पत्नी और बेनी अपने बेटे तक को नहीं जिता पाए तो उनसे किसी और प्रत्याशी का क्या भला हुआ होगा. गौरतलब हो कांग्रेस के युवराज जो कांग्रेसी चुनाव प्रचार को लीड कर रहे थे, पहले ही कांग्रेस की दुर्दशा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुके हैं. राहुल गांधी ने ख़राब प्रदर्शन की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि यह उनके लिए काफ़ी अच्छा सबक है. चुनाव परिणाम आने के बीच मीडिया से मुखातिब हुए राहुल ने कहा कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूं, यह मेरी हार है. चुनाव प्रचार के दौरान 200 से अधिक रैलियों को संबोधित करने वाले कांग्रेस महासचिव ने कहा कि वह देश की राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और आज के चुनावी नतीजे जो भी हों, उनका काम जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि यह मेरे लिए काफ़ी अच्छा सबक है. मुझे लगता है कि इससे मुझे उन विस्तृत तौर तरीक़ों के बारे में सोचने को मिलेगा, जो मैं करना चाहता हूं. राहुल ने कहा कि मैंने प्रचार की कमान संभाली. मैंने सीधे मोर्चा संभाला इसलिए यह मेरी ज़िम्मेदारी बनती है. हम मिलकर लड़े, अच्छा लड़े लेकिन नतीजे अच्छे नहीं रहे. उन्होंने कहा कि पार्टी ने 2007 से अब तक प्रदर्शन में सुधार किया है लेकिन अभी आगे और बहुत कुछ करना है. कांग्रेस के ख़राब प्रदर्शन की वजह पूछने पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आधार कमजोर है और इसे मजबूत करने की ज़रूरत है. सांगठनिक स्तर पर हम इस स्थिति में नहीं हैं, जैसे हमें होना चाहिए इसलिए हमें आगे और काम करना होगा. उन्होंने कहा कि जनता का रुझान आम तौर पर सपा की ओर था.

कांग्रेस के लिए परेशानी यही नहीं है कि राहुल का सिक्का नहीं चला. रायबरेली और अमेठी में जिस तरह से कांग्रेस को शिकस्त मिली इससे प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लगा है. प्रियंका ने रायबरेली और अमेठी में न केवल कांग्रेस के पक्ष में प्रचार और जनसभाएं की थीं, बल्कि राहुल गांधी के साथ रोड शो भी किया था, लेकिन कांग्रेस की स्थिति सुधरने की बजाए और भी ख़राब हो गई. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चौथे नंबर पर पहुंचने के साथ पार्टी ने जनता के फ़ैसले को स्वीकार किया और कहा यह हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है. पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि जनता ने जो भी फ़ैसला दिया है हम इसे स्वीकार करते हैं, यह हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है और हम पता लगाएंगे हमसे कहां ग़लती हुई. राज्य में पार्टी की भविष्य की रणनीति के बारे में पूछे गए सवालों को उन्होंने टाल दिया और कहा कि इस बारे में आलाकमान फ़ैसला करेगा.

अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com

# अखिलेश अभी मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं– अमर सिंह

समाजवादी पार्टी को प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला. राजनीतिज्ञों को उम्मीद था कि प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा बनेगी. समाजवादी पार्टी की जीत का सेहरा जहां अखिलेश सिंह यादव के सिर बंध रहा है, लेकिन इसके पीछे समाजवादी पार्टी का वो मजबूत संगठन है जिनके लिए कभी समाजवादी पार्टी जानी जाती थी. समाजवादी पार्टी ने इस बार किसी फिल्मी चेहरे को सामने नहीं किया जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में फिल्मी चेहरे समाजवादी पार्टी के साथ क़दम से क़दम मिला कर चलते थे. इस बार बुखारी के साथ मुलायम एक टेबल पर बैठे नज़र आए. इस बार मुलायम के साथ अमर सिंह नहीं खड़े थे. मुसलमानों के रहुनमा बनने वाले मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह को गले लगा बैठे जिसके चलते समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी हार गई. रामपुर में आजम खां ने मुलायम का साथ छोड़ दिया और आज पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव भी मुलायम और अखिलेश की तारीफ़ करते हैं जो कि कल तक अमर सिंह के चलते अखिलेश यादव से बात नहीं करते थे. आज की जीत काफ़ी हद तक पार्टी की एकता को जाता है जो अमर सिंह

के रहते भटक चुकी थी. आज अमर सिंह के ना रहने पर ठाकुरों का वोट भी साईकिल को मिला है जबकि जब अमर सिंह के रहते मुसलमानों का वोट भी समाजवादी पार्टी को गंवाना पड़ा था. कुल मिलाकर साल 2012 की विधानसभा की तस्वीर यही कह रही है कि अमर सिंह के हटते ही समाजवादी पार्टी जीतने लगी.

उधर समाजवादी पार्टी से अलग हुए अमर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव फिलहाल मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हैं. उनकी उम्र इतने बड़े पद को संभालने जितनी नहीं है. अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो बेहतर होगा मुलायम सिंह यादव ही गद्दी संभालें. आगे अमर सिंह ने कहा कि अगर मुलायम ने अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया तो समाजवादी पार्टी में फूट पड़ सकती है. क्योंकि ऐसा करने से मुलायम के भाई शिवपाल सिंह यादव के साथ नाइंसाफ़ी होगी. अमर सिंह का कहना है कि शिवपाल सिंह यादव की मेहनत और लगन को अनदेखा किया गया तो पार्टी में दरार पड़ सकती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चुनाव के समय यहां नेता वोट लेने के लिए तो जमावड़ा लगाए रहते हैं, लेकिन चुनकर जाने के बाद फिर कभी इधर का रूख़ नहीं करते.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

## फ़िरोज़ाबाद

# चूड़ी उद्योग को सरकार का संरक्षण नहीं

फ़िरोज़ाबाद ज़िला चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है. छोटी सी आबादी वाला फ़िरोज़ाबाद देशभर में कांच की राजधानी के नाम से मशहूर है. ज़िले में चुनिंदा बड़े कांच उद्योग के अलावा क़रीब 70 फ़ीसदी छोटे कारखाने हैं जो देशभर में कांच के साजो सामान मुहैया कराने के साथ विदेशों में भी चुड़ियां सप्लाई करते हैं, इतना समृद्ध होने के बावजूद यहां के लोग आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं.

यहां के चुड़ी उद्योग को चीन से कड़ी स्पर्धा मिल रही है. चीन के सस्ते और घटिया बाज़ार ने फ़िरोज़ाबाद के चूड़ी उद्योगों की कमर तोड़ दी है. ऊपर से सरकार इन फैक्ट्रियों को मटियामेट होने से बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही. कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आगरा के 10,400 वर्ग किलोमीटर इलाक़े को ताज संरक्षण जोन घोषित कर वहां कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. ताज नगरी से महज 40 किलोमीटर दूर होने के कारण यह शहर और चूड़ी–कंगन, कांच के दूसरे सामानों के उद्योग बूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं.

फ़िरोज़ाबाद में चुनाव के समय नेता वोट लेने के लिए जमावड़ा लगाए रहते हैं, लेकिन चुनकर जाने के बाद फिर कभी इधर का रूख नहीं करते. यहां के लोगों को उम्मीद है कि कभी तो कोई उनकी फरीयाद सुनेगा और उनके दिन फिरेंगे. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर) के क़रीब बसे इन उद्योगों और उनके कामगारों की बेमिसाल कारीगरी का इतिहास क़रीब 700 साल पुराना है. उद्योग की बदहाली और सरकार से किसी भी तरह की सहायता न मिलने के कारण इन उद्योगों के मालिकों और श्रमिकों का भी इस पेशे से मोहभंग हो रहा है. हो सकता है कि आने वाले समय में इस उद्योग पर चाइना का क़ब्ज़ा हो. फ़िरोज़ाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर दो पर आगरा से 40 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है, जो कि देश एवं प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी आदि से सीधे रेल एवं सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है. फ़िरोज़ाबाद का 1/3 भाग आगरा, मथुरा ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में सम्मिलित है. पर इस चमकती दुनिया के पीछे के अंधेरे को कोई भी नहीं देखना चाहता.

आज भी फ़िरोज़ाबाद के कांच औद्योगिक केंद्रों में मजदूरों के स्वास्थ्य, लेबर एक्ट तथा फैक्ट्री एक्ट के नियमों का पालन नहीं हो रहा है. स्थिति यह है कि 40–40 साल तक एक ही संस्थान में कार्य करने वाले मजदूर को दैनिक वेतनभोग दर्शाकर बिना कोई भविष्यनिधि की सुविधा दिए कारखानों से बाहर कर दिया जाता है. फ़िरोज़ाबाद कांच उद्योग का उद्भव तहसील जसराना में हुआ था. जसराना ऊसर बाहुल्य क्षेत्र था, वहां ऊसर की मिट्टी के ऊपर रेह मिलती थी. वहां के धोबियों द्वारा कपड़े धोने के लिए इस रेह का प्रयोग किया जाता था. कपड़े साफ़ करने के उद्देश्य से एक कढ़ाव में वे रेह को पानी में मिलाकर कढ़ाव में नीचे से आग लगाकर रात भर गर्म करते थे. सुबह उन्हें कढ़ाव में ऊपर एक पर्त जमी मिलती थी जो कांच जैसी होती थी. अन्य जगहों की रेह आदि एवं केमिकल लेकर यहां पर कांच बनाने का कार्य आरंभ हो गया. बाद में रेह की जगह सोडे ऐश का इस्तेमाल होने लगा. कांच उद्योग के कार्य स्वरूप और आकार ने तो बहुत विस्तार ले लिया है. रूस्तम उस्ताद ने हिंदुस्तान में कांच की चूड़ियों के निर्माण के लिए बेलन–भट्ठी का सफ़ल प्रयोग कर चूड़ियों का निर्माण शुरू किया. रूस्तम उस्ताद ने रूस्तम ग्लास के नाम से फ़िरोज़ाबाद में पहली चूड़ी की बेलन पॉट भट्ठी की फैक्ट्री स्थापित की थी. चूडियों के लिए कांच सोडा ऐश, सिलिका सेंट आदि के मिश्रण को 1450 डिगी सेंटीग्रेट पर पिघलाकर बनाया जाता है. इस गर्म कांच से महीन एवं हल्की चूड़ियां बनती हैं. फ़िरोज़ाबाद की पहली फैक्ट्री रूस्तम ग्लास आज बंद पड़ी है और करोड़ों का रोज़गार उपलब्ध कराने वाले रूस्तम उस्ताद के वारिस आज इस रोज़गार में काफ़ी पिछड़े हुए हैं. फ़िरोज़ाबाद का कांच एवं चूड़ी उद्योग आज देश का सबसे बड़ा कांच–उद्योग केंद्र बन गया है. आज फ़िरोज़ाबाद में विभिन्न प्रकार की अलंकृत कांच की चूड़ियों के अतिरिक्त ग्लास वेयर्स, टंबलर्स थर्मस रिफिल, लैंप शेड्स, टेज, जग, साइंटिफिक गुड्स, बीड्स, झाड़ फानूश, बल्व सेल्स, हेड लाइट शीशे, फुलदान तथा किचेन वेयर्स, फिरोजाबाद कांच उद्योग के मुख्य उत्पाद हैं. पूंजी विनियोजन, उत्पादन एवं रोज़गार सृजन की दृष्टि से फ़िरोज़ाबाद जनपद में कांच एवं सिरेमिक्स की 410 इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 72 करोड़ रुपए की पूंजी विनियोजन है. यहां लगभग 8 लाख टन कांच के सामानों का वार्षिक उत्पादन किया जाता है. इन उद्योगों में लगभग दो लाख श्रमिक कांच के उपादों एवं चूड़ी आदि की फिनिशिंग, प्रोसेसिंग, चूड़ी जुड़ाई, मुड़ाई, कटाई एवं अलंकरण के कार्यों में लगे हैं. फ़िरोज़ाबाद कांच उद्योग की वर्तमान स्थिति के अनुसार फ़िरोज़ाबाद में कांच उत्पादन की लगभग 185 इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें से 185 औद्योगिक इकाईयां प्राकृतिक गैस का प्रयोग कर रही हैं. लगभग 80 इकाइयां अभी स्टीम कोयले पर आधारित हैं तथा गैस प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं. लगभग 80–90 इकाइयां ग्लास बीड्स, पोट्रीज आदि अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण करने हेतु प्रयासरत हैं. वर्तमान में फ़िरोज़ाबाद में कांच का कुल उत्पादन लगभग 400 से 425 करोड़ रुपया वार्षिक है, जिसमें लगभग 54 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है. जनपद में कुल 53 इकाईयां निर्यातक इकाइयों के रूप में पंजीकृत हैं. जनपद फ़िरोज़ाबाद में कांच–उद्योग में कुल पूंजी विनियोजन लगभग 72 करोड़ रुपया है. भारत के निकटवर्ती देशों में चूड़ी का निर्यात कुल उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत है, जबकि 85 प्रतिशत चूड़ी की खपत स्वदेशी बाज़ारों में होती है. कांच के अन्य उत्पादों जैसे आर्ट वेयर, झाड़ फानूश, किचेन वेयर आदि का निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा खाड़ी, देशों में किया जाता है. वर्तमान में जनपद की लगभग 53 इकाइयां निर्यात कर रही हैं, जिनका सकल निर्यात लगभग 54 करोड़ रुपया है. प्रशिक्षण एवं तकनीकी विकास के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित कांच उद्योग विकास केंद्र (सीडीजीआई) ही प्रशिक्षण कार्यक्रम या अनुसंधान आदि के कार्य संचालित करता है. यहां कारखानों में गैस के आ जाने से कारखानों की हालत काफ़ी सुधर गई है. चूड़ी का कारोबार हज़ारों से लाखों, लाखों से करोड़ों में तब्दील हो गया है, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि चुड़ियों के कारोबार को करोड़ों में पहुंचाने वाले यहां के कारीगरों की स्थिति दिन–ब–दिन बदतर होती जा रही है. यहां मजदूर आज भी 2400 सेंटीग्रेड तापमान पर पिघलते हुए कांच के लावे के सामने काम करते हैं. फ़िरोज़ाबाद के कांच उद्योग का मजदूर ज़्यादातर टीबी आदि की बीमारियों से ग्रस्त होता है. शिक्षा से कोसों दूर होने के कारण वह इलाज से भी दूर रहता है, दो वक्त की रोटी की जुगाड़ के कारण वह पूरे परिवार को दांव पर लगा देता है. आज भी फ़िरोज़ाबाद के कांच औद्योगिक केंद्रों में मजदूरों के स्वास्थ्य, लेबर एक्ट तथा फैक्ट्री एक्ट के नियमों का पालन नहीं हो रहा है. स्थिति यह है कि 40–40 साल तक एक ही संस्थान में कार्य करने वाले मजदूर को दैनिक वेतनभोगी दर्शाकर बिना कोई भविष्यनिधि की सुविधा दिए कारखानों से बाहर कर दिया जाता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

**फ़िरोज़ाबाद कांच उद्योग का उद्भव तहसील जसराना में हुआ था. जसराना ऊसर बाहुल्य क्षेत्र था, वहां ऊसर की मिट्टी के ऊपर रेह मिलती थी. वहां के धोबियों द्वारा कपड़े धोने के लिए इस रेह का प्रयोग किया जाता था. कपड़े साफ़ करने के उद्देश्य से एक कढ़ाव में वे रेह को पानी में मिलाकर कढ़ाव में नीचे से आग लगाकर रात भर गर्म करते थे. सुबह उन्हें कढ़ाव में ऊपर एक पर्त जमी मिलती थी जो कांच जैसी होती थी.**

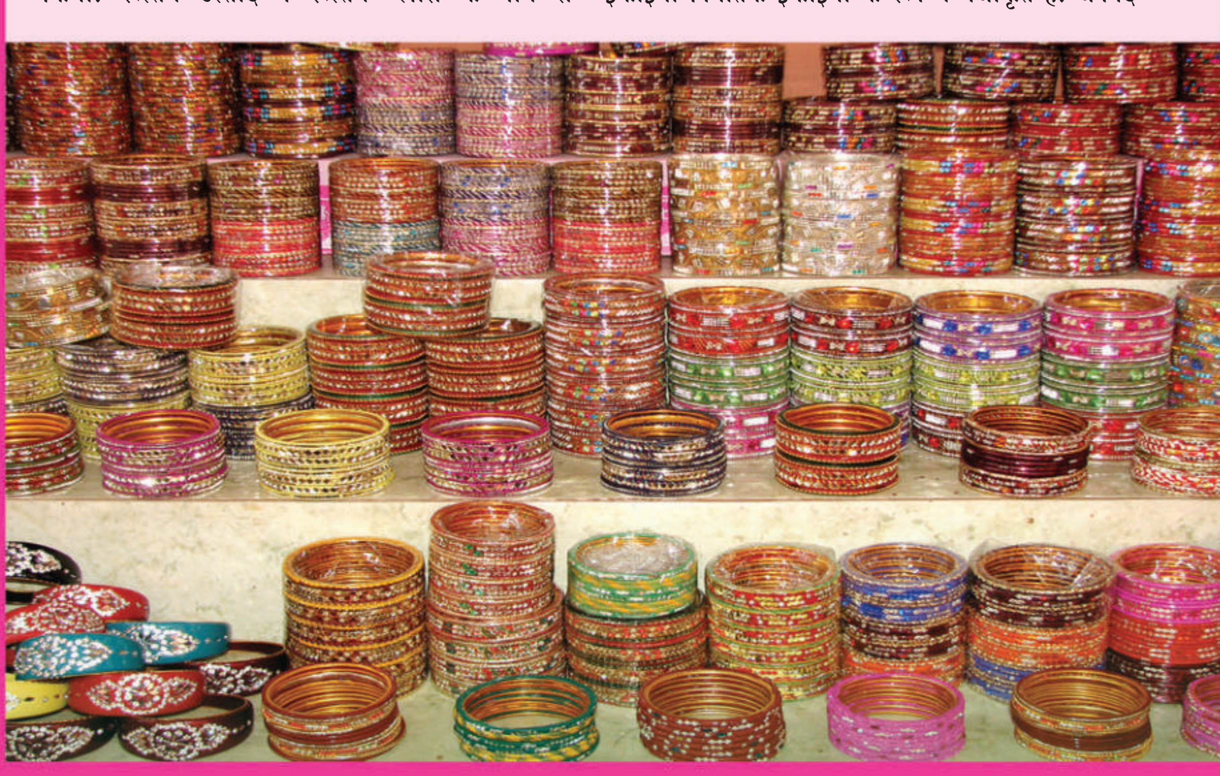

केवल 250/- में वर्ष भर अखबार पढ़ें**
आमंत्रण ऑफर
अख़बार बुक करें और ले जायें आकर्षक उपहार
देश का पहला साप्ताहिक अख़बार
देश के सबसे निर्भीक व विश्वसनीय पत्रकार
संतोष भारतीय
Rs 5
बुकिंग फार्म
रसीद सं. 501
लक्ष्मी मीडिया पब्लिकेशन
कार्यालय प्रबन्ध सम्पादक उ.प्र.एवं उत्तराखण्ड : सी–20, ट्रान्स यमुना, एन.एच.–2, आगरा
फोन : 0526-4064901, ई-मेल : chauthiduniyaup.uk@gmail.com
कृपया विवरण भरें और यह बुकिंग फार्म चौथी दुनिया प्रतिनिधि को दें.
☐ जी हां, मैं इस ऑफर और संलग्न नियमों के अंतर्गत बारह महीने की अवधि के लिए चौथी दुनिया अखबार बुक कराना चाहता/चाहती हूं. बुकिंग राशि 250 रुपये नकद या चेक या डी.डी. तथा अपना आई.डी. प्रूफ लक्ष्मी मीडिया पब्लिकेशन के पक्ष में संलग्न करता/करती हूं.
श्री/श्रीमती..........
पता..........
..........
शहर.......... पिन कोड..........
फोन नं० (घर).......... (मोबाइल)..........
ई-मेल..........
प्राप्त राशि (शब्दों में)..........
द्वारा ड्राफ्ट नं०/चेक नं०..........
दिनांक.......... से.......... तक
हस्ताक्षर प्रतिनिधि
हस्ताक्षर पाठक